Sixth Series, No. 35

Wednesday, April 11, 1979

Chaitra 21, 1901 (Saka)

Lok Sabha Debates

(Seventh Session)

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi

Price Rs-4.00

CONTENTS

No. 35, Wednesday, April 11, 1979, Chaitra 21, 1901 (SAKA)

Oral Answers to Questions.	COLUMS
* Starred Questions Nos. 680 to 685 and 687	1—25
Written Answers to Questions :	
Starred Questions Nos. 686, 688 to 699 and 701	26—40
Unstarred Questions Nos. 6601 to 6605, 6607 to 6621. 6623 6623 to 6646, 6648 to 6745, 6747 to 6770 and 6772 to 6800	40—256
Correcting Statement to Unstarred Question No. 4343 dated 20-12-1978	256—258
Re. Motion for Adjournment	258,261—263
Papers Laid on the Table	258—260
Committee on Private Members' Bills and Resolutions:	
Thirty-first Report	263
Committee on Papers Laid on the Table:	
Fifteenth Report	263
Committee on Petitions:	
Ninth Report	268
Public Account Committee:	
Hundred and Twenty-second Report	268
Committee on Public Undertakings:	
Twenty-second and thirty-third Reports	268-269
Matters Under Rule 377—	
(1) Need for the abolition of capital punishment:	
Shri Ram Vilas Paswan	269-270

The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

COLUMS

(ii) Amenities to the workers of the Steel Yard in Mandi Govind Garh, Punjab:

Shri P. Rajagopal Naidu 270-271

(iii) Reported strike by the employees of Indian Agricultural Research Institute, Pusa, New Delhi:

Shri Saugata Roy 272

(iv) Reported Power crisis in West Bengal:

Prof. Samar Guha 273

Re : Discussion on Demands for Grants 273-274

Demands for Grants, 1979-80 . . . . . 274—373

Ministry of Agriculture and Irrigation:

Shri Nathu Singh . . . . . 274—277
Shri K. Suryanarayana . . . . . 277—282
Shri Mukhtiar Singh Malik . . . . . 282—287
Shri Palas Barman . . . . . 287—290
Shri Tej Pratap Singh . . . . . 290—294
Shri Kacharulal Hemraj Jain . . . . . 294—296
Shri Chandra Shekhar Singh . . . . . 296—303
Shri Venugopal Gounder . . . . . 303—307
Shri Bharat Bhushan. . . . . 307—311
Shri B. K. Nair . . . . . 312—317
Shri R. P. Das . . . . . 317—323
Shri Baldev Singh Jasrotia . . . . . 324—326
Shri Dajiba Desai . . . . . 327—330
Chowdhry Balbir Singh . . . . . 331—334
Shri A. C. George . . . . . 335—339
Shri Dharamasinhbhai Patel . . . . . 339—342
Shri A. R. Badri Narayan . . . . . 342—346
Shri Bhanu Pratap Singh . . . . . 347—358
Shri M. Ram Gopal Reddy . . . . . 358—360
Shri Harikesh Bahadur . . . . . 361—365
Shri K. Mallanna . . . . . 365—369
Shri Hakum Deo Narain Yadav . . . . . 369—373

Half-an-hour Discussion:

Postal Accounts in Haryana:

Shrimati Mrinal Gore . . . . . 373—375
Dr. Ramji Singh 375-376
Shri Brij Lal Verma . . . . . 376—380

Wednesday, April 11, 1979/Chaitra 21, 1901 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Seepage of Cement

+

*680. SHRI NATHU SINGH:

SHRI CHATURBHUJ:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the widespread discontent among the consumers of cement due to seepage of cement from 10 per cent to 40 per cent;

(b) whether Government propose to make it mandatory on cement companies to use kraft paper bags or paper laminated jute sacks to prevent seepage of cement; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (c). Complaints have been received from consumers of loss of cement from the jute bags due to seepage of varying quantities. Government have taken action to encourage the development of better types of jute bags which would minimise seepage to the extent possible. Two different types of improved jute bags are currently undergoing mass trials to judge their suitability. Government are also considering reduction of the proportion of second-hand bags to the minimum to keep down seepage. It is not considered economical to use kraft paper bags or laminated jute sacks for packaging cement.

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आज के दिन और आपके नाम को इतिहास याद रखेगा, क्योंकि पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि आप चार मिनट देरी से आये हैं ।

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब तक कोरम नहीं होगा तब तक वह नहीं आ सकते हैं । **(व्यवधान,)**

MR. SPEAKER: You cannot have both things.

श्री नाथू सिंह : मैं ने आपको धन्यवाद और बधाई दी है । अभी मंत्री महोदय ने बताया कि हम इस बारे में प्रयास कर रहे हैं । आपको मालूम होगा कि इस समय सीमेंट का जितना अधिक ब्लैक हो रहा है, उतना शायद कभी नहीं हुआ है । इसके साथ साथ उपभोक्ताओं को दूसरे तरीके से यह नुक्सान हो रहा है कि सीमेंट को रखने के लिए जो बैग्ज़, बोरे, बनाये जाते हैं, उनमें से बहुत सा सीमेंट बाहर निकल जाता है और उपभोक्ताओं को सीमेंट बहुत कम मात्रा में मिल पाता है । इसके बारे में आज तक कोई प्रयास नहीं हुआ है ।

इसके अलावा कुछ लोग लाभ उठाने के लिए पत्थर पीस कर और राख को सीमेंट में मिला देते हैं । सीमेंट की स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है । बहुत खराब सीमेंट मिलता है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्ज़ और पुलियां वगैरह टूट जाती हैं । क्या सरकार कोई ऐसा इन्तजाम करेगी कि जब सीमेंट कंपनियों में कट्टों या बोरों में सीमेंट भरा जाता है, उससे पहले उनकी जांच हो, ताकि सीमेंट का सीपेज न हो ? जो पुराने बोरे फट चुके हैं, खराब हो चुके हैं, क्या सरकार उनके इस्तेमाल पर पाबन्दी लगायेगी और यह व्यवस्था करेगी कि नये बैग्ज़ काम में लाये जायें ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस समय अधिकांश बोरे नये इस्तेमाल किये जाते हैं, मगर कुछ पुराने भी इस्तेमाल किये जाते हैं । मगर सीपेज का सवाल केवल पुराने बोरों का नहीं है, नये बोरों के बारे में भी यह कहा जा सकता है । आम तौर पर यह सही है कि लगभग 5 फीसदी सीमेंट सीपेज से निकल सकता है । इस बारे में हम कई काम कर चुके है । एक तो सीमेंट रेगुलेशन एकाउंट की मदद से सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से काम करा कर हम दो कंपनियों द्वारा बनाये गये नये बोरों को बाजार में ला रहे हैं, और उसके अनुभव के आधार पर हम आगे का काम करेंगे ।

माननीय सदस्य ने मिलावट वगैरह की बात छेड़ी । अधिकतर राज्य सरकारों ने सीमेंट के वितरण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है । जो एक दो राज्य बचे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वे भी इस के वितरण की जिम्मेदारी अपने हाथ में लें, और इस प्रकार राज्य सरकारें इन सारी शिकायतों को दूर करने के लिए कदम बढ़ायें ।

श्री नाथू सिंह : मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह इस बारे में बहुत जागरुक हैं । क्या वह बतायेंगे कि जो सीमेंट इमपोर्ट किया जाता है, उसमें कौन से बैग्ज काम में लाये जाते हैं—जूट के बने हुए या पालिथीन के बने हुए ? यदि उसमें पालिथीन के बैग्ज काम में आते हैं, जो बरसात में पानी से सीमेंट को खराब नहीं होने देते हैं, और जो बहुत ड्यूरेबल हैं, तो क्या सरकार का इस तरह का कोई विचार है कि जूट के बैग्ज के बजाये वे बैग्ज अधिक काम में लाये जायें ? जूट के बैग्ज भी इस्तेमाल किये जायें, ताकि जूट इंडस्ट्री को भी नुकसान न हो, लेकिन कुछ मात्रा में पालिथीन के बैग्ज भी काम में लाये जायें, जिससे सीमेंट का रखाव ठीक ढंग से हो सके ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह सही है कि विदेशी सीमेंट का आयात पेपर पालिथीन बैग्ज में हो रहा है । लेकिन हमारे यहां एक अर्से से सीमेंट बेचने का काम जूट के बोरों में ही होता रहा है, और जूट उद्योग का भविष्य भी इसके साथ जुड़ा हुआ है । इस लिए मैं नहीं समझता कि हम इस समय इसमें कोई बदल कर सकते हैं । मगर यह भी बात है कि ये जो कागज और पोलिथीन के बोरे ये जूट के बोरे जितने मजबूत नहीं होते । माननीय सदस्य यह भी ध्यान में रखें ।

SHRI JYOTIRMOY BASU: It is a fact that due to serious regional imbalance in the field of production while the cost of production in all plants for a bag of cement is Rs. 4/- and in a new plant Rs. 5/-, the black-market price today has touched the figure of Rs. 60/- per bag. I would like to know from the hon. Minister whether it is or it is not a fact that on an average, a bag of cement has to travel 685 kms. from the point of production to the point of consumption which is much higher than what is used to be sometime ago?

SHRI GEORGE FERNANDES: It is true that the cement has to travel a little longer distance than it used to be in the past. But we are trying to resolve this problem to the extent possible. There are obvious difficulties because cement plants are located in certain parts of the country.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It is a serious regional imbalance.

SHRI GEORGE FERNANDES: We have inherited this imbalance. There is nothing that I can do overnight to set it right. But in respect of the new cement units that we are now commissioning, we are now going in for split location plants where the clirkering of the limestone would be done at one place where the limestone is available and the grinding would be done as far as possible at the principal points of consumption. We have started adopting this new policy. But it will take two years before it really comes into effect. So, we are going to have the problem for a while.

So far as black-marketing is concerned, I want to insist again that today the State Governments are distributing cement. We appealed to the State Governments. There is nothing that I can do as Minister of Industry to end this if the State Governments do not cooperate. Every State Government today is responsible for distributing cement through their agencies and stockists. I would like the State Governments to be a little more concerned about this question and appoint only such stockists who do not indulge in black-marketing. Wherever a stockist indulges in black-marketing, it is possible for the Police and the district administration to identify him and get rid of him. This the State Governments must do and help us.

चौधरी बलबीर सिंह : क्या मंत्री महोदय इस बात की कोशिश करेंगे कि जैसे खाद की जो बोरियां होती हैं उनके अंदर पोलिथिन का एक पैकेज जुदा तौर पर होता है और बाहर दूसरा जूट बैग होता है, उसी तरह सीमेंट में भी वह कर दें ? अगर वह कहते हैं कि बाहर से क्राफ्ट पेपर या दूसरा पोलिथिन का बैग लगवाने में ज्यादा खर्च होता है तो पोलिथिन जो यहां बनता है और खाद में आलरेडी वह इंट्रोड्यूस्ड है उस सिस्टम को क्या यहां इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि बरसात में बाहर का पानी भी असर न कर सके और बोरी जब गिरती है तो उसमें सीमेंट बाहर न निकल सके ? एक बार अगर बोरी सीमेंट की नीचे गिर जाये तो एक किलो हर बार उसमें से सीमेंट बाहर निकल आती है . (व्यवधान).....यह बात है कि दो बार सीमेंट का थैला वह फेंक देते हैं और उसमें से दो किलो सीमेंट निकल आती है । तो यह चीज इससे रुक जाती है अगर पोलिथिन का रैप अलाहिदा से हो जाये और ऊपर जूट बैग हो जाये । ....(व्यवधान)

MR. SPEAKER: This is an advice to the Government.

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह जो नये बैग्स का मैंने यहां जिक्र किया ये दो किस्म के है । यह कहते हैं कि आज जो जूट बैग है उसको और अच्छे ढंग से बीच करा कर जरा मजबूत बैग बनाए जायें, यह काम हो चुका है । दूसरे बिटुमैन लाइन बैग इस समय हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लैमिनेट बैग को इसमें इस्तेमाल में लाना सम्भव नहीं है, इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच गए हैं ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेन्ट के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है । मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेन्ट्स पर जिम्मेदारी डालने से इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है बल्कि सीमेन्ट की ब्लैक-मार्केट प्राइस और बढ़ गई है । जहां पहले सीमेन्ट के एक थैले के पीछे 4-5 रुपए ब्लैक-मार्केट प्राइस थी वहां अब वह बढ़कर 10 रुपए हो गई है । इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स पर जिम्मेदारी डाल कर, जो आपका मकसद था कि भाव कम हो जायेंगे, वह मकसद पूरा नहीं हुआ है । ऐसी हालत में क्या आप कोई दूसरा आल्टर्नेटिव सोच रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसके बारे में हम बातचीत कर लेंगे ।

SHRI RAGAVALU MOHANARANGAM: Even this size of the man cannot catch your eyes so easily!

Sir, it is a well-known fact that especially after the introduction of this permit system consumers are not in a position to get their cement very easily because of inordinate delay on the part of the officers. Here I am not going to talk about the State and the Centre because I know fully well that the hon. Minister has the knack of handling the problems very easily by saying that the State Governments are responsible for this. I want to know a very direct answer for this. Especially after the introduction of the permit system, there is inordinate delay on the part of the officers and the consumers are not in a position to get the permits very easily for their own construction work. I want to know the exact answer from the hon. Minister.

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, there is no Centre-State question involved in this. The distribution of cement is not done by the Ministry of Industry or by the Government of India. The allocation to the State is done by the Ministry of Industry, by the Cement Controller. In so far as the distribution is concerned, it is the State Government's Civil Supplies Department or the concerned Department of the State Government which is today concerned with the distribution of cement in the respective States. They are the ones to give the permits, they are the ones who appoint the stockists and they are the ones to regulate all this. So, as far as I am concerned...

SHRI RAGAVALU MOHANARANGAM: Let us not have the permit system.... (*Interruptions*).

SHRI GEORGE FERNANDES: I am coming to that. It is for each State Government to decide how it wants to sell the cement and prevent blackmarketing. I can only appeal to the State Governments to use the administrative machinery at their disposal

to see that any kind of malpractice is put down.

Development of a Semi-Automatic Dialysis Machine

*681. SHRI DHARMA VIR VASISHT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Engineering Industries, Jaipur, had developed a semi-automatic peritoneal dialysis machine with complete indigenous material; and

(b) if so, whether it had passed the experimental stage together with the details of the unit?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b). It has been ascertained from National Engineering Industries Ltd., Jaipur that no dialysis machine, as such, has been developed by them. At the instance of the Doctors of Sawai Mansingh Hospital, Jaipur the Company's Engineers have only cooperated with the Doctors and developed, designed and manufactured an automatic pump to be used with the dialysis machine of the hospital to expedite dialysis. This pump is undergoing trial tests at the hospital.

SHRI SAUGATA ROY: Sir, this again is another question which has nothing to do with the Central Government. It is not in the national interests. It is meant to favour one company, that too belonging to Birlas. But these things are coming up in Lok Sabha.

SHRI VAYALAR RAVI: It must be in the national interests. Private interests cannot be discussed in this House. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Please sit down. I cannot understand this type of disturbance. (Interruptions). There is nothing prohibiting to talk about a private company because the country is interested in knowing scientific developments. (*Interruptions*).

SHRI VAYALAR RAVI: This Parliament cannot be made so ridiculous.

(*Interruptions*)

SHRI RAGAVALU MOHANARANGAM: They talk so many things about the Members because they are raising a point on a particular company.

श्री धर्मवीर वशिष्ठ : अध्यक्ष महोदय, नेशनल इंजीनियरिंग इस्टीट्यूट में एक ऐसी मशीन डेवलप की गई है । मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि डायलेसिस बजातखुद ईजाद नहीं की गई है लेकिन एक ऐसी स्वचालित पम्पिंग मशीन जरूर बनाई गई है जिससे डायलेसिस करने में जल्दी हो सके । क्या मन्त्री महोदय यह बताना पसन्द करेंगे कि जिससे जल्दी डायलेसिस हो सके और सुविधा हो सके—क्या ऐसी स्वचालित मशीन डेवलप की गई है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस . प्रश्न नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि० जयपुर के बारे में है जोकि बिड़ला की एक कम्पनी है—इस्टीट्यूट के बारे में नहीं है । यह कम्पनी डायलेसिस मशीन बनाने वाली कम्पनी नहीं है ।

Ball Roller and Taper Roller bearings, bicycle steel balls, Rolled Rings, Roller bearing Axleboxes, Spherical Roller bearings for Axleboxes, Steel Castings, Spindle Inserts and Jockey Pulleys.

इन चीजों को बनाने का लाइसेंस उनके पास है और यह चीजें वे बना रहे हैं । डायलेसिस के लिए, किसी औषधि या मरीज के इस्तेमाल में आने वाले किसी यन्त्र के लिए उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और न कोई सम्बन्ध है । अस्पताल के डाक्टर्स गए थे और उन्होंने कहा कि हमारी एक समस्या है, इसमें अगर आप कोई मदद कर सकते हैं तो करें । कम्पनी के जो इन्जीनियर्स थे, उन्होंने अपने ढंग से इस काम को करके उस अस्पताल को मदद पहुंचाने का काम किया है । इस यन्त्र को बना कर न तो बेचने का उनका कोई इरादा है और न यह कोई इस प्रकार का इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च या डवेलपमेन्ट से सम्बन्धित है ।

श्री धर्मवीर वशिष्ठ : जो स्वचालित पम्प बना है उसके लिये मिनिस्टर साहब ने बतलाया है कि इसका ट्रायल हो रहा है । क्या आप यह भी बताने की कृपा करेंगे कि यह ट्रायल कितने दिनों से हो रहा है और अब तक उनका नतीजा क्या रहा है ?

SHRI GEORGE FERNANDES: When we got the question, we made enquiries

and this is what the company has informed us:

—I am quoting from their letter—

"That facts are that the Sawai Mansingh Hospital, Jaipur has a dialysis machine. The doctors wanted improvement in the performance of this machine. Our engineers co-operated with them, developed, designed and manufactured an automatic pump to be used with this machine to expedite dialysis. This pump is under trial in the hospital. This was a gesture of our giving technical help in the field of medicine."

They have got nothing out of this. Nor are we in a position to say that we will utilise their facilities to develop a dialysis machine.

SHRI B. SHANKARANAND: I am on a point of order on this question.

MR. SPEAKER: During Question hour, there is no point of order.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Mr. Saugata Roy takes upon himself the responsibility to decide.... (*Interruptions*).

SHRI B. SHANKARANAND: Members' right to ask questions depends upon certain rules and the question should be restricted under the Rules. My point of order is...

MR. SPEAKER: If questions on private companies are restricted, then many questions will not come.

What does the rule say?

SHRI B. SHANKARANAND: The right to ask a question is governed by the conditions mentioned in Rule 41(2). Sub-rules (vii) and (xvi)... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: There is no point of order during Question Hour. Research and Development is primarily the concern of the Central Government.

SHRI B. SHANKARANAND: This question is not on research and development.

Rule 41(2) says:

"The right to ask a question is governed by the following conditions, namely..."

Sub-rule (vii) reads:

"it shall not relate to a matter which is not primarily the conecrn of the Government of India".

This question has nothing to do with the Government of India. Sub-rule (xvi) says:

"it shall not raise matters under the control of bodies or persons not primarily responsible to the Government of India."

MR. SPEAKER: There is no point of order.... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Qn. 682.

चंबल घाटी क्षेत्र का विकास करने की योजना

682. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा से इटावा तक चंबल घाटी क्षेत्र का आर्थिक विकास करने हेतु केन्द्रीय स्तर पर किन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने परिवारों को लाभ पहुंचा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर रहमान) : अध्यक्ष जी, इसमें तीन तरह की स्कीमें चल रही है—1. मैन्ड्रल पायलेट प्राजेक्ट, जिससे समतल भूमि ठीक रखी जाय, 2. कन्जर्वेशन-आफ़-सायल, और 3. चम्बल-वेली की डेवेलेपमेन्ट स्कीम— ये तीन स्कीमें चल रही हैं।

जहां तक इसमें एम्प्लायमेन्ट देने की बात है— हर परिवार के मुताबिक इत्तिला देना मुश्किल है, लेकिन ये तमाम काम हो जाय तो लगभग 20 हज़ार आदमियों को परमानेन्ट नौकरी मिल सकती है।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : अध्यक्ष जी, मैं आज प्रथम बार किसी मंत्री को बधाई इस लिये दे रहा हूं कि उन्होंने इस सवाल के जवाब को समाप्टल

पर न रख कर सदन में इस का उत्तर दिया है। जहा से ये उत्तर बन कर आते हैं—वह प्लानिंग कमीशन एक सफेद हाथी है और प० जवाहरलाल नेहरू से इस सफेद हाथी को जन्म दिया था। लेकिन वे योग्य महावत थे, जो उस पर सवारी करते थे और अंकुश भी रखते थे, लेकिन अब यह सफेद हाथी यह प्लानिंग कमीशन, बिल्कुल ही निरंकुश हो गया है। और वहा पर नौकरशाही बैठ कर जिस ढंग से सवालों के उत्तर बनाते हैं, वह उचित नहीं है। इस सवाल का जो उत्तर अभी आया है, उस का सवाल से कोई वास्ता नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूं कि पहले सन 1970-71 में तत्कालीन प्रधान मंत्री जी तरफ से जो ई० ई० सी०, यूरोपियन एकोनामिक कम्युनिटी की सहायता से होने वाला काम था, उसको देखने के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री ने एक कमेटी का निर्माण किया था लेकिन वर्तमान सरकार ने उस कमेटी को भंग कर दिया और दूसरी कमेटी को जन्म नहीं दिया है, तो क्या फिर मंत्री महोदय द्वारा डाकुओं से आतंकित उन भयंकर दुर्गम घाटियों चम्बल, यमुना, क्वारी और अन्य सहायक नदियों के कटाव और वहां की जनता की कठिनाइयों, उनके प्रभावग्रस्त जीवन और उनकी आवश्यकताओं को देख कर उनके अनुकूल कोई योजना बनी हुई है या जो बननी है तो उस पर किस तरह से अमल हो, इसके लिये कोई पार्लियामेंटरी टीम बनाने के लिए, क्या वे कोई स्वीकृति देंगे।

श्री फजलुर रहमान माननीय सदस्य ने सवाल तो बहुत लम्बा किया। मैं यहा बताना चाहता हूं कि मैंने जो तीन विषयों का नाम लिया है, वे तीनों स्कीमें आपके लिये हैं। उनमें डाकुओं की वैली और जो आपकी जमीन है, जो आप का क्षेत्र है, वह सब कवर हो जाता है। अब जहा तक पार्लियामेंटरी कमेटी बनाने की बात है तो अध्यक्ष महोदय, आप तो हाउस के सर्वेसर्वा हैं। अगर आप कोई कमेटी बनाते हैं तो मैं उसमें रोड़ा नहीं बन सकता।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया हमें बड़ी खुशी है कि इस टीम के निर्माण के लिए जिम्मेवारी अध्यक्ष जी, आप पर डाली गई है और मैं ऐसा समझता हूं कि आप इसे जरूर स्वीकार करेंगे।

हमारा जो दूसरा पूरक प्रश्न है वह यह है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से पचनदे पर, पंजाब में तो पांच नदियां निकली हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में जहा पचनदा है वे नदियां एक जगह गिरी हैं और उनका वहा संगम हुआ है, एक बांध बनाने के लिए एक योजना 1970-71 में बनी थी और वह 60 करोड़ रुपये की योजना थी। वर्ल्ड बैंक की उस योजना पर, जिसका सर्वे हुआ था, जांच हुई थी और जांच होने के बाद उस पर अमल करने की दिशा में कुछ कदम उठाये गये थे, तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको इस योजना की जानकारी है जिसके तहत विश्व बैंक से सहायता लेकर एक बांध बनाने की बात थी? मैं इसका साफ उत्तर चाहता हूं कि क्या वह योजना कार्यान्वित होगी या नहीं और होगी तो कब तक?

श्री फजलुर रहमान : अध्यक्ष महोदय, योजना किसी खास स्कीम की वर्ल्ड बैंक से बनी थी, इस की इत्तिला तो मुझे नहीं है लेकिन इतना मुझे पता है कि 57 करोड़ रुपया इस नदी घाटी योजना के लिए, चम्बल वैली के लिए मिला था और उस में से अभी तक आप की प्रान्तीय सरकार सिर्फ 17 करोड़ रुपये खर्च कर पाई है।

डा० रामजी सिंह अध्यक्ष महोदय, चम्बल घाटी में जो कुछ हुआ है, वह इतिहास की विशेष बात है, जहां 400 बड़े डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था। चम्बल घाटी का समस्या लॉ एण्ड आर्डर की समस्या नहीं है, वह आर्थिक और सामाजिक समस्या है। तो क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि चम्बल घाटी शांति मिशन की जो योजना सरकार के पास लम्बित है, उसमें से कितनों की उन्होंने स्वीकृति दी है और कितने के विषय में वे विचार कर रहे हैं और वहा की कौन सी विशेष योजना है? आदरणीय प्रधान मंत्री जी से चम्बल घाटी शांति मिशन के लोग मिले थे और वे बहुत आशावान हैं। उनके लिये आर्थिक सर्वेक्षण का कार्यक्रम चालू हो चुका है या नहीं और उनके लिए आर्थिक योजना को पूरा करने के लिये वर्तमान सरकार क्या कर रही है? इस के बारे में मैं जानना चाहता हूं?

श्री फजलुर रहमान अध्यक्ष महोदय, स्कीमों की जहा तक सूची का सवाल है, माननीय सदस्य अगर इसके लिए अलग से सवाल पूछें, तो मैं जवाब दे दूंगा मगर मैंने जो जवाब में बताया है वह यह है कि ये सारी स्कीमें पाइलेट प्राजेक्ट, कन्जरवेशन आफ सायल, डेवलपमेंट आफ केचमेंट एरिया आफ चम्बल वैली, ये सारी चीजें एक दूसरे से सम्बन्धित हैं, जिस से वहा की जमीन की सुरक्षा हो, ऊबड़-खाबड़ जमीन ठीक की जाए, एफारस्टेशन हो और इरींगेशन की फैसिलिटीज हों। उसी मसले को मद्देनजर रखते हुए यह सब किया गया है।

अब जहां तक डकैतों का सवाल है, मैं माननीय सदस्य से यह आग्रह करूंगा कि इसका जवाब देने के लिए काम्पीटेंट होम मिनिस्टर हैं। वह स्कीम बना देंगे कि कब कैसे होगा।

श्री अनन्त राम जायसवाल . वर्ल्ड बैंक की सहायता से इस घाटी के विकास के लिए जो योजना बनाई गई है उसके क्रियान्वयन में आपने बताया है कि अभी तक केवल 17 करोड़ खर्च हुआ है और चालीस करोड़ खर्च नहीं हुआ है। वह योजना शायद 1974 में बनी थी। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेवारी

किस पर है, राज्य पर है या आप पर है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि गति को तेज करने के लिए आपने क्या किया है ?

इस विकास के काम को आपने क्या राज्य पर ही छोड़ दिया है या केन्द्र के प्लान में भी इस के लिए कुछ किया जा रहा है ?

श्री फजलुर रहमान : जहां तक योजना विभाग का सवाल है आवश्यकता के अनुसार, जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हम सकीम्ज और प्लान बनाते हैं । जहां तक एक्सीक्यूशन का सवाल है ज्यादा तर एक्सीक्यूशन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । कोई भी सरकार हो वह निष्क्रिय नहीं बैठ सकती है । लेकिन आप तो जानते ही हैं कि क्या क्या दिक्कत पेश आती है स्कीम का एक्सीक्यूट करने में ।

श्री अनन्त राम जायसवाल : चार्मास करोड़ खर्च क्यों नहीं हुआ ? इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री फजलुर रहमान : काफी लम्बी अवधि तक के लिए यह स्कीम है, उसकी गतिविधि लम्बा चलना है । जर्मन अगर मिल जाए, सारी सुविधाय मिल जाए और जिस एरिया में काम करना है उस एरिया में कितनी कठिनाई है ये सब चीजें आड़े आती हैं । मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि एक बार जा कर स्वयं देख लें और मुझे आशा है कि देखने के बाद वह कहेंगे कि बहुत मेहनत के बाद यह सत्तरह करोड़ रुपया खर्च हुआ है ।

Fire in Nuclear Fuel Complex Hyderabad

*683. SHRI M. RAMGOPAL REDDY: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether fire broke out in one of the wings of the Nuclear Fuel Complex at Hyderabad on the 12th March, 1979; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS & SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The fire broke out in the Zircaloy Fabrication Plant of the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad a little after mid-night in the night shift of 12th March, 1979.

SHRI RAM GOPAL REDDY: It is a very dry reply. The Minister has not given details about the damage. The Minister has not taken a serious note of my question. पूछा था आग लगी क्या, जवाब दे दिया आग लग गई।

It is not the way of replying my question. I have also requested for the details regarding the damage it has done as to how the fire broke out and what are the remedial measures he proposes to take in future. He has not mentioned about this.

PROF SHER SINGH: He has asked a question as to how the fire broke out. The hon. Member has also asked about the damage. There has been a damage to the roof slab, above the kerosene tanks and steel structural members were badly damaged PVC electrical fittings were completely burnt. PVC exhaustive system has also melted. These are the losses. The loss comes to about Rs. 20 lakhs.

SHRI RAM GOPAL REDDY: This is a very serious thing and it is a very dangerous thing and such things are happening in our nuclear complex. I want to know what are the remedial measures which he proposes to take and whether any inquiry has been instituted. If so, what are the details? If the inquiry has not been instituted, I want to know why there is negligence on the part of the Government.

PROF SHER SINGH: An investigation Committee was constituted and that Committee submitted its report. The report is under examination. In the report they have also suggested some measures which should be taken to avoid recurrence of fire.

SHRI SAUGATA ROY: Sir, it is not the first time after the Government has taken over the nuclear complex that there has been fire in such a vital nuclear installation. As you know, last year there was a fire in the Baroda Heavy Water Plant which has put off our nuclear energy programme by almost one year and now we have fire

in the Nuclear Fuel Complex at Hyderabad. There is a consistent effort here and abroad to do some damage or other to the nuclear installations so that the nuclear energy programme of India does not go ahead as per schedule. I would like to know from the hon. Minister whether he would undertake a comprehensive inquiry into the whole security system of our nuclear installations and also find out whether there is any linkage between the different fires and accidents that have occurred in the nuclear installations during the last two year to find out whether there are foreign connections or domestic connections for these accidents.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Or American hand in the matter.

PROF. SHER SINGH: The Investigation Committee has come to the conclusion that this fire was accidental and there was no sabotage involved in this.

DR. KARAN SINGH: With the growth of utilisation of nuclear technology for peaceful purposes, there is going to be expansion of nuclear plants and, as the recent incident in Harrisburg in the United States has shown, there are very real dangers, unless safety measures are built into the system from the very beginning. Will the Government please let the House know whether they are taking adequate measures to ensure that, with the growth of our nuclear capability and technology, these safety measures are built in so that our population is saved from the possible adverse effects of radiation? The Harrisburg incident which is going on even now is a pointer to what should be done by this Government as a preventive measure. Is it being done or not?

PROF. SHER SINGH: Safety measures are in-built into the system and all precautions are taken to see that accidents do not take place. The hon. Member has referred to the Harrisburg incident. Our system is a little different from theirs, but still there could be a possibility. So, all precautions are being taken. I have recently been to the ERC and I myself asked this question whether we have taken all precautions to foresee what type of accidents can take place and whether we have made arrangements for safety measures in-built into the system itself. I have been told that we have done that.

PROF. SAMAR GUHA: It is known that nuclear technology involves very sophisticated machinery and also, that any accident in the nuclear installations may lead to disaster. The Minister has said that precautionary measures are in-built into the system but, in view of what happened earlier in our heavy water plant and also in Hyderabad and, as Dr. Karan Singh has pointed out, in view of the recent incident which created great havoc in USA also, will the Government take immediate steps for reviewing the safety and precautionary measures which are in-built, to see whether these in-built precautionary measures are sufficient or some additional precautionary measures are necessary? Will the Government review the whole system of preacution and safety in all our nuclear installations all over the country?

PROF. SHER SINGH: I welcome the suggestion of the Hon. Member and will take steps to see that all precautions are taken and also to foresee what could be the causes of accidents and how to avoid them.

E.E.C. Delegation to study Electronics Industry

+

*684. SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA:

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to state:

(a) whether a delegation from European Economic Community visit-

ed India recently to study Electronics Industry of the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any agreement has been signed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS & SCIENCE AND TECHNOLOGY & SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) yes, Sir.

(b) A delegation consisting of 27 experts representing major computer companies from the EEC Countries visited India during March, 1979 to explore cooperation in the field of Computers & Electronic Components.

(c) No, Sir.

श्री शंकरसिंह जी वाघेला : इलैक्ट्रोनिक इंडस्ट्रीज की आजकल हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी डिमांड है और इसका अध्ययन करने के लिये यूरोपीय आर्थिक समुदाय से एक प्रतिनिधि-मंडल यहां आया भी था। जवाब में जो कहा गया है कि कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रोनिक संघटक पुर्जों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिये मार्च, 1979 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से एक प्रतिनिधि-मंडल आया था, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उसका आशय क्या था, वह कमर्शियल परपज से आया था या ऐसे ही आया था ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 10 साल में जो बेकारी दूर करने की बात कही जाती है, उसको देखते हुए कम्प्यूटरों के मामले में गवर्नमैंट की नीति क्या है? अब कम्प्यूटर बेकारी को और बढ़ावा देंगे, तो भी क्या सरकार कम्प्यूटरों की और मांग करेगी ? जो प्रतिनिधि-मंडल यहां आया था, क्या उसके आने का परपज बिजनेस था ?

प्रो० शेर सिंह : मैंने निवेदन किया कि यह शिष्टमंडल मार्च के इसी महीने में आया था और पिछले साल भी एक शिष्टमंडल एरिया डिफाइन करने के लिये आया था कि कौन से एरिया में काम हो सकता है, जिसमें दोनों की को-आपरेशन हो सकती है। इस बार जो शिष्ट मंडल आया, उसने पिछले शिष्ट-मंडल का अनुमोदन किया और आगे के लिये कोई ज्वायन्ट बैंचर मिडिल ईस्ट या अफरीकन कंट्रीज में लगा सकते हैं, ट्रेनिंग से कुछ हो सकता है या हार्ड-वेयर और सौफ्ट वेयर की सप्लाई कर सकते हैं, और अपने देश में पैदा कर सकते हैं और हम अपना एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सब बातों पर विचार हुआ, और आगे के लिए क्या हो सकता है, वे सब एरियाज आइडेंटीफाई हुए। इस प्रतिनिधिमंडल ने भी पिछले प्रतिनधिमंडल का अनुमोदन किया।

श्री शंकरसिंहजी वाघेला : हर एक प्रतिनिधि-मंडल का अपना आशय होना है। जो प्रतिनिधिमंडल यहां आया था, क्या उसके साथ इलैक्ट्रानिक एक्विपमेंट मैनुफैक्चर करने वाली हमारी डिफैंस एस्टब्लिशमेंट्स के बारे में भी चर्चा हुई थी ? देश की सुरक्षा के बारे में रैडार एक बहुत नाजुक साधन है। क्या उसके बारे में भी चर्चा हुई थी ?

प्रो० शेर सिंह : डिफैंस के बारे में विशेषरूप से जो इलैक्ट्रोनिक्स चाहिए, उसके बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं हुई।

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Mr. Speaker, Sir, it is said that they have been invited for a meeting and a discussion and exchange of views had taken place and then we dispersed. Now, as far as part (c) of the question is concerned, the hon. Minister has not informed the House as to whether any agreement has been reached or not. The Delegation came to India last year and this year too. I want to know from the hon. Minister whether the delegation that visited last year and this year also had come on its own or they were invited by the Government of India. I want to know whether this delegation drew blank or whether it had met with a total failure.

PROF. SHER SINGH: Sir, under the auspices of the Indo-EEC Joint Commission, our team consisting of 12 computer experts—and they were in a delegation—went to EEC countries including Brussels in November 1977. Now, that was under the auspices of Indo-EEC Joint Commission and their delegation also came to India last year and again we have also received another delegation. Now, this is under the auspices of the Indo-EEC Joint Commission and as I said it is not that they withdrew blank. Areas were identified where we would have cooperation in future. Even for increasing the export in those countries and so many other things were discussed. It is not that they drew blank. But

no formal agreement was signed But areas of potential co-operations were identified.

SHRI VINODBHAI B. SHETH. In this country we have got electronics Engineers of a very high calibre and still we are lagging behind in so far as electronic applicances are concerned. I would like the hon. Minister to give specific reply as to whether the Government is thinking to introduce electronic devices in the services like ports, railways, aircrafts, etc

MR SPEAKER. It does not arise here

अनियंत्रित कपड़े के मूल्य में वृद्धि

+

*685. **श्री अनन्त राम जायसवाल :**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1978 से मार्च, 1979 तक की अवधि में रुई के मूल्यों में कमी होने के बावजूद कपड़ा मिलों ने इस अवधि में अनियंत्रित किस्म के कपड़े के मूल्यों में वृद्धि की थी,

(ख) यदि हां, तो 1 सितम्बर, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक की अवधि में रूई के थोक विक्रय मूल्य सूचकांक में कितनी कमी हुई थी और उसी अवधि में अनियंत्रित किस्म के कपड़े के मूल्य में कितनी वृद्धि की गई थी,

(ग) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मिलों तथा निजी क्षेत्र की मिलों द्वारा तैयार किये जाने वाले अनियंत्रित किस्म के कपड़े के मूल्यों को विनियमित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार का विचार अनियंत्रित किस्म के कपड़े के मूल्य में वृद्धि पर नियंत्रण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, 1978 से मार्च, 1979 की अवधि में कच्ची रूई का थोक बिक्री मूल्य सूचकांक 2.4 प्रतिशत गिरा, जबकि उसी अवधि में सूती कपड़े के थोक बिक्री मूल्य सूचकांक में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ). कपड़े के मूल्यों में घटा-बढ़ी के समूचे प्रश्न के सम्बन्ध में सूती वस्त्र उद्योगपतियों से चर्चा हुई थी तथा उद्योगपतियों से कपड़े के मूल्यों को कम करने के बारे में तुरन्त कदम उठाने के लिये कहा गया था। उद्योगपतियों ने कुछ सुझाव दिये हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री अनन्त राम जायसवाल . क्रय शक्ति की कमी की वजह से अपने देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा साल के ज्यादा हिस्से में अधनंगा रहता है और सन् 64-65 के मुकाबले प्रति व्यक्ति साल की खपत में सन् 77-78 में 3.4 मीटर की कमी हुई है जो अपने में आप में बहुत एलार्मिंग है। इसके अलावा आप ने केवल छः महीने की फिगर दी है। साल भर की यह स्थिति है कि जहां पर रूई के दाम गिरे हैं साढ़े नौ परसेंट वहां कपड़े के दाम करीब तीन परसेंट बढ़ गये हैं और कपड़े के ही नहीं, सूत के, धागे के भी दाम बढ़ गये हैं। तो एक तरफ तो किसान और दूसरी तरफ जिन उद्योगों का आप बढ़ाना चाहते हैं, हैंडलूम वगैरह, उन को इस में नुकसान हुआ है क्योंकि धागे के दाम इतने बढ़ रहे हैं मैन मेड फाइबर के भी और क्लाथ के भी कि उस का चलना मुश्किल हो रहा है। कल एक डेलीगेशन आप से मिला था। तो मैं यह कह रहा हूं कि जो हथकरघा, कन्ज्यूमर और किसान इन तीनों की कीमत पर मिल मालिक दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं उस के बारे में आप ने अपने जवाब में कोई जिक्र नहीं किया है कि आप की तरफ से उसके लिए क्या कार्यवाही हो रही है। आप ने खाली यह बता दिया कि मात्र मालिकों की तरफ से यह आफर है। आप ने इन दामों को रोकने के लिए क्या निश्चित कार्यवाही की यह बताने का कष्ट करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम तो इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन के लोगों से मिले और उन से हमने यह कहा कि उन लोगों ने आज जिस रूप में दाम बढ़ाए हैं वह कम किए जाने चाहिए। उसके बाद यह दाम कम करने की दृष्टि से उन की तरफ से तीन सुझाव आए हैं जिनका मैं ने यहां पर जिक्र किया। हम ने उन से बताया है कि ये तीनों सुझाव हमें मंजूर नहीं है और दामों को उन्हें गिराना पड़ेगा। सूत और कपड़ा दोनों क्षेत्रों में जहां भी दामों को बहुत बढ़ाने का सिलसिला चला है उस को गिराने का काम उन्हें करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से किसी और कदम के उठाए बिना दामों को गिराने का काम वह करेंगे। इस वक्त उन लोगों की बातचीत हमारे मंत्रालय के साथ चल रही है और अगर उन की तरफ से दाम घटने के सिलसिले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जो हमें मंजूर हो तो हम कोई और कदम अपनी तरफ से उठाएंगे जिस के द्वारा दामों को गिराने में मदद मिले।

श्री अनन्त राम जायसवाल : पहले कपड़े के हर मीटर पर रिटेल प्राइस छपा करती थी। आजकल वाली एक्स-फैक्ट्री प्राइस प्लस ड्यूटी छाप देते हैं और शिकायत यह है कि वह भी इतना बढ़ा कर छापते

हैं कि जिस से वे खूब फायदा उठाएं। तो क्या आप पहले की तरह रिटेल प्राइस छपाएंगी और दूसरे, मूल्य को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कंट्रोल लागू करेंगे ? इस के अलावा साल भर तक जो यह स्थिति रही कि बराबर कपड़े के दाम बढ़ते रहे इस बीच में आप का मंत्रालय क्यों सोता रहा इस पर कुछ प्रकाश आप डालेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय, जहां तक दामों पर कंट्रोल लगाने का सवाल है यह जहां तक हमारी समझ है संभव नहीं है क्योंकि कपड़े के दाम पर कंट्रोल लगा कर उस को फिर अमल में लाना एक असंभव जैसी चीज हमें नजर आती है। लेकिन और कई उपाय हैं जिन को अमल में लाया जा सकता है जिन के बारे में हम इस समय विचार कर रहे हैं और जहां तक हर मीटर पर कपड़े का दाम छापने का सवाल है यह मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा कि जब दाम एक अरसे से बढ़ते रहे तो सरकार ने उस के बारे में कोई कदम क्यों नहीं उठाया ?

श्री अनन्त राम जायसवाल : अरबों रुपया मिल मालिकों ने कमा लिया और खाली प्राइवेट ने ही नहीं नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन ने भी कमाया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन इस समय 40 प्रतिशत अपना कपड़ा कंट्रोल कपड़ा बना रहा है और बाकी जो नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन का कपड़ा है वह आम तौर पर चार और पांच रुपये प्रति मीटर के दाम के भीतर है, तो अरबों रुपया नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन के द्वारा मुनाफे के रूप में कमाने का सवाल नहीं है। यह सही है कि निजी मिलों ने इस प्रकार की कोई अपनी नीयत नहीं दिखाई जिस से यह मालूम हो कि लोगों को कपड़ा उचित मूल्य पर मिल सके इस जिम्मेदारी को उन लोगों ने निभाया हो। तो इस पर जो कार्यवाही हमें करनी है वह कार्यवाही हम लोग करने जा रहे हैं।

श्री चिमनभाई एच शुक्ल : जहां तक इस इंडस्ट्री का सवाल है कभी भी सरकार की बात इन्होंने नहीं मानी है।

They are taking Government for granted.

तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि सरकार रा मैटीरियल और फिनिश्ड गुड्स, इन दोनों के बीच में कितना फर्क होना चाहिए यह मानती है तो सरकार जो मानती है उस के लिए वह क्या कदम उठाना चाहती है ?

एक बात मैं और पूछना चाहूंगा। ये मिल वाले कभी भी मानने वाले नहीं हैं। तो क्या सरकार जिस सख्त कदम की बात करती है उस में वह यह बात भी सोचेगी कि सारी मिलों में केवल स्पिनिंग होने दे, बुनाई न होने दे ?

बुनाई का काम भारत सरकार हथकर्घा उद्योग को सौंपे। जबतक यह नहीं होगा तब तक वे अपना मुनाफा कम करने वाले नहीं हैं क्योंकि उनको मुनाफा कमाने की आदत हो गई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को समझता हूं। इसमें मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है कि मिल मालिक इस मामले में जो रुख अपना रहे हैं वह लोकहित वाला रुख नहीं है। सामान्य लोगों की समस्याओं के बारे में उनको किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं है—यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन माननीय सदस्य का जो प्रश्न है कि हम सिर्फ स्पिनिंग का काम इन मिलों में करें और सारा वीविंग का काम बाहर निकाल दें—यह सम्भव नहीं होगा। जितनी पूंजी इस उद्योग में लगी हुई है और जितना कपड़ा मिलें बनाती हैं उसको मद्देनजर रखते हुए यह चीज इस वक्त सम्भव नहीं है। रा-मैटीरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट के जो रिश्ते का सवाल है वह अलग अलग उद्योगों में अलग अलग किस्म का होता रहेगा। टेक्सटाइल मिल्स में भी रा-मैटीरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो अन्तर है उसमें जरूर फर्क रहेगा।

श्रीमती जन्नावती : अध्यक्ष महोदय, 1966-67 में जब रूई का भाव शायद 400—500 रुपए के बीच रहा तब कपड़ा साढ़े चार, पांच रुपए मीटर पर था लेकिन आज रूई का भाव 260 पर चले जाने के बाद भी कपड़ा 11 रुपए मीटर बिक रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं क्या सरकार ने इस मुनाफे को कंट्रोल करके, रूई के जो उत्पादक हैं उनके साथ कोई सामंजस्य करने की चेष्टा भी की है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यही चेष्टा इस समय हो रही है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री जी ने अभी शायद दो तीन दिन पहले कहा कि सरकारी काटन टेक्सटाइल मिलें इस साल बहुत नफा कमायेंगी। उसका कारण यह नहीं है कि उनकी एफीशिएन्सी बढ़ गई है बल्कि उसका कारण यह है कि रूई के दाम बहुत गिर गए हैं और काटन क्लाथ के दाम बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट मिलें उनसे भी ज्यादा गडबड़ कर रही हैं। यह मंत्रालय पिछले दो साल से पेसिव स्पेक्टेटर रहा है। एक एक गज पर बीस-बीस पैसे दाम बढ़े हैं। मेरे पास काटन का इन्डेक्स है।

The cotton index for May 1977 was 214, and for October 1977 it has come down to 160.6. There is a fall of 22.6 per cent.

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप दाम कितना कम करना चाहते हैं और क्या मांग आपने रखी है ? अगर वे दाम कम नहीं करते हैं तो आप क्या कार्यवाही करेंगे ? अभी जैसा यहां पर रिटेल प्राइस छापने के लिए कहा गया तो अगर पहले यह दाम छापे जा सकते थे तो अब क्यों नहीं छापे जा सकते हैं ? आप उनकी कास्टिंग करके एक्स-मिल प्राइस छापिए न कि आप उनके हाथ में दें दें कि जो भी चाहें वे छाप दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जहां तक एन टी सी मिल्स के मुनाफे का सवाल है, इस साल पहली बार एन टी सी. मिलों ने तीन करोड़ का मुनाफा कमाया है। मैं माननीय सदस्य की इस राय से सहमत नहीं हो सकता कि यह मुनाफा रुई का दाम कम होने के कारण या कपड़े का दाम बढ़ाने के कारण हुआ है। जैसा मैं ने पहले बताया, एन टी.सी.की मिलें प्रति वर्ष चालीस करोड़ गज कन्ट्रोल का कपड़ा बनाने के काम में लगी है जिसमें मुनाफा कमाने की कोई बात नहीं है। जो दाम कपड़ा बनाने में लगता है वही दिया जाता है एन टी.सी. मिलों में मुनाफे का कारण यह है कि मार्डनाईजेशन का काम वहां पर किया गया है और एफीशिएन्सी बढ़ाने का काम भी हुआ है। मैनेजमेन्ट में जहां जहां कमजोरियां थीं उनको भी दूर करने का काम हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक कई प्रकार के प्रयास हमने डेढ़ साल में किए हैं। हमने पहली बार एन टी सी की 111 मिलों के जनरल मैनेजर्स को एक जगह पर बुलाकर, उनकी समस्याओं को समझ कर, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया ताकि उनका काम ठीक ढंग से हो। इस तरह से हम ने इस दिशा में कई प्रकार के प्रयास किए हैं जिसका नतीजा यह है कि आज एन टी सी. मुनाफे की ओर बढ़ रही है।

जहां तक मिलों द्वारा मुनाफा कमाने का सवाल है, मिलें मुनाफा जरूर कमायेंगी। कोई मिल मुनाफा कमानी है, यह कोई सवाल नहीं हो सकता है मुनाफा जरूर होगा—उद्योग में निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो—मुनाफा होगा, इस के बारे में कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो उद्योग मुनाफा कमा रहे हैं और दामों पर लगाम लगाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं—इस सम्बन्ध में उन की तरफ से तीन प्रस्ताव हमारे सामने आये हैं और हम ने कहा है कि ये हमें मन्जूर नहीं है। अब जो ठोस सुझाव है वे हम ने रखे हैं और उन से जैसा जवाब आयेगा फिर उस पर कार्यवाही करेंगे।

Memorandum by Christian Welfare Association, Bihar

*687. SHRI KISHORE LAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Christian Welfare Association presented a Memorandum to Governor of Bihar in a mass deputation on 5th March, 1979,

(b) what are their main demands;

(c) whether it is a fact that during the last one year there have been many attacks on their missions/institutions/individuals in various parts of Bihar; and

(d) the forces/institutions behind this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (d) The information is being collected from the Government of Bihar and will be laid on the Table of the House. But just a few hours back we got information from the Bihar Government and on the basis of that I wish to correct my answer.

In regard to part (a), whether it is a fact that Christian Welfare Association presented a memorandum to the Governor of Bihar, the answer is: yes, on the 5th March a memorandum was submitted to the Deputy Secretary to the Governer.

With regard to (b), the demands are: to institute a high level enquiry into the matter of the incident and find out whether there is any institutionalised agency behind this and to bring the culprits to book.

As regards the other parts of the question, information is being collected from the Government of Bihar.

श्री किशोर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं—इन के मेमोरेण्डम देने से पहले वहां कितने क्रिश्चियन-मिशनरीज के मर्डर हुए, जिस से उन के अन्दर सेन्स-आफ-इनसिक्योरिटी पैदा हुई तथा जिन मिशनरीज का मर्डर हुआ क्या उन के बारे में कोई इन्वेस्टीगेशन हुआ ? मैं यह भी जानना चाहता हूं—क्या कोई सेन्ट्रल एजेन्सी जैसे इंटेलीजेन्स ब्यूरो या कोई अन्य एजेन्सी इन क्रिश्चियन मिशनरीज के मर्डर की जांच में लगी हुई है ?

श्री धनिक लाल मण्डल : मुकामा में एक क्रिश्चियन फादर की मृत्यु हुई थी, उस के बाद यह मेमोरेण्डम राज्यपाल महोदय को दिया गया। उस मेमोरेण्डम में उसके पहले की घटनाओं के बारे में जो बातें कही गई है—उन में कहा गया है कि मुंगेर में इस तरह की घटना हुई है, उस के बाद बरौनी में हुई, चनपुटिया, चम्पारन में हुई, रोहतास में हुई—इस तरह की कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है। जहां-जहां इस तरह की घटनायें हुई, उन के सम्बन्ध में मैं ने अभी बताया है, लेकिन इन पर जो सूचना मांगी गई है, वह हम को अभी उपलब्ध

नही है, इस लिये इस सम्बन्ध मे हम आगे नहीं बतला सकते हैं।

श्री किशोर लाल : उस मेमोरेण्डम की चार घटनाओं का जिक्र मंत्री महोदय ने किया, जो बिहार में हुई हैं। ये घटनायें डिस्ट्रिक्ट टाउन्ज में हुई है और 5 मार्च के बाद एक महीने से ज्यादा हो गया है, बिहार सरकार ने गवर्नमेन्ट आफ़ इण्डिया को अभी तक इत्तिला नही दी। क्या गवर्नमेंट आफ इण्डिया यह मुनासिब नही समझती कि माइनारिटी कम्यूनिटीज ने जो मेमोरेण्डम दिया है और उन के अन्दर जो सन्स-आफ़- इन्सिक्योरिटी पैदा हुई है —उस को दृष्टि में रखते हुए सी०बी०आई० या किसी अन्य सैन्ट्रल एजेन्सी से इन्वेस्टीगेशन करावे , ताकि जो लोग उस के पीछे है या जो इंस्टीगेटर्स उन के खिलाफ़ हैं— उन के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जा सके और हमारी माइनारिटी कम्यूनिटीज में जो सेन्स-आफ इन्सिक्योरिटी पैदा हो गई है, उस को दूर किया जा सके ? क्या गवनमेन्ट इस बात को कन्सीडर करेगी कि वह अपनी किसी सैन्ट्रल एजेन्सी के जरिये इसको इन्वेस्टीगेट कराये ?

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, इस में सी०बी०आई० की एन्कवायरी की बात नही है। [अभी जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है— वे उस मेमोरेण्डम में दी गई है —मोकामा, हवेली-खड़गपुर, बरौनी, चनपुटिया, रोहतास— ये सब डिस्ट्रिक्ट टाउन्ज नहीं, हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। इन के सम्बन्ध में बिहार सरकार से जानकारी मंगाई गई है, वह अभी हमें मिली नही है। हम जरूर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जानकारी आ जाय, जो देरी हुई है, उस के लिये हमें खेद है।

SHRI B. P. MANDAL: I want to know, when on 5th March a deputation met the Governor of Bihar, what steps were taken and whether the Governor of Bihar, as the agent of the Government of India, brought it to the notice of the Government of India that minorities in Bihar, especially the Christian minorities, are harassed? May I know also whether it is a fact that RSS is behind these atrocities? (*Interruptions*).

SHRI DHANIK LAL MANDAL: No, Sir.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Development of productivity services by the National Productivity Council

*686. SHRI NATVARLAL B. PARMAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the National Productivity Council had considered proposals for development of productivity services; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b). The development of productivity services is a continuing process with the National Productivity Council since its inception, brief details of which are set out below:

(i) It has developed specialised services in Industrial Engineering, Fuel Efficiency, Plant Engineering, Production Engineering, Behavioural Science and Financial Management.

(ii) It provides training and productivity survey and implementation service in the above areas, undertakes applied research projects and propagates these through publications and various audio-visual aids.

(iii) It is engaged in developing productivity services for small scale industries through the cells established in close collaboration with State Govts.

(iv) It has undertaken the National scheme on supervisory development leading to the award of National Certificate in Supervision and development of trade unions and workers in Productivity.

(v) It is engaged in the development of productivity services

in| Corporate Planning, Management Information System, Marketing, Training Technology and electronic data processing.

(vi) It has developed specialised services in the conservation of furnace oil and non-ferrous metals, postharvest operations of agriculture and rural marketing surveys.

The NPC at its meeting held at New Delhi on 15th March, 1979 decided to reorient its activities to the economic and industrial policy objectives of the Government. The NPC has identified the following areas for immediate action:—

(i) Development of soap and match industries in collaboration with Khadi & Village Industries Commission, Development Commissioner, Small Scale Industries and others.

(ii) Development of Small Scale Sector—Productivity improvement in the existing units and promoting growth of Small Scale Units for the reserved items in collaboration with DCSSI.

(iii) Productivity improvement in public sector organisations where productivity is low or are considered sick. Some of the units|areas identified for immediate studies are State Electricity Board, sick units of the National Textile Corporation and Engineering Industry, Bombay Port, Railway yard in Mugalsarai, etc.

(iv) Promoting appropriate schemes for securing involvement of Trade Unions to enable them to adopt Productivity as an integral part of their movement.

The NPC has already worked out detailed proposals for development of soap and match industries in the cottage|small sector. Proposals in respect of other areas are being worked out by the NPC.

आर्थिक आंकड़ों का संकलन करने की प्रक्रिया

*688. **श्री राम विलास पासवान** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आर्थिक आकड़ों को एकत्र करने की पद्धति और तरीका वर्तमान योजना के लिये पर्याप्त और प्रभावी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसे प्रभावी और अधिक व्यापक बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना के लिए एकत्र आकड़ों का मद-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर रहमान) : (क) से (ग). आर्थिक आकड़ों के एकत्र करने की प्रक्रिया तथा पद्धतियों को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ये अधिक प्रभावी तथा व्यापक बन सकें । इस दिशा में जो मुख्य कदम उठाये गये हैं उन को दर्शाने वाली एक टिप्पणी (अनुबन्ध—I) तथा एक विवरण (अनुबंध—II) जिस में मद-वार तथा वर्षवार आंकड़ों का एकत्र करना दर्शाया गया है, सभा पटल पर रखे गए हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या** LT.—4280/79]

Presence of Mineral deposits in the seas around Andamans

*689. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the presence of highly productive pockets and traces of mineral deposits in the seas around Andamans has been indicated in the preliminary survey by the National Oceanographic Survey Researches recently;

(b) if so, whether Government consider it desirable and feasible to take further exploratory drive in this behalf; and

(c) if not the reasons thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The National Institute of Oceanography, Goa, carried out a preliminary survey of the waters around the Andaman islands in January-February, 1979. The surveys indicated pockets of high biological productivity and trace metals in the waters off the Andamans.

(b) The area is proposed to be surveyed more intensively after completion of the analysis of data already taken

(c) Does not arise.

Plan for better process of Handloom cloth

*690 SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to lay a statement showing:

(a) whether Government have made any plan or propose to take initiative or creating infrastructure like production of yarn, creating facilities for pre-weaving and post weaving and for better processing of the handloom cloth during the Sixth Five Year Plan; and

(b) if so, the details regarding the expected investment?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b). Consistent with the priority given to handloom in the Textile Policy announcement, an integrated set of proposals has been submitted by the Sub-Group for Handlooms and Powerlooms to the Main Working Group on Textiles This includes production of an additional 120 million Kgs. of hank yarn, for which about 1 million new spindles will have to be established. Half of these will be in existing units and the other half in new units proposed to be set up. As regards pre-weaving, post-weaving and processing facilities, a total sum of Rs. 406 lakhs has so far been released by the Central Government to 12 States/Union Territories for the creation of such facilities in the last three years. During the sixth plan period, the Sub-Group of the Main Working Group has proposed a Central outlay of Rs. 1200 lakhs for this purpose. It is envisaged that this amount will be matched by a Sum of Rs. 1500 lakhs in the State sector for the same purpose. These facilities will be set up near handloom clusters to improve the quality and marketability of handloom cloth. The final report of the Main Working Group on Textiles is awaited

Correspondence in Hindi for Banks and Public Undertakings

*691. SHRI A. BALA PAJANOR:

SHRI P. S. RAMALINGAM:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Hindi Committee have decided that correspondence should exclusively be in Hindi for Banks and Public Undertakings in Hindi speaking States, and

(b) if so, the rationale of the decision in the light of the assurances against imposition of Hindi given from time to time?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI H. M. PATEL) (a). No Sir, After a discussion on the subject, the Committee decided that the Deputy Prime Minister (Finance) will consider the issue in the context of the existing rules and the assurances given by the Government.

(b) Does not arise.

Progress of Rajasthan and Narora Atomic Power Stations

*692. SHRI EDUARDO FALEIRO: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Rajasthan and Narora Atomic Power Stations are lagging behind schedule;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) the steps taken in this regard?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) The full quantity of heavy water required for initial filling up of the Rajasthan Station and final commissioning is not yet available. As regards Narora Atomic Power Project there have been delays in the manufacture of some critical nuclear equipments, which could not be obtained from other sources.

(c) In respect of the second unit of the Rajasthan Atomic Power Station, Government has already made arrangements for the procurement of the bulk of heavy water required for the initial inventory and the balance is expected in the current year. As far as Narora Atomic Power Project is concerned, all efforts are being made to expedite the manufacture of critical nuclear equipments.

Utilisation of Raw material for Textile Industry

*693. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item in the *Times of India*, New Delhi, dated February 22, 1979 in connection with the scientific break through in technology for gainful utilisation of agricultural waste materials like banana sheath and pineapple leaf for the utilisation of raw materials for the textile industry:

(b) if so, whether Government have taken any follow-up measures in this regard; and

(c) if so, details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (c). The news item in reference has been seen. This refers to certain processes developed by the Jute Technological Research Laboratory, Calcutta. However, local and indigenous technology using banana leaf and pineapple fibre has been developed in Kerala and Manipur respectively where fabric is being made out of these materials. Government have decided to give full support to the further development of this technology in order to spread this further. Detailed programmes are being formulated in consultation with the concerned State Governments.

H.M.T. Watches

*694. SHRI ISHWAR CHAUDHRY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that proper facilities for sale of H.M.T. watches are not available in the capital;

(b) whether it is also a fact that the maintenance cost is much higher in comparison with those of other makes of watches;

(c) whether Government's attention has also been drawn to short supply of H.M.T. watches resulting in higher price being charged from buyers; and

(d) if so, the measures being taken to improve the situation?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d). There is an increasing demand for H.M.T. watches because of their quality and performance. These watches both at Delhi and elsewhere in the country are sold at prescribed prices through HMT's authorised outlets. In order to eliminate scope for possible malpractices arising from unfulfilled demand for HMT watches,

and to cater to the increasing public demand for these products throughout the country, the production of these watches has been increased. HMT's production in 1978-79 was 33,38,197 watches as compared to 20,58,000 in 1977-78 and 11,71,710 watches in 1976-1977.

New Switch Board Factory by Siemens

*695. SHRI K. A RAJAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Siemens India has a proposal to set up a new Switch Board factory near Calcutta; and

(b) if so, the details of the proposal and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Criminal cases filed for Demolition of Buildings in Turkman Gate, Delhi

*696. SHRI RASHEED MASOOD:
SHRI DINEN BHATTACHARYA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether criminal cases were filed against the residents of Turkman Gate while their buildings were demolished;

(b) if so, the number thereof; and

(c) the number of cases which have been withdrawn so far and the number still pending for withdrawal and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) to (c). Four cases were registered on 19-4-1976. For reasons of inadequacy of evidence, the investigation by the police was closed in respect of two cases The other two cases were withdrawn. No case, is, therefore, now pending.

सिविल सेवाओं में पदों के लिए साक्षात्कार में भाषा का प्रयोग

*697. श्री बलपत सिंह परस्ते :

श्री सरत कार:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सिविल सेवाओं में पदो के लिये साक्षात्कार में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का चयन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बैंकिंग सेवा आयोग, रेलवे तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं मे अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय बनाने का है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०डी० पाटिल): (क) तथा (ख). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ग) फरवरी, 1977 मे गठित बैंकिंग सेवा आयोग को मई , 1978 मे समाप्त कर दिया गया था । राष्ट्रीयकृत बैंको मे लिपिकीय स्टाफ तथा अधिकारी स्टाफ की भर्ती का कार्य अब असाविधिक आधार पर बैंकिंग सेवा भर्ती के सात बोर्डों को सौंप दिया गया है । विभिन्न बैंकिंग भर्ती बोर्डों के अध्यक्षो ने सामान्यतया: (क) वस्तुनिष्ठ स्वरूप के परीक्षण तथा (ख) निबन्ध तथा संक्षेपण के लिये निर्णय किया है । वस्तुनिष्ठ स्वरूप के परीक्षण मे तर्क के परीक्षण तथा अंग्रेजी के परीक्षण सहित कई प्रश्न पत्र शामिल होगे । निबन्ध तथा संक्षेपण का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होगा । बैंक अभी भी अपना अधिकांश कार्य अंग्रेजी मे कर रहे है और इस प्रकार अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक समझा जाता है ।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी तथा हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दी जाती है । इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नही है कि उन परीक्षाओं में अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय बनाया जाए, जिन में इस भाषा का कुछ ज्ञान अनिवार्य समझा जाता है ।

कार्यालय लिपिकों, वाणिज्यिक लिपिकों, टिकट कलेक्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों आदि जैसी, गैर-तकनीकी सामान्य-वर्गों की भर्ती के लिये रेल सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों को सामान्य अंग्रेजी के प्रश्नों के उत्तर देने आवश्यक होते हैं । रेल कर्मचारियों का तबादला समस्त भारतीय रेलों में किया जा सकता है । अतः यह आवश्यक समझा गया है कि समूह "ग" सेवाओं के उम्मीदवारों को रेलों के दिन प्रति दिन के कार्य के लिये अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिये । अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय के रूप में रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं की श्रेणी--I तथा श्रेणी-II में भर्ती के लिए अपनाई गई प्रणाली की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए तथा परीक्षाओं की योजना तथा चयन पद्धतियों में ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए जिनसे कि राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण के कार्यों के संदर्भ में उक्त सेवाओं की भूमिका तथा कार्यों के परिप्रेक्ष्य में समुचित ज्ञान, कौशिल्य तथा गुणों पर पर्याप्त बल दिया जाए, दिनांक 6-2-74 को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त कोठारी समिति के नाम से प्रसिद्ध, भर्ती नीति एवं चयन पद्धति समिति ने साक्षात्कारों में प्रश्नों का उत्तर देने को लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने के संबंध में निम्नलिखित सिफारिश की थी :—

"विचार के लिए हमें भेजा गया एक प्रश्न यह है कि क्या साक्षात्कारों में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उम्मीदवारों को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए । बड़ी सावधानी के साथ विचार करने के बाद हमारी यह राय है कि सामान्य रूप से उम्मीदवारों को अंग्रेजी में उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए । इससे निर्णय की प्रक्रिया में सुविधा होगी, क्योंकि साक्षात्कार बोर्ड के मदस्य, जैसाकि अब है, देश के विभिन्न प्रदेशों से लिए जाते हैं, उन सभी को सामान्य भाषा के रूप में अंग्रेजी का ज्ञान होता है । इससे किसी उम्मीदवार को दूसरी उम्मीदवारों की तुलना में, योग्यता का निर्णय करते समय एकरूपता बनाए रखने में मदद मिलेगी । फिर भी, साक्षात्कार में उम्मीदवारों की योग्यता की जांच करते समय उनके अंग्रेजी भाषा पर अधिकार को इतना अधिक महत्व न देकर उनके गुणों, विशेषताओं और उनके विचार-तत्व को महत्व दिया जाए । अगर किसी आपवादिक मामले में कोई उम्मीदवार किसी भारतीय भाषा में बोलने की इच्छा प्रकट करता है क्योंकि वह अंग्रेजी में अपने विचार पर्याप्त रूप में स्पष्ट करने में असमर्थ है, तो साक्षात्कार बोर्ड को उम्मीदवार को आराम देना चाहिए और उसे किसी भी भारतीय भाषा में उत्तर देने की अनुमति दे दें ।"

सरकार ने कोठारी समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। संघ लोक सेवा आयोग भी इस सिफारिश को उपयुक्त रूप मे कार्यान्वित करेगा ।

Number of Foreign Contracts obtained by E.P.I.

*698. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to lay a statement showing:

(a) what is the total number and value of foreign contracts obtained by the Engineering Projects India Ltd. (E.P.I.) during the last three years;

(b) how many of those foreign contracts have been executed; and

(c) what is the position about the remaining contracts during the same period?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) The Engineering Projects (India) Lt., (EPI) secured fifteen contracts of the total value of Rs. 557.57 crores during the three years 1976-77 to 1978-79. A statement showing the names and value of the contracts is placed on the table of the House.

(b) Four, out of fifteen contracts have been completed.

(c) The remaining eleven contracts are at various stages of implementation.

Statement

Foreign contracts secured by EPI during the period 1976-77 *to* 1978-79

Year in which contract secured/Name of Project	Value of Project (Rs. in lakhs)	Remarks
1976-77		
1. Water Treatment Plant, Bangkok	192·00	Completed.
2 Ain Baghze (Aridiya) Housing Project, Kuwait	23000·00	
3 Mechanical Training Centre, Iskandriya, Iraq	1027·00	Completed.
4 Supply of Surveying Instruments, Iraq	6·04	Completed.
5 Consultancy Report for Guyana Steel Plant	1·30	Completed.
	24226·34	
1977-78		
1 Wadi Jizan Electrification Scheme, Saudi Arabia	1842·00	
2 Sief Palace Area Building, Kuwait	3264·00	
3 35th Brigade Camp, Kuwait	8010·00	
	13116·00	
1978-79		
1. Northern Grain Silos, Iraq	4600·00	
2 Water Research Centre, Iraq	1550·00	
3 Central Grain Silos, Iraq	4200·00	
4 SAAD-3 Project, Iraq	4200·00	
5 Radio & Coloured TV Centre, Iraq	1350·00	
6. Civil Works for Ruwais Refinery, Abu Dhabi	2000·00	
7. Oil Storage Tanks Project, Jaddak, Saudi Arabia	515·00	
	18415·00	

Grand Total (Value)—Rs. 55,757·34 lakhs.

कागज की कालाबाजारी

699. **श्री गंगा भक्त सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि छपाई के लिए प्रयोग मे लाये जाने वाले सफेद कागज के व्यापार में काला बाजारी हो रही है जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रु० का कागज निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने के स्थान पर अधिक कीमतो पर बेचा जाता है,

(ख) यदि हा, तो इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या काम उठाये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार छपाई के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले सफेद कागज के व्यापार में एकाधिकार को समाप्त करने का है जिससे कि छापेखाने को यह कागज उचित मूल्यो पर मिल सके ।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) और (ख). कागज के मूल्यो पर कोई कानूनी नियंत्रण नही है ; फिर भी, यह सच है कि कागज निर्माता तथा व्यापारी कागज की माग मे तेजी से हुई वृद्धि का लाभ उठाकर कागज के मूल्यो मे अनुचित वृद्धि कर रहे है । सरकार कागज की मांग व पूर्ति के बीच के सीमान्त असंतुलन के कारण कागज के मूल्यो मे सट्टे संबधी वृद्धि न होने देने का सुनिश्चय करने हेतु कागज का उत्पादन बढाने हेतु अनेक कदम उठा रही है और वह कागज का आयात करने पर भी विचार कर रही है । कागज उद्योग के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें उनसे कहा गया था कि वे मूल्यो को कम करें। कागज उद्योग की ओर से अभी तक कोई उत्तर नही मिला है । सरकार कागज उद्योग द्वारा मुनाफाखोरी को समाप्त करने एवं कागज का अधिक समान वितरण करने के लिये अनेक उपायो पर विचार कर रही है ।

(ग) कागज के उत्पादन या वितरण में से किसी पर भी एकाधिकार नही है ।

Progress in use of Thorium for Atomic Energy

*701. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) the progress made in India to use Thorium in place of enriched uranium as the principal source of deriving atomic energy in the country;

(b) whether it is a fact that India's source of low quality meagre uranium ore would never make her uranium based atomic energy a viable commercial solution to her energy problem; and

(c) if so, the facts in details and the steps taken thereon?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Thorium cannot replace enriched uranium in reactors which are based exclsively on use of enriched uranium. However, a programme is in hand which will ultimately provide for generating power using thorium which is relatively more abundant. A prototype fast reactor is being constructed at Kalpakkam near Madras.

(b) and (c). The reserves of natural uranium in the country are adequate for the level of nuclear power programme currently envisaged.

Use of CRP in atrocities on Adivasis in Baharagorah Area of Singhbhum District, Bihar

6601. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether he is aware of the atrocities on Adivasis in Baharagorah area of Singhbhum District in Bihar in the month of January, 1979; if so, the facts in details;

(b) whether Adivasis houses have been demolished and ladies have been tortured in the same area, if so, the facts in details;

(c) whether C.R.P. was used in the torture of Adivasis; and

(d) whether Central Government would put a ban on use of CRP by the State Government against the Harijans and Adivasis?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). The Bihar Govenment has reported that no incident of atrocity in the Baharagoran area in January 1979 has been brought to its notice, nor any case of molestation or torture There was, however, one case of alleged rape but on enquiry by the local administration the allegation was found to be incorrect.

(c) and d) The C R P. has been deployed in the area for maintenance of law and order and not for torturing the adivasis The C R.P is deployed whenever re-inforcement is necessary and the State police fall short of requirement.

मध्य प्रदेश कपड़ा निगम के अधीन मिलो को हानियां

6602. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या उद्योग मन्त्री अतारांकित प्रश्न सं० 1387 दिनांक 29 नवम्बर, 1978 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश कपड़ा निगम के अधीन 6 अन्य वस्त्र मिलों में से प्रत्येक मिल को जनवरी, 1976 से नवम्बर, 1978 के दौरान कितनी हानि हुई ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान जिन विभिन्न पार्टियों और फर्मों को तैयार कपड़ा बेचा गया उनसे अदायगियां प्राप्त न हो के कारण कितनी हानि हुई , और

(ग) उक्त मिलो के कपड़े के उत्पादन में प्रयोग में लाये गये घटिया रसायनों और रद्दी एवं रद्दी माल से कपड़े में आये दोषों के कारण कितनी हानि हुई ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जनवरी, 1976 से नवम्बर, 1978 के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) लिमिटेड के नियंत्रणाधीन 6 अन्य वस्त्र मिलों में से प्रत्येक मिल को निम्न प्रकार हानि हुई :—

(लाख रुपयों में)

मिल का नाम	हानि/लाभ की राशि (अनन्तिम)
1. हीरा मिल्स	(—) 155 66
2. स्वदेशी काटन एंड फ्लोर मिल्स	(—) 290 74
3. न्यू भोपाल टैक्सटाईल मिल्स	(—) 145 77
4 बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	(—) 44 75
5. इन्दौर युनाइटेड मिल्स	(—) 595 01
6. कल्याण मिल्स	(—) 319 02

(ख) विभिन्न पार्टियों व फर्मों द्वारा भुगतान न करने/हुण्डियां वापिस कर देने की वजह से इन 6 मिलों को जनवरी, 1976 से नवम्बर, 1978 की अवधि में हुई हानि सम्बंधी जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है । तथापि, उपर्युक्त कारणों से अप्रैल, 1975 से अप्रैल, 1978 की अवधि में 4,00, 111 11 रुपए की हानि हुई थी । (उपर्युक्त हानियों में भुगतान न किए जाने/हुंडियां वापिस हो जाने की वजह से कार्यकारी पूंजी में आई कमी के फलस्वरूप हुई हानि जैसी न दिखने वाली हानियां भी शामिल है ।

(ग) उपयोग में लाए जाने वाले माल के नमूनों की जांच वास्तविक उपयोग से पूर्व की जाती है तथा घटिया माल का उपयोग नहीं किया जाता है । अत इसकी वजह से हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Contracts won in foreign countries by Indian firms in the field of Textiles

6603. SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) how many Indian Firms have won contracts in foreign countries for providing training, teaching and consultancy services in the field of textiles during the last one and a half year;

(b) the amount of the contracts signed by each; and

(c) whether these firms have clean record as far as the payment of taxes in the country is concerned?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

जम्मू व काश्मीर में हथकरघा उद्योग का विकास

6604. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार जम्मू व काश्मीर में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख). जी, हां। जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने कनी शाल उद्योग के विकास हेतु एक परियोजना स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में कार्यकारी पूंजी के अतिरिक्त, तीन वर्ष में 9 43 लाख रु० के अनुमानित व्यय से 100 करघे स्थापित करने की कल्पना है। इसमें सामान्य जाडो में 350 व्यक्ति नियुक्त किये जाएंगे और तीसरे वर्ष के अन्त तक वार्षिक उत्पादन 600 शालो का होगा।

Production of Cotton in Punjab

6605. CHOWDHURY BALBIR SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Punjab is producing a lot of cotton;

(b) whether it is also a fact that there is no cotton and spinning mill there in Public Sector;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether Government propose to open the same in the backward district of Hoshiarpur for the uplift of the same; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) A spinning mill has been set up at Bhatinda in public sector.

(c) Does not arise.

(d) and (e). There is no proposal at present to set up a cotton spinning mill in public sector in Hoshiarpur District However, in addition to one spinning mill of about 50,000 spindles already working in private sector in that District, another spinning mill is being set up there in joint sector.

Bharat Industries and Commercial Corporation

6607 SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to state:

(a) what items of electronics will be manufactured by Bharat Industries and Commercial Corporation and what will be their uses;

(b) when this Corporation is expected to go into production and what items will be manufactured in the initial stages,

(c) how much emuloyment will be provided by this unit directly and indirectly; and

(d) will this unit export certain items manufactured by it and also impart know-how to Indian industries abroad?

THE MINISTER OF STATE ELECTRONICS (PROF. SHER SINGH): (a) and (d). The Department of Electronics has not received any proposal for small scale approval or industrial licence for the manufacture of electronics goods from a firm named M/s. Bharat Industries and Commercial Corporation.

Improvement in Financial Condition of Harijans

6608. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the extent to which the financial condition of the Harijans in the country has been improved during the last two years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): The assessment of the improvements in the financial conditions of the Harijans in the country would require extensive and detailed studies. No information on this scale and magnitude is available. The Planning Commission in the Draft Five Year Plan 1978—83, has made references to the financial conditions of Harijans, like the following:—

> "The prevalence of poverty and inequality, virtually unchanged over the years, can be seen most clearly in the conditions of life of the two disadvantaged groups in our society, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes...So far they have been only marginally involved in the process of development...Scheduled Castes generally constitute a substantial fraction of the population below the poverty line. They have few assets and are generally dependent on share-cropping or agricultural labour."

Charter of Demands by Employees of Rajasthan Atomic Power Project

6609. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the charter of demands submitted by the employees of the Rajasthan Atomic Power Project is pending consideration with Government for more than five years and as a result the employees have now threatened to go on an indefinite hunger strike to press the Government to meet their demand in near future;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps proposed to be taken to take a decision in the matter and preventing the hunger strike?

THE MINISTER OF STATE ATOMIC ENERGY (PROF SHER SINGH): (a), (b) and (c). No, Sir A charter of demands was submitted in June 1977 by the employees of the Rajasthan Atomic Power Project. Conciliation proceedings were held. But they failed. There was then a strike in the Station from September 8, 1977 to January 7, 1978. After the strike was called off unconditionally a series of discussion were held with the Union leaders upto the level of Union Labour Minister. Certain concessions were offered to the employees with a view to an amicable settlement. The Union, however, rejected the offer. Two workmen representing non-recognised union started relay hunger strike on March 12, 1979. In addition another workmen commenced hunger strike on March 19, 1979 and was removed by the police on March 26, 1979. Conciliation proceedings with the recognised Union are in progress.

कारों, स्कूटरों और टायरों तथा ट्यूबों के मूल्यों में वृद्धि

6610. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1978, तथा 28 फरवरी, 1979 को ट्रैक्टरों, ट्रकों, मोटरकारों, स्कूटरों, साइकिलों तथा ट्यूबों और टायरों के दाम क्या क्या थे ;

(ख) क्या इनके मूल्य घटाने के लिये कोई कार्यवाही की गई ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इनके मूल्यों को कब तथा कैसे कम किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) विवरण I तथा II संलग्न है।

(ख) से (घ). इस समय ट्रैक्टरों, ट्रकों, मोटर कारों, स्कूटरों, साइकलों तथा टायरों और ट्यूबों की कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। फिर भी सरकार स्थिति पर निगरानी रखे हुए है।

विवरण—I

थोक मूल्य सूचकांक में शामिल किए गए परिवहन उपस्करों की कीमतें।

वस्तु	विशिष्टता	विपठान	(कीमत रु० में) 1-4-1978 को	28-2-79 को
1	2	3	4	5
ट्रैक्टर . .	एम एफ–19.35 डीजल ट्रैक्टर (खुदरा कीमत)	गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा मुक्त	42966.53	5395 0 50
ट्रक	(1) अशोक लेलैंड "कोमट एल्को 3/1-76" डब्ल्यू बी हुडस चैसी	मद्रास में कारखाने से निकलते समय की कीमत	90012.47	97063 56
	(2) टाटा माडल एल पी 1210 ई/ 52–5195	कारखाने से निकलते समय की कीमत	93021 56	95175 22
कार	(1) स्टैंडर्ड गेज कार	वही	21686 47	कीमत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं
	(2) प्रीमियर पद्मनी कार	वही	28477.48	1–1–79 से तालबन्दी होने के कारण कीमत आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
	(3) सफेद किनारा (साइजो) हिन्दुस्तान एम्बेसडर कार		31056.87	35508.95
स्कूटर .	(1) लाम्बी स्कूटर 150 सी सी	बम्बई में कारखाने से निकलते समय का मूल्य	4172.61	4355.88
	(2) बजाज स्कूटर 150 सी सी वेस्पा	कारखाने से निकलते समय का मूल्य	34.11,51	4052,59
साईकल	(1) एटलस साईकल	गन्तव्य स्थान तक	262.23	287.43
	(2) रैले 24 साइकल (खुदरा कीमत)	रेल भाड़ा मुक्त दिल्ली	358.00	396.00
	(3) हरकुलिस पापुलर ब्लैक टी आई साइकल	गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा मुक्त	312.28	345.00

विवरण-II

थोक मूल्य सूचकांक में शामिल किए गए टायरों तथा ट्यूबों की बीजक बनाते समय की कीमत

क्रमांक	विशिष्टता के साथ वस्तु	विपणन	इकाई	कीमत रु० में	
	टायर	गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा मुक्त	एक	1 4 78 को	28-2 79 को
1	कार टायर रयन बी एस डबल्यू ग्राड-II स्नैपकोट करब 6 70 15— 6 प्लाई रेटिंग ट्रैक सी० 49	वही	वही	279 73	331 28
2	5 90—15 सी० 19	वही	वही	228 74	279 22
3	5 20—14 सी० 49	वही	वही	197 19	241 36
4	5 60—13 सी० 49	वही	वही	208 23	235 05
	ट्रक टायर रयन स्टैण्डर्ड साथ 5 आर आई बी 9 25—20 12 प्लाई रेटिंग एच डब्ल्य/105	वही	वही	1077 43	1304 59
6	9 00—20 12 पी० आर० डब्ल्यू 115/ डब्ल्यू० डब्ल्यू 195	वही	वही	1370 85	1558 57
7	साइकल टायर 28—1—1/2 डब्ल्य० टी० गोल्ड सील	वही	वही	12 20	3 40
8	मोटर साइकल टायर 3—25—19 4 प्लाई रेटिंग यनिवसल	वही	वही	112 36	122 46
9	इनर ट विलर टायर 50—10 4 प्लाई	वही	वही	73 23	80 80
10	ट्रैक्टर टायर रियर 11 2—28 10—28 जी० जी० ए०टी० 6 प्लाई एक्स 99	वही	वही	893 85	998 00
11	ट्रैक्टर टायर रियर 12 4 28/11/—28 जी जी / टी आर ए टी एफ एण्ड आर 6 प्लाई	वही	वही	1074 39	1232 00
12	आफ दी हाई वे टायर्स नायलन टायर्स 12 00 24/25/16 प्लाई	वही	वही	3113 99	4065 85
13	आफ दी हाई वे टायर्स नायलन टायर्स 18 00— 24/25 20 प्लाई	वही	वही	9805 74	9805 74
	ट्यूब	गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा मुक्त	एक	1—4—78 को	28—2—79 को
1	मोटर कार ट्यूब्स 5 90—15(जी—15)	वही	वही	33 13	37 86
2	बड़ी ट्रक ट्यूब्स 9 00 2 (बाइटाइल)	वही	वही	120 05	140 40
3	मोटर साइकल ट्यूबस 3 25 से 16	वही	वही	22 72	26 51
4	टू विलर स्कूटर ट्यूब 3 50 10	वही	वही	16 41	18 94
5	साइकल ट्यूबें हैवी सर्विस	वही	वही	5 00	5 55
6	साइकल ट्यूबें (रोड स्टार)	वही	वही	5 15	5 70
7	ट्रैक्टर ट्यूबें/2 4 28/11—28 जी०जी०टी० आर०/ए०टी०एफ० एण्ड आर०	वही	वही	126 10	145 00
8	ट्रैक्टर ट्यूबें 13 6 28 (12—28) ए०टी०एम० एफ० एण्ड आर	वही	वही	175 12	200 00
9	आफ दी हाई वे ट्यूब्स नायलन 12 00—24/25	वही	वही	217 21	233 44
10.	आफ दी हाई वे ट्यूबस नायलन 18 00—24/25	वही	वही	653 21	653 21

Review of Controlled Cloth Scheme

6611. SHRI K: MALLANNA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to review the controlled cloth scheme;

(b) whether there has been decline in the standard cloth; and

(c) if so, the details regarding the policy of Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) No, Sir.

(b) and (c). As against the production of 419.63 million sq. metres of controlled cloth in mill sector and handloom sector during the entire year 1977-78, production during April, 1978 to December, 1978 (9 months) is about 337.66 million sq. metres. While production figures for the period January, 1979 to March, 1979 are not yet available, the production for the year, 1978-79 as a whole is likely to be higher than the production level of 1977-78.

Preparation of Panel for Selection Grade (Deputy Secretary) of C.S.S.

6612. SHRI ISMAIL HOSSAIN KHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether for preparing panel for Selection Grade (Deputy Secretaries) of the Central Secretariat Services only those officers of Grade-I of the Service (Under Secretaries) whose last five years' reports have been categorised atleast 'very good' are considered.

(b) if so, whether this criteria is being adopted in respect of other services also or only in the case of Central Secretariat Service;

(c) whether adequate weightage is given to the officers who have put in sufficiently long service as Under Secretaries and have also reached the maximum of the scale; or is there any proposal to compensate them by giving them special increments or allowance; and

(d) whether there is any proposal for the premature retirement of such of the officers who have been left over for promotion for several years by giving them same retirement benefits such as cash payment of Leave Salary etc.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S D. PATIL): (a) No, Sir. Vacancies in the Selection Grade of the Central Secretariat Service are to be filled up by promotion of permanent officers of Grade I who have rendered not less than 5 years approved service in that Grade and are included in the Select List for Selection Grade prepared under sub-rule 4 of Rule 12 of the C.S.S. Rule 1962 and related regulations framed thereunder.

(b) Does not arise.

(c) and (d The selection of eligible Grade I officers of the C.S.S for promotion to Selection Grade is made on the basis of merit. No proposal for compensating the officers left over for promotion is under consideration.

Representation from the Staff of Richardson and Cruddas Ltd.

6613. SHRI R. K MHALGI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have received a representation dated 20th February, 1979 from the members of the Staff of Richardson and Cruddas Ltd. Byculla Bombay (a Govt. of India Undertaking);

(b) if so, when and what are the grievances put forth and demands made therein; and

(c) what action Government have taken so far or propose to take in near future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) Yes, Sir.

(b) The monthly rated staff and peons of the Byculla Iron Works of M/s. Richardson & Cruddas (1972) Lt, went on strike from 7-9-78 to 8-1-79 During the period of the strike, some employees were found indulging in acts of vandalism and inciting other striking employees to indulge in such acts of misconduct. Thirteen such employees were suspended pending completion of departmental enquiries against them. In the representation dated 20-2-79, two of the suspended employees had requested for withdrawal of orders of suspensions and payments of wages for the period of their suspension. They had also stated that the management had not taken similar action in respect of the employees of the Mulund Works of the Company, who were also on strike during the same period.

(c) After the suspended employees had submitted a written apology expressing regret for their conduct, the management have withdrawn the orders of suspension and they have also closed the enquiries against them. These employees have since been allowed to resume their duties. Since the Company's Standing Orders do not provide for payment of wages during the period of suspension, it is not possible for the Company to pay wages to these employees for that period.

No charge sheets were served on the employees of the Mulund Works as none of them had indulged in acts of vandalism or misconduct during the period of strike.

Seizure of Tools of Cultivators in Andaman and Nicobar Islands

6614. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in 1st week of February, 1979, the tools of the cultivators belonging to Mowa Dera, Tushnabad Panchayat, under South Andaman Tahsil in Andaman and Nicobar Islands were seized by the Forest Officers by using armed forest Guards,

(b) whether it is a fact that these cultivators were working on the land allotted to them by Andaman and Nicobar Administration; if so, the reasons of harassing the cultivators and seizing their agricultural tools with details of the tools and the further development in the matter, and

(c) whether Government are aware about the similar seizure of Agricultural tools from the farmers of Chouldari while they were working on their allotted lands on the 10th January, 1978 by one K. P. Achaiya, Range Officer; if so, the details thereof and the action Government propose to take against the Forest Department?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) Yes, Sir.

(b) According to the report received from Andaman and Nicobar Administration these cultivators were clearing forest growth within an area which according to forest records and maps was protected forest area and clearing of forest growth within such areas is prohibited under the forest Act. Five dahas and two felling axes were seized from them which were subsequently released on intervention by the revenue authorities.

(c) Seizure of Agricultural tools from the farmers of Chouldari area was made because they were clearing forest growth within the protected forest area. The seized implements are still in the custody of the Forest Department pending finalization of the case.

News Item Captioned 'Tribunals for Government Employees'

6615. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the news report appearing in the *Indian Express* dated the 21st March, 1979 under the caption "Tribunals for Government employees", and

(b) if so, what is the reaction of Government to the various decisions reported to have been taken or under consideration of Government, facts of the matter and the latest position regarding the proposals finalised and details of action taken/proposed for the implementation of the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) A news item captioned 'Tribunals for Government employees' appeared in the Indian Express dated the 21st March, 1979.

(b) The details of the proposal to set up Administrative Tribunal for employees engaged in connection with the affairs of the Union have not yet been finalised.

News item captioned 'Abdullah ready for Partition of State'

6616. SHRI VIJAY KUMAR N. PATIL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news report appearing in the *Indian Express* dated 21st March, 1979 under the caption "Abdullah ready for partition of State"; and

(b) if so, what is the reaction of Government to the various observations made therein?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) Yes, Sir.

(b) According to our information, the Chief Minister of Jammu and Kashmir had, while speaking in the State Legislative Assembly on the 21st March, 1979, refuted the allegation that he wanted a division of the State.

The Government are opposed to, and disapprove of, any suggestion or move towards the division of the State on regional considerations.

Setting up of Vanaspati Factory in Orissa

6617. SHRI D. AMAT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government of Orissa has planned to set up a Vanaspati factory and a spinning mill at Bolangir and Titlagarh of Bolangir district of Orissa; and

(b) if so, when the concerned factory and mill will be set up and the proposed amount to be invested in these concerns?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Engaging of a Lawyer by CSIO, Chandigarh

6618. DR. SARADISH ROY: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether the Central Scientific Instruments Organisation (CSIO) Chandigarh engaged a lawyer for representing them before the Assistant Labour Commissioner (Central) Chandigarh and before the Registrar, Trade Unions, Chandigarh in the matter of certain industrial disputes between the management and the workers;

(b) how much fees was paid to the lawyer and whether lawyer represented the management in both the cases; and

(c) why the job could not be done by the full time Law Officer of CSIR to save the expenditure?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) A sum of Rs. 1,500/- (Rupees one thousand and five hundred only) was paid as fee to the lawyer. He was engaged to represent the management in both the cases. However, the Assistant Labour Commissioner (Central) did not allow him to represent the management before him.

(c) In accordance with the practice in vogue in CSIR, lawyers are engaged to present/defend cases in various Courts. In this case a local lawyer experienced in Labour Laws was considered necessary and was engaged in addition to the Law Officer of the CSIR who deals with legal matters of all the National Laboratories/Institutes.

Suspension of Pension to Freedom Fighters

6619. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1214 on 28th February, 1979 regarding pension to freedom fighters and state:

(a) in how many cases Government have stopped or suspended the pension given to freedom fighters in each State after March 1977;

(b) the reasons for doing so; and

(c) in how many pending cases decision to grant or not to grant pension has been taken during the same period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (c). Pension has been sanctioned in 2028 cases, rejected in 4999 cases, suspended in 2281 cases and stopped (cancelled) in 550 cases during the period from 1-4-1977 to 31-3-1979. A State-wise statement is attached.

(b) The pension has been suspended/stopped on one or more of the following grounds:—

(i) Applicant is not a genuine freedom fighter.

(ii) Suffering is less than six months.

(iii) Suffering not in connection with freedom movement.

(iv) Submission of false documentary evidence.

(v) Internment/externment/abscondence is not supported by evidence based on official records.

(vi) Annual income from all sources is more than Rs. 5000/-.

Statement

Statement showing the number of cases in which pension has been sanctioned, rejected, suspended and stopped (cancelled) during the period from 1-4-1977 to 31-3-1979 (State-wise)

States/Union Territories	Sanctioned	Rejected	Suspended	Stopped (Cancelled)
1	2	3	4	5
1. Andhra Pradesh	157	286	16	20
2. Assam	19	107		10
3. Bihar	178	1699	45	44
4. Chandigarh			1	
5. Delhi	4	20		9
6. Goa	29	25	1	.
7. Gujarat	19	96	8	1
8. Haryana	2	32	30	1
9. Himachal Pradesh	2	12	11	1
10. Jammu & Kashmir	2	7	4	.
11. Kerala	87	405	..	47
12. Karnataka	105	365	1241	74
13. Madhya Pradesh	26	76	..	33
14. Maharashtra	225	437	75	14
15. Manipur	..	.	..	7
16. Meghalaya	..	..	4	13
17. Orissa	17	35	..	21
18. Pondicherry	4	23	..	36
19. Punjab	29	104	47	15
20. Rajasthan	7	18	16	3
21. Tamil Nadu	52	201	..	36
22. Tripura	3	77	.	35
23. Uttar Pradesh	42	456	402	30
24. West Bengal	551	283	70	93
25. INA Personnel	468	206	312	8
Total	2028	4999	2281	550

Constitution of Thana Level Peace Committees in Delhi

6620. SHRI MAHI LAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the procedure and criteria adopted for the constitution of Thana Level Peace Committees in the respective Police Stations in Delhi;

(b) the constitution, functions of these peace committees and the qualifications of a person for being a member of such a peace committee;

(c) whether the present enrolment of members for the Thana Level Peace Committees is screened by the Police authorities and finally cleared by the Member of the Metropolitan Council of a particular political party; and

(d) if so, the reasons for giving authority to the members of a particular political party only of clearing the final list of candidates for the peace committees which are considered to be purely non-political?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D PATIL): (a) to (d). A Thana Level Committee with the Member of the Metropolitan Council of the area as the Chairman is functioning in each Police Station in the capital. The Committee is constituted in accordance with the guidelines (Statment attached) formulated by the Delhi Administration in this regard.

Statement

Guidelines regarding constitution of the Thana Level Committee in Delhi.

1. There will be one Committee for each police station in the Union Territory of Delhi whose Chairman will be the Metropolitan Councillor of the area. Where there are more than one Metropolitan Councillor in the jurisdiction of a police station, they will be nominated as Chairman of the Committee each for a year by rotation. Chairman will be appointed by the Chief Executive Councillor.

2. The Asstt. Commissioner of Police of the area will be the convener of the Thana Level Committee within his jurisdiction.

3 There will be not more than 25 members in each committee two of whom shall be ladies. The names of the members will be approved by the Chairman. The names suggested by the Commissioner of Police and others can also be considered by him.

The following are the categories of persons from whom nominations shall be made:—

(i) Municipal Councillor (S) of the area/Member of the NDMC.

(ii) President/Secretary of the renowned religious Institutions.

(iii) President/Secretary of the local Bazar Association.

(iv) Principal of the local School/College.

(v) Rrepresentative of the Residents Welfare Association.

(vi) Representative of Industrial Labour.

There is no objection to more than one or two members being drawn from each category according to need, but the ceiling of membership as a whole should be kept at 25.

4. The approval of the Chairman regarding the names of persons to be associated in Thana Level Committees from the categories as above shall be subject to review by the Admn., as may be called for.

5. The Thana Level Committee shall meet at least once a month and

the convenor shall record the proceedings of the meeting and send copies thereof, *interalia* to the Lt. Governor, Chief Executive Councillor, Chief Secy. and Secy. (Home) Delhi Administration.

6. Deputy Commissioner of Police of the Distt. shall attend all meetings of the Committee within his jurisdiction.

7. The term of Committee shall be one calender year and the Chairman/ Members will be eligible for renomination.

8. The convenor of the Committee shall finalise the constitution of the respective committee by the month of November preceding the year for which the Committee is to be constituted.

9. The Committee constituted as at present will continue to function till new Committees in their place are constituted in accordance with these guidelines.

G.P. Fund of Delhi Administration Employees

6621. SHRI HALIMUDDIN AHMED: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the statement of the Chief Executive Councillor, Delhi regarding issuing the Pass Books to Delhi Administartion employees about their GPF contribution from April 1979 onwards and state:

(a) what action is being taken to issue the statement of account of GPF contributions for the year 1976-77 and 1977-78 by the Controller of Accounts, Delhi Administration, Delhi; and

(b) what remedy is being suggested to adjust the missing credits of GPF of the employees which runs into crores of rupees and how will it be reflected in the Pass Books?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) Delhi Administration have intimated that statement of GPF Account in respect of their employees for the year 1976-77 which were to be issued by the Controller of Accounts, Ministry of Finance (Computer Cell) could not be issued so far since all the computers in Delhi in which the programme can be run are out of order.

The Statement of Accounts for the year 1977-78 are likely to be issued by the Controller of Accounts, Delhi Administration by the 31st October, 1979

(b) The Administration propose to obtain collateral evidence from the offices of the employees in respect of whom credits are missing for necessary adjustment and for this purpose the Administration propose to depute perapatetic parties to visit the concerned offices.

The question of reflecting missing credits in the Pass Books will arise only after the Delhi Administration decides to introduce the system of Pass Books.

Regularisation of Class III and IV Employees Appointed on Ad-hoc Basis

6623. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Class III and Class IV employees have been appointed on *ad-hoc* basis in various Ministries/ Departments of the Central Government;

(b) if so, the year-wise (up to December, 1978) number and class of the *ad-hoc* employees in various Ministries/Departments,

(c) whether it is stated in Ministry of Home Affairs OM No.

30/10/E.G. 1|60 dated 14th December, 1960 that there is no objection in regularising the services of the *ad-hoc* employees who have at their credit the service of not less than one year;

(d) if so, whether a copy thereof will be laid on the Table of the House and whether this order is being implemented;

(e) if not, whether Government propose to regularise such *ad-hoc* employees who have completed the service from one to three years; and

(f) if so, the time by which and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D PATIL): (a) and (b). The recruitments rules prescribe for all appointments to be made in a regular manner. However, due to exigencies of service and immediate needs, in some cases, *ad hoc* appointments are resorted to by Ministries/ Departments themselves. Government do not monitor such information.

(c) and (d). The O.M. No. 30|10-EG I/60 dated 14th December, 1960 issued from Ministry of Finance (not from M.H.A) relates to conversion of temporary posts into permanent ones at successive reviews and does not contain anything about regularising the services of *ad-hoc* employees. Copy of the aobve O.M. is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-4281/79].

(e) and (f). Appointments can be made only in accordance with the prescribed Recruitment Rules. While making regular appointments, persons appointed on *ad-hoc* basis can also apply for being considered alongwith other eligible persons, provided they satisfy the requirements prescribed in the Recruitment Rules.

Per Capita Income of Poors

6624. SHRI B. C. KAMBLE: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) is it a fact that severe destitute and the poor constitute nearby 85 per cent of our Indian people;

(b) what kinds of social groups to which each of these categories of people belong;

(c) what is the *per capita* income of each of the above mentioned three categories of people; and

(d) what are specific schemes and the details of each of such schemes to relieve the distress of these categories Government have undertaken or propose to undertake?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) No, Sir. According to the norm adopted by the Planning Commission in the formulation of the Draft Five Year Plan 1978—83, the percentage of the people below the poverty line including destitutes was 46.33 in 1977-78. It was stated in the Fourth Five Year Plan document that the poorest 10 per cent of the population consist mostly of destitute, disabled persons and others who cannot participate much in economic activity.

(b) Precise information is not available about the social composition of the population below the poverty line. However, as indicated in the Draft Plan 1978—83, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are among the poorest sections of the population. The vast majority of the poor are landless labourers and marginal farmers. Village artisans progressively thrown out of their traditional employment are included among these groups.

(c) Preeise estimates of the per capita income of the three categories

of people *viz.* the destitute, the poor and the not-so-poor are not available.

(d) The main thrust of the development strategy now adopted aims at significant reduction of poverty and unemployment in a decade. The Draft Plan (1978—83) has, therefore, accorded the highest priority to agriculture and allied sectors, irrigation and village and cottage industries which have the greatest capacity to absorb surplus labour. An expanded Minimum Needs Programme has also been provided for so that the living standards of the poor can be directly supplemented by the provision of certain basic amenities.

The Plan also gives special attention to the poor. It seeks to integrate provisions for the backward classes in general development programmes so that these can be effectively implemented. It provides for special subplans for the tribal areas. For area planning the selection of blocks is made in such a manner as to favour backward classes, agricultural labourers and small and marginal farmers.

In some States, such as Rajasthan, Antyodaya schemes are being implemented. These attempt to attack directly the poverty of the poorest and the destitutes.

Cotton Growers hit by unrestricted imports of Viscose Fibre

6625. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the cotton growers in the country have been badly hit by the unrestricted imports of viscose fibre from Japan; and

(b) if so, the measures proposed to be taken to protect the interests of cotton growers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). In view of acute domestic shortage of cotton during the cotton season 1976-77, Government made it obligatory on cotton textile mills to use from January, 1977 non-cotton fibres to the extent of at least 10 per cent of their total fibre consumption and for this purpose liberal imports of man-made fibres were permitted. With the cotton situation turning out to be favourable during the current season (1978-79), the Government imposed import duty on viscose staple fibre and also increased excise duty on indigenous viscose staple fibre from January, 1979 and also withdraw the above statutory stipulatitn in February, 1979.

Ashes of Netaji Subhash Chandra Bose

6626 SHRI K. T. KOSALRAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the action taken on the suggestion of General Fujiwara of the Japanese Imperial Army, the custodian of the ashes of Netaji Subhash Chandra Bose for ceremoniously handing it over to the Government of India;

(b) whether the Chief Monk, Matsasuki of Renkoji Shrine near Tokyo under whose care the urn containing the ashes is being kept has been contacted for this purpose; and

(c) if so, when the Government of India are going to receive the urn of ashes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) In the light of reasonable doubts cast on the correctness of the conclusions reached in the two inquiry reports on the death of Netaji Subhash Chandra Bose, Govt. find it difficult to accept that the earlier conclusions are decisive. It will, therefore, not be possible to take any action at present on the suggestion of General Fujiwara.

(b) and (c). Do not arise.

Conference of senior police officials and M.Ps. on Law and Order in Delhi

6627. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether he held recently a high level conference of senior police officials and Members of Parliament from Delhi to discuss the law and order situation in the capital;

(b) if so, the facts thereof

(c) whether it is a fact that he expressed dissatisfaction at the said conference over the prevailing law and order situation in the capital; and

(d) if so, what measures are being taken by Government to improve the situation and what steps were suggested in this regard at the said conference?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) to (d) Yes, Sir. A meeting was taken by the Home Minister on 16-3-1979 to discuss the law and order situation in Delhi. A copy of the minutes is laid on the Table of the House [*Placed in Library. See* No LT-4282/79]

The police organisation in Delhi, has taken and is taking a number of steps to improve its efficiency and functioning. These include creation of a new police district called West Delhi, setting up of 8 new police stations and 12 police posts, increasing the number of CRP Bns. from 4 to 6, intensifying patrolling with the help of CRP and Home Guards, launching special drive against bad characters (233 persons have been externed between 1-8-1978 and 5-3-1979) and setting up of a special centralised squad for dealing with important cases and for improving the intelligence system. The Police Commissioner keeps close contact with his senior officers, meeting them everyday to review the situation in various parts of the city. The Lt. Governor also periodically reviews the situation.

Development of Sericulture Industry

6628. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have drawn up definite programme for wider development of Sericulture industry in the country, if so, what are the details;

(b) how many silk Research Centres are operating in Madhya Pradesh; and

(c) whether Government propose to encourage development of Sericulture in Mulberry and non-mulberry backward areas of Madhya Pradesh, if so, the details of such plans?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir The Central Silk Board has drawn up programmes for the development of sericulture industry in the country during the Sixth Plan period with the following objectives:

(i) Doubling the production of raw silk in the country to 75 lakh Kgs.,

(ii) Trebling the exports of silk goods to Rs. 100 crores per annum; and

(iii) Providing additional employment to 10 lakh persons.

(b) None at present.

(c) Particulars of the programmes drawn up for development of Sericulture in Madhya Pradesh during the Sixth Plan period are as under:

(i) to establish 92 tasar production centres and a few production-

cum-training centres with a view to increase production of tasar silk from 51000 Kgs. to 2,34,000 Kgs.

(ii) to expand the area of mulberry cultivation to 1000 acres and achieve a production level of 20,000 Kgs. mulberry raw silk;

(iii) to provide additional employment to 3700 families.

Representation from Werkers of Wimco Match Factory

6629. PROF. SAMAR GUHA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the workers of Wimco Match Factory have made a representation to Government expressing their fear that if the increase excise duty on matches is not reduced, the five units of the company are likely to face closure;

(b) if so, facts thereabout; and

(c) the reaction of Government about the Memorandum and various other appeals made to the Government for deduction of taxes on manufacture of matches by Wimco?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c) The workers of WIMCO Match Factory have submitted a representation to Government expressing their fear that if the increased excise duty on matches produced in the mechanised sector is not reduced there is a likelihood of closure of some of the units of this company and large scale retrenchment of its workers. The rates of duty announced in the Budget Proposals for the year 1979-80 is a conscious decision of the Government and is expected to accelerate the growth of non-mechanised sector in general and cottage units in particular. It is hoped that the tax differential should induce WIMCO to expedite formulation of its plans for diversification of its activities to maintain its financial liability. Pending such diversification it should be possible for WIMCO to absorb a substantial portion of the incidence of enhanced excise duty. According to the provisions of Industrial Disputes Act (Amended) units employing more than 300 persons are required to obtain prior permission of the appropriate Govt. before any retrenchment is effected.

माण्डवा तथा सोनगढ गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों का परियोजनाओं पर व्यय

6630. श्री छोटू भाई वासवा : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में माण्डवी तथा सोनगढ के आदिवासी क्षेत्रो मे परियोजनाओ पर जून, 1978 तक किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है

(ख) (योजनावार) कितनी धनराशि खर्च की गई है और आदिवासी कृषि श्रमिकों के लिये योजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) उक्त योजना के लिये चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार का कितनी सहायता देने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण मे दी गई है ।

(ग) गुजरात में वर्ष 1979-80 के लिए जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के लिए 4.86 करोड़ रुपए की रकम धनराशि निर्धारित की गई है ।

विवरण

खर्च की गई धनराशि (29 मार्च, 1978 को राज्य सरकार द्वारा यथा सूचित) और गुजरात के सोनगढ और माण्डवी क्षेत्रों की योजनाओं के ब्यौरों का विवरण ।

क्र० सं०	परियोजना का नाम	खर्च की गई राशि
1	सोनगढ़ (जिला सूरत)	49,06,710
2	माण्डवी (जिला सूरत)	95,90,154
	धनराशि निम्नलिखित कार्यक्रमों पर खर्च की गई थी	
1	कृषि	
2	भूमि सुधार	
3	लघु सिंचाई	
4.	भूमि तथा जल संरक्षण	
5	क्षेत्र विकास	
6	डेरी विकास	
7	पशु पालन	
8	मत्स्य उद्योग	
9	वन	
10	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थाओं में निवेश	
11	सामुदायिक विकास	
12	सहकारिता	
	(क) सामान्य (पंचायतें)	
	(ख) सामुदायिक विकास	
	(ग) ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम	
13	सिंचाई	
14	विद्युत	
15	बाढ़ नियंत्रण	
16	उद्योग	
17	ग्रामीण और लघु उद्योग	
18	खनन और धातु उद्योग	
19	पत्तन प्रकाश गृह और नौवहन	
20	सड़कें तथा पुल	
21	सड़क यातायात	
22	पर्यटन	
23	कला और संस्कृति सहित केन्द्रीय शिक्षा	
24	तकनीकी शिक्षा	
25	चिकित्सा लोक स्वास्थ्य और सफाई	
26	मल व्यवस्था और जन पूर्ति	
27	आवास	
28	शहरी विकास	
29	सूचना और प्रचार	
30	श्रम तथा श्रम कल्याण	
31	समाज कल्याण (मद्य निषेध)[1]	
32	पाषण	
33	विकास केन्द्र	
34	जन-जातीय क्षेत्र उप-योजना के लिये प्रशासनिक तंत्र	
35	तालुक स्थानों पर आवासीय क्वार्टर्स	

Textile Machinery Manufacturing Industry

6631 DR P V PERIASAMY Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) whether it is a fact that out of the licensed capacity of Rs 250 crores and installed capacity of Rs 230 crores in the textile machinery manufacturing industry, the production during the current year is expected to be only about Rs 100 crores,

(b) if so, the reasons for the same; and

(c) the steps being taken to improve the productivity of the textile machinery manufacturing industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MATI) (a) to((c).

Because of lack of demand from the textile industry, the utilisation of capacity of the textile machinery industry has not registered appreciable progress. The industry has been given facilities for stepping up production, modernisation and diversification to manufacture machinery of new types and also exports. Production of textile machinery during the year 1978 has been around Rs. 120 crores, being 42 per cent higher as compared to the production during 1977. Based on the current pattern of production, particularly during the last quarter of 1978, it is expected that production during 1979 will be over Rs. 150 crores.

ईरान द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के कर्मचारियों की सेवाओं के लिये अनुरोध

6632. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ईरान सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के इंजीनियरों और कुशल कर्मचारियों की सेवाओं के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने इंजीनियरों की सेवाओं के लिये अनुरोध किया गया है और उन्हें कब तक भेजा जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आशा भाईती) : (क) जी, हां ।

(ख) ईरान सरकार के एक उद्यम ईरान ट्रान्फो में बी०एच०ई०एल० के इंजीनियरों और कुशल कर्मचारियों की सेवाओं के लिये अनुरोध किया था । पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार जनवरी, 1979 से जून, 1979 तक दलों में 16 इंजीनियर ईरान पहुचने थे परन्तु तेहरान में भारतीय दूतावास की सलाह पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई है ।

Setting up of a Paper Mill using Bagasse in Tamil Nadu

6633. SHRI R. KOLANTHAIVELU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the policy followed in encouraging paper production from bagasse indicating the quantum of paper already produced from bagasse;

(b) whether there is a proposal to start such paper mills using bagasse in Tamil Nadu; and

(c) if so, the names of the mills proposed to be set up in Tamil Nadu and their location?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) In order to encourage the utilisation of bagasse for manufacture of paper, Government have decided on a package of policy measures which include priority in consideration of such schemes for institutional assistance exemption from excise duty for writing and printing paper made with atleast 75 per cent bagasse for a period of three years initially, and priority in movement of coal by the Railways.

(b) and (c). An application has recently been received from the Government of Tamil Nadu for a licence under Industries (Development and Regulation) Act, 1951 for setting up a new unit in the Salem District (Tamil Nadu) for the manufacture 83,000 tonnes/annum of Newsprint and 17,000 tonnes/annum of writing and printing paper utilising bagasse as the main raw material.

Malpractices in Distribution of Inputs

6634. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the malpractices in the distribution of inputs, failure of multi-agency approach and lack of coordination which are causing damage to the rural industrial development, and

(b) if so, the steps being proposed to remedy the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b) Rural industrial development is primarily the responsibility

of State Governments. The Central Government has not received any information or complaint of malpractices in the distribution of inputs. The problems of multi-agency approach and lack of coordination among the various agencies responsible for rural industrial development are sought to be overcome by evolving closer coordination among the different agencies, involved in the rural development effort. Guidelines have been issued by the Department of Rural Development on inter-action between District Industries Centres and Integrated Rural Development Blocks in regard to assistance programmes for rural artisans. A Co-ordination Committee of decentralised sector agencies at the Central level has been formed, which meets regularly to review common programmes, inter-facing of multi-agency activities and linkages. The District Industries Centres is conceived as an administrative mechanism to coordinate inter-agency efforts to provide the assistance and support to small entrepreneurs and rural artisans in a well defined district action plan.

Setting up of Industries in W.B

6635. SHRI DHIRENDRA NATH BASU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are considering to take up a scheme for setting up different industrial units in the Hill district and also backward areas of West Bengal through State Level Corporations;

(b) whether the Centre have received any request or suggestion from the State Government in this regard; and

(c) if so, what are the details of the proposed units and the time limits for the implementation of the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) In the Draft Five Year Plan (1978—83), the Government of West Bengal have proposed to set up industrial units through various State Corporations in hill/backward areas.

West Bengal Industrial Infrastructure Development Corporation has proposed to expand the growth centres at Kalyani and Haldia and develop a new one at Siliguri.

West Bengal Sugar Industries Development Corporation has obtained an industrial licence for expanding the capacity of Ahmedpur Sugar Mills (Birbhum District)) from 600 TCD to 1250 TCD.

The West Bengal Tea Development Corporation proposes to expand its activities by developing new gardens and purchasing 18 gardens in hill areas of the State.

In addition to the modernisation of Kalyani Spinning Mills, a spinning mill with 25,000 spindles is proposed to be set up at West Dinajpur.

West Bengal Mineral Development and Trading Corporation is currently engaged in drawing up new schemes for ceramic raw materials complex and a pozzolona cement project in Purulia/Bankura

The departmental quinine factory at Darjeeling is proposed to be modernised and a project for bottling the thermal spring water at Bakreswar is under consideration.

(b and (c). The suggestions of the State Government are contained in the Draft Five Year Plan proposals which are yet to be finalised.

Expenditure for the modernisation of the N.T.C.

6636 SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) is it a fact that Government propose to spend a large amount of money for the modernisation of the National Textile Corporation;

(b) if so, the details thereof,

(c) how much amount will be spent in the next year in the public sector for its modernisation and improvement; and

(d) what specific steps Government propose to take to improve the working of the public sector undertakings?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). The National Textile Corporation has prepared a plan for Rs. 250 crores for modernisation of the textile mills being managed by it to be implemented by the end of the Sixth Year Plan. Out of this amount, modernisation programme costing Rs. 130 crores have already been sanctioned by the National Textile Corporation.

(c) During the financial year 1979-80, the National Textile Corporation proposes to spend Rs. 42 crores for modernisation and improvement of its units.

(d) The following steps have been taken and/or being taken to improve the working results of these mills:

(i) modernisation/renovation of machinery;

(ii) bulk procurement of raw material on centralised basis;

(iii) improved marketing strategy;

(iv) rationalisation of work loads and labour force;

(v) techno-economic survey of heavily losing mills.

Bringing down prices of Non-controlled Cloth

6637. SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether he has asked the cotton textile industry to come out with concrete proposals immediately for bringing down the prices of non-controlled variety of cloth; and

(b) if so, the details and industry's response thereto?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Yes, Sir.

(b) The industry has responded with the following three alternatives:—

(i) a roll back to the level of cloth prices prevailing in December 1978;

or

(ii) a price freeze on cotton cloth at the levels prevailing prior to 16th March, 1979;

or

(iii) a reduction in ex-mill prices of cotton cloth to the extent of two percent of the invoice rates obtaining prior to 16th March, 1979

None of these alternatives has been acceptable to Government. The Government is presently considering measures to compel the mills to roll back the prices to a reasonable level.

Opposing the Nationalisation of Industries

6638. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have received 'No' from big business houses in regard to nationalisation of certain bringing down the prices of non-con-

(b) if so, the details regarding the arguments placed by big business interests opposing the Government's move in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Government have not so

far taken any decision in regard to nationalisation of industries. Big business houses who are likely to be affected would naturally oppose such proposals.

(b) Does not arise.

Finalisation of Sixth Five Year Plan

6639 SHRI K. GOPAL: Will the Miniser of PLANNING be pleased to state:

(a) when the Sixth Plan is expected to be finalised;

(b) the reasons for delay in the finalization of the Plan even though one year of its implementation is already over, and

(c) whether resources mobilization is one of the factors standing in the way of finalization of the plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) to (c) As the Hon'ble Member is aware the Draft Five Year Plan for 1978—83 prepared by the Planning Commission was submitted to the National Development Council in March, 1978. The Council accepted the objectives and strategy proposed in the Draft Plan and recommended that the Plan should be finalised in the light of the decision of the Government of India on the recommendations of the Seventh Finance Commission and decisions to be taken in regard to the principles of distribution of Central Plan assistance to the States. These exercises have since been completed and approved by the National Development Council in late February, 1979. The work of finalising the Plan is now under way. There has, therefore, been no delay in the finalisation of the Plan; nor has it been affected by any difficulties in resource—mobilisation.

Bringing out of a separate Land Document

6640. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of PANNING be pleased to state.

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Planning Commission to bringing out a separate land document exclusively for hilly and backward states in the country in view of their special requirements;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons thereof; and

(d) whether any hilly and backward states have approached the Planning Commission for the purpose, if so, the names of such states?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) and (b) The meaning of 'land document' is not clear. Perhaps the question really refers to a 'plan document'. It is not proposed to bring out such document.

(c) The National Plan deals with the strategy and programmes for development of backward areas including hill areas in different States. Provision for hill areas and tribal areas is made separately in the Plans of the States in which these areas lie, and special central assistance is earmarked for these schemes. It has not been considered necessary to publish a separate plan document for hilly and backward States.

(d) No State has suggested a separate plan document of this nature.

Facilities in Tihar Jail

6641. SHRI HARI VISHNU KAMATH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question

Dy. No. 3262 on the 13th December, 1978 and state:

(a) the details of the remedial measures taken with a view to removing the deficiencies in regard to over crowding, unhygienic and insanitary conditions and inadequate medical and drinking water facilities in Tihar Jail; and

(b) what action has been taken against the officials indicated by the Baweja Inquiry Commission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) and (b). The Delhi Administration have reported that with a view to removing overcrowding in the Central Jail, Tihar, one Camp Jail with a capacity of 500 undertrials was started on 11-4-1978. Similarly, seven special jails, each with a capacity of 500, have been set up. As a long-term solution of the problem a proposal for construction of two District Jails one at Shahdara and the other at Hyderpur, is under consideration of the Administration. To remove the insanitary and unhygenic conditions, a new sewerage line has already been laid. A steriliation plant is being installed for disinfecting the clothes and the bedding. The water supply from the Municipal Corporation of Delhi, has been supplemented by energising one extra tube-well. The Central Jail has a 28 bedded-hospital with four doctors to attend to the patient prisoners. The serious and emergent cases are referred to the Lok Nayak Jay Prakash Narayan hospital and a Jail van is earmarked for transportation of these patients.

2. On the basis of the Baweja Inquiry Commission Report, seven officials were found responsible for the lathi charge in the Central Jail on 2nd October, 1975. Three of them were on deputation from different states. They have been reverted to their respective States and the charge-sheets in respect of them have been sent to the concerned State Governments. Disciplinary proceedings have been initiated against the remaining four officials by the Delhi Administration. Besides, the Delhi Administration have decided to initiate departmental proceedings against the then Deputy Inspector General (Prison) against whose conduct, the Baweja Commission had made certain observations.

Licences issued to Entrepreneurs for setting up industries in Assam and North Eastern region

6642. SHRI BEDABRATA BARUA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) how many licences and letters of intent were issued for new industrial enterprises in the last two completed years;

(b) in how many cases of these licences and letters of intent are the locations specifically mentioned and approved State-wise;

(c) how many licences and letters of intent have been issued for locations of industry in Assam and North Eastern area; and

(d) what are the proposed industrial projects for Assam for which these licences and letters of intent have been issued?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADEV): (a) Under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, 211 Letters of Intent and 141 Industrial Licences were issued during 1977 and 206 Letters of Intent and 93 Industrial Licences were issued during 1978 for setting up a new industrial undertakings.

(b) The state-wise location has been indicated specifically in every Letter of Intent and Industrial Licence

issued during 1977 and 1978 for the establishment of new industrial undertakings.

(c) One Letter of Intent and 2 Industrial Licences during 1977 and 3 Letters of Intent and 1 Industrial Licence during 1978 were issued for location of new undertakings in Assam. Similarly 3 Letters of Intent and 2 Industrial Licences during 1977 and 3 Letters of Intent and 1 Industrial Licence during 1978 were issued for location of new undertakings in North Eastern area.

(d) The Letters of Intent and Industrial Licences issued during the last two years for setting up of new undertakings in Assam are for taking up the manufacture of items relating to Chemical industries, Vanaspathi, Leather Goods, Timber products and Paper and Pulp including Paper products.

Acquisition of Tribal Lands for Projects

6643. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it has come to the notice of Government that although many big industries and construction projects have come up in tribal areas, the Scheduled Tribes are not benefited from these developments;

(b) whether it has also come to the notice of Government that in a number of cases good agricultural lands belonging to the tribals were acquired for projects, but the displaced tribal were not provided with any alternate land for rehabilitation;

(c) if so, what steps Government propose to take to protect the interest of such displaced tribal people; and

(d) the steps Government propose to take to ensure proper rehabilitation of tribal people whenever their lands are acquired for future projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) Government is aware that members of Scheduled Tribe communities have not benefited much from big industries and construction projects established in tribal areas.

(b) Further, the Government is also aware that goods agricultural land belonging to the tribals was acquired and in lieu thereof they were not provided with alternative land for rehabilitation.

(c) The Centre has suggested to the State Governments that wherever lands belonging to tribals have been taken away, special area programmes should be undertaken for their rehabilitation.

(d) Guidelines have been issued that all areas where medium and major industries have been established, or are likely to be established in the next five or ten years should be identified, and special area programmes should be drawn up and implemented for their development. Further, advance action should be taken to educate and train the tribals for their absorption in the projects.

बिहार के जिला भागलपुर में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

6644. डा० रामजी सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला भागलपुर के कितने स्वतंत्रता सेनानियों को इस समय पेंशन प्राप्त हो रही है और कितनों की पेंशन रोक दी गई है ; और

(ख) क्या बिहार राज्य का गृह विभाग ऐसे मामलों में स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदन पत्र केन्द्र को भेजने अथवा सिफारिश करने में अत्यधिक विलम्ब करता है जिनमें स्पष्टीकरण अपेक्षित होता है और स्पष्टीकरण न मिलने पर केन्द्र को इस बारे में उसे वायरलेस द्वारा जानकारी मांगनी पड़ती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) बिहार के जिला भागलपुर में

अब तक स्वतंत्रता सेनानियों के 2564 मामलो में पेंशन स्वीकृत की गई है । इनमें से, आगे और जांच होने तक 48 मामलो में पेंशन रोक दी गई है, 26 मामलो में पेंशन राज्य सरकार द्वारा आवश्यक जांच करने के बाद अंतिम रूप से रद्द कर दी गई है ।

(ख) स्वतंत्रता सेनानियो की पेंशन के लिये बिहार से आवेदन पत्रों की संख्या 47,000 से अधिक हो चुकी है तथा लगभग 12,000 मामलों को पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य और/या राज्य सरकार की विशिष्ट सिफारिश के अभाव मे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । राज्य सरकार को अपनी रिपोर्टें भेजने में निःसन्देह कुछ विलम्ब हुआ है संभवत इसलिए कि उन्हे हजारो मामलो मे जिला प्राधिकारियो से उनकी जांच करवाई गई हो, रिपोर्टो को सामान्य पत्र व्यवहार तथा वायरलैस संदेशो के जरिये सावधिक अनुस्मारक भेज कर शीघ्र प्राप्त करने के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं ।

Promotion case of Delhi Police Personnel

6645. SHRI C. R. MAHATA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government have ascertained the position in connection with the promotion case of Delhi Police Personnel whose promotions have been held up pending the decision of the Supreme Court in Criminal Case No. 86/73 State *versus* Vijay Pal; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) and (b) The Government have ascertained the position in this regard. No promotion of any personnel of the Delhi Police has been held up pending a decision in the criminal case No. 86/73 State versus Vijay Pal.

Multinational Companies producing Consumer Goods

6646. SHRI S. S. SOMANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the details regarding the multinational companies which are presently engaged in the production of consumer goods; and

(b) the efforts of Government to ensure that there is minimum dislocation in the production of consumer goods and that there is no adverse effect on the existing employment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) This information is not centrally maintained in the Ministry of Industry. However, a list of foreign companies, having more than 40 per cent foreign equity and engaged in the manufacture of certain consumer goods, is given in the attached statement.

(b) It is presumed that the reference is to the Government's Industrial Policy, as laid before the Parliament on 23rd December, 1977, which provides that where large scale units are already engaged in the manufacture of items since reserved for the small scale sector, the share of these large units in the total capacity for these items will be steadily reduced and that of small scale and cottage sector increased. Consistent with this policy, a dialogue has been initiated with the large scale manufacturers of certain consumer goods to work out a plan of action by which the organised sector vacates its manufacturing activities in favour of the small scale sector, at the same time ensuring that there is minimum dislocation in the production of these consumer goods and that there is no adverse effect on the existing employment.

Statement

A list of foreign companies having more than 40 per cent foreign equity engaged in the manufacture of consumer goods.

S. No.	Name of the Company	Items of manufacture
1	M/s Brooke Bond India Ltd.	Tea, seafoods etc.
2	M/s Lipton Tea India Ltd.	Tea
3	M/s Dunlop India Ltd.	Cycle tyres and tubes
4	M/s Goodyear India Ltd.	Do.
5	M/s Ceat Tyres of India Ltd	Do.
6	M/s Hindustan Lever Ltd.	Soaps, toothpaste etc.
7	M/s Ciba-Geigy of India Ltd.	Toothpaste, cosmetics etc.
8	M/s Hindustan Milkfood Manufacturers Ltd.	Do.
9	M/s Geoffrey Manners and Co. Ltd.	Do.
10	M/s Burroughs Wellcome & Co. (I) Pvt. Ltd.	Cosmetics, toiletries etc.
11	M/s Glaxo Laboratories (I) Ltd.	Cosmetics, food items etc.
12	M/s Johnson and Johnson Ltd.	Cosmetics, toiletries etc.
13	M/s Cadbury Fry (I) Ltd.	Chocolate confectionery etc.
14	M/s Corn Products Co. (I) Ltd.	Food items.
15	M/s Godfrey Philips (I) Ltd.	Cigarettes.
16	M/s Shalimar Paints Ltd.	Paints, Enamels etc.
17	M/s Alkali and Chemical Corpn. of India Ltd.	Do.
18	M/s Union Carbide India Ltd.	Flash-light cases, dry cells.
19	M/s Electric Lamp Mfg. (I) Pvt. Ltd.	Electric lamp, miniature lamp.
20	M/s Philips India Ltd.	Do.
21	M/s Polydor of India Ltd.	Gramophone records etc.
22	M/s G.E.C. (INDIA) Ltd.	Electric fans.
23	M/s Hooghly Ink Co. Ltd.	Inks etc.
24	M/s Tube Investments of India Ltd.	Cycle and its parts
25	M/s Sansar Machines Ltd.	Sewing machines.

NOTE: This list includes the companies which have got their schemes for reduction of foreign equity to 40% approved.

Survey of Problems of Undeveloped Areas

6648. SHRI S. R. REDDY: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government have appointed any committee to survey and study problems of undeveloped areas and to have views of the various State Governments and public representatives in the matter; and

(b) if so, the details?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) and (b). A National Committee on the Development of Backward Areas has been constituted with the following terms of reference:

1 To examine the validity of the various concepts of backwardness underlying the definitions in use or present policy purposes and recommend the criteria by which backward areas should be identified.

2. To review the working of:

(a) Existing plans for dealing with the general developmental problems of backward areas like tribal sub-Plans, Plans for Hill Areas etc., and

(b) Existing schemes for stimulating industrial development in backward areas such as the schemes for concessional finance, investment subsidy, transport subsidy, sales tax concessions, etc., similar schemes in the agricultural and allied fields like DPAP, and general measures for tackling the problems of poverty and unemployment with a view to find out their efficacy in the removal of backwardness; and

3. To recommend an appropriate strategy or strategies for effectively tackling the problem of backward areas, classified, if necessary, according to areas, causes for prescribed remedies.

Collaboration of Escorts with Yamaha of Japan for manufacture of Broader Range of Motor Cycles

6649. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Government have finally opened the doors for foreign collaboration in the automotive sector,

(b) whether the first such collaboration has been allowed to Escorts with the world renowned Yamaha of Japan for the manufacture of a broader range of motor cycles;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) the reasons why collaboration has been allowed in this field particularly when indigenous know-how is readily available?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) Proposals for foreign collaboration in respect of automotive sector are approved on merits taking into account the need for upgradation, technological advancements provided by the foreign collaborator particularly in respect of fuel efficiency, better performance, export generation, material conservation etc.

(b) and (c). Escorts have been allowed to make lumpsum payment to Yamaha Motor Company Limited, Japan, for upgradation of the motorcycle engine. The amount is US $ 3,12,000/- subject to the deduction of applicable Indian taxes. The arrangements with Yamaha were approved in 1977. Foreign collaborations in the automotive sector have also been approved earlier.

(d) Lumpsum payment in this case would permit the upgradation of the engine of the motor-cycle for increased efficiency and low fuel consumption with substantial material conservation since the weight of the entire motor-cycle dove-tailed to the engine of the new version would be substantially less compared to the existing motor-cycle. The competitiveness of the product in the export market would also improve

Production of Standard Cloth

6650 SHRI K S VEERABHADRAPPA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) the details regarding the production of standard cloth in the country during the last three years, State-wise, in length,

(b) the details regarding the production of standard cloth in the large scale and the handloom sectors for the current year, and

(c) whether there has been any decline in the production of standard cloth in the year 1977-78?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(b) Production of controlled cloth during the current year (April—December, 1978) is as under:—

	Production in Million Sq Metres.
Mill Sector	249·00
Handloom Sector . . .	88·66
TOTAL	337·66

(c) No, Sir.

Consumption of Iodine Salt

6651. SHRI AMAR ROYPRADHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that only Iodine Salt is consumed by the North Bengal people;

(b) whether it is a fact that Iodine Salt is procured from other places for the consumption of North Bengal people as there is no industry in that area, and

(c) if so the details thereof and whether Government have any intention to open an Iodine Salt Factory in North Bengal, if so, when, and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) to (c) Iodised Salt is supplied to districts of Darjeeling, Jalpaiguri, West Dinapur, Cooch Behar and Malda in North Bengal, which have been declared as goitre-endemic areas, from the four iodisation plants installed at Howrah As salt is imported by sea route at Calcutta, the location of these iodisation plants at Howrah ensures adequate and regular supplies of common salt for iodisation and facilitates despatch of iodised salt to the goitre-endemic North Eastern region of the country. It is not considered necessary to install an iodisation plant in North Bengal exclusively for meeting the local requirements

Criteria of C.R. for Promotion of S.C. and S.T. Candidates

6652 SHRI SOMJIBHAI DAMOR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Confidential Reports of SC and ST employees are spoiled without any basis and sometimes letters are issued highlighting even the very small mistakes of SC and ST employees whereas for a similar or bigger mistakes of general candidates, no cognisance is taken;

(b) what steps Government propose to take to remove such disparity; and

(c) whether Government would frame some rules whereby the CRs should not be the only criteria for considering a SC and ST candidate for promotion of higher posts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL). (a) The Department of Personnel and Administrative Reforms is not aware of such situations.

(b) Does not arise.

(c) Rules already exist under which, for certain categories of promotion other methods and criteria than mere assessment of past performance as reflected in the CR e.g. departmental examination, interviews etc. are resorted to for all classes of employees. For Scheduled Caste/Scheduled Tribe members, in promotion by selection upto the lowest rung of Group A (Class I), and in promotion by seniority, in all Groups of posts, there is reservation, and relaxed standards of suitability and assessment are applied for them—whatever be the method of promotion, either seniority, or selection through the C.R., limited examination, interview, etc.

MHD Power Generation

6653. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether research on MHD power generation (power through low temperature thermal plasma) is being made; and

(b) if so, the result thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The first phase of the programme, which comprises some of the auxiliary laboratories and a 5 MW (Thermal) R&D Plant, is expected to be operational by 1982. Results of this R&D effort would be available thereafter.

संसद सदस्यों, विधायकों तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए बजाज और प्रिया स्कूटरों की बुकिंग

6654. **श्री दया राम शाक्य :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्रतिरक्षा कर्मचारियों और अति विशिष्ट व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रिया और बजाज स्कूटरों की सप्लाई करने हेतु उनके लिए बुकिंग की व्यवस्था की गई थी और विधायकों तथा संसद सदस्यों ने अनेक वर्षों से इन स्कूटरों के लिए बुकिंग करा रखी थी तथा क्या उन्हें बुकिंग के आधार पर यह स्कूटर नहीं दिए जा रहे हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार वितरकों को निदेश देगी कि जिनके नाम बुकिंग हो गई है, उन्हें स्कूटर दिए जाएं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख). स्कूटरों के वितरण तथा बिक्री पर लगा कानूनी नियंत्रण, जो आखीर में बजाज और प्रिया मेक के स्कूटरों पर लागू था, 1 जनवरी, 1978 से समाप्त कर दिया गया है ताकि देश में मांगों को कारगर ढंग से पूरा करने हेतु सारे स्कूटर उद्योग की प्रत्युत्तरदायिता और विकास को बढ़ावा मिल सके । बजाज तथा प्रिया मेक के स्कूटरों का कोई विशेष कोटा किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को आवंटन करने के लिए अब उपलब्ध नहीं है । अनेक दूसरे मेक के स्कूटर उपलब्ध हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम—स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड—द्वारा निर्मित स्कूटर भी शामिल हैं । बजाज/प्रिया मेक के स्कूटरों के लिए मांग की पूर्ति अन्य मेक के स्कूटरों, यदि ग्राहक ऐसा चाहे,—से की जा सकती है, जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम—स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, द्वारा निर्मित स्कूटर भी शामिल हैं ।

कपड़ा मिलों और छपाई कारखानों का बन्द होना

6655. **श्री दौलत राम सारण :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी कपड़ा मिलें और कपड़े की छपाई और रंगाई के कितने कारखाने बन्द पड़े है तथा कब से बन्द पड़े है और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए तथा उन्हें रोजगार दिलाने के लिए क्या उपाय किये गये है ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप उत्पादन की कितनी हानि हुई है तथा इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई है ;

(घ) सरकार तथा बैंको ने उनमें कितनी कितनी पूंजी लगाई है तथा इस पूंजी की सुरक्षा के लिये क्या उपाय किये गये है ; और

(ङ) क्या उक्त मिलों के मालिको तथा निदेशको ने भी इन मिलों और कारखानो को चलाने मे उन्हें हो रही कठिनाईयो को हल करने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिये थे, तथा क्या इस मामले में कोई कार्यवाही न किये जाने पर मिलो को बन्द करना पड़ा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Allotment of Mutton Tallow to Govt. Soap Factory, Bangalore

6656. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have stopped the allotment of mutton tallow, an essential ingredient in the manufacture of soaps, to the Government Soap Factory, Bangalore; and

(b) if so, the reasons for the same and whether Government are aware that the stoppage of supply of mutton tallow will adversely affect production in the factory?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). The policy is that units in the organised sector who do not have hydrogenation facilities should set up such facilities at the earliest. Pending establishment of such facilities requests for import of mutton tallow are being considered by Government.

The Government Soap Factory, Bangalore, is a unit without hydrogenation facilities and it has been asked to establish such facilities at the earliest. *Ad-hoc* import allocations of mutton tallow were made to this unit till 1977. For the licensing period 1978-79, the question of allocation of imported mutton tallow has been taken up with the Ministry of Commerce.

Issue of Licences

6657. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of INDUSTRY be please to state:

(a) how many new licences and letters of intent have been issued by Government during the last six months; and

(b) the items for the manufacture of which the licences and letters of intent were issued?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) A tota number of 226 Letters of Intent and 192 Industrial Licences were issued under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 during the last 6 months *i.e.* from 1st September, 1978 to 28th February, 1979.

(b) The Letters of Intent and Industrial Licences were issued for the manufacture of items falling under Scheduled industries *viz.* metallurgical industries, electrical equipment

transportation, industrial machinery, machine tools, chemicals, textiles, paper and pulp including paper products, sugar, food processing industries, vegetable oils and vanaspati, leather and leather goods, ceramics, cement, timber products, etc. Details of all these Letters of Intent and Industrial Licences including name of the party, item of manufacture, capacity, location of the unit etc. issued under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 are published in the "Weekly Bulletin of Import Licences, Export Licences and Industrial Licences" and in the Supplement to the "Monthly News Letter" published by the Indian Investment Centre. Copies of these publications are available in the Parliament Library.

Issue of Identity Cards to Persons of Non-Indian Origin entering North Eastern States

6658. SHRI PURNANARAYAN SINHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a proposal has been received to prepare a sort of Nationalities Register for persons of Bangladesh (former East Bengal/East Pakistan), Nepal and other non-Indian origin and issue them with Identity Cards so that persons illegally entering States of North Eastern Council area could be detected;

(b) if so, whether Government propose to hold a special census in order to ascertain the national status of all residents of the States of North Eastern Council; and

(c) if so, when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Appointment of Managers of District Industries Centres

6659. SHRI KUMARI ANANTHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has questioned the wisdom of appointing Managers of District Industries centres without giving them any statutory powers in the absence of which they would not be able to disburse effectively the financial or other material help to District Industries Centres;

(b) whether it is felt that this scheme of District Industries Centres would promote multiplicity of development agencies and create avoidable confusion in rural industries department;

(c) whether a high level inter ministerial working group has been set up to suggest the necessary changes in the District Industries Centres scheme; and

(d) if so, whether the expenditure on DICs is going to be infructuous till the submission of the Report by the above working Group?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) No, Sir. However, with a view to enable the District Industries Centres to render effective assistance and support to the Small entrepreneurs, a schedule of delegated powers has been circulated to all State Governments. Central and State Governments are progressively delegating powers at various levels.

(b) No, Sir. The District Industries Centre is conceived as an administrative machanism to remove bottlenecks and coordinate the different activities and inter-agency requirements for setting up small and rural industries.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

कुछ वस्तुओं का उत्पादन लघु क्षेत्र के एककों के लिए सुरक्षित करना

6660. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय साबुन, टूथपेस्ट, माचिस, चमड़े के जूते और स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का निर्माण लघु क्षेत्र के एककों के लिए सुरक्षित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि वस्त्रोद्योग में भी धोती, तौलिया और आम उपयोग की ऐसी ही वस्तुओं को पावरलूम और हैण्डलूम सेक्टर में सुरक्षित रखा जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) कपड़े धोने के साबुन, टूथपेस्ट, सेफ्टी माचिस तथा चमड़े के जूतों का उत्पादन विकास के लिए केवल लघु क्षेत्र में पहले ही आरक्षित कर दिया गया है। स्टेनलैस स्टील के बर्तनों को अभी तक आरक्षित नहीं किया गया है। आरक्षित वस्तुओं की सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि लघु क्षेत्र में बनाये जा सकने वाले नये उत्पादों व नई प्रक्रियाओं का पता लगने पर ऐसी वस्तुओं की सूची में निरन्तर विस्तार किया जा सके।

(ख) और (ग) औद्योगिक नीति विवरण के पैरा 14 में यह स्पष्ट किया गया है कि जनता की वस्त्र सबंधी आवश्यकताओं खादी सहित हथकरघा क्षेत्र जो वस्त्रों के उत्पादन में लगे अनेक लोगों को रोजगार देता है। सरकार संगठित तथा विद्युत करघा क्षेत्र की बनाई क्षमता में किसी प्रकार का विस्तार करने की अनुमति नहीं देगी।

Investigation Re Fall in Price of Cotton

6661. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) whether any investigation has been made by Government regarding fall in price of cotton though there has been increase in the cloth price, and

(b) if so, with what results, indicating measures that have been taken by Government to ensure that neither textile industry nor the middle men take additional money at the cost of consumers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). While no formal investigation has been made, it is found that during the period February, 1978 and February, 1979, the wholesale prices of cottin textiles have increased marginally by 2.9 per cent though the wholesale prices of cotton have fallen by about 9.4 per cent. The above increase in price of cotton textiles is attributed to the termination of sluggish demand for cloth during the three years 1975, 1976 and 1977 and to the increase in the cost of other inputs in making the cloth. The fall in prices of cotton does not appear to have created any additional money that could be taken by the textile industry or the middle men. Nevertheless the price situation was discussed with the cotton textile industry who have been asked to devise steps to reduce the prices of cotton cloth.

M/s Porritts and Spencer (Asia) Ltd.

6662 SHRI ANANT DAVE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to give the information asked for in Unstarred Question No 4147 on the 16th August 1978 in respect of M/s Porritts and Spencer (Asia) Ltd Faridabad?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) The information asked for in Unstarred Question No. 4147 on 16th August, 1978 in respect of M/s Porritts and Spencer (Asia) Ltd, Faridabad, is as follows:—

(a) and (b) M/s Porritts and Spencer (Asia) Ltd was given an Industrial Licence for setting up a felt manufacturing unit in collaboration with its foreign principals The collaboration agreement approved by Government in April, 1968 provided *inter-alia* that:—

(i) the authorised capital of the proposed company to be set up at

Faridabad, Haryana State, would be Rs. 2.5 crores with an initial paid up capital of Rs. one crore, in equity shares of Rs. 10 each *at par*.

(ii) 60 per cent of the initial paid up capital of Rs. one crore shall be allotted to M/s. Porritts and Spencer, U.K. out of which shares to the extent of paid up capital of Rs. 10 lakhs may be allotted for supply of technical know-how and the balance of Rs. 50 lakhs for the supply of capital equipment. Not more than 60 per cent of equity capital shall be held by non-Indians.

(iii) No royalty will be allowed to the foreign collaborator. The firm was issued an import licence on 26th August, 1968 for import of plant and machinery valued at Rs. 44,08,300. Major part of the machinery allowed was second-hand. Subsequently, the value of the import licence was enhanced to Rs. 47,98,300 in July, 1971.

(c) As reply to (a) and (b) above would indicate Rs. 50 akhs worth of share capital was allotted to the foreign collaborator against import of capital equipment. The repatriation of dividends linked with this equity, however, would be governed by the provisions of Foreign Exchange Regulation Act, 1973, which is administered by the Department of Economic Affairs.

Crisis faced by Small Scale Wax Industries, Kot Kapura, Punjab

6663. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the manufacturers of small scale industry of wax are facing crisis in Punjab especially in Kot Kapura;

(b) whether the dealers of Kot Kapura are wandering with permits of wax but they had not got even a kilogram till now; and

(c) whether the dates of getting wax on permits have expired two to three times?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) There has been an overall short supply of wax against the requirements of units all over the country.

(b) No specific instance has come to notice of Director of Industries, Punjab.

(c) The validity of all permits issued in the first week of February, 1979 was extended only once in view of freezing of stocks with the dealers by the Ministry of Petroleum through a circular No. 19023 dated 31st January, 1979 pending fixation and finalisation of new sale price of wax. Validity of permits was accordingly extended upto 25th March on intimation of revised rates from M/s. Bharat Petroleum in the first week of March, 1979.

भारत का मानचित्र

6664. श्री लालजी भाई : क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का मानचित्र सर्वप्रथम कब तैयार किया गया था, और

(ख) इसे कब पुनरीक्षित किया गया था और क्या सभी त्रुटियां दूर कर दी गई हैं ?

रक्षा मंत्रालय में और परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) भारतीय सर्वेक्षण में भारत का पहला मानचित्र 1881 में तैयार किया गया था।

(ख) भारतीय सर्वेक्षण भारत के मानचित्र में निरन्तर संशोधन करता रहा है, नवीनतम संस्करण, जिसे छठा संस्करण कहा जाता है 1972 में प्रकाशित किया गया था।

'रोड मैप आफ इंडिया' (भारत का सड़क मानचित्र) (छठा संस्करण) और 'रेलवे मैप आफ इंडिया' (भारत का रेल मानचित्र) (नवां संस्करण) का प्रकाशन 1977 में किया गया।

एक मानचित्र, सर्वेक्षण के समय में विद्यमान सांस्कृतिक (मानव-निर्मित) विवरण और भौतिक विशेषताओं को चित्रित करता है। प्रत्येक अनुवर्ती सर्वेक्षण से मानचित्रों की परिशुद्धता और रचना अन्तर्वस्तु में निरन्तर सुधार किया जा रहा है।

Automobile Industry Units

6665. SHRI GANANATH PRADHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state the number of automobile industry units in the country and their manufacturing capacity of of each of them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): The installed capacities of vehicle manufacturing units in the country are given in the statement attached.

Statement

A. *Commercial Vehicles:*

Sr. No.	Name of the Unit	Installed capacity as on 1-4-1979 (Nos.)
1	M/s. Tata Engineering & Locomotive Co. Ltd., Bombay/Poona	36,000
2	M/s. Ashok Leyland Ltd., Madras	13,000
3	M/s. Hindustan Motors Ltd., Uttarpara (West Bengal)	15,000
4	M/s. Premier Automobiles Ltd., Bombay	6,000
5	M/s. Mahindra & Mahindra Ltd, Bombay	3,000
6	M/s. Bajaj Tempo Ltd., Poona	8,000
7	M/s. Standard Motor Products of India Ltd., Madras	3,000
B. *Jeeps:*		
1	M/s. Mahindra & Mahindra Ltd., Bombay	13,000
C. *Passenger Cars:*		
1	M/s. Hindustan Motors Ltd., Uttarpara (West Bengal)	30,000
2	M/s. Premier Automobiles Ltd., Bombay	18,000
3	M/s. Standard Motor Products of India Ltd., Madras	3,400
4	M/s. Sunrise Auto Industries Limited, Bangalore	1,000

Utilisation of Jute Stock

6666. SHRI SUSHIL KUMAR DHARA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have any plan to utilise the jute-stock produced in abundance every year in the country and has been a waste for its non-utilisation;

(b) if so, the quantity of jute-stock produced every year in the country;

(c) how much not utilised; and

(d) what is the reasons for non-utilisation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (d). The normal annual production of Jute stock is estimated to be three million tonnes. At present most of this is put to use as fuel and for thatching and fencing purposes. Jute Technological Research Laboratories are conducting research to determine the feasibility of

utilising the jute stock for industrial purposes and they are reported to be already colaborating with a firm for manufacture of particle board from jute stock. Some of the small paper mills as well as Messrs India Paper and Pulp Ltd. are utlising jute stocks along with other raw materials. However, the exact quantity of jute stocks being put to such uses is not available. The main reasons which hinder the use of jute stocks for industrial purposes *inter alia* are difficulties in collection, transport, storage and its non-availability throughout the year.

Promotion of a Deputy Director of I.B. as Joint Director

6667. SHRI G. M. BANATWALLA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a Deputy Director in the Intelligence Bureau has been promoted as Joint Director superseding seven other officers senior to him; and

(b) if so, the circumstances under which Government promoted a junior officer superseding his seniors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Declaration of Koraput District as Hilly and Remote Area

6668. SHRI BAIRAGI JENA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state whether Government have considered the proposal of the State Government of Orissa to categorise Koraput district as one of the hilly and remote areas of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): No such proposal has been received by the Planning Commission.

Loss to Cement Factories for not-lifting the Cement

6669. SHRI G. NARSIMHA REDDY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether certain factories had to reduce their production due to their storing capacity being full as cement could not be lifted;

(b) if so, the names of such factories and the loss of total quantity of cement production in tonnes, factory-wise and month-wise for last nine months;

(c) what action Government have taken to see that cement factories do not suffer production for want of storing capacity, what are the results;

(d) whether Government are prepared to allow all such cement factories who are losing production to sell the cement to persons or dealers who are prepared to lift cement immediately at factory upto the quantity which may create sufficient storing capacity to continue their full production; and

(e) if so, the details and how it will be implemented; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). During the year 1978-79, some of the cement production units reported that their production was affected as their silos remained full due to inadequate availabilty of railway wagons or movement restrictions. Since capacity utilisation is also affected by a number of other factors including power restrictions, coal shortage, labour disputes etc., it is not practicable to determine the quantity lost due to silos remaining full.

(c) Government have taken a number of steps including liberalisation of rules for reimbursement of freight for movement of cement by road and general permission to the State Govts. in whose jurisdiction the concerned production units are situated for the immediate lifting of

cement in cases where the units reported that their silos were full. The Railways have also been requested in such cases to provide wagons on priorty basis to the extent possible.

(d) No, Sir.

(e) Any general permission to the cement production units to sell cement to persons or dealers of their choice may lead to malpractices and will not be in accordance with the policy of the Government for controls on price and distribution of cement.

सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों की तुलनात्मक विकास दर

6670. **श्री राम सागर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 से 1978–79 तक वित्तीय तथा कलैण्डर वर्षों में कुल औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर क्या है;

(ख) उक्त वर्षों में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दरें क्या हैं;

(ग) व्यापार तथा विकास महानिदेशक के अन्तर्गत आने वाले कारखानों और लघु क्षेत्र के कारखानों में उक्त अवधि में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर क्या थी; और

(घ) लघु क्षेत्र के उद्योगों के बारे में आंकड़ों के आधार क्या है और उसमें कितनी छूट दी गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख). औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के माप (1970-100) के अनुसार वित्तीय वर्ष 1976–77, 1977–78, तथा 1978–79 के (अप्रैल से दिसम्बर) की विकास दर क्रमशः 9.5 प्रतिशत, 3.9 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत थी तथा कैलेन्डर (पंचांग) वर्ष 1976, 1977 तथा 1978 की विकास दर क्रमशः 9.8 प्रतिशत 5.2 प्रतिशत तथा 6.8 प्रतिशत थी। सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के विकास दर विषयक तुलनात्मक सूचकांक अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ). तकनीकी विकास के महानिदेशालय की संवीक्षा के अन्तर्गत आने वाले एककों के बारे में लगाये गये अनुमानों के अनुसार उत्पादन की विकास दर 1976–77 में 11.5 प्रतिशत, 1977–78 में 6 प्रतिशत तथा 1978–79 में 10 प्रतिशत बतायी गई है। तकनीकी विकास का महानिदेशालय (डी०जी०टी०डी०) क्षेत्र के लिये तीन कलेन्डर वर्षों के आंकड़े क्रमशः 12 प्रतिशत, 8.5 प्रतिशत तथा 8.6 प्रतिशत है। लघु क्षेत्र के सम्बंध में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय पंजीयित एककों के दो प्रतिशत के लघु नमूने के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाता रहा है। इस नमूने के आधार पर लगाया गया अनुमान 1977–78 तथा 1978–79 में लगभग 16 प्रतिशत की विकास दर बताता है। इन आंकड़ों को और भी ठीक कर के तथा लघु क्षेत्र को समाविष्ट कर उसमें और भी सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्पादकता सेवाओं के विकास के लिए प्रस्ताव

6671. **श्री बागुन सुमबरूई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा विचार विमर्श किये गये उत्पादकता सेवाओं के विकास सम्बन्धी नये प्रस्ताव क्या हैं; और

(ख) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख). राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् ने अपनी 15 मार्च, 1979 को हुई बैठक में अपनी गतिविधियों को सरकार की आर्थिक एवं औद्योगिक नीति विषयक उद्देश्यों के अनुरूप बनाने का निश्चय किया है। परिषद ने तत्काल ही कार्यवाही करने के लिये निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाया है :—

(1) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, लघु उद्योगों के विकास आयुक्त तथा अन्यों के सहयोग से साबुन तथा दियासलाई उद्योगों का विकास करना।

(2) विद्यमान एककों में लघु क्षेत्र उत्पादकता सुधार का विकास तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के सहयोग से आरक्षित वस्तुओं के लिये लघु एककों का विकास संवर्धन करना।

(3) सरकारी क्षेत्र के संगठनों में जहां उत्पादकता कम है अथवा रुग्ण समझी जाती है, उत्पादकता में सुधार तत्काल ही अध्ययन के लिये पता लगाये गये कुछ एककों/क्षेत्रों में राज्य विद्युत मंडल, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के रुग्ण एकक तथा इंजीनियरी उद्योग बंबई बंदरगाह, तथा मुगलसराय के रेलवे यार्ड आदि हैं।

(4) मजदूर संघों की रुचि जाग्रत करने हेतु उपयुक्त योजनाओं का संवर्धन करना ताकि वे उत्पादिता को अपने आंदोलन का एक अविभाज्य अंग बना लें।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद साबुन तथा [illegible] उद्योगों का कुटीर/लघु क्षेत्र में विकास करने हेतु विस्तार से प्रस्ताव बना चुकी है। अन्य क्षेत्रों के बारे में परिषद प्रस्ताव बना रही है।

आदिवासियों की भूमि को वापिस लौटाने के लिये संथाल परगना में आन्दोलन

6672. **श्री बटेश्वर हेमराम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के परगना संथाल परगना जिले में आदिवासियों की भूमि को, जिसे अन्य व्यक्तियों के नाम कर दिया गया है और वह उनके कब्जे में चली गई है, उन्हें वापिस दिलाने के लिये कई महीनों से आन्दोलन चला रही है और इस संबंध में हत्यायें और आगजनी की घटनायें हो रही हैं,

(ख) क्या 2 दिसम्बर, से 8 दिसम्बर तक संथाल परगना के मुख्यालय दुमका की आन्दोलनकारियों ने नाकाबन्दी की थी और राष्ट्रीय ध्वज को भी मुख्यालय से उतारने का प्रयास किया था, और

(ग) क्या इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप अमनीयाआर थाना सुन्दरपहाड़ी में तीन व्यक्तियोंयें की हत्यायें हुई और ग्राम पकुड़िया, थाना पथर गामा, में हत्याएँ और आगजनी की घटनायें हुई और ग्राम मकरमपुर, थाना मसलियां, जिला संथाल में हत्यायें हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना बिहार सरकार से मांगी गई है और जब प्राप्त होगी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Inquiry against Director Electronics Testing and Development Centre

6673. SHRI BHAGAT RAM Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 8259 on 26th April, 1978 regarding inquiry against Director, Electronics Testing and Development Centre and state:

(a) whether the Enquiry Officer has submitted his report;

(b) what are the findings of the Enquiry Officer and what action has been taken on the report;

(c) whether it is a fact that a committee has further been constituted to look into the same charges; and

(d) what is the justification for such a committee and why no action has so far been taken against the guilty officer in accordance with the findings of the enquiry officer?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) to (d). An enquiry was conducted into the allegations levelled against the Director of Electronics and Development Centre, Chandigarh:—

1. The Enquiry Officer in his report held as proved the following charges.—

(i) Misuse of Oxygen Gas Cylinder belonging to Electronics Testing and Development Corporation to benefit the industry owned by his wife.

(ii) Tampering with quotation of M/s Decent Furnitures in order to give him pecuniary benefits and drawing commission on account of this favour.

(iii) Claiming false T.A.

(iv) Changing of Joining Report of one Workshop Mechanic from afternoon to forenoon.

(v) Payment of daily wages to one Sweeper-cum-Chowkidar for the period when he was on leave.

(vi) Compelling a Glass Blower, A Class III employee to perform the duties of Sweeper-cum-Chowkidar

(vii) Termination of the services of a number of employees within a span of two years on account of their refusal to carry out his orders to do his private work.

(viii) Vindictive attitude towards the subordinate staff.

2. According to the report received from the Chandigarh Administration. The report was placed before the Appointing Authority, the Board of Directors of Chandigarh Small Industries Development Corporation The Board of Directors decided that the enquiry report needed further scrutiny as it lacked clarity on some points and the Director, Electronics Testing and Development Corporation had not been afforded adequate opportunity by the enquiry officer to explain his position in respect of each charge. Therefore, a Sub Committee was appointed to analyse the enquiry report. The report of the Sub Committee is awaited.

Rise in Cloth Prices

6674. SHRI F. P. GAEKWAD: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Cotton cloth prices last year had risen in disproportion to the fall in the cotton prices;

(b) whether the like in prices was due to the higher cost of inputs;

(c) if so, whether it a fact that the input cost had gone up ranging from one per cent to ten per cent whereas the rise in cloth prices at the consumer and was 25 per cent to 30 per cent; and

(d) in view of (c) above, what measures are proposed to be taken to arrest rise in cotton cloth prices immediately?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (d). The wholesale prices of cotton textiles have increased marginally by 2.9 per cent between February 1978 and February 1979 though the wholesale prices of cotton fallen by about 9.4 per cent during the same period. The increase of 2.9 per cent is attributed to the termination of sluggish demand for cloth during the three years 1975, 1976 and 1977 and to the increase in the cost of other inputs in making the cloth.

The cost of other inputs had gone up differently by 2 3 per cent to 14.6 per cent in December, 1978 over December 1977. Government have no information regarding increase in the prices of cloth at the consumers end.

The Minister of Industry recently discussed the matter with the industry, who were asked to devise steps to reduce prices of cotton cloth and the industry had responded with certain suggestions which are under consideration of Government.

महाराष्ट्र के जिला उद्योग केन्द्रों के लिए राजसहायता

6675. श्री गंगाधर अप्पा बुरांडे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के कितने जिलों में 15 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान योजना क्रियान्वित की जा रही है और उसका आधार क्या है; और

(ख) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) महाराष्ट्र के 3 जिलों अर्थात रत्नागिरि, औरंगाबाद तथा चन्द्रपुर में केन्द्रीय निवेश योजना कार्यान्वित की जा रही है। केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के पात्र बनाने हेतु जिलों/क्षेत्रों का चयन करने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति के निर्णय के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया था कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े पाये गए प्रत्येक राज्य

के 6 जिले/क्षेत्र तथा महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों 3 जिले/क्षेत्र रियायती वित्त सुविधाओं के पात्र बनने के लिए तथा केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के भी पात्र बनने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किये गए जिलों में से चुने जाएं। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव के आधार पर इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त 3 जिले चुने गये हैं।

(ख) योजना आयोग ने जो निवेश राजसहायता क्षेत्रों का पुनः सीमा निर्धारण करता है बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल, 1974 में केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया था कि निवेश राजसहायता योजना के पात्र बनने के लिए चुने गए 3 जिलों के स्थान पर रियायती वित्त सुविधा के लिए राज्य के चुने गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 13 जिलों में से 13 विकास केन्द्रों वाले 53 पंचायत समिति प्रखंडों का (13 जिलों में से प्रत्येक में एक केन्द्र के हिसाब से) चुना जाना चाहिए। चूंकि यह प्रस्ताव राज्य के मुख्य मंत्रियों की राष्ट्रीय विकास परिषद समिति के निर्णय के अनुरूप नहीं पाया गया था अतएव इस प्रस्ताव के लिए सहमति देने संबंधी योजना आयोग की असमर्थता के बारे में महाराष्ट्र सरकार को 16-5-1974 को सूचित कर दिया गया था।

महाराष्ट्र सरकार ने निवेश राजसहायता के क्षेत्रों का पुनः सीमा निर्धारण करने के लिए अप्रैल, 1974 के अपने पहले प्रस्ताव के लिए स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मई, 1975 में योजना आयोग से दोबारा अनुरोध किया था। विस्तार से विचार करने के बाद योजना आयोग ने 31 जुलाई, 1975 को राज्य को सूचना दी थी कि चूंकि विद्यमान राजसहायता योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति की गई थी, अतः इस नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए उसी समिति द्वारा सावधानीपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए तथा स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

श्री बी० शिवारामन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में पिछड़े क्षेत्रों की एक राष्ट्रीय समिति का हाल ही में गठन किया गया है। इस समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की विद्यमान योजनाओं, जैसे रियायती वित्त, निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता, बिक्रीकर में रियायत आदि कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों की इसी प्रकार की योजनाएं जैसे डी० पी०ए०पी० तथा पिछड़ापन दूर करने के लिए गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए किए जाने वाले सामान्य उपायों की योजना के संचालन की समीक्षा करना है। केन्द्रीय राजसहायता योजना में यदि कोई संशोधन करने पड़े तो ऊपर इस समिति की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

Reserves of Rock Salt in Mandi

6676. SHRI GANGA SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the areas and the etimated reserves of Rock Salt in Mandi (Himachal) Salt Mines;

(b) the daily discharge of Saline Waters from the rivulets of Drang, Maigal and Guma flowing adjacent to the Mandi Salt Mines;

(c) whether it is a fact that the production of both cattle lick and potable salt has fallen down in the above salt sources during the last ten years; and

(d) whether Government want to increase the production of salt and bye products from the above sources; if so, how?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) According to the report of the India Bureau of Mines, the area of, and estimated reserves of rock salt in Mandi Salt Mines are about 29,465 sq. metres and 8.52 million tonnes, respectively.

(b) While no authentic statistics are available about daily discharge of saline water from rivulets of Drang, Maigal and Guma, a report prepared by the National Industrial Development Corporation had estimated the discharge at 22.5 cu. metres of brine of 9 degrees (Be) per hour.

(c) and (d). The production of rock salt (cattle-lick) at Mandi has remained fairly stable around 4,000 tonnes during the last ten years. However, the production of pan and refined salt, which is produced in small quantities, has declined due to unfavourable weather conditions and shortage of coal. The production of rock salt is at present limited by its demand in the market and can be increased if there is more demand.

The salt produced at Mandi does not contain any important by-products for economic recovery.

Research by Engineers and Architects of Engineering Unit of CSIR

6677. SHRI T. S. NEGI:

DR. RAMJI SINGH:

Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2326 on 7th March, 1979 re: Engineers and Architects of engineering unit of CSIR and state:

(a) whether it is a fact that Engineers and Architects of Engineering Unit, CSIR are connected with research as they are implementing the works of SERC and CBRI;

(b) whether by virtue of their nature of job and technical qualifications the Engineers and Architects of this Unit are not primarily the technical persons;

(c) whether the persons like plumbers, masons, mates, polishers etc. working under them have been classified as Technical; and

(d) if so, how long it will take to review these categorisation and putting the Engineers and Architects in Technical Category?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) The Engineers and Architects of the Engineering Unit, CSIR are essentially engaged in planning and costruction of buildings and services. In doing so, they utilise some of the products and techniques developed by SERC and CBRI. They do not carry out any research as such themselves.

(b) The Governing Body of the CSIR felt that as the Engineering and Architectural personnel of CSIR are not contributing towards research they may be classified as 'Administrative'. The work they are engaged in is however technical and they possess technical qualifications.

(c) The Governing Body of the CSIR took a decision to reclassify the staff of the CSIR into three categories namely, Scientific, Technical and Administrative against four categories of Scientific, Technical, Auxiliary Technical and Administratve, existing earlier. The posts of plumbers, masons, mates and polishers earlier included as 'Auxiliary Technical' have thus been classified as 'Technical'.

(d) The position is somewhat anomalous. The matter is therefore being reconsidered; no definite time limit can be given at this stage.

Disposal of Cases of Offences by Police Personnel in Delhi

6678. SHRI MOHAN LAL PIPIL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have carried out any survey regarding the adequacy of police personnel in the face of growing cases of offences in the Union Territory of Delhi;

(b) the total number of cases presently under investigation of the Delhi Police for various offences which are pending for less than (i) one year (ii) three years (iii) five years (iv) eight years and (v) ten years;

(c) the total number of Enquiry Officers handling these cases and the average number of cases being investigated into by an enquiry officer; and

(d) whether there is any proposal under Government's consideration to augment the staff strength of police personnel for speedy disposal of cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) to (d) The requirements of the Delhi Police are constantly reviewed and measures necessary to promote their efficiency are taken subject to financial constraints. An Expert Committee has also been set up to formulate yardsticks for the manpower, transport and communication requirements of Delhi Police

The details of cases, presently, under investigation of the Delhi Police for the various offences are as below:—

Period	No of cases pending investigation
One year	12105
Three years	650
Five years	38
Eight years	2
Ten years	Nil
Total	12795

394 Investigating officers are handling the above cases. There are approximately 32 cases with each investigating officer.

Trouble in T.I. Cycles of India

6679. SHRI C. N. VISVANATHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the factors behind the trouble in T.I. Cycles of India, Madras have been studied in depth;

(b) the causes for the trouble and the present position; and

(c) the positive steps proposed to ensure that retrenched employees are reinstated and the production is resumed with vigour in the country's interest?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). The management of M/s. T.I. Cycles of India Ltd., Madras suspended operations of the factory in January, 1978 on grounds of labour trouble. Negotiations were held by the management and an agreement was reached with the workers' representatives, with the assistance of the State Government of Tamil Nadu. The factory was reopened and production commenced in October, 1978.

(c) The State Government of Tamil Nadu has reported that some of the workers dismissed have raised industrial disputes which are pending disposal. The State Government has also reported that there has been increase in productivity after the reopening of the factory.

Working out of Plan by the Khadi and Village Industries Commission Re: Production of Matches

6680. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the details of the plan that has been worked out by the Khadi and Village Industries Commission at the instance of the Government which would enable the small and cottage industry sector to take over the entire production of matches in the country; and

(b) the places in which the new 18 raw material banks have been set up by the Commission to help the 2700 cottage match units?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The Khadi and Village

Industries Commission's programme for the rapid development of Cottage Match Industry envisages the following outlays (besides institutional finance), production and employment targets:—

Year	Outlay (Grant and Loan)	Production	Employment
	Rs. in Crores	Rs. in Crores	Persons in Lakhs
1	2	3	4
1978-79	6·88	11·50	0·27
1979-80	14·61	21·64	0·54
1980-81	18·66	39·34	0·94
1981-82	11·50	60·23	1·49
1982-83	14·45	76·92	1·88

(b) The Commission has set up the following 16 Raw Material Banks/Depots:—

State	Place(s) where Raw Materials Banks/Depots set up	Number of Raw Material Banks/ Depots set up
1. Andhra Pradesh	Hyderabad	2
2. Haryana	Ambala	2
3. Maharashtra	Bombay . .	3
	Dahanu . .	1
4. Tripura	Agartala	1
5. Tamilnadu	Sattur . . .	1
	Kovilpatti	1
	Srivilliputhur . . .	1
6. Uttar Pradesh	Kanpur	1
	Varanasi	1
	Meerut	1
	Chandrawal	1

Working of Hindustan Photo Film Corporation

6681. SHRI SHYAM SUNDAR GUPTA:

SHRI G. M. BANATWALLA:

DR. BIJOY MONDAL:

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government of India have since inquired into the working of the Hindustan Photo Film Corporation of India since it was set up;

(b) if so, whether any irregularities have been found and if so, the nature thereof; and

(c) whether any action has been taken to uplift the working of this Corporation and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). Based on the recommendations contained in the 55th and 70th reports of the Committee on Public Undertakings which had gone into the working of Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd. (HPF) during 1974-75 and 1975-76, Government had appointed two inquiry Committees:

(i) Committee under the Chairmanship of Shri Bazle Karim, Adviser, Bureau of Public Enterprises, to examine the various lapses on the part of the management of HPF pointed out by COPU (in its 70 report) and to fix responsibility therefor. The Committee was also requested to make suitable recommendations for streamlining the administrative procedure so as to avoid recurrence of similar lapses.

(ii) A High Level Committee under the Chairmanship of Prof. K. V. Subramanyam, Chairman-cum-Managing Director of Bharat Gold Mines, to investigate the entire matter of silver losses and to pin-point lapses on the part of the management of HPF and others concerned (in terms of COPU's 70th report).

The reports of both the Committees have been received. The findings and recommendations (summary attached herewith) of the Bazle Karim Committee have been accepted by the Government. The report of the Subramanyam Committee is still under examination.

(c) During the first 8 years of its working, HPF was incurring losses and did not achieve its rated capacity of 61.5 lakh sq. m. However, with improvements in its technological and managerial skills, the company has since turned the corner and for the first time in 1975-76, exceeded its rated capacity as well as made a profit of Rs. 16.06 lakhs. Since then, the company has been maintaining steady progress as is seen from the data given below:—

			lakhs sq.m.
Production	1975-76	. .	70·17
	1976-77	. .	91·80
	1977-78	. .	92·23
			Rs. lakhs
Sales	1975-76	. .	222·80
	1976-77	. .	312·00
	1977-78	. .	356·70
Profits	1975-76	. .	16·06
	1976-77	. .	142·63
	1977-78	. .	164·10

During the year 1978-79 the company is expected to achieve a production of 94 lakhs sq. m., sales of Rs. 394 lakhs and profit of Rs. 210 lakhs.

SUMMARY OF CONCLUSIONS/RECOMMENDATIONS MADE BY THE COMMITTEE CONSTITUTED UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI BAZLE KARIM, ADVISER, BUREAU OF PUBLIC ENTERPRISES

CONCLUSIONS

1. The present location and site were chosen with due care and attention. Excellent atmospheric conditions, availability of good water and other favourable factors tended to favour Ootacamund as the location. Before choosing the site, soil and water analyses and trial borings were done by appropriate agencies.

2. The delay in commissioning the project was due to multiplicity of factors The management of HPF were operating under highly trying situations due to construction delay, claim for compensation from foreign collaborators for delay in construction, change in management of collaborating firm and inadequacies in the collaboration agreement leading to protracted negotiations

3 The management could not invoke penalty clauses for non-fulfilment of certain obligations by the foreign party due to various reasons Invoking penalty clause would have led to litigation to be carried through French courts adding further delay and uncertainty

4 The collaboration agreement was not of a turn-key nature whereby responsibility could be pin-pointed on the collaborators.

5 The Company management were constantly seized of the problem of delay and sought directions from the Board of Directors from time to time to overcome difficulties.

6. The collaborators had no managerial control and holding them responsible for achieving or non-achieving a certain production level would not have been of much help in such a highly sophisticated industry as manufacture of photo films. With the rapid charge in demand for types of photo films, incorporation of capacity build-up would hardly have served as a useful guidance to HPF management for watching progress.

7. There was tacit understanding between MACC and HPF for supply of cellulose triacetate for manufacture of photo films MACC, which is a semi-Government Company promoted by Mysore Sugar Co. (Karnataka State Government Company) was headed by a senior officer of IAS from Karnataka State Cadre. The question of seeking compensation from MACC was considered by the Board of Directors of HPF, which decided to drop the issue.

MACC was itself in a difficult financial situation due to poor off take of its product and was not in a position to meet loan commitments entered into with IDBI, ICICI, etc. In such circumstances, the question of recovering any portion of the cost of modifications would not have been of help.

8 The problem of losses of solvent and the need for designing a system to improve the efficiency of recovery engaged the attention of HPF management sufficiently early The services of Indian consultancy firm (Dastur&co) were engaged by the management in April, 1970 to study inter alia the solvent recovery system. Global tenders were floated by the management in November, 1971, an offer received in response from a Dutch firm was accepted in 1972 and the recovery plant received in June, 1973 was commissioned in August, 1973 There has been no lapse of management in this regard

9. It is a commendable effort on the part of HPF that they on their own efforts without the benefit of foreign collaborators, developed process technology for manufacture of silver nitrate. The design of the

plant was provided by HPF technicians and the plant totally fabricated in India is operating since 1969-70 with very little modifications.

10. The assumption at the time of setting up Silver Nitrate Plant that all the silver used in process could be recovered was an unrealistic estimate, according to Bauchot and Co., the average yield of recovery was not more than 50 per cent of silver used in preparation section.

11. Silver loss accounting is suited only to Accounts Department, in as much as theoretically there should be no silver loss in the Emulsion and Coating Section ,as all Waste material is sent to silver recovery system; yet in reality there is loss.

12. Silver from all silver bearing materials, except samples drawn for quality control and slag arising during conversion of sludge into silver and photographic clippings and waste paper was being recovered on a regular basis from January, 1971. Upto December, 1970, the quantity of silver recovered was about 1000 kgs. reckoning the first year of operation of the plant as 1968-69.

13. Slag arisings are being sent to BGML from October, 1972 due to lack of facility within HPF. Earlier to this period, the slag was allowed to accumulate with the expectation that HPF technicians themselves would find a solution.

14. Transporation of bulk quantity of slag to a distance of about 250 km. away from Coty and traversing back the same distance the recovered silver with all the security precautions necessary in one of the less frequented roads, is not a very satisfactory arrangement.

15. The rejection levels of main film products were in such a high range as 65 per cent to 152 per cent for cine film (positive) 176 per cent to 444 per cent for X-ray, between the years 1968-69 to 1971-72. In such a situation, the natural concern of management would be to contain these rejections and make attempts to turn out acceptable quality of products. The question of recycling of watches is of secondary importance; nevertheless, considerable attention had been paid by management to the aspects of recovery of silver within the constraints of available know-how. There was, however, scope for improvements.

16. With know-how maturity, production stabilisation capital improvements made in the manufacturing sections, and in silver recovery plant and improved management practices, there has been improvement in the recovery of silver from 1971-72. Over the last few years, there has been substantial increase in output of photo-sensitised materials.

Recommendations:

1. HPF is in a unique position holding monopoly in the manufacture of photographic goods in the whole of Asia, barring Japan. A special responsibility is cast on it to keep a careful watch on the improvements/developments in technology/know-how taking place in the leading countries of photographic manufacture so as to avail of improved facilities through fresh collaboration schemes.

2. The role of foreign collaborator should be clearly spelt out to avoid any ambiquities in the interpretation of agreements with foreign parties.

3. In photographic goods, leading manufacturers have specialised in different types of products (X-ray, Roll film, Colour Film, etc.). Future agreements should be split up into separate schemes for individual products so as to ensure that the most suitable manufacturer is chosen for collaboration. Such agreements

should incorporate clauses insisting on foreign parties to supply detailed design sheets and specifications in time.

4. Any future agreement should provide for preshipment inspection/testing by independent inspection agencies before shipment of equipment and materials for use in HPF factory.

5. Further agreement should also ensure that before accepting any equipment or process from abroad, its performance should be thoroughly tested regarding capacity, quality and suitability of process. Any performance guarantee should cover performance over a fairly long period.

6. The collaboration agreement should include provision for arbitration in case of dispute between the Indian party and foreign collaborator to be settled in India, as far as possible.

7. Slag arisings in the process of conversion of sludge into silver are sent to a distance of 250 kms. to Bharat Gold Mines, with all security risk, for recycling. HPF has also no arrangement for recovery of silver from photographic paper clippings and wastes. Silver from waste water drawn for laboratory purposes is also not recovered. HPF management should, therefore, make a study of practices abroad in all the above three areas and come forward to Government with proposals for creating suitable facilities.

8. Silver loss accounting should be in the form of material balance after establishing input-output relationships at various stages of recovery.

9. With product stabilisation know-how maturity and improved management practices, the HPF plant is now poised for product diversification and growth. The photographic plant has withstood many vicissitudes. The scientists and engineers of HPF have by their own efforts, solved many of their problems. The need for continuous upgradation of knowledge and techniques in photo film manufacture is born out by our study.

Sale of Bajaj and Priya Scooters

6682. SHRI SHRIKRISHNA SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the total number of various types of scooters, such as Bajaj 150 and Priya, etc. sold by M/s. Bajaj Auto Ltd. to the persons registered in general and against Government quota, separately, in the country and Delhi/New Delhi in particular immediately preceding one year (month-wise) of decontrol of scooters by Government and the number of scooters sold in the corresponding months thereafter against general list and others separately;

(b) whether there has been any fall in the number of scooters sold after decontrol; if so, the reasons therefor with reference to their manufacturing capacity; and

(c) the total number of persons in general waiting list for Bajaj 150 and Priya Scooters and the approximate time to be taken to meet the requirement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) M/s. Bajaj Auto Limited, Poona are manufacturing Bajaj Super and Bajaj Chetak scooters. 'Priya' scooters are being manufactured by M/s Maharashtra Scooters Limited, Satara, under sub-licensing arrangements with M/s. Bajaj Auto Limited, Bajaj Chetak scooters are being allotted against inward remittances of foreign exchange. The Statutory Control on distirbution and sale of all makes of scooters, which was last applicable only to Bajaj and Priya makes of

scooters, was rescinded on 1st January, 1978. There are, therefore now no quotas for allotment of scooters at the disposal of Government authorities. Deliveries, however, in 1978 were made against quotas during the period of control. On the basis of the information reported, (which is not available month-wise) the data in respect of sales of scooters during the year 1977 and 1978 is given in the statement attached.

(b) Supplies effected in 1978 were less than in 1977, mainly because of disruption in production due to strike in the unit of M/s. Bajaj Auto Ltd. for about 1½ months.

(c) The total number of orders booked with various dealers in the country for Bajaj-150/Bajaj Super and Priya scooters stood at 3.70 lakhs and 1.14 lakhs respectively as on 1st January, 1979. The manufacturing capacity of M/s. Bajaj Auto Limited is being increased. The industry, as a whole, including the public sector organisation—Scooters India Limited—is also being developed so that consumer demand for scooters is met both qualitatively and quantitatively. It is expected that with this development in the industry, imbalanced preferences for a particular brand of scooter would be corrected expeditiously.

Statement

Bajaj/Chetak/Priya	1977		1978	
	Against quotas	Public booking/ Foreign exchange	Against quotas prio to de-control	Public booking/ Foreign exchange
Delhi	3,026	14,800	1,086	11,485
Other than Delhi	11,385	60,687	2,511	59,973
Total	14,411	75,496	3,597	71,458

Strike in Cement Companies

6683 SHRI NIHAR LASKAR:

SHRI M. V. CHANDRASHEKHARA MURTHY:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Associated cement company is facing an indefinite strike from 20th March following failure of talks of Bonus for 1977-78 with the Indian National cement and allied workers federation;

(b) if so, whether there will be a great loss due to strike; and

(c) whether Union Government have intervened in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c) The Indian National Cement and Allied Workers' Federation had given notice of strike to the Associated Cement Companies from 20th March, 1979 on the bonus issue The strike was averted as both the parties reached a settlement on the 19th March, 1979. The strike notice was consequently withdrawn.

Concessions to SC & ST in Lakshadweep

6684. SHRI P. M. SAYEED: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether concessions granted to the Scheduled Castes and Scheduled

Tribes in Lakshadweep by the Union Government have not been implemented by the Administration of the Union Territory so far;

(b) if so, whether the periodic instructions from the Department of Personnel and Administrative Reforms, Cabinet Secretariat to the Lakshadweep administration for the speedy implementation of the concessions and relaxations had no effect on them;

(c) if so, how many of the concessions have so far been implemented in the Union Territory with details thereof and how many are still left, and

(d) the schemes and concessions that are proposed to be implemented during the current financial year for the welfare of the Scheduled Tribes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) There are no Scheduled Castes in Lakshadweep All orders relating to Concessions to Scheduled Tribes in service matters are implemented by the Lakshadweep Administration

(b) and (c). Does not arise.

(d) A statement is attached.

Statement

The entire plan funds of the territory are for the benefit of the local inhabitants who are Scheduled Tribes. Some of the important concessions/ schemes being implemented under the current Annual Plan are:—

1. Free distribution of coconut seedlings to farmers affected by the cyclone.

2. Distribution of fertilisers with 50 per cent subsidy.

3. Distribution of power tillers with 50 per cent subsidy.

4. Distribution of milch cows with 50 per cent subsidy.

5. Supply of seeds and plants, agricultural implements, cattlefeed, sewing machines etc. under community development programme with 50 per cent subsidy.

6. Subsidised issue of mechanised fishing boats with 50 per cent subsidy on engine and 25 per cent subsidy on hull.

7 Issue of fishing gear with 33-1/3 per cent subsidy.

8. Issue of subsidy at the rate of Rs. 1875/- per dwelling unit.

बेरोजगारी दूर करना

6685. **श्री राम कंवार बेरवा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश से बेरोजगारी दूर करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमे राजस्थान को किस सीमा तक लाभ मिला है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अब्दुल रहमान) : (क) : योजना के प्रारूप (1978-83) मे यह बताया गया है कि योजना के प्रधान उद्देश्यो मे से एक उद्देश्य होना चाहिए 10 वर्ष की अवधि मे बेरोजगारी और पर्याप्त अल्प-रोजगार को दूर करना ।

(ख) यह अनुमान लगाना इस समय संभव नही है कि बेरोजगारी को कम करने के लिए वर्तमान योजना में परियोजनाओ और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा राजस्थान को कहां तक लाभ हुआ है ।

छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप से तैयार करना

6686. **श्री केशव राव धोंडगे** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना इस बीच अन्तिम रूप से तैयार की जा चुकी है ;

(ख) दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के बारे में तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़जलुर-रहमान . (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है और जल्दी ही पूरा हो जाने की आशा है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने, जिसकी बैठक नई दिल्ली में 24–25 फरवरी, 1979 को हुई थी, सरकारी क्षेत्र की योजना के कुल आकार को अनुमोदित किया और योजना के अगले चार वर्षों के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय योजना सहायता की मात्रा के संबंध में भी निर्णय किया।

परिषद् का निर्णय यह था कि अगले चार वर्षों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध होने वाली सम्भावित कुल धनराशि में से 1800 करोड़ रु० विशेष श्रेणी राज्यों के लिए और 600 करोड़ रु० राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए आरक्षित रखे जाने चाहिए ; तथा 4200 करोड़ रु० विशेष श्रेणी के इतर 14 राज्यों के बीच में, विशेष समस्याओं से संबंधित मापदंड के अलावा फार्मूले में निर्धारित किए गए विभिन्न मापदंडों के आधार पर वितरित किए जाने चाहिए। इनके अलावा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में कुल आयोजनों को करके अगले चार वर्षों में दी जाने वाली 2000 करोड़ रु० की राशि को हरेक राज्य की आय से संचित कुल उत्पादन के आधार पर, अर्थात् जनसंख्या द्वारा गुणित राज्य की प्रति व्यक्ति आय के दिलोम के आधार पर, विशेष श्रेणी से इतर 14 राज्यों के बीच में वितरित किया जाना चाहिए।

Strength of SC/ST Officers in Central Police Organisations

6687. SHRI R. L. KUREEL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the total strength of the following categories of officers in the Central Police Organisations and Union Territories separately (i) Director Generals (ii) Inspector Generals of Police (iii) Deputy Inspector Generals of Police (iv) Superintendents of Police (v) Commandants (vi) Deputy Supdts./A.S.P./Assistant Commandants (vii) Police Officers posted in the Central Secretariat or other allied organisations in the above mentioned ranks; and

(b) what is the percentage of S.C. and S.T. in each rank?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House on receipt.

Amount sanctioned to National Federation of Industrial Cooperatives Limited by Ministry of Finance

6688. SHRI BIRENDRA PRASAD: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large amount has been sanctioned to the National Federation of Industrial Cooperatives Limited, New Delhi by his Ministry from time to time during the last four years;

(b) has the objectives stipulated in the Grants been fully achieved;

(c) what is the maintenance expenditure of the N.F.I.C. on Salaries, Rents and also TA/DA of the Chairman for the last three years;

(d) whether it is a fact that N.F.I. has failed to submit the Audited Re-

ports of Accountant General as per conditions of Grants sanctioned for the last several years; and

(e) if so, how Government nominated Directors kept proper watch over the Government funds entrusted to this organisation and how further funds are being released to it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) During the last four years following amounts (Share capital investments and grants) were released to National Federation of Industrial Cooperatives for different approved schemes by the Ministry of Industry.

Year	Grants (Rs. in lakhs)	Share Capital Investment (Rs. in lakhs)
1975-76	3·62	..
1976-77	5·76	6·00
1977-78	4·07	5·00
1978-79	2·22	..

(b) The Federation has helped in marketing the goods produced by the Industrial Cooperatives which comprise the weaker sections of the society.

(c) The yearwise details are given below:

Heads	1975-76	1976-77	1977-78
(i) Salary	3,43,979·54	4,52,344·69	5,23,164·46
(ii) Rent	74,235·40	2,33,630·23	3,09,934·71
(iii) TA & DA to Chairman	11, 310·00	3,774·00	[illegible]

(d) The Statutory Auditors have completed the audit for the year 1974-75 but the audit report is awaited. Statutory Auditors for conducting the audit for subsequent years have yet to be appointed.

(e) An enquiry into the working of the Federation was conducted A time-bound programme is being formulated for implementation by the Federation so that it is revitalised and is able to serve the objects for which it has been established In the meanwhile funds were released only to meet committed expenditure.

Cars in American Cell of the C.I.B

6689. SHRI RAJ NARAIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there are 6 cars in American Cell of the Central/Intelligence Bureau (I.B.);

(b) if so, the purpose for which these cars are used;

(c) whether it is a fact that a car of I.B. was stolen from the residence of the chauffeur; and

(d) if so, the reasons for which this car was taken to Driver's house instead of being parked in the garage for staff cars?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) and (b). It would not be in public interest to disclose any information on this matter.

(c) and (d). A car was stolen from the residence of a driver on 10-9-78 and was recovered five days later. Disciplinary action has been initiated against the driver for lapses on his part.

Promotion Opportunities to Upper Division Clerks

6690. SHRI SUKHENDRA SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether certain Upper Division Clerks of Central Secretariat Service have been stagnating for a number of years for lack of promotion opportunities;

(b) whether they have not been promoted despite the fact that they have rendered over 25 years of service;

(c) whether Central Secretariat Service rules provide a small percentage for inclusion of Upper Division Clerks to grade of Assistants; and

(d) what steps are being taken to provide (i) incentives and (ii) relieve stagnation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) and (b). The Central Secretariat Clerical Service is a decentralised service, each Ministry/Department administering its own cadre However, in order to remove imbalances in promotion as between the cadres the Department of Personnel and Administrative Reforms fixes annually zones i.e. range of seniority for promotion from the grade of Upper Division Clerk to that of Assistant. In accordance with the zone now prescribed, U.D. Cs. with approximately 9 years of service in the grade are within the zone for promotion. According to the Central Secretariat Service Rules, 1962, U.D.Cs. with 5 years of approved service in the grade are eligible for promotion to the Assistants' grade. There is hardly any U D C. with 25 years service in the grade who has still not been promoted to the Assistants' grade.

(c) Percentage of posts for promotion of Upper Division Clerks to Assistants' Grade is not small because 50 per cent of permanent vacancies and all temporary vacancies in the grade of Assistant are available for promotion of Upper Division Clerks.

(d) In view of the position explained above, the question of providing incentives and relieving stagnation does not arise.

रेलगाड़ियों द्वारा सीमेंट सप्लाई करने में कठिनाइयां

6691. श्री कचरूलाल हेमराज जैन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न राज्यों में रेलगाड़ियों द्वारा सीमेंट सप्लाई करने के सम्बन्ध में कठिनाई अनुभव की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) जी, हां ।

(ख) अपर्याप्त रेल डिब्बों तथा रेलवे द्वारा समय-समय पर कुछ दिशाओं में लगाये गये ढुलाई संबंधी प्रतिबन्धों से सीमेंट की ढुलाई पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसका सुनिश्चिय करने की दृष्टि से मागकर्त्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे यथासंभव सड़क के द्वारा सीमेंट उठाएं तथा इस प्रयोजन के लिये सड़क भाड़े की प्रतिपूर्ति को उदार बना दिया गया है । रेलवे बोर्ड से भी सीमेंट की ढुलाई करने के लिये रेल के माल डिब्बों की सप्लाई पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया गया है ।

Puting Hindustan Levers "Lifebuoy" in Category of Carbolic

6692. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether IDR Act has classified soaps in three different categories;

(b) whether Life Buoy a product of Hindustan Lever has been put in the category of "Carbolic";

(c) the reasons for putting Life Buoy a hard washing soap in the category of "carbolic";

(d) whether Government are aware of the fact that Hindustan Lever has changed the chemical composition to suit the category of carbolic; and

(e) whether Government propose to examine this issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No, Sir.

(b) and (c). There is no separate Indian standard specification for Carbolic soap. A Carbolic soap should comply with the specifications for laundry soap if it is meant to be used as laundry soap or with the specifications for toilet soap if it is to be used as a toilet soap.

(d) and (e). M/s. Hindustan Lever Ltd. have not applied to ISI for grant of a licence for their brand of carbolic soap. Government is, therefore, not aware of any change in the chemical compositioin of Life Buoy by the Company.

राष्ट्रीय आय में वृद्धि

6693. श्री सुरेन्द्र नाथ सुमन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान प्रचलित मूल्य के आधार पर इन तीन वर्षों में वर्षवार राष्ट्रीय आय कितनी थी ; और

(ख) इस वर्ष कितनी राष्ट्रीय आय होने का अनुमान है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर रहमान : (क) और (ख). वर्ष 1976-77 व 1977-78 के लिए प्रचलित मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय आय क्रमश 66561 करोड़ रुपये तथा 73157 करोड़ रुपये अनुमानित की गयी है । वर्ष 1978-79 के लिए ऐसे ही अनुमान अभी तैयार किये जाने हैं ।

Synthetic Detergents

6694. DR. BAPU KALDATE : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that synthetic detergents were classified as a core sector industry in the initial stages;

(b) whether there is any proposal to declare the field of synthetic detergents as reserved for small scale sector and to take synthetic detergents out of the core sector; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Synthetic detergents are included in Appendix I to the Industrial Policy Statement of 2-2-1973.

(b) and (c). The question of reservation of manufacture of detergents for the small scale sector is under consideration.

Memorandum from Nagrik Sangharasha Samiti, Gangtok

6695. SHRI AMAR ROY PRADHAN :
SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have received a Memorandum from the Nagrik Sangharsha Samiti, Gangtok, on denial of full citizenship rights to the non-Sikkimite Indians in Sikkim in 1977; and

(b) if so, the details thereof and action taken so far in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS : (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) Yes Sir.

(b) The Samiti mentioned that all the seats in the 32-member Legislative Assembly of Sikkim were reserved for Bhutia-Lepcha communities, Nepalis of Sikkimese origin, Scheduled Castes and Sanghas of monastries and consequently Indian citizens not belonging to the above mentioned four categories were not entitled to contest elections to the Legislative Assembly The demand of the Samiti was that every Indian citizen in Sikkim, who had the right to vote, should also have the right to contest election to the Assembly

The matter has been under the active consideration of the Government and appropriate legislation in this regard is likely to be introduced in Parliament before long for consideration.

बंगाल नागपुर काटन मिल्स

6696. **श्री हुकम चन्द कछवाय:** क्या उद्योग मंत्री 16 अगस्त 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 437 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि बंगाल नागपुर काटन मिल्स पर जनवरी, 1976 से अक्तूबर, 1978 के अवधि से सम्बन्धित राशि बकाया है और अब तक कितनी राशि जमा कराई गई है तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत जमा करवानी है और क्या इन दोनो राशियो को वसूल करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या उक्त मिल में ऐसे प्रमुख व्यक्ति है जिनके व्यापार सम्बन्धी अन्य बहुत से हित भी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : (क) जी, नही। इस समय जनवरी, 1976 से अक्तूबर 1978 की अवधि विषयक कर्मचारी राज्य बीमा (ई०एस०आई०) की कोई भी देय बकाया राशि बंगाल नागपुर काटन मिल्स की ओर नही निकलती है।

(ख) जी नहीं।

Setting up of Paper Mills in Hoshiarpur

6697 CHOWDHRY BALBIR SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether two paper mills have since been sanctioned in the Hosmarpur District;

(b) the total production target per month likely to be done by these mills; and

(c) when these mills will start production of paper?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Approval has been given to three units for setting up paper mills in Hoshiarpur District.

(b) The total installed capacity of those units is about 2800 tonnes per month.

(c) One of the units is likely to commence production by the middle of 1979 The other two units are expected to commence production in 1980.

Loss to Jute Mills in Public Sector

6698 CHOWDHRY BALBIR SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the almost all the Jute Mills in Public Sector are going in loss since long;

(b) if so, the total loss suffered by all the jute mills in the country during 1978-79; and

(c) the steps Government have taken to stop this loss and the planning for future to stop such loss?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No jute mill has been commissioned in public sector so far.

(b) The figure of profit/loss of all the jute mills in the country during 1978-79 is not available as the year has just ended.

(c) The following are the important steps taken to restore the viability of jute industry:—

(1) To promote exports, which came down drastically, export duty on all jute products has been abolished.

(2) Cash Compensatory Support has been given on export of selected jute goods

(3) Cess has been levied on jute manufactures to finance R&D activities through the Development Council constituted for the jute industry.

(4) A soft loan scheme has been introduced to enable the industry to modernise the plants and machinery at a concessional rate of interest etc., so as to improve productivity and make their products competitive.

Subversive activities by Chinese trained Nagas coming to Nagaland from Burma

6699. SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Chinese trained Nagas who have sneaked into the State of Nagaland from the Burma border in large numbers have indulged in blowing up of a power station and other serious works of sabotage; and

(b) if so, the number of arrests made in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANADL): (a) and (b). Recently, some violent incidents have taken place in Mon and Tuensang Districts of Nagaland These include an attack on the power house at Mon by some unknown miscreants. No damage was caused to the power house. Although the identity of the persons involved in the attack has not yet been established, it is however suspected that members of the China-returned gang who are staying across the border may be behind the incidents. No arrests have been made so far in this regard.

Increase in Central Plan Aid

6700. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether many State Governments have asked for increase in the Central Plan Aid; and

(b) if so, the names of these States and additional amount asked for each State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) and (b). The National Development Coucil in its meeting held on February 24 and 25, 1979 has determined the quantum of Central assistance for State Plans for 1979—83 and decided the principles on which this should be distributed among the States. The State-wise allocations are yet to be finalised. The question of any State asking for increase in the Central Plan aid, therefore, does not arise.

Cases of Murder and Rape in Delhi

6701. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of cases of murder and rape reported in Delhi during 1978; and

(b) the number of cases that have been solved and the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL) : (a) and (b). The details of the number of cases of murder and rape reported in Delhi during the year 1978 are as under:--

	Reported	Cancelled	Admitted	Solved
Murder	185	4	181	135
Rape	80	4	76	71

Recruitment of SC/ST Members to Junior Posts in Central and State Services

6702. SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a two days conference of the officials of U.P.S.C., State P.S.C., Ministry of Education, Social Welfare and Culture and his Ministry and Labour was to be held during the last week of March, 1979 to discuss the matter with regard to promotion recruitment of SC/ST members to junior posts in the Central and State services; and

(b) if so, outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL) : (a) Yes Sir. A two-day conference of Recruiting Agencies like State Public Service Commissions etc. was organised by Staff Selection Commission on 24th and 26th March, 1979.

(b) The conference concluded with several recommendations. Some of the main recommendations of the conference are as follows:--

(i) to make up the shortfall in recruitment against vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, special recruitment may be held exclusively for them.

(ii) Where necessary and possible, additional examination centres may be set up in areas where Scheduled Castes and Scheduled Tribes population is concentrated.

(iii) Adequate number of pre-examination training centres may be set up for providing coaching facilities to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(iv) Facilities like hostel accommodation, typewriters etc. should also be made available.

(v) Extensive publicity may be given about examinations and recruitments in which reservations for Scheduled Castes/Tribes exist.

(vi) Recruiting agencies may be vested with the discretion of relaxing to the extent necessary, qualifications relating to experience prescribed for recruitment to various posts and services reserved for Scheduled Castes/Tribes.

Meeting of National Productivity Council

6703. SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a meeting of National Productivity Council was held recently in Delhi;

(b) if so, whether Government have advised the Committee to reorient

its activities to new economic and industrial policy;

(c) if so, details of discussions therein; and

(d) outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b). Yes, Sir

(c) The National Productivity Council at its meeting held at New Delhi on 15th March, 1979, identified the following areas for immediate action :—

(i) Development of soap and match industries in collaboration with Khadi and Village Industries Commission, Development Commissioner for Small Scale Industries and others.

(ii) Development of small-scale sector-productivity improvement in the existing units and promoting growth of small scale units for the reserved items in collaboration with DCSSI.

(iii) Productivity improvement in public sector organisations where productivity is low or are considered sick. Some of the units/areas identified for immediate studies are State Electricity Boards, sick units of the National Textile Corporation and Engineering Industry, Bombay, Port, Railway Yard in Mugalsarai, etc.

(iv) Promoting appropriate schemes for securing involvement of Trade Unions to enable them to adopt productivity as an integral part of their movement.

(d) The National Productivity Council has already worked out detailed proposals for development of soap and match industries in the cottage/small sector. Proposals in respect of other areas are being worked out by the Council.

कल्याण मिल द्वारा वस्तुओं की बिक्री

6704. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या उद्योग मंत्री 16 अगस्त, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 437 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याण मिल जनवरी, 1976 से अक्तूबर, 1978 के बीच कुछ पार्टियों को मिल में बने धागे, कपड़ों कटपीसों करतनों तथा अन्य छोटना एवं अवशिष्टों आदि जैसे अनेक वस्तुओं की बिक्री करता रहा था, यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य की ऐसी वस्तुएं बेची गई और किन किन पार्टियों को बेची गई,

(ख) किन किन पार्टियों को बेचे गये माल की कितनी राशि की अदायगी अभी प्राप्त नहीं हुई है, कब तक उसे वसूल कर लिया जायेगा और उक्त सामान सामान्यतः किन शर्तों पर बेचा जाता है, और

(ग) क्या अदायगी प्राप्त करने के लिये भुगतान न करने की दोषी फर्मों की कोई नोटिस जारी किये गये हैं और यदि हां, तो उन्हें कितनी बार नोटिस दिये गये, इस प्रयोजन के लिये कितनी फर्मों के विरुद्ध मुकदमे दायर किये गये और कितने मुकदमे दायर किये गये,

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) . (क) से (ग) अधिकांश जानकारी उन जिल्दों में प्राप्त है जो दिनांक 19-5-79 और 10-5-78 को पूछे गये प्रश्न संख्या क्रमशः 7460 और 9827 संबंधी आश्वासनों को पूरा करने हेतु संसद पुस्तकालय में रखी जायेगी। यह समझा जाता है कि इस जानकारी को एकत्र करने में लगने वाले परिश्रम के अनुकूल फल नहीं निकलेगा।

Formation of Reception Committees to Freedom Fighters at Port Blair

6705 SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during the inauguration of Cellular Jail as a National Memorial at Port Blair by the Prime Minister of India when large number of freedom fighters were present two reception committees to freedom fighters, one official committee and other citizens committee were formed if so, the details thereof, and

(b) whether the Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Islands, Shri S. M. Krishnatry had issued special instructions in spite of the request made by ex-Andaman Political Prisoners Fraternity Circle, to have a official, non-official joint reception committee, to keep away the non-officials if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL). (a) In connection with the inauguration ceremony of the Cellular Jail Memorial at Port Blair held in February, 1979, the Andaman and Nicobar Administration had constituted a Reception Committee consisting of both officials and non-officials It is learnt that the local political parties, cultural institutions and other organisations had also formed a Citizens Committee, the details of which are not available with the Andaman and Nicobar Administration

(b) No such instructions were issued.

Schemes for Rural Development in Andaman and Nicobar Islands

6706 SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has gone through the details of Sixth Five Year Plan Schemes of Andaman and Nicobar Islands; if so, details of the schemes of rural development and the total percentage of plan outlay;

(b) whether it is fact that there is a huge cut in the rural road sector which shall cause setback in the rural development in the outlying and remote areas if so, the details thereof; and

(c) whether the Planning Commission will reconsider the urgent need for construction of rural roads in the Union Territory of Andaman and Nicobar Island; if so, whether Government will like to send a senior personnel to examine the whole case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN) (a) to (c). The Sixth Five Year Plan 1978-83 of Andaman and Nicobar Islands is under finalisation.

Production of Keyboard for Hindi Typewriters

6707 SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to encourage production of indigenous Hindi typewriters in the country as part of the programme for popularising the use of Hindi in Government and semi-Government organisation;

(b) if so, the present annual production of the Hindi-typewriters in the country, production unit-wise for the last three years, year-wise;

(c) whether Government have received a proposal sometime back from Shri S. N. Nilakhe of Akola, a World Typewriting Wizard and Research Scholar regarding his improved keyboard of Devnagri script and details of the proposal made by him for production of his keyboard as a media for popularising Hindi; and

(d) what action Government have taken to provide incentives to the said scholar and small scale entrepreneur like Mr. Nilakhe to manufacture his keyboard on a larger scale and the reaction of Government to the keyboard devised by him?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). The Government are making efforts for the production of more Devnagri Typewriters than the requirement. The various companies have produced the Devanagri

Typewriters in the following number during the last three years.

	1976	1977	1978
Godrej, Bombay .	2723	2260	3104
Remington Rand Calcutta .	3019	5311	4720
Remington Rand Faridabad .	..	1059	1302
Royala, Madras .	1115	732	1066
	6857	9362	10192

(c) and (d). Some time back Sh. Nilakhe suggested for manufacturing a key board for Devnagri script Typewriter based on the Key Board of Roman script Typewriter. He was requested to make available his machine for some time for trial. He did not do so. Under these circumstances it is not possible for Government to frame any opinion about the said Key Board without making a thorough trial.

Study of Labour Intensive Nature Schemes

6708. SHRI VIJAY KUMAR N PATIL: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission have carried out some studies of the job oriented centrally sponsored central sector schemes of labour intensive nature during the 5th plan period and important findings regarding the programme Planning, programme content, administrative and other arrangements made at the Central/State and field level in the project areas, technical viability of the schemes executed and the results achieved on completion of schemes *vis-a-vis* the targets set; and

(b) if so, important findings thereof and how far these observations/findings have been taken into account for formulation of new schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) and (b). The Programme Evaluation Organisation of the Commission has carried out evaluation studies of the Crash Scheme for Rural Employment and the Special Employment Programme for the Educated Unemployed implemented during the Fifth Plan period. Summaries of the findings of these studies are laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No LT-4283/79] No such scheme is either in operation or under the consideration of the Government at present.

Special Assistance to Artisans, and Small Scale Industries

6709 SHRI NATHU SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is proposed to provide special assistance to the artisans, village and cottage industries and small scale industries and reduce the rate of interest in the backward districts, and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir

(b) According to the instructions issued by the Reserve Bank of India to all commercial banks on the 12th December, 1978, bank credit for artisans and village and cottage industries and small scale industries in the tiny sector would be treated as composite term loan for equipment finance or working capital or both upto Rs 25,000/-. In respect of credit limits for working capital above Rs. 25,000/- but less than Rs. 1 lakh

granted to artisans, village and cottage industries and small scale industries in the tiny sector, bank may charge at a rate not exceeding 12½ per cent per annum (except for small banks with aggregate demand and time liability of less than Rs. 25 crores, it may charge interest at a rate not exceeding 13½ per cent per annum)

The Reserve Bank of India has also issued guidelines to all scheduled banks on the 12th December, 1977 advising the banks to charge rate of interest not exceeding 11 per cent to small scale units covered under the Credit Guarantee Scheme and units promoted by technical entrepreneurs in order to stimulate capital investment in the small scale sector.

For promoting the development of industries in backward areas, the scheme of charging low rate of interest as also extending longer amortisation facilities in respect of projects located there will continue. The District Industries Centres which include all erstwhile areas declared industrially backward will continue to operate these schemes The maximum rate of interest on loans refinanced by IDBI in backward districts is 9½ per cent per annum for primary lenders

Setting up of a Mini Cement Factory in Orissa

6710. SHRI D AMAT. Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Minister of Industry, Government of Orissa has proposed that a mini cement factory should be set up in Sundergarh district of Orissa under the expansion programme of Industrial Development Corporation; and

(b) if so, in which particular place it will be set up and by when the work of construction will start and at what cost?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b). A scheme of the State Industrial Development Corporation of Orissa Ltd. (Bhubaneswar) has been registered on 23rd August, 1978 with D.G.TD. for setting up of a mini-cement plant with a capacity of 33,000 tonnes per annum at Kiringsera, District Sundergarh, at a cost of Rs. 172 lakhs (estimated): It is too early to state when the work of construction will start.

Reservation of Posts for SC/ST in CSIO, Chandigarh

6711 DR SARADISH ROY: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) how many posts have been filled up in the Central Scientific Instruments Organisation (CSIO) Chandigarh during the last five years (vacancies and newly created posts) category-wise;

(b) how many of these posts were reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, category-wise;

(c) how many Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applied and how many of them were selected; and

(d) how many Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees are working in CSIO at present in Class I, Class II, Class III and Class IV categories and what is the total strength of staff in each category of staff?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Persons Working Under Engineers and Architects of C.S.I.R:

6712. SHRI RAM VILAS PASWAN:

SHRI SHYAMLAL DHURVE:

Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question Nos. 2326 and 2346 on 7th March, 1979 and state:

(a) whether persons like plumbers, masons, welders, working directly under Engineers and Architects of CSIR have been declared as 'Technical' and the later category have been singled out;

(b) if so, the reasons thereof;

(c) whether by virtue of their qualifications and nature of work, the Engineers and Architects of CSIR are technical persons;

(d) whether it is a fact that Engineers and Architects of Headquarters are implementing research works of CBRI and SERC in planning and execution and as such are a coordinating link;

(e) whether Vardarajan Committee report on staff categorisation was based on some inbuilt prejudices to deprive Architectural and Engineering personnel of some consequential benefits like 5 years assessment and retirement age; and

(f) if so, by when these anomalies are likely to be removed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) to (c). The Governing Body of the CSIR took a decision to reclassify the staff of the CSIR into three categories namely, Scientific, Technical and Administrative against four categories of Scientific, Technical, Auxiliary Technical and Administrative existing earlier. The posts of plumbers, masons, welders earlier included as 'Auxiliary Technical' have thus been classified as 'Technical'. At the same time, the Governing Body of CSIR felt that as Engineers and Architects of the CSIR are not contributing towards research, they may be classified as 'Administrative'. It is true that the Engineers and Architects of the CSIR are engaged on technical work and possess technical qualifications.

(d) The Engineers and Architects of the Engineering Unit, CSIR are essentially engaged in planning and construction of buildings and services. In doing so, they utilise some of the products and techniques developed by SERC and CBRI.

(e) No, Sir.

(f) The position is somewhat anomalous and the matter is therefore being reconsidered; no definite time limit can be given at this stage.

Import of Computer by Glaxo Industries

6713. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether permission has been given to a multi-national pharmaceutical company Glaxo Laboratories (India) Ltd. Bombay to import a giant computer throttling the employment potential in the industry; if so, facts in detail;

(b) whether this is against the policy of job oriented industrialisation of the country declared by Government; and

(c) if so, whether Government propose to withdraw permission; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Senior Executives of Central Government Serving in Private Enterprises after Retirements

6714. SHRI A. K. ROY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the number of Senior Executives of the Central Government now serving the private enterprises after retirement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL) : This information is not monitored by the Department of Personnel and Administrative Reforms.

Finding of the Study Group

6715. SHRI A. K. ROY : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the findings of the Study Group of the Ministry of Industry that Senior Executives of Central Government serving the private enterprises after retirement are often used for their old contacts to take undue benefit from Government machinery; and

(b) if so, steps taken thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The Study Group of the Ministry of Industry on Industrial Regulations and Procedures has made a number of recommendations. However, this Group has not given any finding about the employment of senior officers of the Central Government after retirement by private enterprises and the use of their old contacts for undue benefits.

(b) Does not arise.

Trade Fair in Purnea Distt. (Bihar) for Development of Jute Products

6716 SHRI HALIMUDDIN AHMED : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government propose to arrange any trade fair in the Purnea District of Bihar for the development of Jute and its products;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor and the steps proposed to be taken by Government to promote Jute Production there?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) to (c). Government of India have no proposal to hold any trade fair in Purnea District of Bihar for the development of jute and its products. However, a Centrally Sponsored Scheme of Intensive Jute District Programme was initiated in 1972-73 in that district to raise the unit yield and production. This scheme is being continued during 1979-80 also. Under the scheme, the Government of India is providing cent per cent financial assistance for the development of jute in Purnea District. 80,000 hectares of the district have been covered by IJD programme and the production of jute in Bihar has increased from 516,000 bales in 1974-75 to 881000 bales in 1978-79.

Import of Bivoltine Silk

6717. SHRI A. R. BADRI NARAYAN:

SHRI M. V. CHANDRA SHEKHARA MURTHY:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Union Government have decided to import 100 tonnes of Bivoltine silk which is roughly equal to the entire Bivoltine production in Karnataka:

(b) if so, whether this import of Bivoltine silk will reduce the prices of Karnataka's Bivoltine silk;

(c) if so, to what extent the prices will be reduced;

(d) whether the price decrease will result in Karnataka Growers continuing to produce low quality multivoltine only;

(e) if so, whether Karnataka growers have objected to the import of 100 tonnes of Bivoltine silk; and

(f) if so, the reaction of the Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No, Sir. Import of bivoltine raw silk is, however allowed under replenishment scheme against export of natural silk goods as an export promotion measure. There is also a provision for import of a very limited quantity of raw silk for operating the mulberry price stabilisation scheme.

(b) No, Sir.

(c) to (f). Do not arise.

Use of Max Factor Trade Mark in India

6718. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state.

(a) whether Government are aware that Max Factor trade mark is used in India;

(b) the basis under which the trade Mark is permitted to be used; and

(c) whether Government have checked if there is an indirect consideration?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Yes, Sir.

(b) "Max Factor" trade mark is being used in India by M/s. Swastik Household and Industrial Products (Division of Ambalal Sarabhai Enterprises Pvt. Ltd.) on the basis of the Registered User Agreement with M/s Max Factor & Co., U.S.A.

(c) The Reserve Bank of India has undertaken an investigation to check if the use of Max Factor trade mark involves any indirect consideration.

राजस्थान में आदिवासीय क्षेत्रों के विकास के लिए योजना

6719. श्री नाथू सिंह :

श्री चतुर्भुज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान मे आदिवासी क्षेत्रो के विकास क लिये बनायी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और चालू छठी पंचवर्षीय योजना मे आदिवासियो कि स्थिति में सुधार करने के लिये किये जाने वाले उपायो का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या इसके लिये क्षेत्रों का चयन कर लिया गया है और यदि हा, तो उनके नाम क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) और (ख) . एक उप-योजना, 50 प्रतिशत या उससे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए बनाई गई है । ये अनुलग्न में दिए गए है ।

इन क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं में विकास के सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं अर्थात् :—

1. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र ।
2. सहकारिता ।
3. जल और बिजली विकास ।
4. उद्योग ।
5. संचार ।
6. सामाजिक और सामुदायिक सेवायें ।
7. आर्थिक सेवायें और
8. केन्द्रीय सेवायें ।

विभिन्न प्रकार के शोषण अर्थात् भूमि हस्तांतरण, ऋणग्रस्तता आदि को रोकने के लिए भी उपाय किए गए हैं ।

मध्यम-अवधि योजना 1978-83 में इन योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है ।

विवरण

राजस्थान

आदिवासी उप-योजना क्षेत्र

जिले का नाम	खण्ड
बांसवाड़ा .	घाटोल
	गढ़ी
	तलवाड़ा
	पिपलखूंट
	कुशालगढ़
	सज्जनगढ़
	भुकिया
	बागीडोरा
डूंगरपुर . .	डूंगरपुर
	बीछीवाड़ा
	आसपुर
	सगवाड़ा
	सिमलवाड़ा
चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़
	अरनोद
उदयपुर	फलासिया, खेरवाड़ा, लसादिया, सालम्बर, सारदा, कोटड़ा, गिर्वा खण्ड (पुनर्गठित)
सिरोही	आबुरोड (पुनर्गठित)

Cooperation agreement with Yugoslavia for peaceful uses of Atomic Energy

6720. SHRI NATHU SINGH:
SHRI SHANKER SINHJI VAGHELA:
SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:
SHRI G. M. BANATWALLA:
DR. BIJOY MONDAL:
SHRI BAGUN SUMBRUI:

Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India and Yugoslavia had entered into an agreement for cooperation in the utilisation of atomic energy for peaceful purposes; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) and (b). An agreement between India and Yugoslavia on cooperation regarding the utilization of atomic energy for peaceful purposes was signed in Bombay on March 16, 1979. The Agreement provides for fellowships for training of scientists, exchange of unclassified information, exchange of scientific visits, lease or sale of material and equipment and carrying out of collaborative programmes as may be mutually agreed upon from time to time. Work programmes for carrying out joint activities uder the agreement are being drawn up.

Growth rate of various Industries

6721. SHRI DHARMAVIR VASISHT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the overall performance of Heavy Industries and Engineering Industries during 1978-79;

(b) the production and growth rate achieved in Industrial Machine boil-

ers, cement machinery, tractors, cranes, machine tools, motor cars, commercial vehicles, motor cycles electrical equipment and drycells; and

(c) the exportable surpluses, if any?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a):- The rate of growth of industries which can be classified as 'Engineering Industries' (which covers industry groups such as basic metal industries, metal products, non-electrical machinery, electrical machinery, transport equipment, etc.) during the first nine months (April-December) of 1978-79 was 7.2 per cent according to the general index compiled by the CSO. No comparable estimate for "Heavy Industries" is available.

(b) A statement is attached.

(c) For most of the engineering industries, export targets are fixed by Export Promotion Council/Ministry of Commerce. No estimates of exportable surpluses as such, are available.

Statement

Production and growth rates of selected Engineering Industries during April, 1978—January 1979.

	Industry	(A/c Unit)	April, 1977—Jan 1978	Apr. '78 Jan. '79	Rate of Growth %
1.	Boilers	Rs. crores	156·6	170·8	+9·1
2.	Cement Machinery	Do.	16·88	31·69	+87·7
3.	Tractors	Th. Nos.	31·8	44·9	+41·2
4.	Cranes	Th. Tonnes	14·6	15·1	+3·4
5.	Machine tools	Rs. crores	81·3	100·9	+24·1
6.	Cars	Th. Nos.	30·2	29·8	—1·3
7.	Commercial vehicles	Do.	32·7	45·8	+40·1
8.	Motor cycles	Do.	55·2	74·9	+35.7
9.	Dry cells	Mil Nos.	522	684	+31·0

NOTE:—Figures are provisional.

Ban on Expansion of Multinationals

6722. SHRI DHARMAVIR VASISHT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the steps taken to limit the activity of large industrial houses and to bring them in line with the country's socio-economic goals; and

(b) in what specific areas, with details the large houses had been prevented from expansion and with what results?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). Government have in the Industrial Policy Statement of December, 1977 stated that where large scale units are already engaged in the manufacture of items reserved for small scale sector, there will be no expansion in their capacity. On the other hand, the share of these units in the total capacity for these items will be steadily reduced and that of the small scale and cottage sector increased. This policy is being strictly enforced.

Reduction of Import Duty on Leather Chemicals and Footwear Accessories

6723 SHRI DHARMAVIR VASISHT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the reduction of import duty on certain leather chemicals and footwear accessories has achieved the objects in view;

(b) the detailed list of the identified chemicals; and

(c) the expected target during the Sixth Plan of finished leather goods export?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Since the reduction in Customs duty on certain leather chemicals and footwear accessories/Components has been notified only on 10th Feb, 1979, it is too early to assess whether it has achieved the desired objective.

(b) A statement containing the list of chemicals for leather industry and the componenfs/accessories for footwear industry where reduction in Customs Duty has been effected, is attached.

(c) The value of exports of finished leather and leather goods by 1982-83 is expected to be of the order of Rs. 423 crores at current prices.

Statement

S. No.	Description
1	Sulphonated cod oil or sulphated cod oil or oxidised cod oil or chlorinated cod oilor sulphonated neats foot oil or sulphated neats foot oil or oxidised neats foot oil or chlorinated neats foot oil or sulphonated fish oil of sulphated fish oil or oxidised fish oil or chlorinated fish oil or mixtures thereof.
2	Syntans.
3	Pigment finishes for leather.
4	Synthetic fat liquors (with or without hydrocarbons) Non-ionic fat liquors and mixture thereof.
5	Self buffying chrome tanning agents, Aluminium tanning agents, Oil tanning agents, resin tanning agents, zirconium tanning agents.
6	Sole Leather from ox hides and cut soles and units thereof.
7	Polyurethane Soles cut to size.
8	Steel reinforced in soles.
9	Leather and Plastic Heels.
10	Thermoplastic toe caps and counters.
11	Welts made from leather or plastic.
12	Buckles and other emblishments for footwear.
13	Shoe eyelets.
14	Shoe finishing polishes in solution or in blocks.

15. The following solvent soluble dyes:—

Number	Dyes	Hue No.	Colour Index Number
(1)	Direct brown	214	..
(2)	Acid Brown	150	..
(3)	Acid Brown	52	..
(4)	Acid Brown	238	..
(5)	Acid Brown	151	..
(6)	Acid Brown	239	..
(7)	Acid Brown	147	..
(8)	Acid Brown	188	..
(9)	Acid Brown	189	..
(10)	Acid Brown	314	..
(11)	Acid Brown	235	..
(12)	Acid Brown	191	..
(13)	Acid Brown	192	..
(14)	Acid Black	162	..
(15)	Acid Black	67	..
(16)	Acid Black	169	..
(17)	Acid Brown	143	..
(18)	Direct Blue	59	..
(19)	Acid Brown	321	..
(20)	Acid Brown	290	..
(21)	Acid Brown	322	..
(22)	Acid Green	93	..
(23)	Acid Brown	127	..
(24)	Acid Black	82	20265
(25)	Acid Brown	145	20260
(26)	Acid Brown	265	13230
(27)	Acid Green	49	..
(28)	Acid Black	83	..

Number	Dyes	Hue No.	Colour Index Number
(29)	Acid Brown	144	14295
(30)	Acid Brown	146	26531
(31)	Acid Yellow	86	23310
(32)	Acid Blue	133	..
(33)	Acid Red	234	..
(34)	Acid Red	235	..
(35)	Acid Red	236	..
(36)	Acid Brown	159	..
(37)	Acid Brown	160	..
(38)	Acid Brown	161	..
(39)	Acid Brown	162	..
(40)	Acid Brown	163	..
(41)	Acid Green	48	—
(42)	Acid Brown	311	..
(43)	Acid Brown	126	..
(44)	Acid Brown	236	..
(45)	Acid Brown	276	..
(46)	Acid Brown	188	..
(47)	Acid Brown	277	..
(48)	Acid Brown	130	..
(49)	Acid Brown	303	..
(50)	Acid Brown	237	..
(51)	Acid Black	76	..
(52)	Acid Black	94	30336
(53)	Acid Brown	279	..
(54)	Acid Brown	165	..
(55)	Acid Blue	134	..
(56)	Acid Green	26	..

Number	Dyes	Hue No.	Colour Index Number
(57)	Acid Orange	78	..
(58)	Acid Violet	80	..
(59)	Acid Yellow	96	..
(60)	Direct Brown	206	25010
(61)	Acid Black	84	17560
(62)	Acid Brown	103	10415
(63)	Acid Brown	75	34905
(64)	Acid Brown	85	34900
(65)	Acid Brown	84	20255
(66)	Acid Brown	325	..
(67)	Acid Black	173	..
(68)	Acid Brown	92	36020
(69)	Acid Brown	324	..
(70)	Acid Brown	86	17595
(71)	Acid Brown	87	17596
(72)	Acid Brown	92	36020
(73)	Acid Brown	86	34900
(74)	Acid Black	69	30260
(75)	Acid Blue	36	29115

Recommendations of Committee on Kanjhawala Land Dispute

6724. SHRI DHARMAVIR VASISHT: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the detailed recommendations of the nine-Member Committee constituted in September, 1978 by the Delhi Administration to go into dispute and suggest a solution to the Kanjhawala land dispute between villagers and allottees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): Delhi Administration have reported that no such Committee was constituted by them.

Charging of High Rates on Papers by Shopkeepers ..

6725. SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA:

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

DR. BIJOY MONDAL:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the rates at which the various kinds of paper is supplied to the shopkeepers by the mills in the country;

(b) whether it has come to the notice of Government that shopkeepers have been selling the paper by charging Rs. 150|- to 200|- per

quintal over and above the rates specified by Government for which they do not issue any receipt; and

(c) whether Government propose to set up an inquiry committee or get it probed through C.B.I. as to why the paper is sold in the black market in such a manner and action taken or proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a). There is a chain of intermediaries in the paper trade, and the retail price takes into account the ex-mill rate, excise duty, freight, local taxes and distributors' margin. As there are also a large number of varieties and qualities of paper, the rates are not uniform.

(b) and (c). As there is no statutory control on prices of paper, the question of legal action does not arise. Govt. are however taking various steps to increase production and are also planning to import paper to ensure that the marginal imbalance between demand and supply does not result in speculative increase in price of paper.

Report on Institute of Applied Manpower Research

6726. SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA:

SHRI G. M. BANATWALLA:

DR. BIJOY MONDAL:

Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Government have since received the report of Professor P. R. Sengupta on the Institute of Applied Manpower Research;

(b) if so, the recommendations made;

(c) whether Government have since contemplated any action to implement the recommendations; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) Yes, Sir. The Report has been prepared by the Institute of Applied Man Power Research in response to a request made by the National Committee on Science and Technology.

(b) The salient features of the recommendations are given in the enclosed statement.

(c) and (d). The reports are under study.

STATEMENT

The report brings out the pattern of employment and characteristics of scientific manpower, and also a norm for assessing future requirement of manpower for R&D on the basis of proposed outlay.

Although the report is mainly in the form of a status report, there are few general recommendations. The Report covers (i) the Institutional Sector covering the CSIR chain and a few large public sector industries such as FCI; (ii) Industrial Sector covering R&D labs. in the public and private sector on a sampling basis; and (iii) University Sector (of some Universities and IITs) but largely based on the IIT system.

The main recommendations are:

1. Industrial Sector:

(1) In a free market situation, every industry has to take enough precaution against obsolesence, so that it may not suffer in competition against more sophisticated technology or by the introduction of a more attractive product.

(2) As regards functional distribution of S&T personnel, it is stated

that, as the purpose of R&D in the industrial sector is to develop marketable technology and technical innovation, R&D programme in the industry should be design and development oriented. An overall functional ratio of 1:1 of the R&D and Auxiliary personnel, is fairly reasonable.

(3). The poor utilisation pattern of post-graduates in Science & Technology in industrial R&D is a matter of great concern, and calls for in-depth study for asecrtaining the reasons for this.

(4) R&D in the industrial Sector should include mainly (a) design and development and (b) marketing.

For every rupee spent on the R&D part, the economy should be prepared to invest five to ten times as much, depending on the nature of the industry, for successfully marketing the product or innovation.

(5) The manufacturing industries should spend matching amount to utilise the R&D results of the various Institutions, on developmental or technical R&D. Industry should be committed to industrial growth through technological development.

II. Industrial Sector

(1) There should be an interdisciplinary approach with regard to technology and better utilisation of professionals.

(2) The pattern of distribution of S&T personnel, by salary, needs to be examined thoroughly in order to make R&D more productive and to draw more young brilliant scholars to it. A cylinderical pattern is prefered to a pyramidal pattern.

(3) Technical services should constitute a more important wing of R&D than administration and clerical functions.

Increase in Price of Cloth

6727. SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA:

DR. BIJOY MONDAL:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there has been considerable increase in the prices of cloth in the country after the presentation of Finance Budget and if so, to what extent;

(b) whether it is also a fact that the prices of cotton have gone down by 13.8 per cent at present as compared to the last year; and

(c) whether any steps have been taken by Government to check the prices of cloth in the country and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) No, Sir. In fact, the wholesale price index for cotton textiles has fallen from 185.7 for the week ending 24-2-1979 to 185.4 for the week ending 24-3-1979.

(b) The wholesale prices of cotton decreased by about 9.4 per cent between February, 1978 and February, 1979.

(c) There is no statutory control on the prices of cloth. The price movement is conditioned by a multiplicity of factors, important of which are production costs and demand and supply. Nevertheless, the Minister of Industry has recently discussed the matter with the industry, who have been asked to devise steps to reduce prices of cotton cloth.

अनियन्त्रित कपड़े का निर्माण और उसके मूल्य में वृद्धि

6728. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च, 1979 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन संचालित मिलों द्वारा गैर-नियन्त्रित कपड़े के मूल्यों मे वृद्धि की गई थी, जबकि ऐसी अवधि के दौरान रुई की कीमतों में कमी हुई थी ।

(ख) वर्ष 1978 के दौरान उपर्युक्त मिलों द्वारा अनियन्त्रित कपड़े का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया और ऐसे कपड़े के मूल्यों में प्रत्येक मिल द्वारा कितनी औसत वृद्धि की गई ; और

(ग) क्या वर्ष 1978 और 1979 की प्रथम तिमाहियों के दौरान इन मिलों को अपनी मूल्य निर्धारण नीति के बारे में सरकार ने कुछ मार्गदर्शीय सिद्धान्त जारी किये थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां, रुई के मूल्य में कमी होने के बावजूद, वर्ष, 1978–79 के दौरान अन्य निविष्टियों की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा उत्पादित अनियन्त्रित किस्म के कपड़े के मिल से निकलते समय के लागत मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) 1978 के कलैंडर वर्ष में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में लगभग 7771·70 लाख मीटर गैर-नियंत्रित कपड़े का उत्पादन किया । उत्पादित कपड़े की मिल से निकलते समय की कीमत में औसत 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ग) जी, नहीं । कपड़े की गैर-नियंत्रित किस्मों के मूल्यों पर कोई भी कानूनी नियंत्रण नही है ।

बसों और ट्रकों का आयात

6729. श्री राम विलास पासवान : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसों, ट्रकों अथवा उनके चेसिस का आयात करने से रोजगार के अवसर प्रदान करने में और वित्तीय लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ;

(ख) क्या वर्तमान कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृदि करके उनके उत्पादन में तत्काल वृद्धि नहीं की जा सकती ; और

(ग) इनके स्वदेशी उत्पादन और इनके आयात के पक्ष और विपक्ष में क्या आर्थिक कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति : (क) पब्लिक परिवहन और माल का परिवहन, जिसमें बसों और ट्रकों का परिचालन अन्तर्ग्रस्त है, एक प्राथमिकता प्राप्त उद्योग है, जिसकी रोजगार क्षमता भी पर्याप्त है ।

(ख) 1979–80 में मांग में प्रत्याशित वृद्धि के अनुरूप वाणिज्यिक गाड़ियों के स्वदेशी निर्माण में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय जारी हैं । इन उपायों के परिणामस्वरूप पहले ही इस वर्ष 1978–79 में देश में निर्मित वाणिज्यिक गाड़ियों की संख्या गत वर्ष 1977–78 की अवधि में 41,244 की तुलना में 58,255 हो गई है । अत: मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए इस वर्ष उत्पादन में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई है ।

(ग) ट्रक/बस चेसिसों का वास्तव मे कोई आयात नही हो रहा है । आयात के विपक्ष में मुख्य कठिनाई यह है कि आयातित गाड़ियां जिनकी तुलना भारत में निर्मित वाणिज्यिक गाड़ियों की विशिष्टियों और काम से की जा सकती है, की कीमतें सीमाशुल्क जोड़े बिना भी काफी अधिक हैं ।

Aid to Handloom Intensive Development Projects in Karnataka

6730. SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Central Government have given assistance for handloom intensive development projects in the State of Karnataka during the current financial year; and

(b) if so, the district-wise details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). Central assistance is given according to prescribed pattern for projects. For the Ilkal intensive handloom development project (covering parts of Bihar, Gulbarga and Bijapur districts), a sum of Rs. 22.50 lacs was released by the Central Government during 1978-79.

Indo-Soviet Cooperation in Fast Neutron Breeders

6731. SHRI EDUARDO FALEIRO: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have taken steps towards Indo-Soviet Cooperation in the field of "fast neutron breeders" for operating the next generation of nuclear power plants; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) and (b). A new agreement between India and USSR has been signed on January 22, 1979 which *inter alia* includes cooperation in the field of fast breeder reactors. Work programmes for carrying out joint activities in accordance with the new agreement are being worked out.

Resumption of Dialogue with Naga Rebels

6732. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government contemplate any possibility in near future to resume dialogue with the rebel Nagas and adopt a policy of conciliation rather than confrontation;

(b) whether there are some moves to arrange for a fresh dialogue between Government and Naga rebels; and

(c) if so, the reaction and attitude of the Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (c). Government have all along been following, and continue to follow a policy of reconciliation. It was in pursuance of this policy that the talks were held with the ex-underground Nagas and an Agreement reached in November, 1975. Representatives of the ex-underground who were signatories to this Agreement have been in contact with underground Nagas staying across our border in Burma with a view to persuading them to accept the Shillong Agreement. Talks between tehm are to centinue. Besides, at present there is no other proposal for any dialogue between the Government and underground Nagas.

Meeting of D.I.G.s of Police in Delhi

6733. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a meeting of Deputy Inspectors General of Police was held in Delhi on 8th March, 1979;

(b) if so, the details and where the meeting was held;

(c) total amount spent for the meeting;

(d) whether it is a fact that Rs. 6600/- was spent on dinner attended by these 120 D.I.Gs.; and

(e) if so, whether this is in keeping with the policy of Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) Yes, Sir

(b) This is an Annual Conference which is held at New Delhi and was attended by DIG's and other senior police officers from all State Governments and Union Territories.

(c) A sum of Rs. 33,124.70 was spent in connection with the Conference.

(d) An expenditure of Rs. 12,358/- was incurred on the dinner which was attended by these delegates and some other officers.

(e) It is a usual practice to host dinner on such occasions to provide an opportunity to the delegates for greater informal discussions.

Criminal Cases Filed for Demonstration against Simla Pact

6734. SHRI RASHEED MASOOD: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether certain criminal cases were filed against some persons when they demonstrated in Delhi against Simla Pact with Pakistan; and

(b) if so, what has happened to those cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) and (b). Delhi Administration have reported that eight cases were registered in connection with the demonstration held in Delhi against Simla Pact. Out of these, 5 cases were decided by the Court. The accused were sentenced till rising of the Court in 4 of these cases and discharged in the 5th case. The other cases were withdrawn by the Delhi Administration.

मध्य प्रदेश के आदिवासियों के जीवन यापन की पद्धति का सर्वेक्षण

6735. श्री बलपत सिंह परस्ते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासियों (प्राचीन जातियों) के जीवन यापन की पद्धति और उनकी संख्या के बारे में पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख). संभवत: सदस्य का आशय उन आदिम जनजातीय समुदायों से है जो पूर्व कृषि स्तर तकनीक के अनुसार रह रहे है । इन वर्गों को पहिचानने के लिए तीन महत्वपूर्ण अभिलक्षण लिए गए हैं, अर्थात् :–

(i) वर्ग पूर्व कृषि स्तर तकनीक का होना चाहिए, स्थानान्तरित खेती विभाजन रेखा के रूप में मानी जा रही है ?

(ii) वर्ग पूर्व-साक्षरता या 5 प्रतिशत साक्षरता से कम का होना चाहिए, तथा

(iii) वर्ग के विकास की दर स्थिरता के निकट या केवल सीमान्त की होनी चाहिए ।

उपरोक्त आधार पर, मध्य प्रदेश सरकार ने अबुजमारियाज, बेगस, भरियास, पहाड़ी कोरवास तथा साहारियास आदिम जनजाति समुदायो का पता लगाया है ।

इन समुदायो के विकास के लिए विशेष कार्यक्रमो को शुरू करने की आवश्यकता है । इस उद्देश्य के लिए राज्य उसरकार प्रत्येक समुदाय के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है । इन रिपोर्टों को, विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद तैयार करने की आवश्यकता है ।

Recommendations of the Working Group on Automotive Industry

6736. SHRI SUBHASH CHANDER BOSE ALLURI:

SHRI K. RAMAMURTHY:

Will the Minister of INDUSTRY be plesaed to state:

(a) whether it is a fact that a high level working group appointed by Government on the automotive industry has submitted its report to Government;

(b) if so, what are the main recommendations of the group; and

(c) whether Government have examined the report, what are the recommendations that Government have accepted and implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) and (b). The Working Group on Transport, Earth Moving Equipment and Agricultural Machinery set up to formulate programmes of development for the Five Year Plan Period 1978—83 has submitted its report recently. The recommendations cover the main sectors of the Automotive Industry comprising commerical vehicles, jeeps,, cars, 2-wheelers, agricultural tractors, earth-moving equipment, diesel engines, automotive ancillaries and railway equipment. The main

recommendations relate to augmenting and upgrading, where necessary, productive capacities and capabilities in the country for meeting the demand, particularly with reference to national priorities, concerning increased employment opportunities, public transporation, movement of goods and capital inputs for projects concerning power, mining, rural development, etc. Besides outlining the industry status and future trends of each of these sectors of automotive industry, the report of the Working Group also indicates long-term production projections, investments required to achieve the projected production employment potential., rationalisation and technological upgradation.

(c) The main thrust of the report has been accepted by the Government. The modalities, direction and progress of implementation will depend on several factors including the response of the Industry, the actual growth of damand and resources available.

Inquiry into Alleged Atrocities on Harijans in Muzaffar Nagar

6737. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission have enquired into the alleged atrocities on the Harijans in Muzaffar Nagar recently;

(b) whether the commission has since submitted its report; and

(c) if so, the essential findings of the Commission and their specific recommendations on this particular issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a). Yes, Sir.

(b). No, Sir.

(c). Does not arise.

'लो कास्ट स्माल कार' शीर्षक से समाचार

6738. श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री दयाराम शाक्य :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 मार्च, 1979 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में कम कीमत पर छोटी कार के बारे में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त छोटी कार का निर्माण करने के लिय किस कम्पनी को आशय पत्र जारी किया गया है और देश में इस कार का निर्माण किस स्थान पर होगा और इसकी लागत निर्माण आदि का पूर्ण ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख). 6 मार्च, 1979 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित रिपोर्ट में मोटरगाड़ी उद्योग के उन्नयन के प्रस्तावों का उल्लेख है, जिसमें अन्य बातो के साथ-साथ देश में विद्यमान यात्री कारों की तुलना में ईंधन क्षमता आदि की दृष्टि से एक और अच्छी कार के निर्माण की व्यवस्था है। इन प्रस्तावो का अध्ययन किया जा रहा है और रिपोर्ट में यह कहा गया है कि प्रस्तावित कार के निर्माण के संबंध में समय और मूल्य के बारे में बताना सम्भव नही है। इस परियोजना के लिए किसी कम्पनी को आशय पत्र नही दिया गया है।

राजस्थान में एच० एम० टी० की घड़ी कारखाना स्थापित करना

6739. श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में एच०एम०टी० की घड़ी बनाने का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की स्थापना कब तक की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख). राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा अजमेर में एच० एम०टी० सहायता प्राप्त राजस्थान की वाच असेम्बली यूनिट की स्थापना की जा रही है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है। चालू वर्ष में एकक के कार्य शुरू कर देने की आशा है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता देना

6740. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता न देने के क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा आईत) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियो को डाक्टरी उपचार तथा चिकित्सा की उदार व पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है। कम्पनी के भोपाल स्थित एकक में कर्मचारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत भी डाक्टरी इलाज पाने के हकदार है। सरकारी नीति के अनुरूप अन्य प्रभागो में भी देशी चिकित्सा पद्धतियो के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाए शुरु करने के सवाल पर बी.एच.ई.एल. विचार कर रहा है ।

राजस्थान में सीमेंट उद्योग स्थापित करने के लिये आवेदन पत्र

6741. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सीमेंट उद्योग स्थापित करने के लिये सरकार को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रो की सख्या अलग-अलग कितनी है, और

(ग) आवेदनो को अस्वीकार करने के मुख्य कारण क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) और (ख). राजस्थान में सीमेंट सयत्र स्थापित करने के लिए 1 अप्रैल, 1977 से औद्योगिक लाइसेसो/आशय पत्रो के लिए 22 आवेदन तथा तकनेकी विकास के हानिदेशालय में पंजीकरण हेतु 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15 प्रस्ताव स्वीकार कर दिये गये हैं। 8 प्रस्ताव रद्द कर दिये गये हैं तथा 11 प्रस्तावो की जाँच की जा रही

(ग) राजस्थान में सीमेंट संयत्रो की स्थापना संबधी आवेदन रद्द होने के मुख्य कारण रेल परिवहन की अपर्याप्त सुविधा का होना तथा जिन क्षेत्रो के के लिए आवेदन किया गया है, उनमें सीमेंट ग्रेड के चूने पत्थर का न होना है ।

Coir Production in Coimbatore

6742. SHRI R. KOLANTHAIVELU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the quantity of coir fibre produced in Coimbatore and Salem districts of Tamil Nadu;

(b) whether Government have studied the feasibility of starting a rubberised coir unit in Tamil Nadu making use of the immense quantity of coir fibre available there; and

(c) if so, the results of the study and the further steps proposed to be taken for developing the industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a). The estimated production of fibre during 1977-78 is 880 tonnes in Coimbatore and 350 tonnes in Salem districts of Tamil Nadu.

(b) and (c). The Government of Tamil Nadu have prepared a scheme for setting up of a rubberized coir unit in Thanjavoor district for the consideration of the Coir Board. The Coir Board after due consideration will send a viability report to the Government of Tamil Nadu taking into account the existing installed capacity of the rubberized coir manufacturing units. The actual implementation of developmental programmes in respect of coir industry the responsibility of the State Governments under their respective Plan Schemes.

Launching of Geosynchronous Satellite

6743. SHRI R. KOLANTHAIVELU: Will the Minister of SPACE be pleased to state:

(a) whether Government propose to launch geosynchronous satellite in 1981;

(b) if so, the particulars thereof; and

(c) whether such a satellite is considered to be of great importance for Tamil Nadu which has to depend mostly on monsoon rains?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The geosynchronous satellite, called the INSAT-I, is a multi-purpose domestic satellite system for telecommunications, TV and Meteorology. Its telecommunications and TV coverages are designed for national coverage. However, its Very High Resolution Radiometer (VHRR) for meterological earth imaging is designed to cover about 25 per cent of the world area directly below the satellite.

(c) The satellite will be of prime importance to the whole country, as the meteorology components of INSAT-I system will significantly improve the country's weather forecasting capability which will benefit, in particular, agricultural operations, aviation, port and shipping operations, hydro-electric power generation planning, and cyclone and flood disaster warning.

Issue of Licences for increasing production of items reserved for Small Scale Industries

6744. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have issued fresh licences or allowed to increase the production capacity with regard to the production of items reserved for small scale sector on the consideration of 100 per cent exports on a continued basis, during the course of the year;

(b) if so, the names of the companies who were allowed to increase the production capacity or given fresh licences in this regard; and

(c) the items for which the fresh licences were issued or allowed to increase the production capacity?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a). Yes, Sir.

(b) and (c). Under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the following 2 Industrial Licences and 5 Letters of Intent were issued during 1978 for the manufacture of items reserved for the Small Scale Sector subject to the conditions that they would export 100 per cent of their annual production on a continuing basis.

Name of the Company and Location of the Undertaking	Item of Manufacture
A. *Industrial Licences*	
1. M/s. Anspa-Knit (Pvt.) Ltd., (Kandla Free Trade Zone, Gandhidham, Kutch, Gujarat)	Pulovers, Cardigans, Ladies Blouses. (New Undertaking)
2. M/s. Pentagon Screws & Fasteners Ltd., (Sahibabad, Ghaziabad, U.P.)	Wood Screws, M.S. Screws etc. (New Undertaking)
B. *Letters of Intent*	
1. Shri Darshanjit Singh (Ghaziabad—U.P.)	M.S Screws, Wood Screws, etc. (New Undertaking)
2. M/s. Britania Biscuit Co. Ltd. (Nadia—West Bengal)	Leather Footwear (New Article)
3. Shri M. Syed Mohomed (Pudukottai—T.N.)	Shoe Uppers (New Undertaking)
4. M/s. Farida Shoes Pvt. Ltd. (North Arrot—T.N.)	Leather Shoe Uppers, Leather Footwears (New Undertaking)
5. M/s. Gedore Tools India Pvt. Ltd., (Maharashtra)	Cast Tools—Vices of different sizes (New Articles)

Reduction in Capacity of Multinationals Manufacturing Items Reserved for Small Scale Industries

6745. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have reduced the capacity of production while fixing capacities in the C.O.B. licences with regard to the Multinational Companies which are manufacturing consumer goods which have been reserved for small scale sector during the course of the year;

(b) if so, the names of the companies and items thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c). Following criteria are taken into account while fixing capacities in COB licences.

(i) Where production has been established and reported for a period of more than one year prior to the specified date, the capacity may be fixed at the level corresponding to the highest annual production, subject to a minimum economic capacity to be determined in respect of the concerned industries/products, whichever is higher. There may, however, be cases where it may not be practicable to fix a minimum economic capacity. In such cases, the capacity will be fixed provisionally on the basis of peak production in any of the previous years.

(ii) Where production had commenced within less than one year before the specified date or the undertaking has not yet gone into production, the capacity may be provisionally determined on the basis of the minimum economic capacity. But in cases where it is not practicable to fix the minimum economic capacity, the capacity may be provisionally determined on the basis of the capacity claimed or the computation based on plant and equipment installed.

(iii) Where a minimum economic capacity or a provisional capacity is fixed, this capacity will have to be fixed finally on the basis of the highest annual production, after the unit has been in production for a period of three years.

The above criteria are uniformly applied in all cases including multinationals.

Policy to Attract Investment and Foreign Entrepreneurial Talent

6747. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government of India announced a policy to attract investment and foreign entrepreneurial talent from non-resident industrialists willing to set up industries in the country;

(b) if so, how many applications and for what type of industries have been received so far and out of which how many have been cleared;

(c) how many applications are pending for import of texturising and crimping machines; and

(d) what decision Government had taken in the above applications?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Permits for Soda and Oil Used in Soap Manufacture

6748. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the details regarding the big chunk of quotas and permits

for soda and oil used in soap manufacture and imported from foreign countries granted to the large houses;

(b) whether Government are aware that small scale soap industry is facing hardship as a result thereof;

(c) whether Government have received complaints in this regard and if so, the details thereof; and

(d) the steps Government propose to take to help the small scale soap industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) None of the large industrial houses was recommended for grant of quota and licence for soda and oil for preparation of soap. In 1978, release orders were issued for about 10,000 tonnes of mutton tallow to DGTD registered users for the manufacture of fatty acids used in soap manufacture. At present, import of soda is under open general licence and import of oil is canalised through STC. Details of licences granted are published in Weekly Bulletins issued by the Chief Controller of Imports and Exports, copies of which are available in the Parliament Library.

(b) During the calendar year 1978, against an allocation of 20,158 tonnes of imported tallow/fatty acids, only 12,416 tonnes had been lifted. It would, therefore appear that small scale units are able to get their requirements of oil for soap manufacture Soda ash is used in the manufacture of soap to a small extent. Due to scarcity of indigenous soda ash, however, some units did experience difficulties.

(c) Some complaints have been received in regard to supplies of soda ash and they are from units who are not eligible for supplies of indigenous soda ash according to the guidelines of the Department of Chemicals and Fertilizers. These guidelines state that indigenous soda is to be supplied on the basis of off-take of 1977.

(d) It has been decided to supply 18,000 tonnes of tallow/fatty acids to small scale soap industries during the year 1979 through State Governments. Keeping the 1978 performance in view it is considered that this quantity would be adequate to meet anticipated demand.

Government have recently issued guidelines to all manufacturers to supply soda ash to individual units based on off-take, Further, imports of soda ash are allowed under open General Licence and import duty has also been reduced.

Percentage of Population engaged in Industry

6749. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have made any survey regarding the percentage of population engaged in industry in the country at present;

(b) if so, what is the percentage;

(c) what is the percentage of people engaged in industry in each state;

(d) whether Government have formulated any scheme to shift people from agriculture to non-agricultural occuptions;

(e) if so, what are the details thereof; and

(f) whether the State Government and voluntary organisations are consulted in this regard; if so, what are the details and what is the response of the State Governments and voluntary agencies in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). While comprehensive data

on employment in factories covered by the Factories Act, 1948 are available from year to year on the basis of Annual Survey of Industries no such data are, however, available in respect of non-factory manufacturing sector as a whole. The National Sample Survey Organisation in its 20th Round covering the period July 1974—June 1975 undertook a household enquiry of self employment in non-agricultural enterprises which *inter alia* included the non-factory manufacturing sector also. The sample number of non-household non-factory reporting units was, however, so small that no analysis of these data have been carried out. Recently in 1977 the Central Statistical Organisation had conducted an Economic Census of all establishments employing at least one hired worker on a fairly regular basis in the non-agricultural sector of the economy, including, *inter alia*, the manufacturing sector. The data collected in the course of the Census is under tabulation. In addition to the above, presently the National Sample Survey Organisation and the CSO are also conducting surveys on non-factory manufacturing sector. The surveys are in progress.

(c) Information on persons returned as workers for their main activity and classified into nine broad industrial categories as per 1971 Population Census is given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-4284/79].

(d) to (f). In pursuance of the policy of Government to promote the development of rural areas licences for new undertakings or for substantial expansions would not be given for industries in standard urban areas of metropolitan cities and industries within the municipal limits of cities with a population of 5 lakhs or more. The only exception would be in the case of sick units which cannot be revived except through expansion and diversification and in the case of uneconomic units which needed expansion or diversification to avoid sickness.

The District Industries Centre programme is a totally new effort in promoting rural industrialisation and taking industry to rural areas. Periodic review meetings are being held with the State Governments to clarify doubts remove impediments and generally to speed up the implementation of the programme.

Ex-Factory Price of Car

6750. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the ex-factory price of car of each make separately manufactured in the country;

(b) what is the amount of excise duty and other taxes on car of each make separately;

(c) what is the progress so far made in the manufacture of small car; and

(d) by when the small car will come in the market?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI). (a) and (b). A statement is attached indicating the prices as reported by manufacturers.

(c) and (d). In comparison to the wide-range configuration of passenger cars manufactured in developed countries, the passenger cars manufactured in India are considered small cars. The objectives are to upgrade the Automobile Industry particularly in the interest of improving fuel efficiency and reliability for the end users. Government are presently considering various proposals, including the participation of the Public Sector for upgradation of the passenger car industry.

Statement

Sl. No.	Name of the manufacturer	Make of Car	Ex-factory/ Net Dealer price of Car (Rs.)	Excise duty (Rs.)
1.	M/s. Hindustan Motors Ltd., Uttarpara (W.B.)	(a) Ambassador Mark-4 (Petrol)	30,362·00	7,590·00
		(b) Ambassador Mark-4 (Diesel)	41,362·00	10,341·00
2.	M/s. Premier Automobiles Ltd., Bombay.	Premier	26,991·00	6,747·75
3.	M/s. Standard Motor Products of India Ltd., Madras.	Standard Gazel	19,727·00 (As in Feb., 1979)	3,744·28
4.	M/s. Sunrise Auto Industries Ltd., Bangalore.	BADAL	15,500·00	3,100·00

NOTE: The actual price to be paid by the customer will include dealer's margin. It will also include Sales Tax, Octroi Duty, Transportation Charges, etc., which differ from State to State.

Nnmber of cars in the Ministry and Attached and Subordinate Offices

6751. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the number of cars of each make in the Ministry of industry, attached and subordinate offices and public undertakings under the Ministry, separately;

(b) whether there is any proposal to reduce the number of cars in the Ministry and other offices;

(c) if so, the details thereof; and

(d) what is the expenditure on maintenance of these cars during the last 3 years year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Nuclear Power Plant in Coastal Region of West Bengal

6752. PROF. SAMAR GUHA: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether the question of setting up a Nuclear Plant in the coastal region of West Bengal was under consideration of the earlier Government;

(b) whether the matter was discussed earlier with the representatives of the West Bengal Government and the Atomic Energy Commission several times; and

(c) if so, the latest position in regard to finalisation of the plan for setting up a Nuclear Power Plant in the coastal region of West Bengal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) No Sir.

(b) and (c). Yes Sir. The question of setting up a nuclear power plant in Eastern Region was raised during discussions held in November 1974 with the West Bengal State Planning Board. The Board was advised that a detailed study may be conducted to determine the most desirable and optimal mix of thermal hydel and nuclear power to cater to the demands of the Region in the context of the overall regional and national energy policy and to approach the Ministry of Energy in case the study revealed that a nuclear power station was economically viable in the Eastern Region.

Supply of Uranium by USA for T.A.P.S.

6753. PROF. SAMAR GUHA: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether the issue of supply of uranium by USA for Tarapur Atomic Power Plant has been finalised;

(b) whether Government have received any communication from the Government of USA in this regard; and

(c) if so, facts thereabout?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) One of the pending export licence applications for 16.8 tonnes of enriched uranium for the Tarapur Atomic Power Station has been cleared by the U.S. Nuclear Regulatory Commission on March 23, 1979

(b) and (c). The U.S. Authorities have informed Government of the recommendation of the Executive Branch of the U.S. Government to the U.S. Nuclear Regulatory Commission regarding the pending export licence application for 19.8 tonnes of enriched uranium for the Tarapur Atomic Power Station. This application is presently under the consideration of the U.S. Nuclear Regulatory Commission.

Production of Cement in Bokajan Factory, Assam

6754. SHRI BEDABRATA BARUA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the total quota of cement allotted to Assam in one year;

(b) what is the total cement produced in the Bokajan Cement Factory in Assam;

(c) what is the full capacity of the Bokajan Factory; and

(d) what are the reasons for the Bokajan factory not producing upto full capacity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The state of Assam was allotted 2.35 lakh tonne of cement during the year 1978.

(b) The production of the Bokajan Cement Factory was 1.23 lakh tonnes during 1978-79.

(c) The annual installed capacity of Bokajan Cement Factory is 2 lakh tonnes.

(d) The capacity utilisation at Bokajan was about 61.5 per cent during the year 1978-79 mainly due to constraints on limestone raising and transport.

Central Assistance for Rural Roads in N.E. Region

6755. SHRI AHMED HUSSAIN: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the quantum of Central assistance/loans/grants given by the Cen-

tre and allotted to each State each year during the last five years ending 31st March, 1979 and earmarked for 1979-80 for the purpose of providing Rural Roads/Rural Link Roads in the N.E. Region;

(b) whether any specific proposal request has been received from the Government of Assam under the minimum needs programme to assist in providing and repairing rural roads/link roads in Assam; and

(c) if so, the details therefor alongwith the action taken or proposed to be taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) Central assistance for State Plan outlays is given in the shape of block loans and grants and is not linked to specific projects. The allocations earmarked for rural roads under the Minimum Needs Programme in the N.E. Region for 1974—1979 and proposed for 1979-80 are given in the Statement enclosed.

(b) No proposal has been received from the Government of Assam for extra assistance under the minimum needs programme.

(c) Does not arise.

Statement

Allocations for Rural Roads under M.N.P. in the N.E.C. Region

(Rs.lakhs)

State	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80 (Provisional)
Assam	110	190	252	350	535	460
Manipur	50	80	88	100	130	200
Meghalaya . . .	30	56	35	50	55	60
Nagaland	45	60	70	71	95	130
Tripura	40	40	50	75	130	180
Arunachal Pradesh . .	..	..	..	..	..	25
Mizoram	10	30	35	42	46	125

Change of Name of "Bombay" to "Mumbai"

6756. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Maharashtra Government have submitted a proposal to change the name of Bombay as Mumbai; and

(b) if so, when such proposal was received and decision taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) Yes, Sir.

(b) The proposal was received from the Government of Maharashtra in December, 1977. It is still under consideration.

सरकारी उपक्रमों में प्रचार के लिये खर्च की गई धनराशि

6757. श्री सखोन्द्र लाल सिंघा :

श्री एम० ए० हनान अनसारी :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी उपक्रमो के नाम क्या हैं,

(ख) एकको के एककवार प्रचार ढाचे का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में वर्षवार, एककवार कितनी धनराशि प्रचार पर खर्च की गई,

(ग) गत तीन वर्षों में इन एकको द्वारा एकक वार, वर्षवार विज्ञापन किन किन दैनिको को दिये गये

(घ) इन एकको का छोटे और मध्यम दर्जे के भाषायी दैनिको के प्रति रुख का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इन एकको द्वारा एककवार आज तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में और परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिक्स, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) (क) (1) नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया (एन० आर०डी० सी०) नई दिल्ली, और

(2) सैन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (सी०ई० एल०), साहिबाबाद (उ० प्र०)

(ख), (ग), (घ) और (ङ) अपेक्षित जानकारी सलग्न वक्तव्य मे दी गई है ।

विवरण

1. नेशनल रिसर्च डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया (एन० आर० डी० सी) :

भाग (ख)—एन०आर०डी०सी० के प्रचार एकक में एक औद्योगिक सम्पर्क और सूचना अधिकारी, एक सूचना और प्रचार अधिकारी, एक उच्च श्रेणी लिपिक और एक कनिष्ठ आशुलिपिक शामिल है। विगत तीन वर्षों के दौरान एन०आर०डी० सी० के प्रचार पर किया गया व्यय नीचे दिया गया है —

1975-76	1,30,138/-रु०
1976-77	1,65,210/-रु०
1977-78 . . .	1,75,582/-रु०

भाग (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान एन०आर० डी०सी० द्वारा निर्मुक्त विज्ञापनो के लिए प्रयुक्त दैनिक समाचार पत्रो की सूची अनुबन्ध–1 में दी गई है ।

भाग (घ) और (ङ) जहां कहीं भी सभव होता है, विज्ञापन छोटे और मध्यम दर्जे के भारतीय भाषाओं के दैनिकों को दिए जाते हैं और यथासभव ऐसे समाचार पत्रो की सेवाओं का उपयोग किया जाता है ।

2. सैन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड सी० ई० एल० :

भाग (ख) सी०ई०एल० नई कम्पनी है जो कि अभी निर्माण अवस्था में है और सी०ई०एल० के लिये पृथक रूप से इस प्रकार की कोई प्रचार सरचना नही है। विपणन ग्रुप भावी उत्पादो के बारे मे जानकारी प्रदान करने और उन्हे लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञापन देता है । विगत तीन वर्षों के दौरान किया गया वर्ष वार व्यय नीचे दिया गया है —

	रु
1975-76 . . .	30,386
1976-77	39,710
1977-78 . . .	33,462

भाग (ग)—विगत तीन वर्षों के दौरान दिए गए विज्ञापन अधिकाशत उन तकनीकी पत्रिकाओं और प्रकाशनो तक ही सीमित थे जिनका इलेक्ट्रानिकी ट्रेड मे परिचालन किया जाता है यथा

1 इलैक्ट्रानिक्स फार यू

2 इलेक्ट्रानिक्स रिव्यू

3 जर्नल आफ इन्स्टीट्यूशन आफ इलेक्ट्रानिक्स एड टेलिकम्युनिकेशन इंजीनियर्स

4 इलेक्ट्रानिक्स टुडे

5 साइंस टुडे, और

6. साइंस रिपोर्टर

भाग (घ) और (ङ)—कम्पनी मुख्यत परिष्कृत इलेक्ट्रानिक सघटको और प्रणालियो का निर्माण करती है और इसके बारे मे विज्ञापन इलेक्ट्रानिकी से सम्बद्ध तकनीकी पत्रिकाओं और प्रकाशनों में दिए जाने होते हैं ताकि प्रचार इस प्रकार के इलेक्ट्रानिक संघटको और प्रणालियो में रूचि रखने वाले उपभोक्ताओं, नामत इलैक्ट्रानिकी उद्योगो, अनुसधान और विकास सगठनों, आदि तक पहुच सके। फिलहाल इस प्रकार के उत्पादो के लिए लघु और मध्यम दर्जे के विभिन्न भारतीय भाषाओ के दैनिको को विज्ञापन देने की बहुत अधिक गुजाइश नही है ।

मेसर्स रिसर्च लिमिटेड, एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा नियुक्त विज्ञापनों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले दैनिक समाचार पत्रों की सूची

1.	इंडियन एक्सप्रेस	नई दिल्ली
2.	इंडियन एक्सप्रेस	बम्बई/अहमदाबाद
3.	इंडियन एक्सप्रेस	दक्षिणी संस्करण, मद्रास
4.	अमृत बाजार पत्रिका	कलकत्ता/इलाहाबाद
5.	ट्रिब्यून	चंडीगढ़
6.	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	दिल्ली/बम्बई
7.	हिन्दू	मद्रास
8.	इकानोमिक टाइम्स	बम्बई/दिल्ली
9.	दक्कन क्रोनिकल	सिकन्दराबाद
10.	इंडियनहेराल्ड	हैदराबाद
11.	नवभारत टाइम्स (हिन्दी)	दिल्ली/बम्बई
12.	दि मेल	मद्रास
13.	हिन्दुस्तान (हिन्दी)	नई दिल्ली
14.	नवज्योति (हिन्दी)	जयपुर/अजमेर
15	टाइम्स आफ इंडिया	दिल्ली/बम्बई/अहमदाबाद
16.	बिजनेस स्टैंडर्ड	कलकत्ता
17.	स्टेट्समैन	दिल्ली/कलकत्ता
18.	इंजीनियरिंग टाइम्स	कलकत्ता
19.	आसाम ट्रिब्यून	गौहाटी
20	फ्री प्रेस जनरल	बम्बई
21.	नागपुर टाइम्स	नागपुर
22.	इंडियन नेशन	पटना
23.	दैनिक आज (हिन्दी)	वाराणसी/कानपुर
24.	राजस्थान पत्रिका	जयपुर
25.	आनन्द बाजार पत्रिका	कलकत्ता
26.	इम्पलायमेंट न्यूज	नई दिल्ली
27.	पैट्रियट	नई दिल्ली
28.	दीनमनी (तमिल)	मद्रास/मदुरै
29.	आन्ध्र प्रभा (तेलुगु)	विजयवाड़ा/बंगलौर/हैदराबाद
30.	मातृभूमि (मलयालम)	कालीकट/कोचीन
31.	रोजाना अजीत (पंजाबी)	जलंधर
32.	दैनिक जागरण (हिन्दी)	कानपुर/गोरखपुर
33.	सण्डे स्टैंडर्ड	नई दिल्ली

Manufacture of Paper by Sehgal Paper Ltd.

6758. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Sehgal Papers Ltd., a new company engaged in the manufacture of various kinds of paper, has entered the capital market on February 5, 1979;

(b) if so, what are the facts thereof;

(c) whether this company has been allowed to enter into technical and financial collaboration agreements with two U.S. multi-nationals;

(d) if so, what are the terms of agreements; and

(e) the reasons why foreign collaboration is being allowed in the paper industry?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b). Yes, Sir. M/s. Sehgal Papers Ltd. were granted consent on 13-7-77 under the Capital Issues Control Act 1947 for the issue of capital of Rs. 565 lakhs in the form of equity shares of Rs. 10 each. Out of this, shares worth Rs. 339 lakhs were to be offered to the public by prospectus and the balance of Rs. 226 lakhs were to be issued to the promoters, Directors of the company, their friends and relatives. The company entered the capital market on 5-2-1979 with a public offer of shares worth Rs. 339 lakhs and the issue was closed on 12th February, 1979.

(c) to (e). M/s. Sehgal Papers have been permitted to enter into a technical collaboration with an American firm for the manufacture of Carbonless Copying Paper. The approval of collaboration is for a period of five years and involved the payment of a technical fee of US $400,000 and royalty at the rate of 3 per cent of net ex-factory sale price on internal sale and 5 per cent of net ex-factory sale price on exports. Foreign technical collaboratio nis permissible on merits for the manufacture of special grades of paper.

Subsidy Grant to Jhalawar District of Rajasthan

6759. SHRI CHATURBHUJ: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to formulate a definite short term plan for bringing about faster economic development of the most backward district of Jhalawar in Rajasthan without involving heavy capital outlay;

(b) whether the Central Government propose to grant all facilities including loans and subsidies for such a plan and would advise the State Government to do the same! and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) There is no proposal with the Ministry of Industry to formulate any separate plan for the faster economic development of Jhalawar district in Rajasthan. However, as part of a national scheme to set up District Industries Centres to provide all service and support required by the small and village entrepreneurs under one roof, one such DIC has been set up at Jhalawar. The Centre has so far identified 334 entrepreneurs and have assisted 148 artisans/small scale units.

(b) and (c). Jhalawar District has already been identified as an industrially backward district making it eligible for the following incentives for eligible entrepreneurs, who desire to set up industries there:

(i) concessional finance facilities by All India Term Lending institutions

(ii) tax concessions

(iii) hire purchase of machinery of small scale units

(iv) consultancy for technical service

(v) interest subsidy

(vi) special facilities for import of raw-materials.

This scheme is operated in association with State Government.

Production of Controlled cloth for the Poor

6760. SHRI K. S. VEERABHADRAPPA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the details regarding the quantity and value of controlled cloth for the poor produced in the Mills controlled by the National Textile Corporation during the last two years; and

(b) the reasons for the shortfall in the production of cloth during the current year and what measures Government have taken to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Production and value of controlled cloth produced in mills under the management of National Textile Corporation is as under:—

Year	Quantity (Million Sq. Metres)	Value (Rs. in Crores)
(1)	(2)	(3)*
1977-78 . . .	64·02	11·84*
1978-79 . . .	204·00	37·74*

*These are calculated at the ex-mill price at consumer level.

(b) There has been no short fall in production in the current year.

News Item "Tarapur Killing Softly"

6761. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the exclusive investigative story on the total criminality involved in all aspects of Tarapur Atomic Plant appearing in "This Fortnight" news magazine dated March, 8—March 21, 1979 under the Caption "Tarapur Killing softly";

(b) if so, the reaction of Government to the various observations of serious nature, observation-wise made therein; and

(c) the details regarding facts of the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The main allegations made in the article of dangerous over exposure to personnel at Tarapur is incorrect. While this reactor built on a turn-key basis and commissioned in 1969, has given rise to problems like other reactors of this design and vintage, these problems have been successfully tackled and the reactor has been operated in complete consonance with international safety regulations. There is an integrated system of comprehensive radiation protection for the workers at Tarapur which is in line with the accepted international standards and it is as a part of this integrated system that workers from outside Tarapur have been drafted for occasional jobs in Tarapur. However, all appropriate records of radiation exposure in respect of these workers including casual workers have been maintained and there has not been even a single case of radiation sickness.

Functioning of Artificial Limbs Manufacturing Corporation

6762. SHRI P. RAJAGOPALA NAIDU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether artificial limbs manufacturing Corporation of India, Kanpur is functioning; and

(b) the work done by it till now?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur was for the setting up of a modern The main objective of the company was for the setting up of a modern plant for the manufacture of a wide range of Orthotics, Prosthetics and Rehabilitation Aids.

With the commissioning of ALIMCO, a wide range of Artificial Limbs etc., have been introduced into the Indian Market for the first time.

The production and sales of the Corporation has so far been as follows:-

	Production	Sales
	(Figures in Rupees lakhs)	
(i) 1976-77 (six months operation) .	13·58	4·98
(ii) 1977-78 . .	40·98	15·36
(iii) 1978-79 (upto Jan. 1979) . .	37·93	16·97

Considering that the nature of the products is such that these cannot be brought and fitted by the patient himself ALIMCO has undertaken to establish a chain of limb fitting centres all over the country in collaboration with the respective State Governments. At present five Regional Limb Fitting Centres and 12 Peripheral Limb Fitting Centres are functioning in our country.

Demand for Democratic set up in Andaman and Nicobar Islands

6763. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government of India are aware of continuous demand by the people of Andaman and Nicobar Islands for providing them democratic set up in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands on the pattern of Arunachal Pradesh and whether any agitation was launched in the territory

(b) if so, details thereof;

(c) whether Government have agreed to have a democratic set up there in the near future; if so, when; and

(d) what shall be the pattern of Government in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands in the new system?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (d). A demand for providing democratic set up in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands has been raised both in the Parliament and outside. Meetings and processions in support of these demands were organised during the month of February, 1979. The Government have decided to constitute a Pradesh Council in these Islands and to appoint 3 Counsellors from among the members of the Council, whom the Administrator may consult on any matter The pattern is similar to the one that obtained in Arunachal Pradesh before a Legislative Assembly was constituted in that Union Territory. The details of the proposal were announced in the Lok Sabha by the Minister of Home Affairs on 6.4.1979 during his reply to the debate on the demands for grants of the Ministry of Home Affairs. A Regulation to give effect to this decision will be promulgated under article 240 of the Constitution.

Industrially backward Taluks in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka

6764. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposals from Tamil

Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka to declare specific taluks as industrially backward, instead of considering entire districts as industrially backward so that the objective of spreading industries could be better achieved; and

(b) if so, whether those proposals have been agreed to and grants/subsidies have been given for new industries to be set up in these taluks?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The proposals were examined in consultation with the Planning Commission. The schemes of backward area development and the selection of districts/areas, both for concessional finance and capital investment subsidy were formulated and finalised in accordance with the norm laid down by the NDC Committee and in consultation with the State Governments concerned. As the proposals received from the State Governments of Andhra Pradeh, Tamil Nadu and Karnataka were in respect of districts/areas which had not been selected earlier under accepted identified norms, it has not been possible to accede to their request.

Government have recently constituted a National Committee on Backward Areas under the Chairmanship of Shri B. Shivaraman former Member, Planning Commission to examine the validity of the various concepts of backwardness underlying the definitions in use for present policy purposes and recommend the criteria by which backward areas should be identified.

The Committee is expected to submit its Final Report by 31st December 1979.

A view on the modification of the present subsidy scheme would be taken after the recommendations of this Committee become available.

Issue of Licences for Cement Industries

6765. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) how many letters of intent and Industrial licences were issued for expansion of or starting new cement projects from 1974-75 upto March, 1977 and for what capacity; and

(b) how many letters of intent and Industrial licences were issued since April, 1977 and for what capacity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Seven Letters of Intent and eleven Industrial Licences for a total capacity of 84.60 lakh tonnes were issued from 1st April, 1974 upto 31st March, 1977.

(b) Thirty-five letters of intent and seven industrial licences for a total capacity of 150.50 lakh tonnes were issued from 1st April, 1977 upto the 7th April, 1979.

Capital Cost and Number of Employees of mini Cement Plants

6766. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the capital cost per tonne of a mini cement plant as compared with that of a bigger plant; and

(b) what is the number of persons employed for the same unit of investment between mini cement plants and bigger cement plants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) According to the Cement Research Institute, the fixed capital cost of a mini cement plant

based on vertical shaft kiln technology with a capacity of 100 tonnes per day would be about Rs. 420 per tonne of installed annual capacity as against the standard cost of Rs. 650 per tonne for a larger sized cement plant with a capacity of 1,200 tonnes per day.

(b) The estimated employment potential in different sizes of cement plants is given below:-

Size of Plants (tonnes per day)	Manpower per tonne of cement
Up to 100 . . .	4—4·55
101—300 . . .	1—4·5
301—1,000 . . .	0·29—2·32
above 1,000 . . .	0·18—2·26

Schemes for utilisation of Indian Scientists Trained Abroad

6767. PROF. P. G. MAVLANKAR:

SHRI CHITTA BASU:

Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Government have one or more schemes for utilising the talents of young Indian Scientists who have had an experience of training and laboratory work abroad for some years;

(b) if so, broad details thereof;

(c) how are the said young scientists attracted, employed and absorbed in various departments/laboratories in the country; and

(d) whether Government's steps in this regard so far have been found adequate and helpful, and if not, why not?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Measures undertaken for utilising the talents of young Indian Scientists trained abroad and to attract and employ them in the country are as under:

(i) A special section titled "Indians Abroad" section of the National Register is maintained for enrolment of Indian Scientists and Technologists abroad; and for the circulation of their particulars, in the form of classified directors, to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Union and State Public Service Commissions, Public Sector Industries and large private sector establishments. Particulars of such personnel are also published in the monthly "Technical Manpower" Bulletin (CSIR), which is distributed free to about 2,500 organisations all over India.

(ii) The Union Public Service Commission and some of the State Public Service Commissions have agreed to treat scientific and technical personnel, whose particulars are in the Indians Abroad section of the National Register, as 'Personal Contact' candidates for posts advertised by them.

(iii) The Scientists' Pool operated by CSIR, provides temporary placement for well-qualified Indian Scientific and Technical personnel who return from abroad without an assured job.

(iv) Supernumerary posts can be created in approved scientific institutions, to which temporary appointments can be made quickly from

among the scientists working and studying abroad.

(v) A 'Package Scheme' has been approved to attract Indin Scientists working in production units abroad to come back and start their own industries in this country, particularly in spheres where they may have acquired skills in production technology.

(vi) CSIR have introduced a scheme for appointment of Research Associates' or 'Visiting Scientists' under which Indian Scientists. etc. visiting India for a short period, can be offered such appointments in CSIR Organisations, in cases where their background fits the requirements of the organisation.

(vii) The University Grants Commission has introduced a scheme under which Indian scholars abroad can be offered shortterm appointment in Indian Universities during their sabbatical leave.

(viii) A scheme for utilisation of talented Indian Scientists and technologists settled abroad, for the development programme of the country was introduce by the Department of Science and Technology.

(d) The steps taken by the Government (as listed above) are considered adequate and have been helpful in placement of many trained persons. There has been a limitation in terms of adequate (appropriate and satisfying employment opportunities to absorb the large number of Indian Scientists who are produced by our educational system as well as those returning from abroad; the best amongst the later have to be persuaded to return to work in India by their friends in the scientific community already working in India with some degree of success and satisfaction.

Steps taken to Improve Police-Community Relations

6768. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government take any concrete and continuous steps at improving the Police-community relations in the country;

(b) if so, what are these and how are these productive;

(c) whether any studies cum research take place in this regard; and

(d) if so, broad outline thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). From time to time State Governments have been issuing instructions to its district and lower police officials in this regard. The subejct have been given more and more importance in the training programmes for the police officials in most of the states. This subject also forms a part under item 11 of the Terms of Reference given to National Police Commission who will deal with this item in great depth and detail while forwarding their report. The said Term of Reference under NPC reads as follows:

> "Examine the manner and extent to which police can enlist ready and willing co-operation of the public in the discharge of their social defence and law enforcement duties and suggest measures regarding the institutional arrangements to secure such co-operation and measure for the growth of healthy and friendly public-police relationship."

(c) and (d). Bureau of Police Research and Development had undertaken a study in 1973 on the subject "Reluctance of the Public to Aid the Police in the Detection of Crime and

Crime Reporting at Police Stations". They have also another study in hand entitled "Image of the Police in India". Parts of this subject are being covered in these studies undertaken by the BPR&D.

सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जारी किये गए लाइसेंस

6769. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए अब तक कितने लाइसेंस दिये गये हैं तथा कितने लाख टन की क्षमता के लिए लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) इस समय सीमेंट उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा 1979 और 1980 मे इस क्षमता मे कतनी वृद्धि होगी ;

(ग) इस समय कितने लाख टन की क्षमता के लिए आशय पत्र दिये गये है तथा कितने लाख टन सीमेंट के उत्पादन के लिए आवेदन पत्रो की जाच की जा रही है ;

(घ) सीमेट के मामले में देश कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ; और

(ङ) इस समय देश में कुल कितने टन सीमेट की आवश्यकता है तथा देश मे कितने टन सीमेट का उत्पादन होता है तथा इसमे से कितनी सीमेट का आयात किया जाता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ग). 1 अप्रैल, 1977 से लेकर 31 मार्च, 1979 की अवधि में 24.73 लाख मी०ट० की क्षमता के लिये 7 औद्योगिक लाइसेंस तथा 115.47 लाख मी० टन की क्षमता के लिये 33 आशयपत्र जारी किये गये हैं। इस समय कुल मिलाकर 116.42 लाख मी०ट० की क्षमता के लिये औद्योगिक लाइसेंसो आशयपत्रों के 29 आवेदनो की जांच की जा रही है।

(ख) इस समय सीमेट उद्योग की कुल अधिष्ठापित क्षमता 230 लाख मी० टन है। 1979–80 तथा 1980–81 में क्रमशः 46.5 लाख मी० टन तथा 21.6 लाख मी० टन की अनुमानित अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न हो जाने की आशा है।

(घ) देश के लगभग 3 वर्षों में सीमेंट के मामले में आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है।

(ङ) देश की सीमेंट की विद्यमान अनुमानित मांग 240 लाख मी० टन है। वर्ष 1978–79 की अवधि में सीमेंट का उत्पादन लगभग 196 लाख मी० टन हुआ है तथा अप्रैल, 1978, से मार्च, 1979 (19 मार्च, 1979 तक) में 15.5 लाख मी०टन सीमेंट का आयात किया गया है।

Request from West Bengal Jute Industry

6770. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased ot state:

(a) whether he has received recently any request by the West Bengal Government for paying more attention to the R and D efforts in the Jute Industry; and

(b) if so, what are the suggestions of the State Government in this regard and what is the reaction of the Central Government to those suggestions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Big Houses taking smaller shapes

6772. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) based on a news item published in Economic Times, New Delhi, dated March 10, 1979, is it a fact that big industrial houses of the country are splitting and taking shapes of several smaller houses as a reaction to "Janata Government's" declaration to disallow concentration of economic power in few hands of the country;

(b) if so, which major houses have so far splitted into several groups and how; and

(c) whether such splitting of big houses will lead to any problems in

managing these industrial houses or normalacy will prevail and whether the Government is keeping an eye on such activities by big houses?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) to (c). In the news item appearing in the Economic Times, New Delhi dated 10th March, 1979, reference has been made to the splitting up of the industrial houses of Jaipurias, Mafatlal and Rohitt. Ih the context of the MRTP Act, information about any splitting up of a large industrial house is likely to come to the notice of the Department of Company Affairs only when an application is made by an undertaking which has already registered under section 26 of the MRTP Act as one to which section 20(a) of the Act is applicable, for cancellation of its registration on the grounds of a split up of the concerned house and consequent inapplicability of the provisions of Section 20(a) of the undertaking. No such indication is seen in the applcations for cancellation which have been received in the Department of Company Affars in recent months.

स्वतंत्रता सेनानियों को पेन्शन

6773. **श्री लालजी भाई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) देश में गत तीन वर्षों मे राज्यवार, कितने कितने स्वतंत्रता सेनानियो को पेंशन मंजूर की गई ; और

(ख) चालू वर्ष में कितने व्यक्तियों को पेंशन देने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है ।

(ख) यह सूचना देना संभव नही है क्योंकि चालू वर्ष के दौरान अगली स्वीकृतियां आवेदकों द्वारा स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर आधारित होगी जिन के मामलो को अभी अंतिम रूप नही दिया गया है तथा/अथवा जिन के मामलों में राज्य सरकारों की विशिष्ट सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान उन व्यक्तियों की संख्या जिनको पेंशन मंजूर की गई है, का विवरण (राज्यवार) ।

राज्य	1976-77	1977-78	1978-79
अन्डमान और निकोबार	—	—	—
आन्ध्र प्रदेश	38	1007	723
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
असम	8	11	35
बिहार	49	129	670
चंडीगढ़	—	—	2
दिल्ली	1	3	20
गोवा	1	28	30
गुजरात	1	18	184
हरियाणा	—	2	7

राज्य	1976–77	1977–78	1978–79
हिमाचल प्रदेश	—	2	13
जम्मू व काश्मीर	—	2	45
केरल	31	56	205
कर्नाटक	6	99	290
मध्य प्रदेश	8	18	35
महाराष्ट्र	23	202	587
मणिपुर	—	—	1
मेघालय	—	—	—
मिजोरम	—	—	—
नागालैंड	—	—	—
उड़ीसा	11	6	22
पांडिचेरी	—	4	21
पंजाब	13	16	120
राजस्थान	—	7	12
तमिलनाडु	22	30	83
त्रिपुरा	1	2	15
उत्तर प्रदेश	8	34	245
पश्चिम बंगाल	181	370	870
कुल स्वतंत्रता सैनानी	402	2046	4235
भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के जवान	297	171	1347
कुल जोड़	699	2217	5609

Setting up of H.M.T. Unit in Hoshiarpur

6774. CHOWDHRY BALBIR SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is an outstanding demand since long by the masses of Punjab that a H.M.T. Unit be installed at the backward district of Hoshiarpur (Punjab);

(b) if so, the action taken by Government so far;

(c) keeping in view the cheap labour and other facilities there, whether Government will open a HMT Unit there; and

(d) if so, when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) to (d). It is not possible for HMT to set up units in several backward districts of the country. However within the constraints of finances and the production lines of HMT, HMT have to the extent possible been developing linked production lines in several parts of the country. In so far as Punjab is concerned, HMT is assisting towards the establishment of a watch assembly unit at a location decided in consultation with the Government of Punjab. This location is at Sahibzada Ajit Singh Nagar near Chandigarh.

हिन्दी टाईपिस्ट और स्टेनोग्राफरों की भर्ती

6775. श्री रामानन्द तिवारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा विभाग को पता है कि देश में हिन्दी टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों की बहुत कमी है ;

(ख) क्या केन्द्रीय हिन्दी समिति हिन्दी स्टेनोग्राफरो तथा हिन्दी टाइपिस्टों की सीधी भर्ती करने के लिये सहमत है परन्तु मंत्रालय ने अभी तक कोई औपचारिक आदेश नही दिये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार हिन्दी टाइपिस्ट और हिन्दी स्टेनोग्राफर सीधे भर्ती करना चाहती है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो सीधी भर्ती करने में क्या कठिनाइयां है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ). देश में हिन्दी टाइपिस्टों और आशुलिपिकों की कमी के बारे म सरकार को कोई निश्चित जानकारी नही है। जहां तक केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागो में स्टेनोग्राफरों और टाइपिस्टों का प्रश्न है, हिन्दी टाइपिस्टो और हिन्दी स्टेनोग्राफरो के कोई अलग पद नही है और प्रत्याशी हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम से परीक्षा देकर सेवा में आ सकते है। भर्ती के बाद स्टेनोग्राफरों को दूसरी भाषा का आशुलिपि का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है ।

केन्द्रीय हिन्दी समिति ने हिन्दी आशुलिपिकों और टाइपिस्टो की भर्ती के लिए केवल ,हिन्दी आशुलिपि और टाइपिंग की परीक्षा लिए जाने की संस्तुति की थी और यह भी कहा था कि जो उम्मीदवार इसके अतिरिक्त अंग्रेजी आशुलिपि और टाइपिंग का ज्ञान रखते हों उन्हें प्राथमिकता दी जाए। इस पर आगे विचार किया जा रहा है।

भोजपुर में गत्ता (दफ्ती) कारखाना स्थापित किया जाना

6776. श्री रामानन्द तिवारी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के भोजपुर जिले में कुटीर तथा लघु उद्योगो का विकास करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि भोजपुर जिले में धान के पुराल का गत्ता (दफ्ती) बनाने का कारखाना स्थापित किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस पर कौन से कदम उठाने जा रही है जिससे अविलम्ब कार्य प्रारम्भ हो ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) बिहार राज्य के भोजपुर जिले को 1977-78 तक केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम की योजना में शामिल कर लिया गया था। कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास को व्यापक रूप से प्रोत्साहन देने सम्बन्धी सरकार की नीति के अनुसरण में भोजपुर जिले को 1978-79 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित जिला उद्योग केन्द्रों की और अधिक व्यापक योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

(ख) और (ग). चूंकि क्षेत्र मे धान की भूसी उपलब्ध है, अतः धान की भूसी से कार्ड बोर्ड बनाने के लिए एक कारखाने की स्थापना व्यवहारिक हो सकती है। जिला उद्योग केन्द्र भोजपुर द्वारा विस्तृत कार्रवाई योजनाएं तैयार की जा रही है तथा इन योजनाओं को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

वैज्ञानिक अनुसंधान-कार्य पर खर्च की गई धनराशि

6777. श्री रामानन्द तिवारी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान, वर्षवार, वैज्ञानिक अनुसंधान-कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) क्या सरकार सन्तुष्ट है कि यह धनराशि राष्ट्रीय विकास के कार्य के लिये उचित तरीके से उपयोग में लाई गई है ?

रक्षा मंत्रालय में और परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिक्स, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह). (क) 1977-78 को समाप्त वर्षों के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य पर व्यय की गई राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	व्यय
	(करोड़ रुपयों में)
1968-69 . . .	107.56
1969-70 . . .	116.62
1970-71 . . .	139.64
1971-72 . . .	151.64
1972-73 . . .	194.67
1973-74 . . .	216.01
1974-75 . . .	291.60
1975-76 . . .	356.69
1976-77 . . .	402.25
1977-78 . . .	460.00 (अनुमान)

उपरोक्त व्यय मुख्यतः 8 प्रमुख वैज्ञानिक अभिकरणों यथा, परमाणु ऊर्जा विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, अन्तरिक्ष विभाग, इलैक्ट्रानिकी विभाग और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा किया गया था। *इन अभिकरणों को आर्द्ध-व्यावसायिक और प्रायोगिक सयंत्र परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के साथ-साथ अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले समय-बद्ध कार्यक्रमों का निष्पादन करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। सही शीर्षों के अनुसार, जिनके अन्तर्गत व्यय की विभिन्न मदें शामिल की गई हैं, दिए गए आंकड़ों में कुछ भिन्नता हो सकती है।

(ख) जी, हां।

Short fall in Plan Outlay

6778 SHRI K. T. KOSALRAM: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the details of sectors in which a shortfall of Rs. 230 crores has occurred in the Plan Outlay for 1977-78, as pointed out by the National Council of Applied Economic Research in its recent study; and

(b) steps taken to remove the deficiencies so that there is full utilisation of the Plan Outlay in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) and (b). The NCAER study refers to the shortfall of Rs. 230 crores in the Revised Estimates for the Central Plan outlay for 1977-78 as compared with the Budget Estimates for that year The statement annexed indicates the Budget Estimates and the Revised Estimates of plan outlay for 1977-78 Ministrywise. The Finance Minister while presenting the Budget for 1978-79 on February 28, 1978 referred to this shortfall and stated that the Plan expenditure on petroleum, fertilizers, steel and telecommunications would be substantially less mainly due to slippages in delivery schedules of machinery and equipment and civil construction. Also some public sector undertakings had been able to generate more internal resources than anticipated earlier and, therefore, needed less budgetary support for financing their Plan outlays.

Steps have been taken to improve the system of monitoring of plan schemes at all levels by the implementing agencies, the Ministries and the Planning Commission

Statement

Budgetary support for Central plan by Ministries/Departments

(Rs. crores)

S. No.	Ministry/Department	Budget Estimates 1977-78	Revised Estimates 1977-78
1	2	3	4
1	Agriculture	198·26	159·92
2	Food	45·76	40·53
3	Rural Development	168·47	198·44
4	Agricultural Research & Education	36·74	38·60
5	Irrigation	24·16	21·82
6	Commerce	8·14	7·69

*इनके द्वारा अभिकरणों के हिसाब में कुल व्यय का लगभग 65% आता है।

1	2	3	4
7	Civil Supplies & Cooperation	31·96	29·58
8	Communication (excluding P&T)	20·57	20·39
9	Posts & Telegraphs	42·35	25·71
10	Education	85·67	82·01
11	Social Welfare	12·87	12·84
12	Power	130·58	113·91
13	Coal	226·66	240·05
14	Economic Affairs	119·91	135·24
15	Revenue	0·62	0·20
16	Health	83·14	96·02
17	Family Welfare	98·61	90·38
18	Home Affairs	24·88	24·79
19	Personnel & Administrative Reforms	0·20	0·20
20	Industrial Development	232·32	226·72
21	Heavy Industry	56·81	61·10
22	Information & Broadcasting	24·62	21·07
23	Labour	4·65	3·64
24	Petroleum, Chemicals & Fertilizers	713·30	590·08
25	Planning	7·39	6·10
26	Shipping & Transport	301·73	297·58
27	Steel	510·85	453·04
28	Mines	79·63	84·05
29	Supply	0·60	0·28
30	Rehabilitation	21·23	25·64
31	Tourism & Civil Aviation	36·04	30·77
32	Works & Housing	115·14	110·91
33	Atomic Energy	129·79	121·55
34	Culture	5·97	4·45
35	Electronics	10·64	10·49
36	Space	30·20	28·65
37	Science & Technology	35·00	33·63
38	Railways	302·15	300·10
	Total	3,977·61	3,748·17

Scheme to produce Salt

6779. SHRI K. T. KOSALRAM : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether any scheme has been formulated to utilise coolant water from Kalpakkam Atomic Energy Plant for producing salt, instead of letting the water into the sea and if so, the salient features of the scheme;

(b) whether it is being implemented now and if so, the details of the same; and

(c) if not, the reasons for the delay in implementing it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) to (c). The Government of Tamil Nadu have formulated a scheme for diverting 50 cusecs of discharged coolant water from the Atomic Power Plant at Kalapakkam to the Buckingham Canal in order to ensure adequate availability of brine in the Canal for salt production. The scheme will be considered by the Central Advisory Board for Salt at its next meeting for grant of assistance out of the salt cess proceeds.

Setting up of a Cement Factory at Koraput, Orissa

6780. SHRI BAIRAGI JENA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Cement Corporation of India has reviewed the position for setting up the Cement Plant in the district of Koraput, Orissa, which was proposed to be Joint Venture Project between Cement Corporation of India and Industrial Development Corporation, Orissa Ltd.; and

(b) a detailed report thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b). The Cement Corporation of India Ltd., had examined the feasibility of setting up of a cement plant in District Koraput in Orissa. This site is connected by the Kottayalasa-Kirandul broadguage railway line, which is exclusively reserved for transportation of iron ore from Bailadila to Visakhapatnam and is not open to other goods traffic. This project is therefore not feasible till either Dantewada-Sukhma-Rajmundry rail line comes up or Kottavalse-Kirundal railway line is thrown open to general goods traffic.

Promotions in Palm Gur Industry

6781. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under the Palm Gur Industry, Khadi and Village Industry Commission, except for few cases of promotions, no promotion of the staff has been made during the last ten years;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the details of the posts either surrendered or allowed to lapse since 1967?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Functions of Central Palm Gur and Palm Products Institute, Madras

6782. SHRI K. A. RAJAN : Will the Minister of INDUSTRY b pleased to state:

(a) the objectives and functions of the Central Palm Gur and Palm Products Institute, Madras of the Khadi and Village Industry Commission;

(b) its achievements, if any; and

(c) future programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The objectives and functions of the Central Palm Gur and Palm Products Institute, Madras are as follows:—

(1) To conduct field trials, undertaken research and experiments for technical problems faced in development programme of the Industry and improvement in equipment to raise productivity.

(2) To undertake extension activities, to study cost structure of various Palm Products, to organise demonstration and exhibition to disseminate Technical and Organisational progress, to render on the spot Technical guidance to implementing agencies and to do monitoring work in respect of development schemes as and when required.

(3) To impart specialised training to supervisory and technical staff.

(4) To undertake working of model trading activity for assessment of economic viability of the Schemes/Projects.

(b) (1) The Institute is in a position to standardise recipes/formulae for certain palm sweets and other edible products under its research and experimentation programme.

(2) A process for making palm sugar using simple appropriate technology has been evolved.

(3) Simple manually operated equipment have been evolved for cutting of palm leaves and weaving the same.

(4) New designs for plam leaf and palm fibre utility articles have been worked out

(5) Use of simple climbing tools have been experimented and optimum condition worked out.

(6) A scheme on palm candy manufacture under NCST programme is in progress at the Institute.

(7) Cost structure of various palm-products from different parts of the country have been studied under extension programme Model Training-cum-Demonstration centres are in operation, introduction of improved furnances and pans at selected societies has been undertaken.

(8) A specialised training course in sugar making is in progress

(9) The Institute runs a model trading operation dealing with various edible and non-edible products

(c) The future programme of the Institute envisages:—

(1) Intensification of training programme and extension activity.

(2) Introduction of regular course in palm gur technology for the benefit of supervisory staff under implementing agencies.

(3) Rendering promotional assistance through spot assessment of various schemes in operation by implementing agencies.

(4) Intensification of research and experiment work under NCST programme.

Introduction of selection Grade in the Khadi and Village Industry Commission

6783. SHRI K. A. RAJAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Khadi and Village Industry Commission has decided to introduce Selection Grade for all the posts;

(b) if so, the details of the scheme; and

(c) the probable date by which the Selection Grade system is to be implemented and completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c). No, Sir. In conformity with the guidelines issued by the Government from time to time Khadi and Village Industries Commission is introducing Selection Grade for Group 'D' posts with effect from the 1st April, 1978. Orders are under issue. For other categories of posts a Committee constituted by the Khadi and Village Industries Commission has recommended that in all groups of posts where there is acute stagnation, 10 per cent of the total number of posts may be converted into selection grade posts. The recommendations of the Committee are being processed further.

Entry of Multinational into Soyabean Industry

6784. SHRI VIJAY KUMAR N. PATIL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have received a memorandum from small Soya Processors Association Nagpur regarding the reported back door entry of multinationals/large house in the field of Soyabean Processing;

(b) if so, the important details of the memorandum and allegations made therein; and

(c) what is the reaction of Government thereto and action taken in the matter?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b). Government have received a memorandum from Small Soya Processors Association, Nagpur, against the entry of large houses and multinationals in the field of soyabean processing on the ground that the existing small-scale units would not be able to withstand competition from large houses/multinationals. It has also been stated in the memorandum that there is no need for foreign collaboration and/or import of capital goods for the manufacture of soya products.

(c) Government have decided to permit the entry of large houses in the soyabean industry as the manufacture of textured protein, isolates and concentrates cannot be undertaken economically in the small scale sector and most of the entrepreneurs in the medium sector could not implement the Letters of Intent given to them. Prohibition of entry of large houses in this industry would cost considerable distress to the growers of soyabean.

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कोटा

6785. श्री राम सागर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा/पुलिस/वन सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोटा केवल परीक्षा के समय ही भरा जाता है तथा उच्च पदों पर नहीं;

(ख) क्या भारतीय अर्थ सेवा में उच्च दो (1500–1800–2000) में कोटा रखा गया है तथा भरा गया है;

(ग) क्या संविधान के उपबन्धों के अधीन यह भेदभाव की नीति है; यदि हां, तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा में उप सचिव तथा उससे ऊपर के पदों में आरक्षित कोटा न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था केवल प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से इन सेवाओं में सीधी भर्ती के स्टेज पर ही है ।

(ङ) सीधी भर्ती से भरी जाने वाली भारतीय अर्थ सेवा के ग्रेड-I (रु० 1800–2000) और ग्रेड–II (रु० 1500–1800) की रिक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अनुसूचित जनजातियों के लिए ग्रेड–I में आरक्षित एक रिक्ति तथा ग्रेड–II में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित एक रिक्ति को उपयुक्त उम्मीदवारों से न मिलने के कारण नहीं भरा जा सका। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इन रिक्तियों को पुन विज्ञापित किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं श्रीमान्।

(घ) चूंकि उप-सचिव और उससे ऊपर के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

Scheme for Development of Adivasi areas in Bihar

6786. SHRI BAGUN SUMBRUI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state

(a) the details of the scheme formulated for bringing improvement in the position of Adivasi and for the development of Adivasi area in Bihar; and

(b) the names of the areas to be covered by this scheme and the amount of expenditure to be incurred thereon during the Sixth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). A sub-Plan has been drawn up for areas having 50 per cent or more tribal population. The areas covered by the Tribal sub-Plan in the State of Bihar are given in the Annexure.

The schemes for these areas include all sectors of development *viz.* (1) Agriculture and Allied sectors (2) Cooperation (3) Water and Power Development (4) Industries and Minerals (5) Communication (6) Social and Community Services (7) Economic Services and (8) General Services.

The Medium Term Plan (1978—83) has not so far been finalised.

Statement

STATEMENT SHOWING THE AREAS UNDER TRIBAL SUB PLAN IN BIHAR.

1. RANCHI district.

2 SINGHBHUM district.

3 Latehar sub-division, and Bhandaria block of Garhwa sub-division, in PALAMAU district.

4 Dumka, Pakur, Rajmahal and Jamtara sub-division, and Sundar Pahari and Boarij or blocks of Godda sub-division in SANTHAL PARGANAS district.

Salt cess proceeds from Gujarat

6787. SHRI F. P. GAEKWAD: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) the amount the Centre had been collecting from Gujarat by way of salt cess during the last three years;

(b) whether it is a fact that Gujarat is a major contributor to this fund;

(c) if so, how this fund is being utilised at present;

(d) whether it is a fact that the Gujarat Chamber of Commerce recently complained before the Salt Enquiry Committee about effective steps not being taken to utilise the fund either for devolepment of salt industry or for welfare of labour; and

(e) if yes, steps proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) (a) The amounts

of salt cess collected from Gujarat State during the last three years were:

(In lakhs of rupees)

1975-76	78·20
1976-77	75·99
1977-78	83·97

(b) Yes, Sir.

(c) The proceeds of salt cess reduced by the cost of collection are to be utilised on all or any of the following objects as provided in section 4 of the Salt Cess Act, 1953:—

(1) meeting the expenditure incurred in connection with the salt organisation maintained by the Central Government,

(2) meeting the cost of measures taken in connection with the manufacture, supply and distribution of salt by Union agencies and the regulation and control of the manufacture, supply and distribution of salt by other agencies; and in particular, measures for—

(i) the establishment and maintenance of research stations and model salt farms;

(ii) the establishment, maintenance and expansion of salt factories;

(iii) fixing the grades of salt;

(iv) promoting and encouraging co-operative effort among manufacturers of salt; and

(v) promoting the welfare of labour employed in the salt industry.

(d) and (e). The Gujarat Chamber of Commerce presented a memorandum to the Salt Enquiry Committee suggesting several measures for the better utilisation of Salt Cess proceeds and for the development of Salt Industry and welfare of labour employed in the Industry These suggestions would be considered by the Salt Enquiry Committee.

Memorandum regarding growth of small scale Industries

6788. SHRI VIJAY KUMAR N. PATIL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum from Shri Prahm Vasudeva, President Small and Developing Industries Association of India P.O. Box 1542 Bombay regarding growth of small scale industries;

(b) if so, important details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir

(b) The representation has referred to the criteria announced through Press Notes of 3rd and 5th Jan. 1979 regarding endorsement of capacity on registration certificates of undertakings pertaining to all industries included in the first schedule of the IDR Act. It has also been pleaded in the representation that small scale units which have crossed investment limit of Rs. 10 lakhs in plant and machinery may be allowed to grow atleast upto Rs. 3 crores investment which is the current level for general exemption in the industrial Licensing Policy.

(c) The Government has stipulated in the above mentioned Press Notes that in respect of items reserved for the small scale sector. the production capacity for the non-small scale units producing these items would be determined with espect to the highest production achieved by the undertakings in the three years prior to the date of reservation of the item for production in the small scale sector or the level of production existing on 29th August.

1973, whichever is earlier, subject to a few additional conditions. This stipulation has been made applicable to all units which are not in the small scale sector. While it has been stipulated that no undertaking should exceed the maximum production levels achieved prior to 31-12-1978, it has been provided that where an undertaking is producing in excess of the capacity as determined above, it would bring down its production to the registered capacity as endorsed on the registration certificates within a period of two years from 1-1-1979. However, if the undertaking agrees to buy and market the same or similar products of small scale industries, its capacity determined according to the above criteria will be enhanced to that extent. However, the representation is receiving further attention.

Production of Bread and Biscuits Industries

6789. SHRI VIJAY KUMAR N. PATIL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have decided to allow bread and biscuits production to Small Scale Industries; and

(b) if so, what measures will be taken to ensure hygienic production of these articles as is done in Britania or Modern Bakeries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir. Manufacture of bread and biscuits has been carried on in the small scale sector for a long time. In December 1977 bakery products, including bread and biscuits, were reserved for exclusive development in the small scale sector.

(b) Small scale industries engaged in the production of bread and biscuits are subject to the norms of hygenic production prescribed by the health authorities in the same way as the units in the organised sector.

महाराष्ट्र में सीमेंट का जिलावार आवंटन

6790. श्री गंगाधर अप्पा बूरांडे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से मार्च, 1979 तक की अवधि मे महाराष्ट्र के लिए सीमेंट का कितना कोटा जिलावार, दिया गया और सीमेंट एजेन्सियो के नाम क्या है,

(ख) 15 मार्च, तक उन जिलो को वास्तव मे कितनी मात्रा मे सीमेंट सप्लाई किया गया; और

(ग) क्या उनकी मागे पूरी करने के लिए सप्लाई पर्याप्त है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव). (क) और (ख). सीमेंट के वितरण की विद्यमान प्रणाली के अनुसार सीमेंट का इकट्ठा आवंटन प्रत्येक तिमाही के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के अधीन विभिन्न श्रेणियो जैसे सरकारी उपभोक्ताओ गैर-सरकारी इकट्ठे खपत वाले उपभोक्ताओं तथा आम जनता मे बिक्री के लिये किया जाता है। जनवरी-मार्च, 1979 की तिमाही के लिए महाराष्ट्र को किया गया इकट्ठा आवंटन 50,000 मी० टन के अतिरिक्त तदर्थ आवंटन को मिलाकर 5.45 लाख मी० टन है। सीमेंट का जिलेवार आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जनवरी-मार्च, 1979 की तिमाही के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा भिन्न जिलो को दी गई सीमेंट की मात्रा, प्रत्येक जिले को सीमेंट संभरण कर रही सीमेंट फैक्टरियों के नाम तथा फरवरी के अन्त तक भेजी गई सीमेंट की मात्रा बताने वाला एक विवरण सलग्न है ;

(ग) राज्य सरकार ने 54 95 लाख मी० टन के मूल आवंटन के अलावा प्रति तिमाही मे 1 00 लाख मी० टन के अतिरिक्त आवंटन के लिए अनुरोध किया था। महाराष्ट्र राज्य की सम्पूर्ण माग पूरी करना सभव नही हो सका है क्योकि देश में सीमेंट की उपलब्धता सारे राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के विभागो की कुल माग से कम है।

विवरण

जनवरी—मार्च, 1979 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र में विभिन्न जिलों को किये गये सीमेंट का आवंटन तथा भेजी गई मात्रा

क्र० सं०	जिले का नाम	सीमेंट फैक्टरियों के नाम जिनसे आवंटन तथा प्रेषण किया जाता है	जनवरी–मार्च 1979 की तिमाही के लिए आवंटन	जनवरी और फरवरी 79 में किए गये प्रेषण
1	2	3	4	5
1.	अहमद नगर	केसोराम, शाहाबाद, वाडी (डम्प)*	5304	686
2.	अंकोला	शाहिबाद वाडी, चांदा, केसोराम	4170	1914
3.	अमरावती	चांदा (डम्प) *	4364	1888
4.	औरंगाबाद	वाड़ी, चांदा, पण्यम, अम्मासान्द्रा, केसोराम	4314	430
5.	भंडारा	चांदा, केसोराम	2808	905
6.	बुलडाना	चांदा, केसोराम (डम्प)*	3300	526
7.	बीर	शाहाबाद, वाडी, पण्यन, अम्मासान्द्रा (डम्प)*	2560	575
8.	चन्द्रपुर	चांदा	2485	1233
9.	धूलियां	चांदा, केसोराम (डम्प)*	3860	934
10.	जलगांव	चांदा, केसोराम (डम्प)*	5012	782
11.	कोल्हापुर	वाडी, बगलकोट, अम्मासान्द्रा (डम्प)*	6880	2162
12.	कोलाबा	शाहाबाद, वाडी, कुरकुन्ता (डम्प)*	3188	1592
13.	नांदेड़	पन्या, अम्मासान्द्रा (डम्प)*	2832	414
14.	नागपुर	चांदा, केसोराम	12892	4488
15.	नासिक	चांदा, केसोराम (डम्प)*	5368	1678
16.	उस्मानाबाद	शाहाबाद, वाड़ी, कुरकुन्ता (डम्प)*	2962	702
17.	परभनी	वाड़ी, पण्यम, अम्मासान्द्रा (डम्प)*	3100	240
18.	पुर्ण	शाहाबाद, वाडी (डम्प)*	20715	8477
19.	रत्नागिरि	शाहाबाद, वाडी, बगलकोट, अम्मासान्द्रा करकुन्ता (डम्प)*	3338	1342
20.	सतारा	शाहाबाद, वाडी, बगलकोट, कुरकुन्ता (डम्प)*	4360	1441
21.	सांगली	वाडी, बगलकोट (अम्मासान्द्रा) (डम्प)*	4796	1034
22.	शोलापुर	शाहाबाद, वाडी, कुरकुन्ता (डम्प)*	6220	2621
23.	थाना	शाहाबाद, वाडी, कुरकुन्ता (डम्प)*	11984	7020
24.	वर्धा	चांदा, केसोराम	3204	1220
25.	यवतमाल	चांदा, पण्यम, केसोराम	3480	2165
26.	बृहत बम्बई	शाहाबाद , वाडी, चांदा, सेवरिया तथा आयातित सीमेंट	66050	33183
			200294	79657

*डम्प—महाराष्ट्र में मै० ए० सी० सी० द्वारा अपनी शाहाबाद तथा वाडी सीमेंट फैक्टरियों में भंडारों (डम्पों) को चलाया जा रहा है।

News-item captioned "Giant's Threat"

6791. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the news report appearing in the *Economic Times* dated the 21st March, 1979 at page 4 under the caption "Giant's threat";

(b) if so, what is the reaction of Government to the various observations of serious nature made therein; and

(c) details of action taken/proposed in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The decision to permit the entry of the large units in the Soyabean processing industry has been mainly based on the following considerations:

(i) Most of the medium entrepreneurs who had been given letters of intent in the past had not yet implemented those letters of intent.

(ii) The manufacture of textured protein, protein isolates and concentrates do not generally lend themselves to economical processing in the small scale sector

(iii) It also requires market promotional effort on a large scale, in which the established market outlets of the large units act as an asset.

(iv) The poor performance of the small and medium scale entrepreneurs, coupled with prohibition of entry of large units, would have caused considerable distress to the growers of Soyabeans. The States where this crop has been produced on a big scale are finding it difficult to ensure raw remunerative prices to the farmer. Its cultivation was promoted to strengthen the protein content in the Indian diet.

(v) It has been made clear in the Ministry of Industry's Press Note dated the 29th January, 1979 that preference will be given to proposals received from non MRTP and non FERA companies. The decision to permit the entry of large units had been taken in consultation with the authorities concerned with protection of the interest of the small scale units, including DC(SSI) and CSIR.

The requests for foreign collaboration would be considered on merits, and normally it will not be allowed where the indigenous technology is available. It would, however, not be desirable to prohibit foreign collaboration altogether because it may be required in the manufacture of more sophisticated products. Similarly where indigenous machinery was available, the import of foreign machinery will not be recommended.

A letter of intent has been issued to M/s. Modipon Limited, Modi Nagar on 30th June, 1977 for the manufacture of the following items for the capacity indicated against each:

Item of manufacture	Annual capacity (Tonnes)
(1) Edible Soya Flour . .	45,000
(2) Soya Textured Protein . .	30,000
(3) Soya Protein isolates and concentrates . .	3,000
(4) Soyabean oil (by-product) .	16,450

The proposal of M/s. Modipon Limited envisages import of plant and equipment to the extent of Rs. 4.34 crores, and this is under examination of the Ministry from indigenous angle. A proposal from M/s. Britannia Biscuit Company Limited is also under consideration of the Government. It is not a MRTP house. No proposal has

been received by the Ministry of Industry so far from M/s. Cadbury India Limited for setting up Soya processing unit. M/s. Food Specialities Limited, whose proposal was rejected earlier, will also be eligible to apply in the light of the Ministry's Press Note dated the 29th January, 1979.

Closure of small scale units due to non-availability of Steel Wires and Rods

6792. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether exactly how many small scale units due to non-availability of steel wire rods have closed down or are working with unutilised capacity;

(b) whether it is a fact that capacity of small scale wire drawing units was 26 lakh tonnes in West Bengal;

(c) how many of them are now on the list of the Iron and Steel Controller and what is the quantity of mild steel black or galvanised wire registered licenced capacity and built in capacity of such units; and

(d) what is the capacity which is lying idle due to lack of supply of raw materials in West Bengal and in other States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Government are aware of the difficulties being faced by the small scale wire drawing units in general in recent months due to the difficulties in the procurement of adequate quantity of wire rods against their enhanced demand.

(b) According to the information available the number of active wire drawing units in West Bengal is 125 and their combined capacity is 1,25,000 MT per annum.

(c) Small scale industries are not required to register themselves with the Iron and Steel Controller. Only the large units are required to be registered with the Iron and Steel Controller.

(d) In a recent survey conducted, 375 small units producing MS and GI wires, in the country, have reported their capacity and production as follows:—

Year	Capacity (Thicker than 18 SWG) (Lakh Tonnes)	Production (Lakh Tonnes)
1977-78 . .	4·5	3·5

Regarding the 125 units of West Bengal, their combined production was 82,350 MT during 1977-78 against the total capacity of 1,25,000 MT.

Inflow of Hippies in Goa Beaches

6793. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is enormous inflow of hippies in the country specially in Goa beaches;

(b) whether it is also a fact that there are number of international gangsters among them who are wanted by interpol; and

(c) if so, what steps Government are taking to tackle the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). In the absence of a precise definition of a 'Hippie', it is difficult to distinguish such persons as a category from other tourists. Reliable information in respect of the inflow into country or Goa, of such foreigners is, therefore, not available. It is also

not, therefore, possible to say whether such persons include international gangsters However, if any foreigner comes to adverse notice, suitable action is taken against him under the relevant law

(c) With a view to limiting the entry into India of such foreigners as are likely to be a social nuisance because of their indulgence in narcotics, indecent behaviour, vagrancy, begging etc, suitable instructions have been issued to the Indian Missions abroad to be particularly cautious in granting tourist visas to such persons State Governments have also been suitably advised to have the activities of such foreigners carefully watched and take prompt penal action for any infringement of law

ग्राम स्तर पर पंचवर्षीय योजना लागू करना

6794. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ग्राम स्तर पर पंच वर्षीय योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो योजना के नगरीय स्वरूप में परिवर्तन करने और उसे ग्रामोन्मुख बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन रहमान) : (क) जी, नहीं । एकीकृत आयोजना के लिए उपयुक्त समझा गया क्षेत्र विकास खंड है । इसलिये देश में खंड स्तर आयोजना शुरू की गई है । इन योजनाओं को तैयार करने में खण्ड में आने वाले गांव और गांवों के समूह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा ।

(ख) पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में कृषि और एकीकृत ग्रामीण विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है और इस लिए इसे नगरोन्मुख नहीं कहा जा सकता ।

Implementation of foreign contribution Act, 1976

6795. SHRI HALIMUDDIN AHMED Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have appointed any authority for implementation of foreign contribution act 1976 and if so, the details thereof;

(b) whether the officials working for implementation of foreign contribution Act have detected and examined any case under the rule; and

(c) if so, the number of cases being examined and details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) The Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 is being administered by the Ministry of Home Affairs.

(b) and (c) Since the commencement of the Act, prosecution under punitive sections of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 has not been sanctioned in any case so far. In some cases, preliminary inquiries are being made regarding alleged violation of the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act. It will not be in public interest at this stage to disclose details thereof

Classification of people on socio-economic basis

6796. SHRI K. MALLANNA:

SHRI S. S. SOMANI:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to make classification of people into majority and minority communities on socio-economic basis instead of on religious basis and to raise them to equal level by allowing various classes to progress on that basis; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) and (b). There is no question of classifying the people into communities for purpose of

planning or economic policy. As the Hon'ble Member is aware, the current Five Years Plan has the primary objective of increasing the incomes and welfare of those sections of the community which are below the poverty line, through increased employment opportunities, higher earnings in agriculture and industry and better access to social services. In that sense, it may be deemed to distinguish between the poor who are in the majority and the non-poor who are in the minority. Success of the Plan would imply a significant reduction in the present gap in the conditions of life of these two groups.

Production of cotton in States

6797 SHRI MOTIBHAI R CHAUDHARY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the total yearly production of cotton in Gujarat, Punjab and Maharashtra;

(b) the total quantum of cotton to be purchased on behalf of the Cotton Corporation from these three States this year, the quantum of cotton purchased upto 31st March State-wise and the rates thereof;

(c) the rates at which cotton is purchased in Maharashtra by the State Cotton Corporation, zone-wise;

(d) the rates at which cotton will be purchased by the National Textiles Corporation in case of necessity from the Cotton Corporation of India and the Maharashtra Cotton Corporation; and

(e) whether the rates offered by the Maharahstra Cotton Corporation are higher than those of the Cotton Corporation of India; if so, the reasons for which higher rates are not offered to the cotton-growers by the Cotton Corporation of India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Final State-wise estimates of cotton production for the current cotton year 1978-79 have not yet become available. However, the estimated cotton production in Gujarat, Punjab and Maharashtra during the previous year 1977-78 is given below:—

State	Production (In lakh bales of 170 kgs. each)
Gujarat	19·42
Punjab	12·24
Maharashtra	12 63

(b) A Statement is attached.

(c) The Maharashtra State Cooperative Maketing Federation purchases kapas at guaranteed prices which are on an average about 10 per cent to 20 per cent higher than the minimum support price announced by the Government for 1978-79 cotton season depending on the variety and grading of cotton.

(d) The National Textile Corporation purchases cotton from Cotton Corporation of India and Maharashtra State Cooperative Marketing Federation on negotiation basis from time to time as per market conditions prevailing at the time of negotiation.

(e) In so far as Maharashtra State is concerned, as the cotton procurement is undertaken exclusively by Maharashtra State Cooperative Marketing Federation from 16th December 1978, there is no basis for comparison of rates offered by the Cotton Corporation of India with that of Maharashtra State Cooperative Marketing Federation.

Statement

Details of total quantity of cotton targeted to be purchased by the Cotton Corporation of India in Gujarat, Punjab and Maharashtra and the quantity of cotton purchased in these States and the rates offered by the Corporation are as under:—

(Quantity in lakh bales of 170 kgs each)

State	Purchase target	Purchases made so far	Rates at which purchases were made by CCI during the second fortnight of March 1979	
			Variety	Rate (Rs. per quintal) High/Low
Gujarat	5·00	1·44	S-4	516/445
			Digvijay	458/425
			CO-2	482/355
			V-797	347/324
Punjab	2·50	1·99	J-34	394/267
Maharashtra*		0·61	..	..

*With the revival of State cotton procurement scheme in Maharashtra with effect from 16th December, 1978, the Cotton Corporation of India is not now operating in Maharashtra. However, up to 15th December, 1978, the Cotton Corporation of India had purchased about 61,278 bale of cotton in Maharashtra.

Setting up of Salt Industry in West Bengal

6798. PROF. SAMAR GUHA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Central Government propose to set up additional salt industry along with by-product industries in the Contai area, coastal belt of West Bengal;

(b) whether the Minister of State visited the area on several occasions and had consultation with the West Bengal Government and the local administration; and

(c) if so, the reason for delay in setting up the project and when the matter will be finalised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) It is proposed to set up a salt factory in Contai Sea Board area in Midnapur District and lands admeasuring about 1,900 acres are to be handed over by Government of West Bengal to M/s. Hindustan Salts Ltd. (A) Government of India Undertaking) for undertaking manufacture of salt in the area.

(b) The Minister of State for Industry Shrimati Abha Maiti, visited Contai on 5th January, 1979 and held discussions in the matter with the Minister of Industries, Government of West Bengal and State Government officials.

(c) Some unauthorised salt manufacturers on the land have obtained injunction from High Court of Calcutta against allotment of land to M/s. Hindustan Salts Ltd. Further action on this project will be taken after the lands are transferred in favour of M/s. Hindustan Salts Ltd. for which purpose

State Government are taking suitable steps.

Nationalisation of Key Industries

6799. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) latest plan of the Government of India in respect of nationalisation of key industries; and

(b) whether Government propose to natonalise the synthetic rubber producing industry of the country in view of its being a monopoly industry to form a rubber corporation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). Minister of Industry has on various occasions, including at a Press Conference on 12th February, 1979, discussed the question of nationalisation of industries as part of the programme to implement the Janata Party resolution on economic policy and in the context of the debate on the concentration of economic power. These issues have also been raised by the Press during their meetings with the Minister of Industry. At his most recent Press Conference of 12th February, 1979 Minister of Industry spelt out the criteria for take over and nationalisation of industries as being the extent of concentration of economic power by large houses, the extent to which there is need to regulate the entire spectrum of industrial output and marketing by the State, and the areas in which the public sector has to make its presence felt. These issues are also dealt with in the Statement on Industrial Policy presented to Parliament on December 23, 1977. The question of nationalisation has been raised at various forms as a matter of public interest. Government have not yet taken any decision in this regard.

Constitution of National Reconstruction Army

6800. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the group constituted to examine the possibility of setting up a National Reconstruction Army has submitted its report;

(b) salient features of the scheme;

(c) whether the Planning Commission have considered the scheme and if so, action taken thereon; and

(d) if the report has not been submitted, the date by which it is likely to be submitted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): (a) No, Sir.

(b) and (c): Do not arise.

(d) No definite date has been set for the submission of the report The Working Group has been asked to report as soon as possible.

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 4343 DT. 20-12-78 RE. TRANSLATION AND VETTING WORK IN MINISTRIES

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): In the reply given to Lok Sabha Unstarred Question No. 4343 on 20-12-1978 it was stated that

"The quota of translation for the Legislative Department has been fixed at 1800 words per translator per day and that of vetting approximetely double the quota for translation."

The above sentence may be read as under:—

"The quota of translation for the Legislative Department has been fixed at 1300 words per translator per day and that of vetting approximately double the quota for translation."

Similarly, in Annexure 'C' (Hindi Version) "1300 words per day" may be read for "1380 words per day."

This correction has been necessitated due to a typographical mistake. The mistake occurred in that part of the answer to the question which relates to another Ministry and it could not be noticed earlier.

12 hrs.

श्री नाथूसिंह (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अमेरिका से बहुत सारा पैसा लिया है। ...(**व्यवधान**)...इट इज डाइरेक्ट इन्टरफीरेन्स इन इन्डियन पालीटिक्स। यह देश के बेचने का कार्य किया है। ...(**व्यवधान**)... ये पहले कहती रही हैं कि जे० पी० अमेरिका से पैसा ले रहे हैं ...(**व्यवधान**)...क्या यह हिन्दुस्तान की राजनीति में इन्टरफीरेन्स नहीं है।

...(**व्यवधान**)...

मैंने काल-एटेंशन दिया है, आप उसे स्वीकार कीजिए।...(**व्यवधान**)..

श्री विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मैंने 377 का नोटिस दिया है, आप ने उस पर क्या फ़ैसला किया है।...

...(**व्यवधान**) ...

MR. SPEAKER: Whatever has been received, I am dealing with according to the rules. (*Interruptions.*) No such calling attention has yet come to me. It is only now, today, it has come. All calling attention notices will be considered. So far as tomorrow is concerned, I have given permission to a calling attention about power failure in Bengal. I am not able to select any other calling attention for tomorrow. It will be considered for next week. (*Interruptions*). I will certainly consider it for next week Papers to be laid.

श्री नाथू सिंह : यह पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। यह बड़ा गंभीर मामला है।

(*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Don't record.

(*Interruptions*)**

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Under rule 58, I am raising a point of order.

MR. SPEAKER: is it about a matter before me today?

SHRI VAYALAR RAVI: Yes. (*Interruptions*).

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT

SHRI VAYALAR RAVI: I am raising this matter under rule 58. Now the Government have permitted their servants to participate in the RSS..... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Do not record. This is not a point of order

SHRI VAYALAR RAVI: * *

12.05 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

DETAILED DEMANDS FOR GRANTS, 1979-80 OF MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): On behalf of Shri Mohan Dharia, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation for 1979-80. [*Placed in Library. See* No. LT-4261/79].

**Not recorded.

DETAILED, DEMANDS FOR GRANTS, 1979-80 OF MINISTRY OF INDUSTRY

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Industry, for 1979-80. [*Placed in Library. See* No LT-4262/79].

SIKH GURDWARAS ELECTION ENQUIRIES (AMDT) RULES, 1979

THE MINISTER OF STATE IN THE THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) I beg to lay on the Table a copy of the Sikh Gurdwaras Election Enquiries (Amendment) Rules 1979 (Hindi and English versions published in Notification No. G.S.R 328(E) in Gazette of India dated the 2nd April, 1979, under sub-section (3) of section 146 of the Sikh Gurdwaras Act, 1925. [*Placed in Library. See* No LT-4263/79].

NOTIFICATIONS UNDER ALL INDIA SERVICES ACT, 1951

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D PATIL): I beg to lay on the Table a copy of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 3 of the All India Service Act, 1951:—

(1) G.S R 435 published in Gazette of India dated the 24th March, 1979 containing corrigendum to Notification No. G.S R. 160 dated the 3rd February, 1979.

(2) G S R 436 published in Gazette of India dated the 24th March, 1979 containing corrigendum to Notification No. G S.R 159 dated the 3rd February, 1979

(3) The Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 1979, published in Notification No G.S.R. 471 in Gazette of India dated the 31st March, 1979.

(4) The Indian Administrative Service (Pay) Second Amendment Rules, 1979, published in Notification No G S R 472 in Gazette of India dated the 31st March, 1979. [*Placed in Library. See* No LT-4264/79].

ANNUAL REPORT OF NATIONAL INSTRUMENTS LTD., CALCUTTA FOR 1977-78

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report (Hindi @version) of the National Instruments Limited, Calcutta, for the year 1977-78 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 [*Placed in Library. See* No. LT-4265/79].

AUDIT REPORTS ON THE ACCOUNTS OF DELHI FINANCIAL CORPORATION FOR THE YEARS FROM 1971-78 TO 1975-76 WITH STATEMENT FOR DELAY

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): I beg to lay on the Table.—

(1) A copy each of the Audit Reports (Hindi and English versions) on the accounts of the Delhi Financial Corporation for the years 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75 and 1975-76, under sub-section (7) of section 37 of the State Financial Corporations Act, 1951.

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above Audit Reports. [*Placed in Library. See* No. LT-4266/79].

@English version of the Report and Hindi and English versions of Review by the Government on the working of the Company, were laid on the Table on 22nd December, 1978.

12.07 hrs.

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT—*Contd.*

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki). Kindly listen to us. There is an adjournment motion before you

MR. SPEAKER: I have not allowed it

SHRI C M. STEPHEN: You have not allowed it. But there is an adjournment motion given notice of The member is asking *(Interruptions)* Under rule 60, when an adjournment motion comes before you, there are only three courses open to you. You can either reject it and explain the reasons for it, or ask the member for more information or you can call for explanation from the Minister concerned Here is an adjournment motion, and it is on the basis of *(Interruptions)* Under article 309, the conditions of service of Government servants are to be regulated ...*(Interruptions)*

MR. SPEAKER The adjournment motion by Shri Vayalar Ravi refers to the decision of the Government to amend the service rules, enabling the Government servants to join RSS, a communal organisation with political overtones, which is against the secular character of the Indian Constitution and which has disastrous consequences. I have rejected it, saying "this is not a matter for the adjournment of the legislative business". There are other courses open to you; adjournment motion is not a course open to you.

SHRI C. M. STEPHEN: This is a matter which is agitating the whole country . *(Interruptions)* Under article 309. . *(Interruptions)* The rules have statutory force. This House.... *(Interruptions)*

MR SPEAKER: This is not a point of order at all. You can have a Calling Attention, but it cannot be an adjournment motion. You can raise it during the Demands.

SHRI C. M. STEPHEN: We are responsible people. Kindly listen to us while we are raising it.

MR. SPEAKER: It is not a matter for Adjournment motion.

SHRI C. M. STEPHEN: The paper has stated that specific permission is given to join the RSS. That impression is dangerous. This is a statutory matter. We have heard your ruling. You have said it is not a matter for adjournment Kindly listen to us. I am convincing you that this is a matter for adjournment

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Is the Leader of the opposition challenging your ruling? This will create a present which you must not allow.

MR SPEAKER There are other ways of raising it

SHRI C M STEPHEN: It is a settled procedure that your ruling on the adjournment motion is not final. All parties have drawn up a procedure that when you reject an adjournment motion, it is open to us to place before you

MR SPEAKER. My predecessors have laid down that during the Budget session, when the Demands are discussed, unless it is something very urgent and exceptional, the Speaker will not give consent to an adjournment motion

SHRI C. M. STEPHEN: The Home Ministry's Demands are over.

MR. SPEAKER: There are so many other ways of raising it. We have to be a little responsible.

SHRI C. M. STEPHEN: This is a statutory matter on which the House has authority, you must understand.

SHRI C. M. STEPHEN: This question is agitating the people of this country.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): It is very unfortunate that a discussion is sought to be raised on your ruling. However, I would like to tell the House that what has appeared in the press is totally wrong.

SHRI C. M. STEPHEN: Let me put one question to the Prime Minister.

MR SPEAKER: The Prime Minister of the country says that what has appeared in the poper is totally wrong What more do you want?

SHRI C. M. STEPHEN: Is it that the conduct rules have not been amended, or is it that the amendment does not give permission to join the RSS? What is baseless?

MR. SPEAKER: You can discuss it with him.

SHRI C. M STEPHEN: I want to know from him ..

MR SPEAKER: He says, it is totally baseless. (*Interruptions*) New precedents are being created in the House Shri Paswan.

12.15 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRTY-FIRST REPORT

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur) I beg to present in Thirty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

FIFTEENTH REPORT

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): I beg to present the Fifteenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table.

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT —*Contd.*

SHRI C. M. STEPHEN: I want an explanation from him....

MR. SPEAKER: You cannot cross-examine him in the House. I am surprised to see that the Leader of the Opposition is persisting in this manner. I had expected better co operation from him, the Leader of the Opposition. The Prime Minister said, this is baseless. If there is anything further, you can discuss the matter with him.

SHRI C M. STEPHEN: When a statement is made by the Prime Minister on the floor of the House, the Leader of the Opposition has got a right to ask what he means by it.... (*Interruptions*)

MR SPEAKER: I cannot compel him to answer.

SHRI C M. STEPHEN: You need not compel him. If he is not prepared to answer, let him say.

Let me frame my question. There is a report in the press and the report says that the conduct rules have been amended Is that report correct or not? If he says, it is incorrect, I want to know whether the conduct rules have been amended or not. This is the question put to him. He says, it is baseless. I want to know what is baseless. (*Interruptions*) I am not shouting. I am asking a question. What is baseless?

MR. SPEAKER: If he does not answer you, what can I do? I cannot compel him. (*Interruptions*)

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN (Satara): It is not our intention to question your authority. But there are issues which exercise the minds not only of the members in this House but the people at large in the country (*Interruptions*) Even in the Janata Party, the issue has become controversial, whether the members

of the Janata Party can become the members of the RSS (*Interruptions*) Now, here is a news which says that the Government have amended the conduct rules to allow Government employees to become the members of the RSS .. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: The Prime Minister says, it is baseless.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: By disallowing such type of discussions and keeping them out of Parliament, you are making Parliament a 'vegetarian' Parliament (*Interruptions*) You must act in the true spirit of Parliament and allow discussions on such vital issues which are exercising the minds of the members and the people in the country

SHRI C M STEPHEN The statement that he made was that the report is baseless The report has got two aspects One is, whether the conduct rules have been amended and the other is, what is the interpretation of it This is an elementary courtesy. When the Prime Minister makes a statement and the Opposition asks for an explanation, the doubt must be cleared It is an elementary courtesy that he must come out and explain what he meant by it I did not understand. Kindly explain what is meant by it You have said that the report is baseless. Is it your statement that the Conduct Rules have not been amended, or, is it your statement that the amendment would not mean that the government employees can join the RSS? What exactly is meant? I want an explanation about that.

SHRI MORARJI DESAI: The Leader of the Opposition wants elementary courtesies. Is it an elementary courtesy to shout at me? Is that an elementary courtesy? How can I respond to that kind of thing? (*Interruptions*). Let me tell him that I have not made the statement without understanding it.

SHRI C. M. STEPHEN: I did not understand. That is why I asked.

SHRI MORARJI DESAI: That is the pity. You do not understand it. Government employees are not allowed to take part in the RSS activities. That does not mean that....

AN HON. MEMBER: That does not mean that!

MR SPEAKER Mr. H V. Kamath. (*Interruptions*)

SHRI C. M. STEPHEN: He is again misleading the House. He is confirming He says, 'What I did say did not mean that the government employees cannot participate in the RSS' That is what he said. Kindly do not keep the House in the darkness

MR SPEAKER· I will direct him to place the amendment on the Table of the House .

SHRI C M STEPHEN No That is not the point

MR. SPEAKER· You cannot dictate to me The Leader of the Opposition has no right to dictate to me

SHRI C M STEPHEN: I do not dictate

MR SPEAKER· I will ask him to place the amendment on the Table of the House and, if necessary, I will allow a debate (*Interruptions*)

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): On a point of order.

MR SPEAKER What is the point of order? About what matter?

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Under rule 184, Sir. You have allowed them to discuss RSS. I have nothing to say That is your sweet will But another matter, which is the most important and to which Mr. Chavan has also agreed, is about the money received by Mrs Gandhi.... (*Interruptions*). This is a serious matter. The whole country is agitated

MR. SPEAKER: All serious matters cannot be discussed in one day. We must find time for it...

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I am raising a serious matter...

MR. SPEAKER: Mr. Kanwar Lal Gupta, this is an attempt to steal a march over others. I have already informed you that I am allowing a call-attention on that. You cannot raise it by a point of order. I am not allowing you any more. Do not record.

SHRI C. M. STEPHEN: Sir, I want to make it clear on behalf of my Party and on behalf of the President of my Party, Mrs. Indira Gandhi, that the report which has appeared is absolutely baseless. Not a pie has been taken: I want to make it clear. I challenge, we are prepared for any inquiry. It is baseless.

MR SPEAKER: I am allowing an opportunity for discussion (*Interruptions*) I have said that I am giving an opportunity for this. Nothing more.

SHRI NATHU SINGH (Dausa): There are CIA agents sitting in Indian Parliament. This is an insult to our country.

SHRI C M STEPHEN: You are the CIA: you have a man, Dr. Subramaniam Swamy.

MR. SPEAKER: I think you are quits now.

(*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamand Hurbour): Indira Gandhi Party took money from everybody.

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : स्टीफन साहब के बयान के बाद इस बात पर एक बहस यहां पर होनी चाहिये ....**

MR. SPEAKER: Don't record.

Shri Hari Vishnu Kamath.

CHOWDHRY BALBIR SINGH: **

MR. SPEAKER: Nothing is recorded

Mr. Kamath.

12.25 hrs.

COMMITTEE ON PETITIONS

NINTH REPORT

श्री हरि विष्णु कामत (होशगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से छठी लोकसभा की याचिका समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

HUNDRED AND TWENTY-SECOND REPORT

SHRI ASOKE KRISHNA DUTT (Dum Dum): I beg to present the hundred and twenty-second Report of the Public Accounts Committee on Action Taken by Government on the recommendations contained in their Fifteenth Report on Custom Receipts relating to Ministry of Finance.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

THIRTY-SECOND AND THIRTY-THIRD REPORTS

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I beg to present the following Reports of the Committee on Public Undertakings:—

(1) Thirty-second Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Eighth Report of the Committee on Jute Corporation of India Limited—Government's Unfair Pricing Policy for Raw Jute.

**Not recorded.

(2) Thirty-third Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Third Report of the Committee on Jute Corporattion of India Limited—Jute and Exploitation of Jute Growers.

12.27 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED FOR THE ABOLITION OF CAPITAL PUNISHMENT

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, विश्व के विभिन्न भागों में राजनीतिक हत्या से भारत को चिंतित होना स्वाभाविक है । लोकतंत्र का जीवन विरोध पक्ष है । यदि विरोध पक्ष मर जाए तो लोकतंत्र स्वत: समाप्त हो जाएगा । महात्मा गांधी तथा डा० राम मनोहर लोहिया के अनुसार अच्छे साध्य के लिए उत्तम साधन की आवश्यकता है । जहां सत्ता जनमत पर जबर्दस्ती काबू पाकर कायम की जाती है वहां लोकतंत्र जीवित नहीं रह पाता । लोकतंत्र का आधार विरोध का आदर तथा जीवन के प्रति सम्मान है ।

आज एशिया एवं अफ्रीका के अधिकांश देशों में हत्या की राजनीति तथा अधिनायकवादी प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है । ईरान में शाह ने अपने विरोधियों को अंधाधुंध मरवा डाला और अब इस्लामी गणतंत्र के दावेदार शाह का साथ देने वालों की हत्या करवा रहे हैं । आज भुट्टो की हत्या ने सारे विश्व को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है । विगत 6 अप्रल, 1979 को दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय अपील के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी श्री सोलोमन महालंगू को फांसी दे दी । उनके अलावा और चार व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई । इसके पूर्व भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र से अपील की थी कि वे दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत नेता की जिन्दगी को बचाने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करें ।

राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने भी दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों से अपील की थी कि वे सोलोमन महालंगू को फांसी पर ना लटकायें । समाचार के अनुसार पिछले वर्ष दक्षिण अफ्रीका में 132 व्यक्तियों को फांसी पर लटकाया गया था । इनमें एक श्वेत, 26 मिश्रित नस्ल तथा 105 अफ्रीकी थे ।

इसके पहले नेपाल में दो नेपाली कांग्रेस के नेताओं को फांसी दी गई और इन सारी राजनीतिक हत्याओं का प्रभाव भारत के जनजीवन पर पड़ता है । नेपाली कांग्रेस, भुट्टो तथा दक्षिण अफ्रीका की राजनीतिक हत्या ने भारत के शांतिप्रिय आत्मा को झकझोर दिया है और सब ओर से हत्या के विरोध में प्रदर्शन एवं आवाज उठा रहे हैं । स्वयं भारत में भी कुछ वर्ष पहले यहां के प्रबल विरोध के बावजूद आंध्र के दो नक्सलपंथी किसान नेताओं को फांसी दे दी गई ।

अब पाकिस्तान और बंगलादेश के भीतर से भारत बंगलादेश एवं पाक एकीकरण की मांग जोर पकड़ रही है । भारत सरकार को निश्चित रूप से भारत, पाकिस्तान एवं बंगलादेश के महासंघ की बात चलानी चाहिए ।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि किसी देश के आंतरिक मामले के नाम पर अपनी आत्मा को नहीं बेचना चाहिए । यह चुप्पी भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतिकूल है तथा इससे भारत सरकार की कमजोरी झलकती है । भारत सरकार को अपने देश से फांसी की सजा को समाप्त करना चाहिए तथा विश्व के किसी भी कोने में राजनीति हत्या की जाये तो बिना किसी भेद भाव के उसकी तीव्र भर्त्सना करनी चाहिए ।

MR. SPEAKER: Prof. Mavalankar. Not here. Shri Rajagopal Naidu.

(ii) AMENITIES TO THE WORKERS OF THE STEEL YARD IN MANDI GOVIND GARH, PUNJAB

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Sir, the Steel Yard in Mandi Govind Garh, Punjab is managed by Pujab Small Scale Industries Corporation. It is the consignment agent of the Hindustan Steel Ltd. (SAIL). P.S.S.I.C. took contract from SAIL to load and unload the steel arriving at the Railway Station in Mandi Govind Garh and to give delivery of that steel to the steel rolling mills in that town. This Corporation is getting Rs. 26/- per tonne from the Steel Authority.

This Corporation instead of employing the workers directly engaged a middle-man contractor who is giving only Rs. 6/- per tonne to the workers not only that, he has not provided any facility to the workers as provided in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.

As per that Act, canteens, Rest rooms, first aid facilities, wholesome drinking water, sufficient number of latrines and urinals have to be provided in that establishment. Nothing was arranged in the Steel Yard. Even the drinking water is not provded there.

When the representative of the workers represented to the Union

(Shri P Rajagopal Naidu)

Government about the plight of the workers, the State Government informed the Union Government that all facilities were provided in the Steel Yard which was beyond the truth.

I have visited the place personally and found what the workers were telling was truth I represented the fact to the Minister of Steel and Mines twice but he was not able to do anything to protect the labourers

As per the above Act, the PSSIC which is the consignment agent has to register itself as the principal employer and the middle man contractor has to take the licence They have not done that till now For that contravention, they should have been punished but it was not done or they were not asked to register and to get licence Therefore, the Labour Department is not able to apply labour laws to that Corporation That is why no one was able to protect the workers working under the Corporation

The workers desire that the Small Scale Industries Corporation should cancel the middleman contractor and directly employ the workers or they have to appoint the society of the workers as the contractor

In other steel yards workers are directly employed and they are getting not less than Rs 14/- to Rs 16/- whereas these workers are only getting Rs 6/- which is quite unjust, nothing but exploitation This system is coming in the way of getting fair wages by the workers

I therefore request the Government to compel the Punjab Small Scale Industries Corporation, to register as principal employer and employ workers directly and provide all amenities to the workers as provided in the Act and to pay not less than Rs 15/- per tonne

I hope that the Minister will not yield to political pressures and do justice to the workers.

MR. SPEAKER: Mr Saugata Roy

(iii) REPORTED STRIKE BY THE EMPLOYEES OF INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE, PUSA, NEW DELHI

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore) Sir Under Rule 377, I wish to raise the following matter in the House for the attention of Mr Barnala

"Strike and agitation by the supporting staff of Indian Agricultural Research Institute Pusa

This is to draw the attention of the House to the callous attitude of the Ministry of Agriculture Government of India to the low paid employees of IARI, Pusa Since 5th March 1979 there has been total strike in the Pusa Campus by the 2 600 upporting staff working there Many of them have been on an indefinite hunger strike also Th employees have tried all possible peaceful agitationa methods including holding mass dharna torchlight procession throughout the night in the campus From the last week they started courting arrests before the Krishi Bhawan and already 500 of them have been arrested by the Police The employees have no political affiliation Their demands are

1 Supporting staff to be promoted after every five years' assessment as in the case of Technical staff,

2 The Grade II of the Supporting Staff *viz.* 200-250 to be revised and raised to Rs 210—290,

3 Selection Grade IV of Supporting Staff *viz.* 260—430;

4 Daily wage dismissed employees to be reinstated

I think that the Government should take immediate steps to resolve the legitimate demands and bring back normalcy in the Pusa campus

MR SPEAKER: Prof. Samar Guha.

(iv) REPORTED POWER CRISIS IN WEST BENGAL

PROF. SAMAR GUHA (Contai): The power crisis in West Bengal has created a near catastrophic situation in West Bengal leading to closure of industrial and engineering units, and educational institutions and trade and business markets. The economic and social life of Bengal, as a result of a crisis of unprecedented dimension is almost on the verge of collapse. This crisis will spill over into labour troubles and generate unrest in the State, causing serious law and order stuaton.

The Central Government must intervene immediately to save West Bengal from the impending chaos and extend all assistance for tiding over the crisis.

MR. SPEAKER: I have fixed a Calling Attention on this issue tomorrow.

RE. DISCUSSION ON DEMANDS FOR GRANTS

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): Sir, as the House is aware, rather painfully aware, so far as the Demands discussion is concerned, owing to circumstances mainly or largely beyond our control we are very much behind schedule and as the dreaded doomsday, 23rd April, draws near, there is growing apprehension that more and more Ministries will be laid low by that lethal weapon—the guillotine. I think the ministers concerned will be happy but the House, I am sure, will not be happy. So, I daresay the Ho[illegible] will agree that we must t[illegible]s many Ministries as po[illegible] execution—I mean not mi[illegible]ut Ministries Demands. We have less than forty hours....

MR. SPEAKER: To be exact we have only twenty-five hours and fifteen minutes.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: In that case it is more dangerous. I am sure the House will agree with me, to save as many Ministries as possible, to sit daily till 7 O'clock in the evening and also one Saturday.

MR. SPEAKER: I will put it before the Business Advisory Committee.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: I would, however, like the Minister of Affairs Parliamentary and hard Labour—in a genuine democracy like ours Labour is not a soft portfolio—to give a firm and solemn assurance that the time allocated for the financial business till the passing of the Finance Bill will not be mis-appropriated or encroached upon or intruded into by legislative business.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Sir, on the first part of the hon'ble Member's suggestion you have been pleased to say that you will put it before the Business Advisory Committee. On the second part where he has asked me to give an assurance that no legislative business will be introduced till the Finance Bill is passed, I can say that Government has no intention of appropriating any time that has been allotted for the Demands for Grants. If any inroads are made into this time it will not be by the government.

12.39 hrs

DEMANDS FOR GRANTS, 1979-80—*Contd.*

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION —*contd.*

श्री नाथू सिंह (दौसा) : परसों जब मैं कृषि पर बोल रहा था तो मैंने सिंचाई और बिजली की कमी की चर्चा की थी जिस के अभाव में कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति नहीं हो सकती है और किसान की दशा सुधर नहीं सकती

[श्री नाथ सिंह]

है । मैं उदाहरण देता हू । पूरे देश म जितनी बिजली पैदा होती है उसका केवल साढ चौदह प्रतिशत किसानो को दिया जाता है, कृषि पर खर्च की जाती है और बाकी सारी उद्योगो और शहरो पर खर्च कर दी जाती है । किसानो से रेट भी तीस पैसे की यूनिट चार्ज किया जाता है जबकि टाटा और बिडला की फैक्टरीज को तीन पैसे और पाच पैसे के हिसाब से बिजली दी जाती है । किसानो को क्यो यह महगी दी जाती है, उन्होने कौन सा पाप किया है जिस का खमियाजा उनको भुगतने के लिए मजबूर किया जा रहा है ।

मै राजस्थान मे आता हू । राजस्थान का इलाका हिन्दुस्तान के गलिस्तान पर एक धब्बा है, काला धब्बा है, फोडा है । हिन्दुस्तान को गुलिस्तान कहा जाता है लेकिन उसका जो एक बहुत बडा भाग राजस्थान का रेगिस्तान है उसकी तरफ पिछले तीस साल मे ध्यान नही दिया गया है, वहा न बिजली की और न इरिगेशन की कोई व्यवस्था की गई है । तीसरी लोक सभा मे कामत साहब बैठे हुए है, एक मामला उठाया गया था और उस समय बजट डिवलपमेंट बोड बनाया गया था । उसने आज तक क्या किया है मुझे मालम नही है । उस समय सुब्रह्मण्यम साहब मिनिस्टर थे । तब उन्होने इस सवाल को टाल दिया था । कामत साहब ने इस पर जोर दिया था । उस मे कोई प्रगति नही हुई है । जितना रेगिस्तान उस समय था आज वह और भी ज्यादा बढ गया है । छोटे से देश इजराइल को आप ले । वहा भी भयकर रेगिस्तान था जिस को नैगेव कहा जाता था । उन्होने बडी खबसूरती के साथ उस पर काबू पाया और उसको गुलिस्तान बना कर रख दिया । अब इजराइल मे रेगिस्तान नाम की चीज नही है । दुनिया भर म रेगिस्तान के एक्सपर्ट बहा है । क्या भारत सरकार ने कभी उनको बुलाने की कोशिश की है और उनको हिन्दुस्तान का रेगिस्तान दिखाया है और उन से पूछा है कि किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है । 1965 मे इजराइल के कुछ एक्सपर्ट बधे आए थे और वहा तीन साल तक रुक कर उस इलाके की उन्होने कायापलट कर दी थी । तब से आज तक इजराइल के एक्सपर्ट्स से कभी सम्बन्ध स्थापित नही किया और न ही उनको बुलाया । समय आ गया है कि वहा से विशेषज्ञो को बुला कर उनकी सलाह ले कर राजस्थान के रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाया जाए, उसकी कायापलट की जाए ।

तीस साल तक सरकार कृषि के प्रति उदासीन रही है उसने इसको निगलेक्ट किया है । यह चीज देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है । पचास प्रतिशत आय कृषि से होती है, अस्सी प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है उसके बावजूद सरकार कृषि पर ध्यान नही देती है । परिणाम यह हो रहा है कि कभी महगाई बढती है, कभी कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है । महगाई रोकने के लिए सरकार दूसरे उपाय करती है । किसानों के बारे में बाते बहुत ऊची ऊची की जाती है । यह कहा जाता है कि उन्हें सुविधाये दी जा रही है, फूड फार वर्क उनके लिए चला रहे हैं, गरीब लोगो के लिए चला रहे है, अन्त्योदय योजना चल रही है । काम के बदले अनाज देने की जो योजना आपने चला रखी है इसके अन्दर किसानो और मजदूरो का सडा हुआ अनाज दिया गया है । कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने मे जो अनाज भर कर रख लिया गया था और जो सड़ गया है और जिस को पशु भी नही खाते है, वह उनका दिया जा रहा है । आप इसकी जाच करे और देखे कि कही आपके अधिकारी आपको धोखे मे तो नही रख रहे है । इस योजना के अन्तर्गत जो काम हो रहा है, कच्चा हो रहा है, पाच सौ का काम कराते है तो एक हजार का काम हुआ है, यह दिखा दिया जाता है । जो कच्चा काम करवाया जा रहा है बारिश शुरू होते ही यह साफ हो जाएगा । सडके, रास्ते जो कच्चे बनाए जा रहे है इनको पक्का बनाया जाना चाहिये ।

जहा तक किसानो को लोन देने का सम्बन्ध है केवल ग्यारह प्रतिशत लोन ही बैंको से किसानो को दिया जाता है, कृषि कार्यों के लिए दिया जाता है । किसान का सब्सीडी बहुत कम दी जाती है । अगर कोई इडस्ट्री लगाई जाये तो गवर्नमेंट 75 स 90 परसेंट तक लोन और सब्सीडी देती है, 75 परसेंट लोन दिया जाता है, लेकिन किसान अगर लोन ले तो उसे आसानी से लोन नही मिलता है । आज किसान कृषि का काम मजबूरी म कर रहा है, उसे आपने कृषि के लायक नही छोडा है । अगर कृषि का इडस्ट्री की तरह विकास किया जाये, तो काफी उन्नति हो सकती है । मै जानना चाहता हू कि क्या सरकार ने कभी कोई सर्वेक्षण कराया है कि गावो की दशा कैसे सुधारी जा सकती है ? मेरा निवेदन है कि गाव का इडीपैंडेंट बनाइये । गाव म जट, अनाज, रुई, तेल पैदा होता है, वहा आप छोटी-छोटी इडस्ट्रीज लगाइये । किसानो का सामान खेतो मे उपज और वहा छोटी-छोटी इडस्ट्री हो जिनमे उस कच्चे माल को पक्का माल के रूप मे परिवर्तित कर दिया जाये । उसमे से किसानो की आवश्यकता के अनुसार उनको दिया जाये और बाकी का शहरो मे भेज दिया जाये । अगर आप ऐसा नही करेंगे, तो मै एक उदाहरण देना चाहता हू । भगवान श्रीकृष्ण ने एक मटकी फोड़ आन्दोलन चलाया था और उनका वह आन्दोलन शहरो के विरोध में था । उसका रूप ऐसा था जैसे सत्याग्रह करते है । उनका वह आन्दोलन इसलिये था कि शहर वाले किसानो का शोषण करते है । शहर वाले गाव वालो का घी-दूध मक्खन खरीदते थे, लेकिन गाव वालो को उचित मूल्य नही देते थे । इसीलिए भगवान कृष्ण को मटकी फोड आन्दोलन की जरूरत पडी । इसलिये आज आवश्यकता है कि किसानो की दशा सुधारी जाये, उनका गावो मे इडीपैंडेंट बनाया जाये ।

MR. SPEAKER : Please conclude now

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad) : He is the youngest Member of the House, the baby of the House; so, he may be given some more time.

SHRI C. N. VISVANATHAN (Tiruppattur): And this is the International Year of the Child, he should be given preference.

श्री नाथू सिंह एग्रीकल्चरल एजूकेशन के बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान में केवल एक कृषि विश्वविद्यालय है। वहां राजस्थान में बार-बार फसलों का नुकसान होता है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। राजस्थान में बहुत अकाल पड़ा है, क्या सैंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसी टीम भेजी है कि वह देखे कि इस से वहां कितना नुकसान हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र दौसा में तहसील हैडक्वार्टर में ओले से फसल चौपट हो गयी है, लेकिन आज तक उनको कोई सहायता नहीं मिली। उनसे जो लगान लिया जाता है, राजस्थान सरकार ने केवल उसे आगे के लिये बढ़ा दिया है। क्या आप केन्द्र से कोई इन्तजाम करेंगे कि उनको जो नुकसान हुआ है, उसका कोई मुआवजा उनको मिल सके?

एग्रीकल्चरल एजूकेशन के बारे में एक समिति श्री रन्धावा के नेतृत्व में बनाई गई थी, उसने अपनी 1968 में रिपोर्ट दे दी थी। लेकिन उस रिपोर्ट के बारे में बताया गया कि उसको राज्य सरकारों के पास भेज दिया है। राज्य सरकारें क्या जवाब देंगी? कई राज्य सरकारें तो ऐसी हैं कि सदन में जो कई सवाल पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी कोई जवाब नहीं देतीं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की सरकार हमारे ऊपर है। मैं जानना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के बारे में सरकार की क्या नीति है, और आप कब तक उस रिपोर्ट को प्रकाशित करने जा रहे हैं? इसके बारे में कृषि मंत्री बताने की कृपा करें।

कृषि के काम आने वाले औजारों और जो कृषि पैदा करते हैं उनके बारे में कई बातें कही गई हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आलू का भाव 5 रुपये क्विंटल वहां पर है, मैंने नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस भी दिया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। वहां आलू इतना पड़ा है कि 5 रुपये क्विंटल पर बिक रहा है और यहां दिल्ली के मार्केट में, आप तो शायद लेने नहीं जाते होंगे, डेढ़ रुपये किलो आलू मिल रहा है। वहां कोई खरीदने वाला नहीं है, यह कैसा मजाक किसान के साथ है। मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब कृषि के मामले में सबसे आगे बढ़ा हुआ प्रदेश है और उत्तर प्रदेश सब से बड़ा प्रदेश है। कृषि तथा सिंचाई मंत्री पंजाब के हैं और राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। इसी समय मौका है कि वे किसानों का कुछ भला कर सकते हैं। अगर उन्होंने यह मौका खो दिया, तो मुझे किसानों का भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। वे दोनों कृषि के एक्सपर्ट हैं, योग्य हैं और किसान हैं। इस लिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे किसानों के लिए कुछ करें और उनकी समस्याओं को हल करें।

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): I am very happy to participate in the discussions on the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture. I want to make a few observations for the consideration of the Government.

When the Food Corporation of India was started in Madras in 1965, we expected that it will render good service to the public. But to our disappointment, from that year, our troubles have increased, even though we have produced more. Along with more production by the farmers, more troubles have also been created for the farmers by the policies of the Food Corporation. Even though the previous Government and this Government are sympathetic to the farmers, the officers and their policies are going on as before, as far as rural development is concerned. We were not satisfied even with what was happening during the period of the previous Government. I am not blaming this Government alone. As far as farmers are concerned, the same consideration and treatment are being given in the matter of price fixation and procurement.

As far as Andhra Pradesh is concerned, I have been told that recently 100 telegrams have been sent to the Food Corporation from the Kaikalur taluk in my constituency, which is a Kolleru area, about their not making procurement It is not about the price, even though price also has not been fixed. I have already said that agricultural classes, including agricultural labourers in the rural areas constitute 70 per cent of the people of India. We are pouring on them only slogans and sympathetic words. We are not helping them in any practical way If you see the other countries, you will find that the agricultural communities there are being given all facilities. Whatever our friend has said, is correct. You are procuring the produce from the villages, but you are spending money on industries located in Ghaziabad and Delhi. Because the officers are here, they will try only to give benefits to their children, and not to give benefits to villagers.

I am surprised to see that the banks are giving advances only to mill-

owners and not to the tillers of the soil. For the last 15 years, there is a rule. The Act has not been amended. The Reserve Bank has not been allowed to give a single rupee as produce loan to the farmers. The farmer is not being given a proper price; and the agriculturists are not given other facilities also.

Recently, to my surprise I have found that a circular has been issued by the Ministry of Labour, New Delhi. I asked the Labour Minister about it. He said it was not within his knowledge. It has been said that if rural development goes up, the agricultural labour will be harmed. But agricultural labour will be harmed only by urban people, because you are not paying a proper price for agricultural produce. You are developing industries only in urban areas. That is why I am blaming the officers and the Government. As my friend on the Government side said, the Government has failed, in fixing the sugar cane price, and it has not fixed the responsibility for the losses. Only in the matter of industrial, finished goods, they are taking into account the manufacturing costs while fixing prices.

Go to Korea or Japan; you will find that all the industries are not centralised in cities there, comparable to our Madras, Delhi or Bombay.

12.54 hrs.

[DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*]

Having industries in places like Faridabad is not enough. I want to suggest to the government now or hereafter also, when they are fixing the cost of the finished goods, why they should not consider the price fixation of the products of the rice producer on the basis of the cost of production. Some officers, IAS or IFS who are handling the subject, they are not bothered about agriculture, they are bothered about free education, free transport, free guest houses for their comforts. I have seen the report of the agro-industries corporation which has come today. It shows that every institution lost Rs. 10 lakhs of rupees. People there have manipulated figures; they have manipulated import policy; they keep all the goods which are imported and are not selling them in the market immediately. In the last two months I have brought a case to the notice of the Minister of State in the agriculture ministry and he was kind enough to release the stocks of fertilisers. All high officers are sitting here. Who is responsible for this. In 1975 they imported chemical fertilisers; it is stored in my constituency for the last four years. It is Rs. 1500 only per ton. I think in the black market it is high. 1800—2000 tonnes are in the godown, a private godown. Every month they are paying Rs. 6,000 rent. All the ministers are here. Their departments are having people like this. In six years they have sold only 300 tonnes. When they were approached by the house owner, the godown keeper to vacate the godown they say: you must bear all the cost because it is not transportable, all the bags should be rebagged, and transport it at your cost. Even if the ministry ordered it, for two months it is only correspondence. But four days back I was told that at the cost of the building owner they have moved the stocks to some extent—about 200 tonnes. Is this the way? There is demand for good fertilisers, imported fertilisers. There is demand in my district which has the highest production and highest consumption also in Andhra Pradesh just like Punjab and Haryana. On the other hand, the entire agricultural community, is not satisfied about the government. Even both the Ministers have given so many assurances and both are coming from the agricultural community, we are not satisfied. What is the use of being a minister. We want benefits for their labour and material benefits from you to the agriculturists. Agriculture means what? After all the land reforms and all these things, still they say in their offices, officers drawing 10,000 and 5,000 that who are having 10 acres or 15 acres are called Kulaks, we are not for the kulaks. We are for the people who are without any earning capacity other than agriculture. We are not taking any contract from you to pro-

duce more paddy; we are producing without any contract. But in industry, only 10 or 15 per cent will be collected as share capital. About 80 per cent of the money they are borrowing from the Government. By the time they finish the construction, they are having 20 per cent back in other ways. But what about agricultural labourers? Unless agricultural labour also prospers the country cannot prosper. Please let me know. In the villages how many are without food? There are so many beggars in the cities, without food, round about your secretariat or office. Is there one man in the village like that? That is heriditary socialism or communism. We are feeding the country; we are producing without any hesitation. We, the farmers, are making so much sacrifice. Now this circular from Labour Ministry has been issued which creates a conflict between the agriculturists and agricultural labourers. They want to create an impression as if they are only for agricultural labourers.

13 hrs.

I have got reports here to show how prices are being maintained here and in other countries. In a small country like Korea, in 1970 the income of an agricultural family was 747 dollars per year as against $ 1112 dollars which was the income of a family of workers in the urban area. Within eight years, gradually the income of agricultural families has gone up and now they are getting $ 2876 dollars per year whereas a family of workers in the urban area gets an income of only 2379 dollars per year. In South Korea, in 1970 the price of 80 kg of rice was 7000 Wons. Gradually year by year it was increased without causing hardship to the consumers, whose purchasing capacity also has been gradually going up and in 1977, the price of 80 kg of rice was 26,260 Wons. They have brought the income of agricultural families to the same level as that of families in urban areas. No such thing has been done in our country.

The Food Corporation is a complete failure so far as Andhra Pradesh is concerned. Even the Chief Minister, of Andhra Pradesh, Dr. Chenna Reddy has blamed the Food Corporation. In my district of West Godavari alone, there is a surplus of 3.37 lakh tonnes of rabi crop lying with the farmers. The farmers are not allowed to get loans on their produce. Only the traders and millers are given loans. They are taking advantage of this to purchase the crops from the farmers at low prices. The farmers do not have even money to pay land tax. So, the rules should be amended to enable the farmers to get loans on their produce.

So far as sugar factories are concerned, some factories are making huge profits while others are suffering. Last time also I raised it. I had given a memorandum to Mr. Charan Singh, the then Home Minister, now Finance Minister, to appoint a Commission to enquire into the sugar industry. He told me that he had appointed so many commissions for which he was being blamed, so he wanted to forward my complaint to the Minister of Agriculture. But nobody is prepared to enquire. If there is some enquiry, I am prepared to give evidence. Even if you nationalise sugar industry completely, I have no objection. The Government is giving crores of rupees as loans to the sick mills. Whose money are you giving? You have duped the people. There are so many sugar factories running at losses. In the case of my own cooperative sugar factory at Bhimadole, the managing director is the Collector. The factory has incurred a total loss of Rs. 2 crores and not a pie of dividend has been declared for five seasons. We have paid Rs. 3 crores of excise duty in five seasons to the Government of India. It is not our fault. This year the farmer is not going to grow more sugarcane. The area under cultivation is going to be reduced. As a result, 100 factories would be closed in the country. Please look into the matter immediately and do something constructive.

[श्री मुख्तियार सिंह मलिक]

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (सोनीपत) : मैडम चेयरमैन, आज कृषि विभाग की मांग हमारे सामने जेरे-बहस है। इस में कोई शक नहीं कि किसी भी देश की जिन्दगी और सेहत के लिये कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कृषि के साथ जो सुलूक हो रहा है, वह कुछ ना-जेबा है। इन मांगों का हमें समर्थन तो करना ही है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो दो मिनिस्टर इस काम को देख रहे हैं उन का कृषि से ताल्लुक रहा है, व खुद किसान हैं, इस लिये किसान की जो समस्यायें हैं, उन से वे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन उन की भी कुछ मजबूरियां हैं, लाचारी है। वे करना तो बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते और एक दफा इसी हाउस में हमारे भानु प्रताप सिंह जी ने साफ अलफाज में कहा भी था—इस के बारे में मेरे व्यूज स्पष्ट हैं, लेकिन मेरी मजबूरियां भी इस के साथ हैं।

मैडम, 7–8 रोज की बात है। किसी सवाल के जवाब में हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने किसी मेम्बर को कहा था—अगर आप मेरी जगह यहां पर होते, तो आप को भी ऐसा ही जवाब देना पड़ता। अफसोस यह है कि उस कुर्सी पर कोई भी बैठ जाये, चाहे कोई किसान बैठ जाय या कोई दूसरा आदमी बैठ जाय—उस का वही जवाब आयेगा। पिछले 30 सालों में हम ने पिछले कांग्रेस हुकूमत के अमालो-कमाल को कृषि के बारे में देखा और अब अपनी जनता पार्टी के अन्दाज को भी देख रहे हैं, मुझे तो कोई नुमायां फर्क मालूम नहीं दिया। हमारी हुकूमत कहती है कि हम को एक सब से बड़ा श्रेय यह है कि हम ने देश में एमर्जेन्सी का खात्मा कराया—यह बात ठीक है, लेकिन मैं अपने वजरा सहाबान से पूछना चाहता हूं—किसान के ऊपर तो आज भी एमर्जेन्सी लगी हुई है, आज उस की क्या हालत हो गई है, उस के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है? यहां पर कुछ वेस्टेड इन्टरेस्टस हैं—मुझे बड़ा अफसोस होता है—जब कृषि के बारे में यहां पर बोलते हैं चाहे वे किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हों, यही कहेंगे कि हमें किसानों का भला करना चाहिये, लेकिन जब किसानों को कोई सहूलियत देने की बात आती है, तो वे उस का विरोध करते हैं। एक तरफ कहेंगे कि रिम्युनरेटिव प्राइस दी जाय, लेकिन जब रिम्युनरेटिव प्राइस देने का वक्त आता है तो सब खड़े हो कर कहते हैं कि सब मारे जायेंगे। महंगाई हो जाएगी और इस से लो इन्कम ग्रुप वाले मिडिल इन्कम ग्रुप वाले और कन्जूमर सारे के सारे मर जाएंगे। इस किस्म की बातें हाऊस के अन्दर करने लगेंगे। अगर किसानों को ज्यादा कीमत दी जाएगी, तो ये सब मर जाएंगे लेकिन हम ने देखा है कि आज तक तो कोई मरा नहीं। अफसोस की बात यह है कि कोई मरता नहीं लेकिन उन की लोबी जो है वह बहुत मजबूत है और किसान की लाबी जो है वह बटी हुई है। इन्डस्ट्रियलिस्टस के सहारे स्पोक्समैन ऊपर से कुछ बोलते हैं और होता कुछ और है, बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात है। किसानों के बारे में इस किस्म की बातें करते हैं। कभी कभी यह भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है, उस पर देश की एकानामी, देश की खुशहाली निर्भर है और साथ में यह भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर एक इन्डस्ट्री है लेकिन हमारे वजरा साहबान जरा इस तरफ तवज्जह दें कि इन्डस्ट्री को जहां इतना प्रोटेक्शन मिल रहा है, वहां एग्रीकल्चर को क्या मिलता है। पावर के चार्जेज इन्डस्ट्रीज के लिए हरियाणा और पंजाब में बहुत सीरियस हैं। वहां पर 5 पैसे प्रति यूनिट बिजली इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को, कारखानदारों को मिलती है जबकि किसानों को 31 पैसे प्रति यूनिट दी जाती है। यह हालत आज है। इतने सीरियस चार्जेज इन्डस्ट्री वालों के लिए और इतने हाई चार्जेज किसानों के लिए हैं। इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के लिए इन्श्योरेंस भी होता है और किसानों के लिए क्या होता है। इन्डस्ट्रियलिस्टस को हर तरह का प्रोटेक्शन दिया

What about the kisan? He is entirely left at the mercy of the politician, at the mercy of the middlemen, at the mercy of thieves, at the mercy of pests, at the mercy of hailstorms, floods, droughts, animals, birds. He has to face lack of storage facilities, lack of transportation, so many things

जाता है। किसान के दुश्मन ही दुश्मन खड़े हुए हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों ओले गिरने लगे और पिछली बरसात के अन्दर यू०पी०, बंगाल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और देहली आदि जगहों पर फ्लड्स में सारी फसल बर्बाद हो गई। अभी जो ओले गिरे उस का असर हरियाणा दिल्ली और यू०पी० के अन्दर हुआ और शायद पंजाब के अन्दर भी उस का असर हुआ। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस किसान की दोनों फसलें, रबी की फसल और खरीफ की फसल खराब हो जाए, तो क्या वह जिन्दा रहेगा। कोई सवाल उस के जिन्दा रहने का पैदा नहीं होता। तो आज किसान की यह हालत है। वह जिन्दा रहता है और अनाज की कमी तो वह बर्दाश्त कर लेता है लेकिन चारे की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चारा न हो, तो किसान की तबाही ही तबाही है। इस के साथ ही दो तीन दिन से आलुओं का जिक्र किया जा रहा है। नाथू सिंह जी ने बताया कि राजस्थान में आलू 5 रुपये क्वीटल है और कपास का क्या भाव है। इस के लिए लोग नारे लगाते थे, पिछले कपास के सीजन में हरियाणा के अन्दर सरसे में मैं ने सुना कि लोग यह नारा लगाते थे 'देखा जनता राज का ठाठ, नरमा बिकता 260'। पहले कपास का दाम 400, 500 रुपये था और अब 260 रुपये हो गया। जनता पार्टी के राज में नरमा का यह भाव हो गया और फिर भी कपड़े के भाव को आप देखिये। गन्ने का पिछले साल क्या हाल हुआ। यू०पी० के अन्दर उस को

जलाना पडा और हरियाणा के अन्दर भी बरी हालत हुई। गन्ने का क्या दाम किसान का मिला और आज क्या हालात आलू की है, प्याज की है। जिस चीज की तरफ भी देखो, किसान की मदद किसी वक्त पर हुकूमत करने आई। गन्ना कपास आदि जो किसान पैदा करता है उन सब की कीमते इतना नीचे चली गई लेकिन किसान की मदद किसी ने नही की। मुझे एक शेर याद आता है :

कश्ती तूफान में डूब गई मगर किसी ने मदद न की
अल्लाह भी था मल्लाह भी था लगर को सहारा मिल न सका।

हकूमत भी थी हमारे वजीर साहिबान भी बैठे हुए थे, जनता पार्टी भी यहा पर थी इडस्ट्रियलिस्ट्स भी थे इनके नुमाइदे भी यहा पर थे लेकिन किसान जो आलू, गन्ने, कपास, प्याज आदि की कीमतो की गिरावट की वजह से तबाह होता चला जा रहा था तो किसी ने मदद नही की कोई उसको सहारा देने के लिए नही आया। मै चाहता हू कि आप जा कर किसान की हालत को तब देखे जब वह खेत मे काम कर रहा होता है। एक दिन एक शहरी आदमी जब मैं खाना कर रहा था तो मेरे खेत मे आ गया। मेरी हालत को देख कर वह मजाक मे कहने लग गया कि अगर किसान न होता तो शायद खेती इसान को करनी पडती। मै सभा महोदय से पूछना चाहता हू कि इस किसान को सजा किस चीज की दी जा रही है। बडे फख के साथ हाउस में कहा जाता है, हिन्दुस्तान मे ऐलान किया जाता है कि हमने इतना अनाज पैदा कर दिया है और इतना अनाज पैदा हो जाएगा। किसान का खून पसीना निकल चुका है वह सारा जोर लगा रहा है अनाज पैदा करने के लिए यह सब इसलिए कर रहा है ताकि आपका खिला सके। अगर आप उसको कुछ सहूलियतें दे तो शायद वह एक्सपोर्ट करके भी आपको दिखा दे और बहुत जल्दी दिखा दे। आप आलू का एक्सपोर्ट क्यो नही करते है। श्री माहन धारिया ने एक दिन कहा था कि पच्चीस हजार क्विंटल हम एक्सपोर्ट करेगे। उसी दिन मैंने कहा था कि इससे क्या होगा? आलू की फसल इतनी ज्यादा होने वाली है आप ज्यादा क्यो नही करते है। लेकिन कोई ध्यान नही दिया जाता है। मै पूछता हू कि किस चीज की सजा किसान को आप दे रहे है।

नहर के किनारे तीन मैंढक बैठे हुए थे, एक के ऊपर एक। सब से ऊपर वाला मैंढक जो था उसने आवाज दी टर्रमटर। इस पर खुशी के साथ दूसरे ने कहा जो उसके नीचे बैठा हुआ था दबा बैठा था, खुशी न गम। सब से ऊपर इडस्ट्रियलिस्ट था और उसके नीचे हकूमत थी। हकूमत ने कहा खुशी न गम। हकमत ने कहा कि मेरे नीचे भी तो एक दबा बैठा है और वह किसान था। इस पर तीसरे ने कहा मर वे हया। ऊपर वाला इडस्ट्रियलिस्ट, बीच वाली हकूमत और तीसरे किसान। किसान सब से नीचे था और सब का बोझ किसान के ऊपर था। यही हालत आज किसान की है। किसान को सभी दबाए बैठे है। यह नक्टो वाली बात हो जाती है। बजट मे किसान को क्या मिला है? पाच रुपये यूरिया के अन्दर कम हुए है, डीजल के अन्दर कुछ कम किया गया है। बाकी चीजो पर जो टैक्स बढा दिए गए है क्या उसका सारा बोझ किसान पर नही पडेगा? यहा पर इडस्ट्रियलिस्ट्स की लाबी बनी हुई है। यह तो नक्टे और लम्बी नाक वालो की बात है। जिस की छोटी नाक होती है उसके ऊपर यह नक्टे एतराज करते है। दूसरा को कहते है नाक आए नाक आए। इडस्ट्रियलिस्टस की जो लाबी है इसने कहना शुरू कर दिया मर गए मर गए, सारा बोझ मिडलमैन के ऊपर आ कर पड गया। जब से मैने जन्म लिया है या मियायत मे 45 साल पहले से आया हू मुझे यह पता नही चल सका है कि एम्पलायीज की जो डिमाडज है क्या ये कभी खत्म होगी भी या नही? टीचर्स की आज तक खत्म नही हुई, रेहडीवालो की नही हुई ड्राइवज की, डेसू वालो की खत्म नही हुई। एक के बाद दूसरी निकलती चली आती है, एक को मान लिया जाता है तो दूसरे साल चार और निकल आती है उनको खडा कर दिया जाता है। लेकिन किसान को एक ही डिमाड है, आप कम से कम या तो उसकी बेहतरी के लिये उसे प्रोटेक्शन दे उसकी फसल तबाह हो जाती है, ओले पड जाते है पानी की कमी की वजह से, बरसात की वजह से नुकसान हो जाता है, उसको कितने दिनो से यह डिमाड चली आ रही है कि उसकी फसल का इश्योरेंस किया जाये। आपने उसकी फसल का इश्योरेंस करने का कोई इतजाम नही किया है। यह सरकार जिन्दा को तो चिपके हुए है लेकिन अगर किसान मर जाये तो भी उसके पीछे लग जाती है। उस पर ऐस्टेट डयूटी और वैल्थ टैक्स लगा दिया। एक तरफ तो किसान की जमीन को एक्वायर करने है और दूसरी तरफ जब मर जाता है तो ऐस्टेट डयूटी के लिये यम के दूत और उसके घर पहुच जाते है कि उसकी जायदाद की कीमत क्या थी। यह एस्टेट डयूटी के लिये मरे हुए आदमी को भी चिपटना चाहते है। मै यह भी बताना चाहता हू कि हिन्दुस्तान के किसान के जिस्म पर आज कपडा नही है, सिर्फ एक लगोट उसके जिस्म पर है और ये वेस्टेड इटरेस्ट के लोग इडस्ट्रियलिस्टस उस किसान के लगोट पर भी चिपटे हुए है। अगर यह लगोट टूट गया तो फिर वह क्या करेगे? मुझे गोल्ड स्मिथ की "दी डैजर्टेड विलेज" पोयम का कुछ लाइनें याद आती है, जो कि इस तरह :—

"Princes and Lords may flourish or may fade, A breath can make them as a breath has made; But a bold peasantry, their country's pride, when once destroyed can never be supplied"

[श्री मुख्तियार सिंह मलिक]

मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस किसान ने हिन्दुस्तान में आज अपना सिर ऊंचा किया, आपका हजारों, करोड़ों रुपये का अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था, उसने बचाया जिसके कारण आज आप दूसरे मुल्कों के सामने फख्र के साथ अपना सिर ऊंचा कर के खड़े हो सकते हैं, वर्ल्ड कम्युनिटी में यह कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान आज अनाज के बारे में आत्मनिर्भर है, उस किसान के साथ इस किस्म का सलूक आप न करें।

मैं श्री बरनाला साहब से नम्र निवेदन करना चाहता हूं, मेरा उनमें बहुत अन्ध विश्वास है, मैं जानता हूं कि वह बहुत काबिल हैं, कि वह एग्रीकल्चरल पालिसी, कृषि नीति निर्धारित करने के लिये कृषि का इसके साथ योग करें। आप स्कैंडेनेवियन कंट्रीज, आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में जायें, वहां एग्रीकल्चरल पालिसी किसान की कंसलटेशन से की जाती है, बल्कि किसान उसे डौमिनेट करता है। लेकिन हिन्दुस्तान में किसान के साथ क्या सलूक किया जाता है कि उसको पूछा तक नहीं जाता। किसान के नुमाइन्दे क्या हैं, उनका भेड़ बकरी की तरह ट्रीट करते हैं। नीति निर्धारित करते समय उन लोगों का योग करते हैं जो ठंडे कमरों में बैठकर, शिमले में या कहीं और बैठकर किसान की कृषि पालिसी का निर्धारित करते हैं। इससे काम नहीं चलेगा।

SHRI PALAS BARMAN (Balurghat) : The Janata Government, particularly its Deputy Prime Minister and Finance Minister seems to be very much concerned regarding improving the lot of the rural people In a country where about three-fourths of the population live in the countryside, this is as it should be. The question, however, is who are these rural people, for whom the Janata Government or its Finance Minister is really concerned? What has been the lot of the rural poor—the landless and the poor peasants—the vast army of landless agricultural labour—during the two full years of Janata Rule? How many landless peasants have been given land during this period, what has been done to ensure even the fixed minimum wages to agricultural labourers, what has been done to eradicate the bonded labour system from the face of rural India? It is by this criteria that the concern of any government for the rural poor would be judged and not by parrot-like repetition of concern for the rural people.

The performance of the Agriculture Ministry would be judged not merely on the basis of increase in the agricultural production of the country. It is no doubt an important aspect of its job. However, no less important is the condition in which the production takes place Under what condition the vast majority of the rural people are engaged in agricultural production? The poor peasants having a small plot of land are unable to take advantage of the improved methods of cultivation because they have no resources The major portion of peasants in our country are in this category Though they form a large percentage of land-holding population, the land area occupied by them is a small portion of total cultivable land The largest section of the rural population is, however, without any land of their own They till the land of others Needless to say, they work in the land not of the poor peasant but of the big peasants These are the new aristocrats More often than not they have made nonsense of land ceiling laws and have managed to corner large area of agricultural land by means fair or foul It is they who get maximum benefit of improved agricultural inputs It is for them that Choudhary Charan Singh's budget is liberal it is common knowledge that it is this section of the rural people who have thrived most after the abolition of landlordism It is they who now lord over the country poor and keep them in abject poverty

The Agriculture Minister fails to hold out any hope of a change in this picture and to uphold the interest of the village poor. Have any active steps been taken by him to ensure that surplus land is recovered and distributed among the poor and landless peasants? Even the work of distribution of the existing surplus land has made little headway in most of the States. The Prime Minister's home State which receives more than a fair share of the Prime Minister's

time, is reported not to have distributed any surplus land during these two years of Janata rule. How is it that the Prime Minister with his high moral stature would not make his own Party government move in this matter?

Our country has no dearth of persons who roll in wealth. If our agricultural produces fatten only a small portion of the rural people it cannot be said to have improved the face of rural India The Janata Government seems to be committed to the service of the few rich—whether in the industry or in trade or in agriculture resulting in more and more impoverishment of the common man Unemployment is rampant in villages but, as most of them are illiterates, their unemployment or under-employment seems to go unnoticed The food-for-work programme has been much eulogised but it is no employment programme but a simple variation of test relief. At the end of two years of ten-year deadline set by the Prime Minister for the end of unemployment, more persons stand unemployed.

The village people require today not lip sympathy but concrete measures for their uplift. That would require certain drastic steps The entire agricultural land should be redistributed among those who are actual tillers of the soil. Capitalistic mode of production should be banished from the agricultural field Viable land units should be given to actual tillers of the soil. Cooperative system may be introduced to allow for large scale peasant cooperative forming with improved inputs. Agricultural people who won't be provided with land, should be provided with jobs in agro-industries and cottage and small-scale industries. The setting up of agro-industries and small and cottage industries in countryside should not end in mere talks, of which there have been no dearth. People now want them to materialise. There is no other way to change the face of rural India. As one coming from the village, I can say that the government will be judged by what it does for improving the lot of millions of rural people. I may warn the government that they cannot be fed on mere words much longer. Time is fast running out. If even now, the Government does not change its ways, the people would not take their acute exploitation lying down any longer.

श्री तेज प्रताप सिंह (हमीरपुर) आप को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ने मेरा नाम पुकारा। मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है, तेज बहादुर सिंह नहीं।

मैं बरनाला जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय ने अभूतपूर्व तरक्की की है और इसकी हमें आशा भी थी क्योंकि जनता राज में देहात की ओर और किसानों की ओर यदि ध्यान नहीं जाएगा तो किस की ओर जाएगा? 70–80 प्रतिशत नागरिक हमारे देहातों में रहने वाले हैं और 70–75 प्रतिशत के बीच में जो किसानी का काम करने हैं उन की बहबूदी के लिए अगर काम नहीं किया जाएगा तो हमारे देश की कोई तरक्की नहीं हो सकती है उस की फाउंडेशन मजबूत नहीं हो सकती है। आप कुछ आंकड़ों को देखें—77–78 में 125 6 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ जो कभी नहीं हुआ था। तो इसका श्रेय बरनाला जी को और जनता पार्टी की सरकार को मिलना चाहिए। 77–78 में. (व्यवधान)

सभापति महोदय आप कृपया किसी की तरफ ध्यान न दें, अपनी स्पीच चालू रखें, दस दस मिनट में दे रही हूं।

श्री तेज प्रताप सिंह देखिए उन को बीस बीस मिनट दिया है। बुन्देलखंड के साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय जब सभी लोग इस तरह बीस मिनट लेंगे तो फिर बाकी लोग रह जाएंगे।

श्री तेज प्रताप सिंह : अभी मैं बताऊंगा कि बुन्देलखंड कितना उपेक्षित है। उस की ओर आप नजर रखें। आप भी वहीं से लोक सभा की सदस्या हैं।

77–78 में 2.6 मिलियन हेक्टेयर्स में सिंचाई अतिरिक्त बढ़ी जो पिछले दस वर्षों में 1.5 मिलियन हेक्टेयर के औसत से आगे कभी नहीं बढ़ी। यह कमाल देखिए। अगले वर्ष 79–80 में 3 2 मिलियन हेक्टेयर होने जा रही है। इस से साबित होता है कि बहुत कटिबद्ध हैं और कमर कस कर हमारे कृषि मंत्री जी और हमारी सरकार कृषि की तरक्की के लिए लगी

[श्री तेज प्रताप सिंह]

हुई है। आप ऐसा न समझें कि मैं कोई अतिशयोक्ति कर रहा हूं। जो औसत हमारी पैदावार बढ़ रही है, औसत अतिरिक्त जो सिंचाई के साधन मुहैया किए जा रहे है इस के लिए वे बधाई के पात्र है। इसी तरह फर्टिलाइजर में हुआ है। बिना फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किए हुए हमारे देश की कृषि उन्नति नहीं कर सकती है, पैदावार नहीं बढ़ सकती है। उस में भी आप देखेंगे कि 43 लाख टन का इस्तेमाल 77-78 में हुआ है। यह करीब करीब 26 प्रतिशत बढोतरी है पिछले वर्ष के मुकाबिले में। तो मैं बधाई देना चाहता हूं और यह सही है कि वह पंजाब से आते है, पंजाब पर हमे नाज है, पंजाब पर कई माने मे हमारे देश के लोग नाज कर सकते है, लेकिन बरनाला जी जरा ध्यान देने की कृपा करे वे पंजाब से आए है हमारा नतृत्व कर रहे है और इस पोर्टफोलियो को सभाल रहे है यह हमारे लिए फख्र की बात है। लेकिन एक शिकायत हम को है बरनाला जी से कि पंजाब को तो उन्होने देखा और पंजाब की तरक्की को वह जानते है, हर चीज से अवगत हैं लेकिन देश के और किसी कोने में वह नहीं जाते है। कभी कभार जाते हो तो जाते हो। मैं मंत्री महोदय का ध्यान बुन्देलखंड की ओर खीचना चाहता हूं जहा पर उन्होने कृषि की तरक्की के लिए एक घास का फाम खोल रखा है। भारत सरकार ने खाद्यान्न को तरक्की के लिए वहा पर एक घास के फाम के अलावा और कोई फाम नही खोल रखा है जबकि वहा पर केवल घास ही नही होता है। वहा पर अन्न पैदा भी होता है सरप्लस अन्न पैदा होता है। वहा पर ऐसी ऐसी चीज पैदा होती है जिनके लिए रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है जैसे कि अलसी हैं। तो वहा पर इसके लिए आप क्या कर रहे है।

बुन्देलखंड मे सिचाई के साधनो की ओर कोई भी ध्यान नही दिया जा रहा है। जब तक वहा पर हाई ईल्डिंग वेरायटीज का इस्तेमाल नही होगा और सिचाई के साधन नही बढाये जायेगे तब तक कृषि की तरक्की नही की जा सकती है। इस देश का टोटल कल्टिवेटड एरिया का 25-30 प्रतिशत सिंचित है जबकि बुन्देलखंड मे केवल 10 प्रतिशत एरिया ही सिंचित है। अभी मैं वहां पर गया तो लोग कह रहे थे कि सेन्ट्रल आर्गेनाइजेशन, वाटर बोर्ड से एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल लगाए जा रहे है। हम लोगो को कुछ पता नही कि कौन आता है और क्या प्रोग्राम है। इसलिए ऐसे आदेश दिये जाने चाहिए कि कम से कम जो जनता के प्रतिनिधि है उनको पहले से अवगत कराया जाना चाहिए और अगर कोई अधिकारी अपना यह सूचना देने का फर्ज अदा नही करते है तो उनको सजा मिलनी चाहिये। तो अभी तीन-चार दिन हुए, मैं वहा पर गया था, हमारे पास सभापति यादवजी आए और कहा कि बिगहना ग्राम में एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल की ड्रिलिंग हुई है। उनको कुछ पता नही था कि उसका कितना डिसचार्ज है कितना नही है। मैं ने असिस्टेंट इंजीनियर को बुलाया जोकि उसी गांव में थे तो उन्होंने कहा कि इस ट्यूबवेल को इसलिए फेल कर रहे हैं कि उसका केवल 15 हजार गैलन प्रति घंटे का डिसचार्ज है जबकि सरकार का नार्म यह है कि 30 हजार गैलन प्रति घंटा का डिसचार्ज हो तभी उसको सरकार टेक-ओवर करेगी। लेकिन बुन्देलखंड ऐसा एरिया है जहां पर पानी की निकासी कम ही होगी। इस सम्बन्ध में मैंने लिखित रूप में भी प्रार्थना की है और प्रस्ताव भी पास करके भेजा है कि 30 हजार गैलन प्रति घंटे के डिसचार्ज का जो नार्म है उसको घटा करके बुन्देलखंड के इलाके के लिए 10 हजार गैलन प्रति घंटा रखा जाए। इसके द्वारा वहा पर 100-150 एकड़ भूमि की सिंचाई तो हो सकती है। हमारे यादव जी बता रहे थे कि उस ट्यूबवेल मे पानी खूब निकला है, हा उनको यह बात मालूम नही थी 30 हजार गैलन का डिसचार्ज है या नही। इसलिए मेरा सुझाव है कि बुन्देलखण्ड के लिए दो बाते विशेष रूप से की जानी चाहिए। बुन्देलखण्ड के 10-15 जिले है। वहा पर ट्यूबवेल के लिए 10 हजार गैलन का नार्म निश्चित किया जाना चाहिए। दूसरे जो वहा का पहाडी इलाका है, पथरीला इलाका है वहा पर आपको स्पेशल रिग्ज भेजने चाहिए जोकि पत्थर को भी काट सकें। मध्य प्रदेश मे बुन्देलखण्ड के इलाके में कुछ ऐसा काम हुआ है और वहा पर 10-15 हजार गैलन तक पानी निकल आता है जिससे सैकड़ो एकड़ जमीन पर सिचाई होती है तथा हाई ईल्डिंग वेरायटीज बोई जाती है। तो सिचाई के सम्बन्ध मे मेरे यह दो सुझाव है।

दूसरा निवेदन मुझे यह करना है कि जबतक संस्थाओं के द्वारा, सहकारी समितियो के द्वारा ऋण नही बांटा जायगा तब तक किसान तरक्की नही करेगा। आपने 1977-78 में 2360 करोड़ बांटा है जिसमे मध्यकालीन और दीर्घकालीन 780 करोड़ है। मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की बड़ी आवश्यकता है। आप जितना सालाना अल्पकालीन ऋण देते है उसके अलावा इसको और बढाना चाहिये।

जहा तक नार्थ ईस्टर्न रीजन का सवाल है, मैं अभी जनवरी में गया था मनीपुर देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। वहां पर आप डेम बना रहे है जिससे एलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होगी लेकिन खेत सूखे दिखाई दे रहे थे। आप वहा पर सिचाई के साधन भी बनावें। नागालैंड और मिजोरम मे रेवेन्यू रिकार्ड नही रखे जाते है। वहा लेखपाल भी नही है। वहा के मुख्य मंत्री से जब हम मिलने के लिये गये तो हम को बताया गया कि वहां पर लैंड-रिकार्डस भी नही रखे जाते, क्योंकि सारी जमीन सामूहिक है कम्युनिटी लैंड है। इस में कोई शक नही कि यह बहुत अच्छी व्यवस्था है वे अपने आप उस जमीन को आपस मे वितरित कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उन को उस जमीन पर ऋण नही मिलता है। मैं आप से यह अनुरोध करूंगा —नार्थ ईस्टर्न रिजन में जहा व्यक्तिगत टेनेन्सी की व्यवस्था नही है, उन के लिये ऋण की व्यवस्था कीजिये, वरना वह एरिया पीछे पड जाएगा, उस की तरक्की नही हो सकेगी।

अब मैं तिलहन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं—इस में सन्देह नही कि हमारे मंत्री जी उस तरफ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हजारों करोड़ रुपया हमारे देश से बाहर चला जाय और हम विदेशो से तेल का आयात करें —यह बडे शर्म की बात है। हमारे यहां पेस्टस

ज्यादा लगता है—हम देख रहे हैं पिछले तीन सालों से सरसों और लाही नहीं हो रही है, क्योंकि उस में "माहू" लग जाता है। इस के बारे में रिसर्च होनी चाहिये ताकि हम इस से छुटकारा पा सकें।

आप पांच सालों में 17 मिलियन हैक्टेयर में एडीशनल-इर्रिगेशन-फैसिलिटीज देने जा रहे हैं। लेकिन जब 90 या 100 मिलियन हैक्टेयर भूमि आप के पास असिंचित है तो आप को 10 सालों में हर खेत के लिये पानी देने की योजना बनानी चाहिये, 17 मिलियन हैक्टेयर में पानी पहुंचाने से काम चलने वाला नहीं है। आप इस के लिये कहीं से भी लोन लीजिये, वर्ल्ड बैंक से लीजिये—लेकिन 10 सालों में सारी भूमि को सिंचित कर सकें—ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। आने-वाले सालों में 125 मिलियन टन अनाज पैदा करने का आप का लक्ष्य है—मैं समझता हूं यह पर्याप्त नहीं है, आप का लक्ष्य 500 से 600 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा करने का होना चाहिये। इस तरह से जहां हमारे किसान तरक्कीशुदा होंगे, वहां हर गांव में 30 परसेन्ट लैंड-लेस लेबर है—उन को भी लाभ पहुंचेगा। मैंने आप की रिपोर्ट को पढ़ा है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है, उस की प्रशंसा की जानी चाहिये, लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें लैंड-रिफार्म्ज के बारे में बहुत ही काम्प्लेसेन्ट व्यू लिया है, यह अच्छी बात नहीं है। मैं हर गांव में जाता हूं वहां के किसान, हरिजन मुझ से अलग से आ कर मिलते हैं। 10 साल से दो-ढाई एकड़ के पट्टे दिये हुए हैं, लेकिन आधा एकड़ पर भी कब्जा करने को नहीं मिला—यह दुर्व्यवस्था है। आप कहते हैं कि 6.48 लाख हैक्टेयर भूमि वितरित कर दी है, यह कागज पर वितरित हुई है, लेकिन उन का कब्जा नहीं मिला है। आप ऐसा कानून बनाइये—जो डी० एम० या तहसीलदार उन को कब्जा न दिला सके, उन को जमीन की बाउण्ड्रीज न बता सके, उस का सस्पेण्ड किया जाए, उन को सजा दी जाए। जब तक आप इतनी सख्ती से काम नहीं लेंगे, यह काम नहीं चलेगा।

आखिर में मैं एक बात फूड कारपोरेशन के बारे में कहना चाहता हूं। हमारा हजारों करोड़ रुपया इस में लगा हुआ है, यह भी सही है कि हम को सब्सीडाइज्ड रेट्स पर गल्ला मिले—लेकिन यह बात भी सही है कि हजारों टन गल्ला गायब हो जाता है, चुपचाप बिक जाता है और पता भी नहीं चलता। इस में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस की तरफ आप का ध्यान जाना चाहिये। वहां पर जो मजदूर काम करते हैं—एक साल हुआ उन के सम्मेलन में बरनाला साहब गये थे, उन से निवेदन किया गया था कि वहां पर जो बिचौलिये हैं, ठेकेदार हैं, उन को एलिमिनेट कीजिये—लेकिन अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला। एक बांध टूट गया था, मैंने वहां देखा कि ठेकेदार मजदूरों को 3 रुपया दे रहा था, लेकिन कागज पर 5 रुपये के लिये दस्तखत करा रहा था। इस तरह से ये ठेकेदार लूट करते हैं। पिछले तीस सालों में हमारा जितना रुपया इन कामों पर खर्च हुआ है, यदि ठेकेदार बीच में न लूटते तो आधा रुपया खर्च कर के हम उन कामों को करा सकते थे। इस लिये यह प्रथा समाप्त होनी चाहिये।

आप की रिपोर्ट में एक चीज की तरफ ध्यान दिलाया गया है कि जब गल्ले का उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा, तो उस के मार्केटिंग की प्राब्लम पैदा होगी। अभी हमारे नाथूसिंह जी कह रहे थे कि हमारा आलू २ दामों में मारा मारा फिर रहा है। इसलिये हमको अभी से इसका स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिये और यह काम कोआपरेटिव बेसिज पर होना चाहिये। आज हमारे यहां जो कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटीज हैं वे डारमेंट हैं, मरी जा रही हैं, उन के पास पैसा नहीं है उन का कोई निरीक्षण नहीं हो रहा है। कैनाडा में वहां के किसानों ने मिल कर खुद अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, वहां पर बिचौलिये खत्म हो गये हैं। मुझे एक जगह ले जाया गया और बतलाया गया कि वहां पर जो महल खड़े हुए थे वे पहले बिचौलियों के थे, अब हम ने उन को खत्म कर दिया है। सारा काम किसानों के हाथ में है और अब उन को बहुत अच्छी रिटर्न मिलती है यहां तक कि उन को 2 डालर प्रति बुशल के हिसाब से एक्स्ट्रा कीमत मिली है। जो गल्ले में प्रोफिट होता है, वे बिचौलिये खा जाते हैं। जो गल्ला सरकार को देते हैं, उस में वे एक्स्ट्रा प्रोफिट कर लेते हैं। मैं आप को बताऊं कि मैं 150 रुपए क्वींटल मसूर बेचता हूं और उस मसूर को बिचौलिये 250, 300 रुपये क्वींटल बेचते हैं और इतना ज्यादा मुनाफा वे कमा लेते हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि एक कोआपरेटिव मार्केटिंग स्ट्रक्चर आप तैयार कीजिए। उस से यह जो प्राब्लेम गल्ले को बेचने की है या प्रोसेस करने की है, वह हल हो जाएगी। बुन्देलखण्ड की ओर मैं फिर से आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री कचरूलाल हेमराज जैन (बालाघाट): सभापति महोदया, कृषि मांगों पर जो बोलने के लिए आप ने मुझे अवसर प्रदान किया है, उस के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग हमारे भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि पिछले दो सालों से, नई सरकार के आने के बाद, कुछ एक अच्छी बातें सामने आई हैं और इस सरकार ने 80 फीसदी गांवों में बसे हुए किसानों की ओर ध्यान दिया है और कुछ नई व्यवस्था भी की है जिस के अच्छे परिणाम भी हमारे सामने आए, किन्तु हम यह देखते चले आ रहे हैं कि कृषि का और किसानों का जो सीधा सम्पर्क कोआपरेटिव बैंकों और सोसाइटीज से है और उन को सहायता पहुंचाने के लिए, उन की उन्नति कराने के लिए पिछले शासकों द्वारा जो कोआपरेटिव बैंक, सोसाइटियां और भूमि विकास बैंक आदि संस्थाएं बनाई गई थी, वे हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। कोआपरेटिव बैंक या भूमि विकास बैंक, जिस दिन से इन की स्थापना हुई है, मैं भ्रष्टाचार निरन्तर पिछले दिनों से चला आ रहा है और आज भी वही जारी है। अगर कृषि मंत्रालय किसानों की मदद करना चाहता है और उस के यहां से एलाटमेंट होता है कि इतनी किसानों को सब्सीडी दी जाए या

[श्री कचरूलाल हेमराज जैन]

इतना ऋण दिया जाए, तो वह उन तक ठीक से नही पहुचता है । रसोई कोई बनाएगा और खाने का वितरण कोई करेगा । इसी तरह से यहा पर हो रहा है । अलग-अलग विभाग होने के कारण और कृषि विभाग का सीधा सम्पर्क न होने के कारण, जो लाभ ग्रामीण किसानो को मिलने चाहिए, वे उन्हे नही मिल रहे है । जो लोन उन को मिलना चाहिए, वह समय पर उन को नही मिल पा रहा है । अभी नई स्कीमो के अनुसार, ग्रामीण किसानो को पशुपालन के लिए और कई प्रकार के घरेलू उद्योग खोलने के लिए पैसा दिया जा रहा है तो उस मे भी यह होता है कि कोग्रापरेटिव डिपार्टमेंट मे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वे उन को कहते है कि अगर सरकार 50 फीसदी पैसा माफ करेगी, तो तुम हम को 20 फीसदी दो । अगर 20 फीसदी पैसा देते हो, तो माफ करा देगे । इस तरह की धांधलेशाही चल रही है और मै यह समझता हू कि इस देश के किसानो का सपना पूरा नही कर सकते जब तक कि पूरा नियन्त्रण इस मन्त्रालय के अन्तर्गत न आ जाए । इसलिए कृषि मन्त्रालय के साथ उन सब सम्बन्धित विभागो को जोड देना चाहिए नही तो पचास सौ साल तक भी जो हम उन को मदद पहुचाने की कल्पना करते है वह पूरी नही होगी और उस मे आप सक्षम नही होगे ।

हरिजनो और आदिवासियो को भूमि बाटी गई है और उस का कार्यक्रम भी चल रहा है और गावो मे रोजगार देने की बाते भी चल रही है । अनाज के बदले काम का कार्यक्रम भी चल रहा है लेकिन हम यह देखते है कि जिन इलाको मे भूमि उन लोगो को दस दस और पन्द्रह पन्द्रह साल पहले बाटी जा चुकी है अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि उस का कब्जा भी उन को नही दिलाया गया है और अगर कब्जा भी मिल गया है तो कृषि योग्य वह भूमि नही है और उन मे अपने मे इतनी शक्ति नही है कि वे उस को कृषि योग्य बना सके । मै ने लास्ट टाइम भी कृषि मन्त्रालय की मागो पर बोलते हुए कहा था कि कम से कम उन को कृषि योग्य भूमि दे और इतने सारे जो कार्यक्रम आप के चल रहे है, उन मे आप उन को रोजगार दे और अनाज के बदले काम दे । अगर ऐसा किया गया तो उन की खेती भी दुरूस्त हो जाएगी और हरिजन और आदिवासियो के पास जो भूमि है वह भी खेती करने लायक बन जाएगी । यह नही हो पा रहा है । कृषि मन्त्रालय ने फूड कारपोरेशन आफ इंडिया से अच्छी क्वालिटी का अनाज ऊचे रेट पर खरीदने के लिए कहा है । मै दुखी भी हू और मैने शिकायत भी की है कि जो अनाज उसके द्वारा मडियो से खरीदा जा रहा है वह घटिया किस्म का है और व्यापारियो के साथ उनकी खुली साठगाठ है और आराम से वे घटिया किस्म का माल खरीद रहे है और नियमित रूप से उनका उस मे दो रुपये या चार रुपये क्विटल के हिसाब से बधा हुआ है । इस तरह से जो माल खरीद कर गोडाउन्ज में रखा जा रहा है वह बहुत ही घटिया किस्म का है । मै लिख कर देता हू या कहता हू तो आपके फूड कारपोरेशन के अधिकारी कहते है कि जनता के प्रतिनिधि हमारे काम मे दखल नही दे सकते है, हम सैंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हैं । मेरे जिले बालाघाट में आप जांच करवा कर देख ले कि वहा घटिया माल खरीद कर गोडाउन्ज मे रखा गया है या नही । मैने आप से शिकायत की थी, आपने अपने शासकीय विभाग से कर्मचारियों को भी भेजा लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई । जिस किस्म का माल लेना चाहिये था उससे बहुत ही घटिया किस्म का अनाज लिया जा रहा है और लिया गया है । आप कोई जांच नही करवाते हैं । इस अवस्था मे कैसे आपका विभाग ढग से चल सकता है । पुन मेरा आप से निवेदन है कि आप ने रेट बढाया है तो आप क्वालिटी को भी देखे और इसको भी देखे कि उस क्वालिटी का माल आप के अधिकारी खरीद रहे है जिस क्वालिटी का माल आप चाहते है कि अधिक रेट दे कर खरीदा जाए ।

वायल्ड राइस जिस को कहते है उसकी खरीद के मामले मे भी बडे उद्योग वालो को ही मौका दिया जा रहा है । कुटीर उद्योग या छोटे उद्योग चलाने वालो का माल नही लिया जा रहा है । आपके विभाग वाले कहते है कि यह चावल चलने लायक नही है । बडे उद्योगो से उसकी क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद भी कहा जाता है कि इसको खरीदा नही जा सकता है क्योंकि यह चलने लायक नही है । मै ने आपके विभाग को एक थैलो मे भर कर उस चावल का सैम्पल भी दिया और उसको दिए हुए डेढ महीना हो गया है लेकिन उसका एनालिसिस रिजल्ट प्राप्त किया गया है या नही, मुझे पता नही है । उसका कोई उत्तर मुझे नही मिला है।

मै आपको धन्यवाद देता हू कि आपके विभाग ने काफी तरक्की की है सिचाई मे भी तरक्की हो रही है । लेकिन पुराने शासको के जमाने से जो रिश्वतखोरी और घूसखोरी इस विभाग मे व्याप्त थी वह समाप्त हो गई है और अब इसको खानेवाला नही है इसको मानने के लिए मै तैयार नही हू । आज भी व्यापारियो से धडल्ले से और खुलेआम रुपया लिया जा रहा है । घटिया किस्म का अनाज गोडाउन्ज मे भरा जा रहा है । यह ठीक है कि अनाज के मामले मे अब हम सरप्लस हो गए है और हम को विदेशो को भी अब अनाज भेजना पडेगा । इस वास्ते रेट ज्यादा दे कर हम अच्छी किस्म का अनाज गोडाउन्ज मे रखे इस ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा ।

मै यह भी चाहता हू कि हरिजनो आदिवासियो को जो पिछले शासको ने भूमि बाटी है और आप भी बाट रहे वह कृषि योग्य बना कर ही उनको दी जानी चाहिए । जब तक उसको कृषि योग्य बना कर उनको नही दिया जाता है उनका काम नही बन सकता है । उनके पास इतनी ताकत नही है, इतने साधन नही है कि वे उसको कृषि योग्य बना सके । अगर आपने ऐसा किया तो उन गरीबो की मदद होगी और हमारा देश भी उन्नति करेगा ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी) कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के विकास के लिए जो बजट सदन मे पेश है उसके सम्बन्ध मे जो जनता पार्टी का घोषणापत्र है, उसको मै आपके सामने रखना चाहता हू । कृषि से आमदनी बहुत कम है और गांव के निजी

व्यवसाय को प्रोत्साहन नहीं मिलता, इसलिये गांव में पूंजी नहीं बनती। इसलिए इसके विकास के लिये जनता पार्टी एक राष्ट्र-व्यापी नीति अपनायेगी और इस क्षेत्र में कम-से-कम 40 प्रतिशत खर्च करेगी। पहला बजट जब जनता पार्टी ने पेश किया तो वह 37.2 प्रतिशत था, दूसरा बजट पेश किया तो वह 40.29 प्रतिशत था और तीसरा बजट 43 प्रतिशत है। लेकिन अपने कृषि मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला और कृषि राज्य मंत्री श्री मानुप्रताप सिंह के रहते हुए मैं सोचता था कि यह जो 40 प्रतिशत का प्रस्ताव आपने आज तक पूरा किया, यह देखने में 43 प्रतिशत लगता है। देखने में यह प्रस्ताव साधु है, लेकिन इसमें कुटिलता भरी हुई है। अगर इस कुटिलता के जाल-बट्टे को माननीय मंत्री जी काट सकें तो इस देश पर और देश की खेती के उत्थान पर बड़ी कृपा होगी। इस पूरे के पूरे बजट में जो 43 प्रतिशत का है, इसमें जो फर्टिलाइजर पैदा होता है और उसमें जो फैक्टरियों पर पैसा खर्च होता है, वह भी कृषि और ग्रामीण व्यवस्था में जोड़ दिया गया है। आप देखेंगे कि फैमिली वैलफेयर पर जो पैसा खर्च होता है, उसका 75 प्रतिशत भी इसी ग्रामीण कृषि व्यवस्था पर जोड़ दिया गया है। स्माल स्केल इंडस्ट्री पर जो पैसा खर्च होता है, वह भी इसी बजट में जोड़ दिया गया है। सबसे मजेदार और नोट करने की बात यह है कि स्माल स्केल इंडस्ट्री में जो 15 लाख रुपये तक की फैक्टरी खड़ी करेगा, वह भी लघु उद्योग धंधे में आता है। आज गांव के किस आदमी की हैसियत है कि 15 लाख रुपये का उद्योग धंधा वह खड़ा कर सके? लेकिन उस मद को भी इसमें जोड़ दिया गया है।

जो आर्थिक उन्नयन की पूंजी है, जिसको कहा जाता है कि हमने क्रांतिकारी तबदीली की भूख जगाई है, हमने गांव की ओर जाने का महाप्रयाण किया है, जरा उसकी तरफ भी ध्यान दें।

सार्वजनिक क्षेत्र के लिये रखे गये कुल पूंजी विनियोग के साधनों का कम से कम 40 प्रतिशत कृषि और ग्रामीण विकास के लिये निर्धारित किया जाना सरकार का अति आवश्यक लक्ष्य होना चाहिये। इन पूंजीगत साधनों में पक्की सड़कों, परिवहन और शिक्षा पर लगायी गई राशि शामिल नहीं होगी।

लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि काम के बदले जो अनाज योजना आज चल रही है और उसमें जो ग्रामीण सड़कें बन रही हैं, उनको भी इसमें जोड़ दिया गया है। यदि सब को मिलाकर देखेंगे तो और भी मजे की बात है कि चीनी, शुगरकेन, जूट और काटन की जो इंडस्ट्री है, उनको भी कृषि के अन्तर्गत जोड़ा गया है। यदि फर्टिलाइजर पैदा होकर खेत में इस्तेमाल हो, इसलिये उसको खेती में जोड़ा जाये, तो इन फैक्टरियों में जो चीजें पैदा होती हैं, जो कि खेती में इस्तेमाल नहीं होती हैं, उनको इंडस्ट्री में क्यों नहीं जोड़ा गया। दोनों तरफ कुशाग्र तर्क चलते हैं। एक मुंह में जिसकी दो जीभ होती हैं, वह जानवर बहुत ही खतरनाक होता है। यह पूरे का पूरा शुगर केन और जूट जो पैदा हो, उसको भी इसमें जोड़ दें और फर्टिलाइजर भी इसमें जोड़ दें, यह ठीक नहीं। अगर इन सारी मदों को इसमें से निकाल दें, तो मैं बड़े अदब के साथ कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पिछली बार जो 31, कुछ और अब की बार 34, कुछ खर्च करने जा रहे हैं, तो 40 प्रतिशत की बात अधूरी रह जायेगी। आगे हालत इतनी खराब होगी।

कभी कभी शर्म आती है, लोग पूछते हैं कि जनता पार्टी ने बड़ी शान के साथ कहा था कि हम गांव की ओर जा रहे हैं, महाप्रयाण कर रहे हैं और जब हमारे मंत्री और हमारी जनता सरकार के लोग कहते हैं तो गालिब का एक शेर याद आ जाता है :—

आ वफा ना-आशना, कब तक सुनूं तेरा गिला,
बेवफा कहते हैं तुझको, और शर्माता हूं मैं।

बेवफा श्रीमान को कहते हैं, लेकिन शर्माना हमें पड़ता है। लेकिन शर्माकर भी काम करते चले जा रहे हैं। विचित्र स्थिति है। सारे के सारे कृषि जीवन में आज एक विष घुल रहा है, जरासा इन सब चीजों की तरफ नजर डालें।

14 hrs.

इस देश में चीनी का दाम तय होता है क्योंकि वह फैक्टरी में बनती है लेकिन गन्ने का दाम तय नहीं होता कि इसका लाभप्रद मूल्य क्या है, लागत मूल्य और समता मूल्य क्या है। आज तक इन तीनों मूल्यों—लागत मूल्य, लाभप्रद मूल्य, समता मूल्य—के निर्धारण की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। चीनी का दाम तय होता है, क्योंकि उसको फैक्टरी और इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है—उसका लाभ प्राईवेट सैक्टर में उद्योगपतियों को मिलता है और पब्लिक सैक्टर में ब्यूरोक्रेट्स को मिलता है। पूंजीपतियों, ब्यूरोक्रेट्स और सरकार के इस त्रिगुट से गन्ने का दाम तय नहीं होता है, लेकिन चीनी का दाम तय होता है। यही हालत रूई की है—रूई का दाम तय नहीं होता है मगर कपड़े का दाम तय होता है। आज ही इस सदन में इस बारे में बहस चल रही थी, जिसमें उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फर्नान्डीस, से सवाल किये गये। श्रीमती चन्द्रावती ने कहा कि जब पिछले साल रूई का दाम 355 रुपये प्रति क्विंटल था, तो कपड़े का दाम 5 रुपये प्रति मीटर था, लेकिन इस साल जब रूई का दाम 260 रुपये प्रति क्विंटल है, तो कपड़ का दाम 11 रुपये प्रति मीटर है। जब रूई का दाम घटे, तो कपड़े का दाम बढ़े, यह व्यवस्था कैसे चलेगी? इस व्यवस्था के बारे में हमें और आपको सोचना होगा।

14.02 hrs.

[SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*].

इन चीजो को पैदा करने मे चार तरह के पानी इस्तेमाल होते हैं। कबीर ने कहा है :

माया महाठगनि मैं जानी,

केशव की कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी,

पंडा की मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी।

पानी का बड़ा महत्व है। लेकिन सरकार गेहू और अनाज पैदा करने के लिए जो पानी बेचती है, उस पानी के चार दाम है। राजकीय नलकूप से जो पानी मिलता है, उसके अलग दाम हैं। नहर से मिलने वाले पानी के अलग दाम हैं। बाध मे जो नहर निकलती है, उसके पानी के अलग दाम है। डाल सिचाई योजना, लिफ्ट इरिगेशन, के पानी के अलग दाम है। पाचवा पानी वह है, जो निजी नलकूप से निकाला जाता है, उस के दाम अलग हैं। लेकिन जब गेहू बाजार मे आयेगा, तो उसका एक ही दाम है। ऐसा नही है कि जो चावल और गेहू, 60 रुपये प्रति एकड के पानी से पैदा किया जाये, उस का दाम अधिक है और 15 रुपये प्रति एकड़ वाले पानी से पैदा किये गये चावल और गेहू का दाम कम है।

मेरे एक सवाल के जवाब मे राज्य मत्री ने बहुत पहले कहा था कि सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि सभी पानियो के दाम एक हो जाये। इस बात को साल, डेढ साल हो गया है, आज तक उस योजना पर अमल क्यो नही किया गया ? पानी के दाम क्यो नही एक किये गये, जबकि पानी से उत्पादित चीजो के दाम एक है ?

हमारे देश मे 35 करोड एकड़ जमीन पर खेती हो रही है। उसमे से 10, 11 एकड जमीन ऐसी है जहा एशार्ड इरिगेशन है और जहा उर्वरक का भी इस्तेमाल होता है। अगर फी-एकड डेढ टन भी मान ले तो 11 एकड जमीन से लगभग 16½ करोड टन का उत्पादन होता है। बाकी 25 करोड एकड जमीन बिना सिचाई की है, जिसे आसमान सहारे, आकाश आसरे या भगवान आसरे कहते है। अगर वहा का उत्पादन आध टन फी एकड़ मान लिया जाये, तो वहा 12 करोड टन का उत्पादन होता है। इस प्रकार हमारे देश मे कुल उत्पादन 28 करोड टन का हुआ। लेकिन सरकार की ओर से बताया जाता है कि पिछले साल 12.60 करोड टन का रिकार्ड उत्पादन था और अब 15 करोड टन होने की आशा है।

सवाल यह है कि ये आकड़े बनाने वाले कौन लोग है, किन एजेन्सियो द्वारा ये आकड़े बनाये जाते है ? इस देश में 60 करोड़ लोग रहते है। जेल मैनुअल के अनुसार एक आदमी को 750 ग्राम अनाज मिलना चाहिए। इस हिसाब से 60 करोड लोगो के लिए 16.20 करोड़ टन अनाज बैठता है, लेकिन 12 करोड़ टन उत्पादन बताया जाता है। इस स्थिति मे कहना पड़ता है कि या तो ये आकड़े गलत है और या हिन्दुस्तान के आधे आदमी आज भी भूखे रह रहे है। लेकिन मेरी समझ मे ये आकडे गलत है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है। इस सरकार की निर्यात की नीति के कारण आज इस देश का किसान रोज बरोज दरिद्र हो रहा है। हम गांवो की ओर महाप्रयाण करने की बात करते है, नगर शहर की अट्टालिकाओ को ऊचा करने का काम कर रहे है। 1974 मे अनाज का निर्यात हुआ--48029 हजार टन, 1975 में 24496 हजार टन, 1976 मे 18250 हजार टन 1977 मे 18036 हजार टन--इस का अर्थ है कि निरन्तर घटता गया।

आप चीनी को लीजिये--1974 मे, 443 01 हजार टन का निर्यात हुआ, 1975 मे 996 01 हजार टन, 1976 में 843 07 हजार टन निर्यात हुई, लेकिन 1977 मे 251 08 हजार टन निर्यात हुई--इस का अर्थ है कि 1977 मे आध मे भी कम चीनी निर्यात हुई।

1973-74 मे गन्ने का मूल्य 10 26 रु० प्रति क्विंटल निश्चित किया गया, 1974-75 मे 10 40 रु० प्रति क्विंटल, 1975-76 मे 11 रु० प्रति क्विंटल, 1976-77 मे 10 80 रु० प्रति क्विंटल और 1977-78 मे 10 80 रु० प्रति क्विंटल . ..

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) यह मूल्य कहा है ? यह तो सिर्फ कागज पर है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह यह बात ठीक है--10.80 रु० प्रति क्विंटल कागज पर है जब कि 4 से 5 रुपये प्रति क्विंटल मे गन्ना बिका या किसानो ने उस को दियासलाई लगा कर जला दिया। आप देखिये एक तरफ किसान की हालत यह है कि गन्ना उस को जलाना पड रहा है नई मन्दे भाव पर बेचनी पड रही है दूसरी तरफ आप जरा चावल के थोक सूचकांक को देखिये। यह हमारी अपनी सरकार है, यह सरकार आर्थिक नीति के हिसाब से समता मूल्य चाहती है, पैरिटी-प्राइस चाहती है, लेकिन जरा चीजो के दामो को देखिये। 1971 मे चावल का थोक सूचांक 103 3 था, 1974 में 174 7 था, 1975 मे 188 2 था, 1976 मे 154 9 था, लेकिन 1977 मे 163.6 हो गया। इस का अर्थ है कि 1975 मे 188 2 था लेकिन 1977 मे 163.6 पर चला गया, यानी 6-7 परसेन्ट

लगभग माइनस हो गया । यही हालत गेहूं की रही है ।

अब मैं आप का ध्यान खेती में इस्तेमाल होनेवाली चीजों के मूल्यों की ओर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जो चीजें खेती में पैदा होती हैं उन के मूल्य तो घटते जा रहे हैं लेकिन जो चीजें खेती में इस्तेमाल होनेवाली हैं—उन के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमारी कृषि व्यवस्था रीढ़ से जुड़ी हुई है, आज हमारी रीढ़ टूट रही है, एग्रीकल्चर टूटने जा रही है, इन्सान मरने जा रहा है। आज इन्सान खेती नहीं कर रहा है, आप उस को डांगर कहें, जानवर कहें, आज इन्सान के रूप में जानवर खेती में लगा हुआ है। मैं ने पिछले साल भी कहा था कि कुछ लोग कृषि को "कृषि मत्स्य जीवन" समझते हैं लेकिन मैं इस को 'कृषि मर्दन जीवन' समझता हूं। आज कृषि में सब लोग नंगे हुए हैं जो इतना अधिक परिश्रम करते हैं जो दोपहर की इतनी सख्त धूप में अपना हड्डियां को जलाते हैं लेकिन फिर भी उन को 1975 के मुकाबले में कम दाम मिलते हैं और दूसरी तरफ आप यह देखिये कि खेतों में काम आने वाली जो दूसरी चीजें हैं उन के दाम कितने बढ़ गये हैं। आप बैटरी को ही ले लीजिए। बैटरी ट्रैक्टर में इस्तेमाल होती है और बैटरी का दाम कितना हो गया है। बैटरी में जो लीड और आक्साइड लगता है, उस के दाम एक वर्ष में चार दफा बढ़े हैं। सितम्बर 1978 में उस के दाम 8600 रुपये पर मीट्रिक टन थे और अक्तूबर 1978 में वे 9,100 रुपये पर मेट्रिक टन हो गये। उस के बाद जनवरी में वे बढ़ कर 11000 रुपये पर मेट्रिक टन हो गये और फिर 1 मार्च 1979 को वे बढ़ कर 14,100 रुपये पर मेट्रिक टन हो गये। इस वर्ष के अन्दर दुगने दाम हो गये। 1971 में जो ट्रैक्टर 29 हजार रुपये का मिलता था, उस के बाद बढ़ कर 60 हजार, 61 हजार और 62 हजार रुपये हो गये यानी दुगने और तीन गुने उस के दाम हो गये।

अब आप डीजल को देखिए। 1971 में जहां उस का इन्डेक्स नम्बर 104 5 था, वहां 1977 में वह बढ़ कर 213 9 हो गया। 1971 में 104 5 और 1977 में 213 9 और डीजल का मौजूदा दाम जो बढ़ गया है, उस को अगर मद्देनजर रखा जाए, तो यह 213 9 बढ़ कर 240 हो जाएगा। आप ने यह भी देखा कि जिस गन्ने से चीनी बनती है, चीनी के दाम तो बढ़ गये लेकिन गन्ने का दाम नहीं बढ़ा बल्कि घटा है। कहीं कुछ बात नहीं हुई और चीनी का दाम 30 प्रतिशत बढ़ गया। पहले उस का दाम 2 20 रुपये किलो था और अब यह बढ़ कर 4 रुपये और 3 20 रुपये प्रति किलो हो गया। (व्यवधान) साढ़े चार रुपये की याद करते हैं, तो फिर इन्दिरा गांधी की तारीफ करनी होगी। हम तो आप की तारीफ करना चाहते हैं। 2 15 रुपये प्रति किलो चीनी आप भी देते थे। इसी तरह का बिजली का इन्डेक्स नम्बर आप देखें। 1971 में यह 101 9 था और 1977 में यह बढ़ कर 171 6 हो गया है। ट्रैक्टर का 1971 में 109 6 था और 1977 में यह बढ़ कर 203 हो गया है। फिर कृषि फावड़े का आप देखें, 1971 में जहां इस का इन्डेक्स नम्बर 113 6 था, 1977 में वह बढ़ कर 216 9 हो गया और अभी बीजू पटनायक साहब ने जो दाम बढ़ाए हैं, जो 265 रुपये प्रति क्वींटल हमें छड़ मिलती थी, उन से बने हुए फावड़े के दाम 360 रु० प्रति क्वींटल हो जाएंगे। इसी तरह से आप यह देखें कि पिन्ड लोहा, जिस का इन्डेक्स नम्बर 1971 में 100 था, वह 1977 में बढ़ कर 181 6 हो गया और फर्टिलाइजर्स का जो 1971 में 100 3 था वह बढ़ कर 186 5 हो गया, आप की महान कृपा के बावजूद। इस तरह से आप देखें कि सारी चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, खेती में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, उन के दाम घोड़े की रफ्तार से बढ़ रहे हैं और किसान जो इतना परिश्रम करता है और किसान जो चीजों को पैदा करता है, उस की उन चीजों के दाम अगर चींटी की रफ्तार से भी बढ़ते तो हम आप को मुबारकबाद देते लेकिन मुबारकबाद तो अब भी देंगे क्योंकि दाम माइनस की तरफ जा रहे हैं। आज किसानों को गोदामों की तरफ जाना पड़ता है, गोदाम किसान की तरफ नहीं जाते हैं। व्यवस्था यह होनी चाहिए कि उन के लिए गोदामों वहीं पर हों और जो उन की फसल है, उस का इन्शायरेंश हो। इस के साथ साथ जैसे गोदामों में रखे हुए माल के ऊपर शहरों में कैश-क्रेडिट मिलता है, एडवान्स मिलता है, उसी तरह से जो माल किसान रखे हों उन को भी एडवान्स मिलना चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी तो किसान हमेशा लुटता ही रहेगा। अब उस को पैसे की जरूरत होती है, तो उस को अपना माल बेचना ही पड़ता है और डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिस से किसान को ऐसा न करना पड़े।

काम के बदले अनाज योजना का जिक्र करते हुए, अन्त में मैं एक बात और आप की सेवा में अर्ज करना चाहता हूं। 1 लाख 16 हजार मेट्रिक टन आन्ध्र प्रदेश में पिछले साल गेहूं आवंटित किया गया लेकिन कुल खर्च हुआ 23957 मेट्रिक टन और इसी तरह से हर प्रदेश में हुआ कि जितना आवंटित हुआ काम के बदले अनाज योजना में उस की एक-चौथाई भी खर्च नहीं हुआ। इस का कारण क्या है। इस के कारणों में जाया जाए, तो पता चलेगा कि जो गेहूं या चावल इस योजना के अधीन दिया गया, उस में से 50 से ले कर 75 प्रतिशत तक सड़ा हुआ था या खराब था। इस कारण से यह योजना ठीक से नहीं चल पाई और इस तरफ आप को ध्यान देना होगा।

इस के अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले साल 112 50 रुपये का समर्थन मूल्य आपने दिया था। इस साल के लिए अभी कुछ नहीं

[श्री चन्द्रशेखर सिंह]

किया है लेकिन आज गेहू बाजार में 80, 90 रुपया पर क्वीटल बिक रहा है और जहां समर्थन मल्य पर खरीददारी होती है, वहा बनिये की एजेन्सी रहती है या बिचौलिये की एजेन्सी रहती है और उन के जरिये मे गेहू लिया जाता है और वे ज्यादा मुनाफा कमा लेते है ।

एक माननीय सदस्य बोरे भी नही है ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह . बोरो का तो इन्तजाम कर लेगे । अन्त मे मै इतना ही कहना चाहता हू कि कृषि का अगर उद्योग की तरफ माना जाए, तभी जा कर कृषि का विकास हो सकता है । इस मे जो शासन की कमिया है, उन को छिपाने से कोई फायदा नही होगा । इस सम्बन्ध मे मै एक शेर कहना चाहूगा ।

"इन्सान आज भी है गुलामी मे सरमगू
यह बात और है कि तरीके बदल गये ।।

केवल तरीके ही बदले है, और कुछ नही बदला ।

इन शब्दो के साथ मै यह कह कर समाप्त करता हू कि इतने बुद्धिमान, योग्य, सुशिक्षित सस्कारवा लोगो के मत्रालय मे रहते हुए भी अगर गावो का विकास नही हो सका, तो मै ऐसा ही नही मानता कि आगे यह हो सकेगा । यह श्रेय इन लोगो का जाये और श्रेय का लेने के लिए जहा भी लडना पडे, हमें लडना चाहिए । इन शब्दो के साथ मै कृषि मत्रालय की मागो का समर्थन करता हू ।

SHRI VENUGOPAL GOUNDER (Wandiwash): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands of the Ministry of Agriculture and Irrigation. I would be failing in my duty if I do not congratulate the Ministry for having raised the production of foodgrains to the extent of 125 million tonnes. Though we are proud of raising the prouction to that level, yet what about the man who has achieved this target, who has produced 125 million tonnes of foodgrains? What steps we have taken to take care of his interest? He is not expected any Bharat Ratna or any such thing from you. He wants food, cloth and a shed. We will be failing in our duty if we do not provide him with food, cloth and shelter. We are talking too much that we have achieved our target. But one thing the Minister should not forget. The monsoon was very very favourable to them and because of that, they have achieved this target. So, they should not be complacent about it. Otherwise, the situation would be very difficult. The Ministry should bear in mind the fact that if the monsoon fails what would be the position? And keeping that in mind, they should plan their strategy.

When the Ministry of Agriculture ask us to produce more, they should find markets for the produce in foreign markets. Otherwise, the person who produces will suffer more because the law of supply and demand will have greater force. Unfortunately, in Tamil Nadu and some other States the sugar cane growers have left their land fallow because a proper price is not paid to them. The agriculturists say that they are not getting their dues from the mills and the mill owners say that they are not able to get a proper market because there is no demand for sugar. The result is that the farmers are suffering a lot. The Ministry should come forward to help those farmers in such cases where the demand is less

Of course, organisations like the Food Corporation of India and the Civil Supplies Corporation are purchasing it. But they should not be guided by the rules about grades and so on Now what happens is that when they are purchasing from the farmers, they are guided by the rules about grade and so on. But when they are put to loss, they give some other reason for the loss I would say that the Ministry of Agriculture need not be strictly guided by the rules; at least in the matter of purchasing foodgrains let them be magnanimous. Let them find ways and means to purchase all the foodgrains that the farmers offer for sale Let them not make the farmer go back with his produce on the ground that it is not up to the quality or grade.

Coming to the question of marketing, a person who produces industrial goods fixes the price for his product while a person who produces foodgrains is not in a position to fix the price for his own produces. We should create conditions where a farmer can fix his price for what he produces. Now the price is fixed by a middleman, who

knows nothing about farming. As far as possible, we should try to eliminate the middleman so that we can do something for agriculture.

The FCI is functioning only in big cities like Madras. It has no offices at the taluka or zilla parishad level. There should be branch offices at every taluka so that the farmers can take advantage of it for the disposal of their produce.

Paddy can be cultivated only through irrigation whereas wheat can be cultivated with or without irrigation. The support price fixed for wheat is high, whereas that for rice is very low. There is a lot of discrimination here. There is a demand that the cultivation cost of paddy should be taken into consideration, as it is more on account of irrigation, whereas it is less for wheat because it can be cultivated without irrigation. So I am at a loss to understand why wheat is fixed a higher price in comparison with paddy. This discrimination should be removed and both wheat and paddy should be given the same price.

Now there are Commodity Boards to look after the interests of those commodities like the coconut Board, Coffee Board, Tea Board, Cashewnut Board and so on. In the same way, there should be boards for groundnut, paddy etc. consisting of real farmers, and not those who know about farming only from books. The Board should consist of people who know the practical difficulties and it should look after the interests of the farmers and make necessary recommendations to the Government.

The Agricultural Prices Commission was appointed in 1965. From then onwards there was no further Commission. Of course, it was revived or reintroduced in a different form. So, I suggest that a Price Commission may be appointed so that the cost of the paddy, groundnut, chillies etc. is taken into consideration and a support price is given to these crops.

Another point is that wheat was purchased and it was given to the public at subsidised prices. In these same manner the paddy may be purchased at a higher cost and it may be given to the public at a subsidised rate. Suppose, the prices of industrial goods have increased, nobody bothers. For example, if the price of cloth has gone up more than 20 or 30 times, nobody bothers, not even the Government bothers. But they should bother very much if the prices of foodgrains have increased. People will be interested to see that the prices are reduced. But the Government should take into consideration the fact as to how far the farmers could be benefited by the increase in the price. If there is so much increase then the Government should come forward to subsidise these things.

There is one more important thing which I would like to mention here. I would like the Minister of Agriculture to allot more funds for irrigation because we have got a vast source of water. Particulary, we have got perennial rivers in the North. There is a lot of dispute regarding the sharing of river waters. Each State is quarreling with the other on who should be benefited. Ultimately neither is benefited, the entire water goes to the sea. So, the inter-State waters should at least be nationalised or the Minister should take care to see that the disputes are settled immeditely.

There is a big and ambitious plan for connecting the Ganga and Cauvery rivers, for which the World Bank has agreed to give assistance and the experts have also pointed out that it is feasible. If the two rivers are connected, definitely the farmers will be benefited. Not only that. The employment possibilities are also greater. You can give employment to both educated and uneducated agriculturists. There is a lot of potentiality for employment. In respect of agriculture, definitely there is a chance to increase all such potentialities. So, kindly take interest and consider whether it is possible to unite the Ganga and the Cauvery. You take

[Shri C. Venugopal]

the water to the South so that the southern people will also be benefited. Then not only the South but the entire North also will be benefited.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI VENUGOPAL GOUNDER: Now, there is agrarian unrest throughout the country. If the problems of agriculturists are not solved, and if we fail to give proper attention to agriculture, then we will be failing in our duty.

With these words, I conclude.

श्री भारत भूषण (नैनीताल) सभापति महोदय, आज हम कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। जिस वातावरण में हम आज रह रहे हैं, उसमें मैं इस मंत्रालय के मंत्रियों के भाग्य की सराहना करना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि सभी मंत्रालयों के अन्तर्गत आने वाली चीजों का अभाव है—देश में खनिज तेल, कोयला, बिजली और लोहा नहीं मिलता है सब चीजों का अभाव है—, मगर कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले खाद्यान्नों की बहुतायत है। वे सब जगह मिलते हैं, कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है।

लेकिन इसके लिए किसको धन्यवाद दिया जाये, किसको बधाई दी जाये? प्रकृति को, जिसमें समय पर वर्षा हुई, या उस किसान को जो भूखा रह कर भी, अभाव में रह कर भी, जमीन को जोतता है?

वह हड़ताल नहीं करता है, अन्न पैदा करता है और उस को उपज जो भी भाव मिले बेचना पड़ता है। इस के लिये मैं किस को धन्यवाद दूं—किसान को धन्यवाद दूं या प्रकृति को धन्यवाद दूं, लेकिन इस मंत्रालय को धन्यवाद नहीं दिया जा सकता है। किसान के द्वारा ज्यादा पैदा करने के बाद, देश में खाद्यान्नों की बहुतायत के बाद भी आज किसान की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन यदि आप कारखानों में देखें, वहां जब उत्पादन बढ़ता है, उन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है।

मैनीफेस्टो की बात मैं इस लिये नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे मंत्री जी का सम्बन्ध जनता पार्टी के मैनीफेस्टो से नहीं रहा है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं—किसान होने के नाते उन्होंने भी अपने किसानों से वायदा किया था कि किसान को बोआई के दिनों में मूल्य की घोषणा कर देंगे। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के तौर-तरीकों के बारे में अब तक चिल्ला रहे थे कि वह गलत है, उस को हम ठीक करेंगे—लेकिन क्या हो रहा है? आज गेहूं कट रहा है—मंत्री जी यहां बैठे हैं, आज तक वे किसानों को उसकी कीमत नहीं बतला सके हैं कि वह क्या भाव बिकेगा। आज किसानों द्वारा पैदा की जाने वाली तमाम चीजों की सही लागत निकाली जानी चाहिये और उस पर उस को उचित नफा दिया जाना चाहिये, ताकि वह जीवित रह सके। लेकिन होता क्या है—शहरों में रहने वाली 20 प्रतिशत आबादी की जेब को देखा जा रहा है, उस का बजट क्या एलाउ करता है, वह किस भाव पर खरीद सकता है—उस को दृष्टि में रख कर हिसाब लगाया जाता है, क्योंकि वे जानते हैं —यदि मजदूर को पैसा नहीं मिलेगा तो कारखाने का उत्पादन गिर जाएगा, वह हड़ताल करेगा, शहरों में रहने वालों की बिल्डिंगों को तोड़ेगा, मंत्रियों के घरों पर धरना देगा, ला एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा करेगा, ब्यूरोक्रेट्स आराम से नहीं बैठ सकेंगे, लेकिन बेचारा किसान क्या करेगा—किसान यह सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिये किसान के बारे में उन को कोई चिन्ता नहीं है। किसान खेती छोड़कर हड़ताल नहीं कर सकता, वरना वह क्या खायेगा? वह प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति उस को तनख्वाह का एरियर नहीं दिला सकती। यदि उस ने हड़ताल कर दी और बोआई का मौसम निकल गया, तो वह खाने को कहां से लायेगा। इसलिये, सभापति महोदय, इस नौकरशाही को, इस अफसरशाही को, पूरा अधिकार है कि उस का शोषण करे और हमारे मंत्री जी उन्हीं अधिकारीवर्ग द्वारा दी गई रिपोर्टों का समर्थन और हिमायत करते हैं।

मुझे आश्चर्य हुआ—एक दिन मैं मंत्री जी से बात कर रहा था। उन्होंने कहा—मैंने भी बहुत हड़तालें की हैं, नारे लगाये हैं। इन सब बातों को मैं जानता हूं—क्योंकि हम लोग अपोजीशन में रह चुके हैं। इसलिये अब जब कि मैं मंत्री बना हूं तो हड़तालों और नारों से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने भी मुर्दाबाद कहा था, हम ने भी धरने दिये थे इसलिये अब यह हमारे दरवाजे पर भी हो जाय, तो इस से क्या अन्तर पड़ता है।

किसान की आज जो स्थिति है—अनेक वक्ता उसके बारे में बतला चुके हैं—आज पैदावार से लेकर उसके जीवन से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक वस्तु—चाहे खेती में लगने वाली वस्तु हो या उस के शरीर पर लगने वाली वस्तु हो—सब महंगी होती जा रही है, लेकिन उस के द्वारा जो वस्तुयें पैदा होती हैं, वह यदि अधिक पैदा कर दे तो बाजार में बिखरी बिखरी फिरती है, उन की कोई कीमत नहीं होती, कोई उन का खरीदार नहीं होता। आज आलू की यही हालत है, पिछले साल गन्ने की यही हालत थी। हमारे मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि आप को एक्सपोर्ट करने की छूट है। किसान को कहते हैं कि तुम एक्सपोर्ट कर दो। इसका यही मतलब हुआ कि कमरे के सारे दरवाजे बन्द कर दिये और ताली अपनी जेब में रख ली, फिर कहते हैं कि तुम पर कोई बन्धन नहीं है, तुम बाहर चले जाओ। विदेशों को माल तब तक नहीं भेजा जा सकता, जब तक सरकार दूसरी सरकार से बात कर के निर्यात का प्रबन्ध नहीं करती। किसान स्वयं बाहर नहीं ले जा सकता, यहां पर बिक्री की व्यवस्था नहीं है। कृषि मंत्रालय अगर किसान द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विपणन ठीक से नहीं करा सकता है, किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं दिला सकता है तो उसने किसान की

बहबूदी की जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली हुई है उसका वह निर्वाह नहीं कर सकता है और बधाई का पात्र नहीं हो सकता है।

कृषि मंत्रालय के साथ सिंचाई जुड़ी हुई है। यह सराहनीय चीज है कि इस को कृषि मंत्रालय के साथ ही रहना चाहिये। सिंचाई के मामले में पिछली सरकार के मुकाबले हमारी सरकार ने कम समय में अधिक सिंचाई की सुविधायें जुटाई हैं और आगे के लिए भी उसकी बड़ी भारी योजना है। किन्तु काम किस प्रकार होता है उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। इस सदन के अन्दर पहली बार बोलते हुए भी मैंने इसकी चर्चा की थी। आज दो वर्ष बाद फिर से मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र में 1974 में जिवरानी डैंप बनाने के लिए उसका शिलान्यास कर दिया गया है, योजना आयोग से वह एप्रूव हो गया है। 62 करोड़ उस पर लागत आएगी। 1974, 1975 और 1976 निकल गए। 1977 में निर्वाचन आए। मैं निर्वाचित हो कर आया। तब इस डैंप का कुछ पता नहीं था। एक करोड़ रुपया हर साल उसके लिए रखा जाता था जो उसके डिविजन पर खर्च होता था, व्यवस्था पर खर्च होता था। रिवर बैड तक जाने के लिए सड़कें बना देते थे, छोटी छोटी टम्पोररी पुलिया बना देते थे और बाढ़ आती थी तो सब नष्ट हो जाता था, सब बह जाता था। अगले साल फिर बना देते थे। डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है जो उस में काम करते हैं उनकी नौकरी पक्की है लेकिन डैम क्यों नहीं निकल कर आ रहा, किसान को खेत के वास्ते पानी क्यों नहीं मिल रहा है, परेशानी क्या है, जब मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि डिजाइन अभी एप्रूव नहीं हुआ है, एक नया डिजाइन कोई अमरीका में बना है उस प्रकार का बनाया जाए तो 62 करोड़ खर्च आएगा और अगर अपने परम्परागत डिजाइन के मुताबिक बनाया जाए तो सत्तर करोड़ खर्च आएगा। यह जो खर्चा है यह तब हान की बात थी। जो बड़े इंजीनियर थे वे कहते थे कि खतरा मोल लेना नहीं चाहिये, आठ करोड़ कम खर्च करके अगर बना दिया गया और अगर कल को टूट गया तो क्या हो। भारतीय इंजीनियरों की या तो बुद्धि पर विश्वास नहीं या ईमानदारी पर विश्वास नहीं। ईमानदारी पर विश्वास कैसे हो क्योंकि चोरियां हो रही हैं, बेईमानी हो रही है। इसका नतीजा यह हुआ कि आज चार साल तक डैम नहीं बना और बनना शुरू नहीं हुआ। फीडर चैनल्ज बन गई हैं, बरेज का प्रबन्ध हो गया है लेकिन डैम कहीं नहीं है, चार साल हो गए हैं डिजाइन ही नहीं तैयार हुआ है। 62 करोड़ की जगह अब अस्सी करोड़ में भी नहीं बनेगा क्योंकि इस बीच कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। कल को एक अरब खर्च होगा। इस तरह से आप जो रुपया खर्च कर रहे हैं वह किसान तक पहुंचेगा, उसका लाभ उस तक पहुंचेगा इसका विश्वास नहीं होता है। यह कागजों में ही पड़ा रह जाएगा जैसे पिछले पांच साल से यह डैम पड़ा हुआ है। यही हाल सब जगह है।

कृषि मंत्रालय के अन्दर एक खाद्य विभाग आता है। उसने वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की कल्पना की थी। किसान को उसकी फसल मार्किट में आने पर जो परेशानी होती है, उसके दाम जो गिर जाते हैं, उसके पास होल्डिंग कैपेसेटी जो नहीं होती है, अपने माल को रोके रखने की शक्ति नहीं होती है, उसको होल्डिंग कैपेसेटी प्रदान करने के लिये बैंकों से वह जो माल इन गोडाउज में रखेगा उसके अगेंस्ट कर्जा दिलाने के लिये वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की कल्पना की गई थी। इस तरह से जब भाव ठीक होंगे तब वह बेच देगा इस वास्ते इन गोडाउज की व्यवस्था की गई थी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ने पिछले वर्षों में कितने परसेंट माल एफ० सी० आई० का अपने गोदामों में रखा है और कितने परसेंट किसानों का रखा है। यह कारपोरेशन तो आपका कमाऊ पूत बन गया है और इसने चार करोड़ कमा कर भी आपको दे दिया है लेकिन कितने प्रतिशत माल किसानों का रखा है अपने गोडाउज में इसके आंकड़े तो आप जरा देखें। एफ०सी०आई० के लाभ के लिए वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का क्या निर्माण हुआ था? क्या किसान के लाभ के लिए नहीं हुआ था? अगर किसान का गल्ला नहीं रखेंगे उसको अगर अग्रिम राशि नहीं दिलायेंगे और एफ० सी० आई० को दे कर उन से रुपया कमाया जाएगा और ईंस इस तरह से बना जाएगा और चार करोड़ का लाभ दिखाया जाएगा तो क्या नहीं इन गोडाउज को एफ० सी० आई० को ही ट्रांस्फर कर दिया जाता है? तब इस कारपोरेशन की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। एफ०सी०आई० ने एक करोड़ बीस लाख टन का व्यापार किया उसके पास सत्तर हजार कर्मचारियों की फौज है, पच्चीस हजार मजदूर उस में काम करते हैं इन मजदूरों का शोषण करने के लिए उन्होंने ठेकेदार खड़े कर रखे हैं और ठेकेदार और कर्मचारी मिल कर आप से अनुदान लेते चले जा रहे हैं। गत वर्ष 570 करोड़ का अनुदान आपने दिया था। क्या यह अनुदान उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिये दिया था? आप देखें कि उसके खरीद मूल्य और इशू मूल्य में 19 रुपये का अन्तर होता है यानी 180 रुपये टन का अन्तर होता है और उपभोक्ता के पास पहुंचते पहुंचते वह 250 रुपये प्रति टन हो जाता है। इतना डिफ्रेंस होने के बावजूद एफ०सी०आई० अपना खर्चा नहीं चला सकती है। उसने पिछले साल 456 करोड़ की मांग की थी जो बढ़कर 570 करोड़ हो गया यानी सवाया हो गया। क्या उसका व्यापार घटने वाला है कि इस साल 560 करोड़ की मांग की जा रही है? बाद में चल कर इसको बढ़ाया जाएगा और मैं समझता हूं कि इसको सात सौ करोड़ कर दिया जाएगा। देश में एक करोड़ बीस लाख आपके अपने आंकड़ों के हिसाब से लोग बेरोजगार हैं। अब इनको अगर यह रुपया दिया जाए तो हर एक को साठ रुपए महीना दिया जा सकता है। यह विभाग कितना भ्रष्ट और इनएफिशेंट है यह आप जानते ही हैं। इसके द्वारा खरीदे गए चावल का नमूना आपके पास भी पहुंचा चुका है। रायकोट गोदाम में यह गल्ला रखा हुआ है। इस में दस प्रतिशत भी चावल नहीं है। किसान छान छान कर एफ०सी०आई० का गल्ला देते हैं गेहूं ला कर देते हैं तीन तीन छलनियां लगाई जाती हैं लेकिन जब वह कंज्यूमर के पास आता है तो उसके अन्दर कूड़ा मिला होता है? कूड़ा कौन मिलाता है? आपके एफ०सी०आई० के कर्मचारी मिलाते हैं। आप का जो क्वालिटी इंस्पैक्टर होता है उसका एक प्रतिशत सवा प्रतिशत मिला रहता है और वह एक साल में इस तरह से चार पांच लाख रुपया कमा लेता है। आपकी

[श्री भारत भूषण]

तनख्वाह से कई गुना अधिक आय उसकी होती है। एक दो साल के बाद उसको अगर निकाल भी दिया जाता है तो उसको कोई परवाह नहीं होती है।

रुद्रपुर में जो इनक्वायरी हुई है मैं नहीं समझता हूं कि उस में किसी को कोई सजा होने वाली है। वहां लोग मिले हुए हैं। वे आप से अपनी बात का अनुमोदन करा लेते हैं। हमें आप से यह आशा थी कि कोई बात होगी आपके विभाग की तो मंत्री जी जज बनेंगे हमारी बात भी सुनेंगे और विभाग की बात भी सुनेंगे और जजमैंट देंगे। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि मंत्री महोदय भी वकालत करने लग गए हैं अपने विभाग की और अपने अधिकारियों की जज होने के बजाय। यह हमारी बदकिस्मती है। कुरप्शन का नमूना मैं दे ही चुका हूं। इसके अन्दर दस परसेंट भी चावल नहीं है। नब्बे परसेंट चावल निकाल लिया गया है और ठेकेदारों से कूड़ा मिलवा दिया गया है और गोडाउंज में इसको लगवा दिया। इस सब बेईमानी को छिपाने के लिए करदाताओं से इन्हें सैंकड़ों करोड़ रुपया चाहिये ताकि ये जो माल खराब हो गया है बरबाद हो गया है डैमेज्ड हो गया है इसको छिपा सकें। आपने गांवों में फूड फार वर्क चलाई है। अंधे के हाथ बटेर आ गया है। एफ.सी.आई. द्वारा सारा वह डैमेज्ड माल खराब माल उस में भेज दिया गया है और बांट दिया गया है और सारे गोडाउंज क्लीयर किये जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एफ०सी०आई० को आप वाइंड अप कर दें। बाजार में माल वैसे ही काफी मिल रहा है और किसी को इस की जरूरत नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस मंत्रालय को एफीशियेंटली चलाना है किसान के हित में चलाना है तो कागज पर स्कीम देकर नहीं केवल कागजों में लिख कर नहीं बल्कि किसान को हित पहुंचाने की देखभाल करनी चाहिये। आप किसान और वर्कर के कस्टोडियन बनिये भ्रष्ट अधिकारियों से नजात पाइये। 3 वर्ष से अधिक जहां अधिकारियों को हो गये हैं उनका तबादला कीजिये।

मैं समझता हूं कि फूड कार्पोरेशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बड़ी खूबी के साथ फूड कार्पोरेशन के अन्दर सड़े हुए गल्ले को फूड फार वर्क के लिये बाहर भेजकर फूड कार्पोरेशन को बचाया है। अब उनको विभाग का सचिव बनाया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने मंत्रियों को खुश किया है डिपार्टमैंट को ठीक चलाया है और आपके फूड फार वर्क के काम को खूबी से अच्छा सेहरा पहना दिया हैं।

जो आप के द्वारा हो रहा है इसके लिये तो आपको बधाई है फिर भी मैं मजबूर हूं इस संसद् में आपका साथी हूं इसलिये आपके अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और इस प्रार्थना के साथ कि बजट में जो प्रावीजन दिये गये हैं वह कागज में न रखकर जमीन पर ले आइये और व्यावहारिक रूप में चलाइये ताकि देश की जनता खुशहाल हो सके।

SHRI B. K. NAIR (Mavelikara): I would like to congratulate the Minister for achieving 4½ million tons additional food-grains last years as compared to the year 1975-76. But I would like to remind him that this maximum production has been the result of the labours put in the last 30 years by the previous Government. If Mr. Barnala would refer to the figures of production in earlier years, he will find that in 1950-51 the production was 55 million tonns, it jumped to 104 million tons in 1973-74, in 1974-75 it was 100 million tons and in 1975-76 it was 121 million tons. As compared to 121 million tons he has achieved an increase of 4½ million tons. Certainly this is something to be congratulated upon but, while congratulating the Minister, I would also like to use this forum to send my fervent prayers to the Heavens that the weather Gods may continue to shower their grace and favour cultivation with favourable seasons. More than anything else, in the last two or three years, the Government and the people have been fortunate in having very favourable weather conditions. That, in fact, has contributed to higher production more than anything else.

While there is reason for satisfaction there is no ground for complacency on his part, I would also like to remind him that we in this country have to plan for the future. It is time now that we begin planning for the future. While we have been able to achieve more than a 100 per cent increase in production in the last 30 years, we should be aiming at another 100 per cent increase in the coming twenty years or so because our population is going to be nothing less than 1000 million by the turn of the century and our need for foodgrains would be about 230 million tonnes. How are we getting ready to meet that situation? Are we only going to pat each others back saying we have achieved two million or three million tons more? That sort of thing will not do. We have to plan for a substantially higher rate of increase in production in the coming 20 years or

so. That fact, I don't think, has been properly brought out in the Budget. The seriousness of the problem will bring to our mind what the hurdles are in trying to achieve this substantial increase in production.

The hurdles are many. Firstly, as many friends have emphasized, the peasants of this country, the Kisans of this country feel alienated. They feel they are orphans They feel the Government is against them, that the entire society is against them and that they have to slave for the country. In fact, about 20 per cent of the population is dictating terms to the peasants The peasants are at the mercy of the consumer, of the city man, of the town folk, of the bureaucrats of the officers of the middle-class people, and ultimately, of the merchants. All these people sit on his head and they are reducing the life of the peasant to one of slavery so much so he does not get his dues He is labouring like a slave. Each man in the city is having at least four persons as slaves for him in the villages. All his luxuries and comforts and the high standard of living are being maintained by the city man at the cost of the kisans. That is how the system is functioning Now, what is the solution? It has been said by the Members in this House and I would also say that the solution has to come from the peasants themselves: kisan organizations have to come up Mao-tse-Tung once said that the villagers should encircle the towns; he urged on the under-industrialised countries to encircle the industrialised countries The peasants have to encircle the towns and try to dictate their own terms. Now, as it is, their produce is at the mercy of the traders and consumers. The entire system has to be changed. Of course, that will take a long time, but the process has to be started. Ultimately the time will come when the actual producers, the sons of the soil, will begin dictating their terms to the city-man who is now leading the artificial life of glitter.

Coming to the problem of price-fixation, we have a machinery here, the Agricultural Prices Commission. I do not know what is the standard that they are following. They claim to aim at fixing a uniform price for the produce for the whole country But the cost of cultivation, the labour involved and the inputs involved do not bear out or substantiate their claim that a uniform price can be fixed For example, in 1975-76—I would read out certain figures—the yield per hectare of paddy in different States was as follows: Andhra Pradesh, yield per hectare, 2,485 kilograms, Tamil Nadu 3,225 kgms; Punjab 3,867; and now coming down, in Bihar the yield per hectare was only 1382. Then if you come to my own State, namely, Kerala, the yield will not be more than 1,200 kilograms per hectare. Therefore, what is the philosophy in trying to apply a uniform price for the entire country? The cost of production is different in various States For example, in our own State, Kerala, the wages are higher than in most other States; in Kerala, the agricultural workers get Rs 10 per head per day and the women workers get about Rs. 7 per day While this is so, how can you have a uniform price for the produce for the whole country? The cost of production is entirely different in various States. About fertility and other things, of course, there is no solution; there can be no uniformity I would suggest therefore that there should evolve some method of subsidising the production in high-cost areas In our State, Kerala, we have to pay high electricity charges for pumping out water. That may be subsidised. In high-cost areas, fertilisers, for example, may be supplied at subsidised rates. Without some such method of trying to equalise or make uniform the cost of production, we cannot just fix a uniform price for the whole country.

MR. CHAIRMAN: Please try to conclude in two minutes.

SHRI B K NAIR: I would like to emphasize certain aspects about Kerala.

One is this There is a reference in this Report to the difficulties in Kuttanad In Kuttanad the cost of production is high, and Mr Barnala is advising Why not diversify to some other crops?' For diversification also, the land has to be prepared and money has to be spent Will you subsidise this to some extent? People are prepared to diversify in certain areas Kuttanad measures about 60 000 to 65 000 hectares One part can be separated from the other But certain people have to continue with paddy cultivation because the Government of Kerala is insisting on paddy cultivation being continued because all these years there was shortage of paddy in Kerala and they could not depend on the Centre's supply Now of course the supply position has improved The Central Government has to persuade the Government of Kerala to do away with the Land Utilisation Act That is hanging on the neck of the cultivators Once the Land Utilisation Act or that burden is removed the peasants will be free to go in for their own crops and the peasants will be getting a better return and also the country will be benefited to that extent That is one aspect

The Minister is also in charge of Fisheries We have got about 6 million fishermen employed all along our coast What do we do for these fishermen? Have the government taken any serious note of their plight? Many of them go out into the sea in the monsoon season and die in accidents Serious cyclones are there Have the Government ever thought of having some sort of insurance for them or giving some compensation to them? In Kerala the practice is that the Minister goes to the man's house and gives Rs 500 to the wife of the dead fisherman photos are taken everything is displayed properly and the chapter is closed We have to go in for a serious project for helping the fishermen My suggestion in this, we are getting about Rs 180 crores from exports of fish products Why not have some sort of a cess say 1 or 2 per cent, on the exports? It will easily fetch you about Rs 2 crores and with some contribution from the government also, you can draw up a welfare scheme and help these fishermen families during their days of distress or during the days of unemployment and when fatal accidents take place And then the Food for Work Programme It is not a success in Kerala You supply half wheat and half paddy You have announced that the entire quantity will be given in paddy but that has not been implemented The quantity supplied is very low compared to the wages the agricultural labour gets in Kerala They get Rs 10 per day and you give only 2 1/2 kgs of foodgrains and that is nowhere as a fair compensation Some higher quantum of rice may be given for the day's work and some share of it may also be given in cash While discussing the Sugar Mills take-over Bill I said a portion of the wage may also be given in the form of sugar When you are giving food why not add some sugar too? Why not give them say 1/2 kg of sugar as part of the wage?

There is another aspect The Minister is also in charge of Food There is a lot of complaint about the quality of foodgrains supplied in our State The rice supplied there is fine and superfine which do not sell After all it is meant for the poor people and they cannot pay Rs 1 87 or Rs 2 for your rice So it is lying there and nobody wants it Whenever the wholesaler takes it from the depot he is not able to sell it People insist on having only coarse and medium quality rice If that can be arranged that will go a long way to meet their needs

There is one more aspect A lot of this rice is lying there Why not pass it on to the open market or the superbazar where the well-off people can go and buy it?

Sir, our people are not used to the Punjab boiled rice. A lot of it is lying there unsold. It takes 2 to 3 hours to cook. I suggest the entire thing should be taken away.

Then, a word about land reforms. Kerala Government has been constrained recently to go in for amending the Land Reforms Act. It is a very unfortunate development. We have been claiming all these days that Kerala is the foremost State in the matter of land reforms and we have set up model land reforms. But they have been constrained to go in for amending it, as a result of which 9 per cent of the surplus land is to be retained by the land-owners in the name of gift lands and gift lands are sought to be excluded from the operation of the Land Reforms Act. This is a highly retrograde measure and the Government of India should not give its approval to this Bill particularly because this land should be assigned to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

MR. CHAIRMAN: Shri R P. Das.

SHRI R P. DAS (Krishnagar): Mr. Chairman Sir. While taking part in the discussion....

15 hrs.

SHRI M. R. LAKSHMINARAYANAN (Tindivanam): Sir there is no translation.

SHRI R. P. DAS: Translation is going on.

MR. CHAIRMAN: Translation is there. Mr. Das you may carry on.

SHRI R. P. DAS: Mr. Chairman Sir. While taking part in the discussion on the Demands of the Ministry of Agriculture many hon. friends have already put forward their views. I would like to say my say perhaps in a slightly different way. Sir, during the last two years weather was very kind to us. There was good rain and because of this and because of the millions of the cultivators, the country had a record production of food grains and other crops. It is no doubt an event for which the government should be congratulated and along with the government I would like to congratulate those who were engaged in cultivation and also the fine weather which could make this record production possible. But this record production has also created some difficulties and I would like to deal with them now. One of the foremost problem of bumper production is the sharp fall in the prices of the food grains and other cash crops. The agriculturist's main problem today is how to market his produce at a remunerative price. It may sound paradoxical but it is true that even though there is such good crop, every section of the population has not been equally benefited by it. You will be surprised to know Sir, that more than 30 crores of population do not have any purchasing capacity. This lack of purchasing power is a matter which should be taken a serious note of because we have seen when production of sugarcane was more the price of the sugar had gone down to Rs. 2.10 to 2.15 a Kg. but the consumption of sugar had increased from 37 lakh tons to 45 lakh tons i.e. only an increase of 8 lakh tons. This amply proves that unless the purchasing power of the people is raised, mere good production will not help the poorer sections of the population, on the other hand, it will help only the capitalists and a limited few who control the trade. I would therefore say that if the Government which stands by its promise to uplift the lot of the peasants and poorer sections of the society is really able to fulfil its promise then the problem can be solved as otherwise the over production is a danger signal which will create catastrophic situation in the country particularly in the field of agriculture.

*The original speach was delivered in Bengali.

15.04 hrs.

[SHRI M SATYANARAYAN RAO *in the Chair*]

While on the one hand, the vast majority of the rural population is suffering from the lack of purchasing power on the other hand there has not been no real redistribution of land among the landless The tenancy system in our country today despite various legislations passed both by the Central Government and the States continue to be semi-feudal and capitalistic in pattern According to agricultural census figures 15 per cent of the land owners own 31 per cent of the cultivable land, 5 per cent of the land owners own 37 per cent of the cultivable land and the 4 per cent of the top land owners own 60 per cent of the cultivable land These figures more than amply show how in the matter of land ownership the rich continue to have their stranglehold over the poorer sections and how the real tiller of the soil live in a state of hopeless exploitation The natural consequence of this phenomena is the fast capitalist penetration in the sphere of agriculture which is apparent in the States of Punjab Andhra Coastal areas of the South and to some extent in some blocks and talukas of Maharashtra UP Bihar and West Bengal I may mention here that the characteristic feature of this capitalist penetration arises out of better availability of irrigation facilities, possession of better technological equipment and know-how massive capital investment and accumulation of land in a few hands Although a total capitalistic domination over agriculture has not taken place yet the prevalence of spread of semi-feudal capitalism in the sphere of agriculture is clearly discernable What is the result of this capital penetration? The result obviously is that these very few persons are cornering and arrogating to themselves the benefits of good agricultural production which ought to have been transferred to the actual cultivators As a result of this the poor cultivators marginal farmers landless labourers, share croppers and the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being exploited continuously The rich is becoming richer and the poor poorer As I have already stated the purchasing power of a vast majority of the cultivators and the rural population is dwindling very fast Their condition is so pathetic that they get full meal for 130/140 days in a year They have no work for the whole year and their wages are far from remunerative And all these have caused a disastrous effect on the purchasing power of the common man who has no shelter to live no food to eat no clothes to wear and cannot afford the necessities of life like his brethren in the cities The number of such deprived population is no less than 30 to 35 crores When the production increases and the people have no purchasing power a demand is usually made by the capitalist lobby that the surplus foodgrains should be exported or the Government should buy all the surplus We know that the FCI is purchasing the surplus foodgrains and they have built a buffer stock But one who is aware about the functioning of the FCI knows it too well that there is rampant wastage in the process of collection and storage by the FCI The people and the toiling masses I must warn the Government will not tolerate a paradoxical situation where in the midst of plenty there should be colossal wastage resulting in starvation of the people Unless the Government is able to bring about a rapid change in the whole situation the results are bound to be dangerous

Mr Chairman Sir towards the end of February and early March this year under the leadership of Andhra Kisan Sabha nearly 75 000 cultivators had launched an agitation This agitation had spread rapidly over the 9 districts of the State including Nellur, Wrangal, Krishna West Godavari and other places The agitators took possession of 8000 acres of land held illegally and they distributed it amongst 20,000 cultivators The most remarkable feature

of this agitation was that more than 50 per cent of the agitators were women. In this struggle two cultivators were shot dead. The matter was raised in the Andhra Assembly and the Minister assured the House that all land illegally occupied would he recovered and an enquiry into the matter has been ordered. I am referring to this glorious struggle only to suggest that the above incident is a red signal which tell to the nation that unless land is properly distributed, unless cultivators are given remunerative price for their produce and unless their wages are reasonable, the exploited multitude will not tolerate the exploitation for ever. They will unite and will rise all over the country to take possession of the land from those who hold them in illegal possession as in Andhra and will force the Government to change their agricultural policy Before the situation comes to a point of explosion it becomes a political and moral responsibilities of all the political parties of the country that they should bend their energies to end the present exploitation of the landless and the poor cultivators that is rampant all over the country today.

I would like to touch upon another matter of importance. It is irrigation. When we talk about irrigation in the House an impression is created that irrigation is a new creation which has lived only for the last 32 to 35 years. But everyone of us know that it is not so. All the early civilization of the world had an elaborate system of irrigation but with the afflux of time and because of willfull neglect these systems got destroyed and were replaced by modern techniques. The tragedy of the matter is that while we discorded the old we could not implement the modern schemes of irrigation either completely or fully. As a result of this we still find in our country that only 25 per cent of the cultivable land is irrigated and the rest of the 75 per cent is denied irrigation. During the last 20 years, out of 146 major irrigation projects only 20 could be implemented and the Damodar Valley project in West Bengal is one of them. So far as the medium irrigation projects are concerned out of 756 projects only 447 could be completed. So far as the DVC is concerned it was proposed that 7 dams will be constructed but this was not done. Out of these 7 only 4 were constructed and 3 still remains to be done. As a result of this last year the heavy water discharge. in the catchment area due to heavy rains created such a terrific depression that the surplus water which could have been contained if the proposed 3 bands were constructed, broke through its banks and devastated villages, roads, rail lines, and caused untold sufferings to the inhabitants. It is very unfortunate that such an incidents should occur because we know it can be averted. The flood cannot be described as an accident and it is quite likely that under similar circumstances an equally devastating floods may occur in the State and to remedy the situation I would urge upon the Government that the 3 dams should be constructed without further delay, afforestation should be done on the hills and tributaries made out of the main stream to channel out the surplus water in times of need. The West Bengal Government have been persistently suggesting to the Centre about these needs but the authorities that be do not seem to bother or attach any importance to these measures and the result is that hundreds and millions have suffered last year and may be many more will suffer in future.

A word about the Ganga basin water resources organisation. Circle Office No. 2 of this organisation has been located at Varanasi, without much justification and as a result it, is causing a lot of inconvenience in its operation. This office has to oversee the agreement that India has entered into with Bangladesh regarding distribution of water through Farrakka. The Circle Officials have to come Farrakka and Calcutta every now and then to hold talks with their counter parts to watch the joint observation work. They have

[Shri R. P. Dass]

also to run to Calcutta for purchasing spare parts, hold discussions with Calcutta Port authorities regarding hydrological observations, to deal with the disputes arising out of Teesta water and also their location in Calcutta for the purposes of forecasting floods would be very helpful. For all these reasons it is very necessary that the Circle Office should be shifted from Varanasi to Calcutta and I would urge upon the Government to take immediate steps in this matter.

Finally, I would conclude by saying that I have just now received intimation from Dandakarnaya that the flour supplied by FCI is of very poor quality and I am laying on the Table a specimen of the same and will urge that something should be done in this regard also.

SHRI BALDEV SINGH JASROTIA (Jammu): Mr Chairman, Sir, I am thankful to you for this opportunity that has been given to me to speak on the Demands of the Ministry of Agriculture and Irrigation.

Sir, Agriculture is the main industry of the country. I congratulate the hon. Minister and the farmers who have produced wheat, rice and jowar in abundance so as to surpass all the previous records. But at the same time I feel sorry on the ground that sugar production has fallen. So is going to be the fate of potatoes which have got a poor market and no provision for storage etc. I need not go into details but I share what other hon Members have said.

Sugar and Potatoes need a policy. There should be a common agricultural policy in toto so that the people who produce will not suffer in the matter of marketing, price etc. The country demands that, as in the case of the success in rice, wheat, jowar etc. so also we should have success all round and the present suffering or shortage of oilseeds, cotton and pulses should be reserved. Heavy expenditure is being incurred on the import of oil etc. which can be saved by being self-sufficient in these things. Our farmers have been under a delusion and a confusion. Sometimes they are asked to produce wheat, but when there is some shortage of sugar, they are asked to produce sugar and so on, without any specific policy in this connection So, what is needed is that the hon Minister should take care to see that the farmers are helped by guiding them in these matters as well. Deforestation is going on unabated in this country due to which floods and soil erosion take place in those places where rivers are flowing. This should be stopped. Necessary land reclamation and soil conservation programme should be undertaken for creating an infrastructure for agricultural production in the country In this connection, I may mention about the J&K State, more particularly Jammu region where four rivers—Chenab, Tawi, Ravi and Basantar—are flowing. Due to deforestation these rivers cause erosion in and around so many areas of the villages in this region. If these rivers are tamed by constructing bunds over them, I think hundreds of acres of land can be brought under cultivation and we can increase the agricultural production More agricultural production means more progress in the country. Therefore, the Government should give thought to these problems so that there is more and more agricultural production in the country.

Now, I come to the modern village. If our country is to advance and progress, we should modernise our villages. As it is, in whatever field the country advances, the benefit does not go to the villages and the villagers are continuing in the same old way of living. I would therefore call upon the hon. Minister concerned to kindly look into these matters and see that in the village the block developmental work is entrusted to the Gram Panchayats or B.D.O's.

There is another important point which I would like to bring to the notice of the hon. Minister. In my own

home town, that is, Kathua in J. & K. State, which is 1025 ft. above the sea level, Morchila known as Guchhi is produced. Normally it is produced in the hilly areas at a higher altitude. But now the experiment has shown that it can be produced 1026 ft. above the sea-level. It is a very good commercial crop and it can be produced in large quantities, especially after this experiment has been successful But I am very sorry to say that nothing has been done by the Ministry concerned so far in this direction and early action in this regard is called for.

Now, recently, the Jute Technology Research Laboratory at Calcutta has been successful in developing the technology of commercial utilsation of agricultural waste produced from cotton and jute Out of these waste materials we get fibre like things. If these waste products are put to proper use, I think it can supplement the income of the farmers They will thus be benefited. Now, it has also been revealed that this fibre-like material can also be got from pineapple and bananas. The hon. Minister should pay attention to this aspect so that things like hard-board, paper board, kraft paper, etc can be manufactured from these waste materials and this can be an additional income to the farmers. I hope the hon. Minister will take special care and in this very budget he would make prosion for this. If the hon Minister is not aware of these things, it is high time that the hon. Minister, in his reply, made positive statement on this point.

Much has been said with regard to Food Corporation of India. I would call it 'Food Corruption of India' Mr Bharat Bhushan has already demanded immediate overhaul of this organisation. If the closure of this organisation is attempted, it will benefit the farmers and the nation to the tune of crores of rupees which are at present being wasted. There are about 25,000 labourers in the F.C.I. and these poor people are being exploited by the contractors and the middlemen. The contractors and the middlemen are the beneficiaries. Every year, more than 5.0 crores of rupees are wasted on account of this organisation. And who is earning? It is only the Food Corporation of India employees who are earning and to which they would not be entitled otherwise. This can be utilised for the nation in other ways gainfully. I hope the hon. Minister incharge of this portfolio will take early steps in this direction and the contract labour system would be abolished and the labourers concerned would be given the best benefit.

The other day, the hon. Minister for Agriculture was kind enough to take part in the meeting of the Food Corporation of India, Workers' Union held on 31st March, 1979. There they voiced their grievances and among others their demands are abolition of contract labour, abolition of private storing agency system, doing away with discriminatory treatment to FCI's direct payment workers, equal pay equal work, evolving a scientific system for good of labour welfare scheme, workers participation in management etc. I am sure, the hon. Minister will consider very sympathetically the genuine demands of the FCI workers who have been clamouring for such a long time. These workers have been facing difficulties at the various depots. The hon Minister was pleased to say some time back that direct payment would be introduced to the labourers working in the FCI. I am sure, in keeping with that assurance given to the labourers in the FCI, he will implement this at the earliest and fulfil his promise. The direct contract labour system should go away and direct payment system to the labourers which will benefit the workers and others should be introduced immediately.

With these words, I support the demands for grants of this Ministry and I hope, the hon. Minister will take due notice of the points made by me.

SHRI DAJIBA DESAI (Kolhapur): Mr. Chairman, Sir, a large number of hon. Members have already participated in the discussion and they have pleaded the case of cultivators and agriculturists and have voiced their grievances. Last year also, a number of hon Members advocated the same line of attitude, but we got no response from the Government. Even in the last year, the hon. Minister for Agriculture announced in this House that he would have a fresh look about the terms of reference of the Agricultural Prices Commission and the personnel of the Agricultural Prices Commission, but after six months actually nothing has happened. In his speech even the Finance Minister and the Deputy Prime Minister realised that agriculture has the largest potential for generating employment and for providing purchasing power to the large majority of people and there cannot be any let up in the task of development of agriculture. But can the Minister for Agriculture and Irrigation say that this approach is reflected in the demands for grants, or the programme of agricultural development, programme of irrigation, programme of rural development or the food programme In fact, this requires a large investment and a greater effort in a number of directions and a better organizational set-up.

As I said, the sentiments or the approach expressed by the Finance Minister and Deputy Prime Minister are not reflected in the demands for grants of the Ministry of Agriculture and Irrigation. Take for instance the question of procurement and agricultural price policy. What has been the experience during the last year?

Last year, in spite of demands from every section of the House that remunerative prices should be fixed and Government should come into the market to purchase all available market surplus, Government insisted that the Food Corporation of India and some other agencies will purchase in the open Mandis, paying only a support price. Actually, the result was that the marketing machinery with the Food Corporation or with bodies like NAFED could not reach the Mandis, and the cultivator had to sell his produce at distress prices. All the cultivators in India who were producing wheat, paddy, sugar-cane, potato and jute had to sell their produce in the market at distress prices, price lesser than the support prices Even the Government could not give the support price to the cultivators That is the plight of the cultivators

It is not that the prices of agricultural commodities are going down, that those of industrial commodities are going up, and that there is a big gap between the two. But it is the act of omission on the part of the Government i.e because of Government's policy that this gap has been widening day by day. The result, next year, is going to be the same. The Food Corporation or any other authority or machinery of the Government of India cannot reach every Mandi and every cultivator; and they cannot purchase all the agricultural produce offered by the cultivators. And the Government has dumped the cultivator in the lap of the traders; and the traders have amassed a lot of profits. So, this is the policy of free trade.

Government is taking credit, saying that because of free trade, there is a surplus of agricultural produce, foodgrains etc. and that in every market, you can purchase anything at a reduced or reasonable price. But what is the result? This is the result of free trade which I want to tell the Janata members: this is the policy by which the Government has reduced the cultivators to a pitiable condition.

One hon. Member has just described the working of the Food Corporation. But what is the attitude of the

Government here? Government has calculated the subsidy to the Food Corporation as a subsidy to the cultivators. It is an anomaly, Food Corporation spends Rs. 17 per quintal for just keeping the stock; and again, it spends Rs. 32-80 per quintal for carrying the stock. All these Rs. 560 crores have been debited or credited to the account of cultivators. Is it justice? In fact, this is not given to the consumers. No subsidy is given to them. The only subsidy given to the consumer is Rs. 2.50 for wheat and Rs. 5 or Rs. 7 per quintal for rice. But actually, the carrying cost of buffer stock is supposed to be Rs. 560 crores—or it is there for maintaining the stock. It is not a subsidy given either to the consumer or to the cultivator. It is just a trading account.

In the matter of rural development, Government has come forward now with an Integrated Rural Development Programme. The name appears big. And some voluntary agencies are to be approached and taken into this movement. This Integrated Rural Development Programme is a combination of 5 previous programmes, viz. Small Farmers' Development Agency, DPDA, Desert Area Development Programme, Drought-Prone Area Programme and lastly the Food for Work Programme. Already, out of 5005 blocks, some 2,000 blocks have been covered under these 5 schemes.

Now 300 blocks are to be taken up this year under the integrated rural development scheme, because the Agricultural Department says that financing of these 2000 blocks will be on an old pattern. But the small cultivators—people holding below 5 acres of land—landless labourers, workers will get subsidy at the rate of 25 per cent, 33 per cent and 50 per cent. Is the Government aware that these small cultivators are eligible for getting loan because they are in arrears of loan? Unless they clear their previous loan, they are not eligible for getting further loan. In a number of districts and blocks, the banks are not prepared to finance these projects because of this. The project officers just complete the forms for minor irrigation, for land development and so on and forward them to the banks. If the banks agree to finance them, they are eligible to get subsidy. It means the banks cannot give them loan because they are defaulters. Then the Government has no reason to give them subsidy.

Under the integrated rural development scheme, they have to identify the cultivators. In that process, one or two years ago. Then the proposals have to be submitted to the project officers. That takes one year. For the last three years, I ask the Government to give the estimate of expenditure on this scheme. It is a small scheme. In India, the cultivators who are holding less than half an hectare of land, their number is 2.31 crores; the cultivators who are holding less than one hectare of land, their number is 1.25 crores; and the cultivators who are holding less than 2 hectares of land, their number is 1.34 crores. Then there are six crores landless labourers. It means there are 10 90 crores eligible people. Out of them, they have identified 1.60 crores. This is the report of ten years. In 10 years, they have completed this thing

If you want to take up this scheme, these people must be given the facility of finance and the defaulters must be treated as new applicants. Their loans must be cancelled. This is a good scheme. But if it has to be implemented, then the Government should come forward with definite proposals and take all the people into confidence.

We oppose voluntary agencies, because they are sponsored by Tatas and Birlas. These agencies will play havoc in the rural areas and therefore we oppose them. With these words, I conclude my speech.

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : सभापति महोदय, कृषि मंत्री किसान का बेटा हो और दोनों कृषि मंत्री ही किसान हों फिर भी कृषि और किसान की यह हालत हो कि जो वह पैदा करता है, उसका मूल्य उसे न मिल सके, तो कारखानेदारों की लाबी कितनी ताकतवर है कि बजट पर उन्होंने तूफान मचा दिया है कि यह किसान का बजट है, यह शहरियों के खिलाफ है, यह सिर्फ देहातियों के हक में है। किसान को मिला क्या है ? उसे सिर्फ एक बोरे खाद पर 5 रुपये का मुनाफ़ा हो गया है। एक बोरे खाद पर सिर्फ 5 रुपये की कीमत में कमी हो गई है और उसका जो आलू था, जिसे सरकार ने 50 रुपये खरीदने का हुक्म दिया, कि इससे कम होगा तो सरकार खरीदेगी, इस हाउस में इस बात का एश्योरेंस है, और वह आलू जो कि 50 रुपये वाला है वह 5 रुपये बोरा बिके और यही नहीं बल्कि 3 रुपये बोरा बिके। पौने चार रुपये का बोरा आता है और पौने 3 रुपये का आलू बिके। आलू की छंटाई पर भी 3 रुपये लगते हैं और मण्डी तक पहुंचाने का पैसा भी लगता है।

यह बात अचानक नहीं हो गई है, मंत्री जी को याद होगा कि जब यहां दिसम्बर में इजलास हो रहा था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि आलू का इंतजाम कीजिए। आलू पैदा करने वाले बेचारे उल्लू बन गये हैं, उन्हें सूझ नहीं रहा है कि वह क्या करें। लाखों रुपये का नुक्सान उन्हें हुआ है छोटे-छोटे ज़मीदार का जिसको पैदा करने पर 20, 20 और 25, 25 हजार रूपये खर्च हो चुका है और अब उस आदमी को उसके 2 हजार रुपये नहीं मिल हैं। वे लोग बिल्कुल तबाह हो गए हैं।

मैं एक वार्निंग और आपको देना चाहता हूं कि जो गेहूं की फसल आ रही है उसमें इतना गेहूं आ रहा है कि वह आप संभाल नहीं पायेंगे। बीच के दलाल सत्यानाश कर देंगे, फूड कार्पोरेशन वाले।

जनता पार्टी ने मैनिफैस्टो में कहा था कि किसान जो भी पैदा करेगा, उसको जब वह बीजेगा, उस वक्त उसे बता दिया जायेगा कि उसे यह मोल मिलेगा। यह मैनिफैस्टो अकाली दल और जनता पार्टी का है। हम जितनी देर विरोधी दल में रहे, लगातार इस बात के लिए सरकार की टीका-टिप्पणी करते रहे कि किसान को पहले बता देना चाहिये कि उसकी चीज का क्या भाव होगा। आज मार्केट में गेहूं आना शुरू हो गया है लेकिन सरकार ने अभी तक भी जिस भाव पर गेहूं खरीदा जायेगा, उन भावों का एलान नहीं किया है। तय हो गये हों तो पता नहीं, लेकिन ऐलान नहीं किया है।

यह कितनी बड़ी बात है कि किसान जो पैदा करे, उसका भाव सरकार मुकर्रर करे और सरकार भी उस वक्त मुकर्रर करे जब उसका माल मंडी में आ जाये। एक तरफ तो किसान की चीजों की कीमत सरकार मुकर्रर करती है और दूसरी तरफ कारखानेदार हैं जिसके माल की कीमत वह खुद मुकर्रर करते हैं। वह अपने माल की कीमत जब मर्जी आया बढ़ा लेते हैं।

अम्बेसेडर कार सन् 1970 में 17 हजार रुपये की थी आज उसी कार के दाम 53 हजार रूपये हैं। 1970 और 1979 के बीच में 3 गुना दाम ज्यादा बढ़ गये हैं। आपको शायद याद होगा कि कार की कीमत बढ़ाने के लिए जब जस्टिस हिदायतउल्ला के पास गये तो उन्होंने मज़ाक में कहा था कि इस कार की हर चीज़ बजती है, लेकिन हार्न नहीं बजता है। हार्न के बगैर सब चीज बजती हैं। कार की कीमत 17,000 रुपये से बढ़ कर 53,000 रुपये हो गई है। इसी तरह ट्रैक्टर की कीमत 19,000 रुपये से बढ़ कर 60,000 रुपये हो गई है। कारखानेदार की बनाई हुई हर एक चीज़ की कीमत बढ़ गई है।

आज सवालों के जवाब में उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फ़र्नाण्डीस ने कहा है कि कपास की कीमत कम हुई है और कपड़े की कीमत बढ़ गई है।

हम लोग, जनता पार्टी वाले, इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि हमने प्राइसिज़ को काबू में रखा है। श्री बरनाला और श्री भानु प्रताप सिंह बतायें कि क्या उन्होंने किसान को मार कर प्राइसेज़ को कन्ट्रोल में रखा हुआ है ? कारखानेदार की चीजों की कीमत कहां है और किसान की चीज़ों की कीमत कहां है ? जिन चीजों की कीमतें कम रखने के बारे में सरकार क्रेडिट लेती है, वे तो किसानों की पैदा की हुई चीजें हैं। जो चीज़ किसान पैदा करता है, उसकी कीमत कम है, और जो चीजें वह खरीदता है, उनकी कीमत ज्यादा है, जैसे लोहा, कोयला, और सीमेंट वगैरह।

सीमेंट की कीमत पहले 11, 12 रुपये थी। जब जनता पार्टी ने राज्य सम्भाला तो उसकी कीमत 17 रुपये के करीब थी। लेकिन आज सीमेंट की कीमत 26 रुपये से ऊपर होने वालीं है। ब्लैक में उसकी क्या कीमत है यह कहने की ज़रूरत नहीं है।

किसान जो चीज़ पैदा करे उसको उसका मोल न मिल सके यह इन्साफ़ की बात नहीं है। मैं फिर वार्निंग देना चाहता हूं कि सरकार अपनी मशीनरी को तरतीब दे, उसको कसे। किसान का गेहूं मण्डी में आ जाये और भाव मुकर्रर कर दिया जाये 115 या 120 रुपये और मण्डी में किसान को 90 या 100 रुपये से भी कम मिले। मिनिस्टर साहब मण्डी में जा कर इस बात की एनक्वायरी करें।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : आप एनक्वायरी क्यों नहीं करते हैं और उसकी रिपोर्ट मिनिस्टर साहब को क्यों नहीं देते हैं ? पब्लिक के रिप्रेज़ेन्टेटिव क्या करते हैं ? क्या सिर्फ मिनिस्टर ही एनक्वायरी करेगा ?

चौधरी बलबीर सिंह : हम तो करते हैं--हम अब भी कर रहे हैं। आपकी जुबान बंद थी। आप बोल नहीं सकते थे। हम करते हैं और मंडी में जा कर भी लड़ाई करते हैं कि इस ढंग से नहीं होगा।

मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इसकी एन-क्वायरी करायें। मण्डी में नाफेड वगैरह सरकार की एजेंसियो ने आलू दस रुपये बोरी के हिसाब से लिया है, और वही आलू 50 रुपये बोरी दिया है। किसान को उसकी कीमत नहीं मिल सकी। जो सहूलियत सरकार ने दी, उसका फ़ायदा फिर उस आदमी ने उठाया, जिसके पास पैसा था, जो खरीद सकता था और जो किसान को एक्सप्लायट कर सकता था।

किसान की बातें हर एक सदस्य ने कही है। मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक सुझाव यह है कि सरकार फूड कार्पोरेशन के खर्चे को कम करे। एक बोरी को सारा साल रखने का 32, 33 या 37 रुपये का जो खर्च है, वह बहुत ज्यादा है, उसको कम किया जाये। सरकार किसान के घर में अनाज रखे और उसको खर्च दे। इस खर्च के बारे में एक बार 32 रुपये का ऐलान हुआ था और दूसरी बार 37 रुपये का। पता नहीं कि असली खर्च कितना है। मिनिस्टर साहब मुझे बता दे, तो मैं उसके मुताबिक बात करूं। अगर फूड कार्पोरेशन के गोदाम में 35 रुपये खर्च होते है, तो सरकार किसान से कहे कि वह उसमें गेहूं 115 रुपये -I- 25 रुपये, यानी 140 रुपये में लेगी, और फलां महीने में लेगी। इससे सरकार का खर्च कम हो जायेगा और उसे गोदाम बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। किसान को सरकार कुछ एडवांस रुपया दे दे, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है, वह अपने माल को रोक नहीं सकता है और उसे एकदम मंडी में बेचना पड़ता है। सरकार अपना माल गोदाम में रखती है। वह समझे कि उसका माल किसान के स्टोर मे पड़ा है। किसान इस माल को सम्भाल कर और ठीक तरह से रखेगा, बीमारियो से महफूज रखेगा। सरकार उसको खर्चा दे। इससे किसान को पैसा मिल जायेगा, सरकार स्टोरेज की शार्टेज की समस्या को हलकर सकेगी और किसान को अपनी मेहनत का कुछ मोल मिल सकेगा। यह सुझाव मैंने दिया है-इस पर अमल करा जाये।

मैंने पिछले साल भी कहा था—जितने सरकारी मुलाजिम है, जितने कारखानों में काम करने वाले मुलाजिम हैं—इन सब लोगो को एक साल का राशन दिया जाय और उस की कीमत 12 किस्तों में उन से वसूल की जाय। जो सरकारी कर्मचारी हैं उन की तनख्वाह से हर महीने उस की कीमत का बारहवा हिस्सा काट लिया जाय, इसी तरह से कारखाने के कर्मचारियों के वेतन से काटा जाय। इस से यह फ़ायदा होगा कि करोड़ों मन अनाज जो मंडियो में पड़ा रहता है, लोगों के घरो में पहुंच जायगा और हमारे यहां जो स्टोरेज की दिक्कत है, वह दिक्कत हल हो जायगी।

दूसरा सुझाव यह है कि हमें माल बाहर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस वक्त हमारे यहा बहुतायत-कावक्काइसिज हैं। पिछले 30 सालो के कांग्रेसी राज में हम कासा-गदाई ले कर कभी अमरीका के पास, कभी रूस के पास जाते रहे

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हमने 1 करोड़ टन अनाज आप को दिया था।

चौधरी बलबीर सिंह : रेड्डी साहब तो हर वक्त जवाब देने के लिए रेडी है। लेकिन वह अपनी बात भूल गये। मैं आप को एक कहानी सुना दू। एक राजा शिकार पर गया, अपने साथियों से बहुत आगे निकल गया। एक जगह उस का एक बाग नजर आया, वह अन्दर चला गया। वहां देखा कि एक बुढ़िया बैठी थी। उस ने कहा—मां, पानी पिलाओ। बुढ़िया ने कहा—बेटा, पानी की क्या बात है, मैं तुझे रस पिलाता हूं। उस ने दो सन्तरे पेड़ में से तोड़े और उस का रस निकाला। दो सन्तरों से गिलास भर गया। राजा ने रस पिया और आगे चला। रास्ते में उस ने सोचा कि दो सन्तरों से गिलास भर गया, इसलिए इस पर टैक्स लगाना चाहिए। जब वह वापस लौटा तो फिर उसी जगह पर गया और बुढ़िया से रस पिलाने को कहा। बढ़िया ने फिर दो सन्तरे तोड़े और रस निकालने लगी, लेकिन इस बार उतना रस नही निकला। राजा ने पूछा—माई, क्या बात है, सुबह दो सन्तरो से गिलास भर गया था, इस दफा नहीं भरा? बुढ़िया ने जवाब दिया—बेटा, यहां के राजा की नीयत में फर्क आ गया है।

आप की नीयत खराब थी, इसी लिए लगातार आप के राज्य में कमी रही। वरना आप बतलाइये—आप के जितने प्लान थे, क्या उन का असर 1977 के बाद ही होना था, पहले उन का असर क्यों नहीं हुआ? आज किसान ज्यादा पैदा करता है—तो आप उसे ज्यादा पैदा करने से मत रोकिये। लेकिन हमारे मिनिस्टर कहते हैं कि उस चीज की म फसल कम कर दो। गन्ने की फसल कम कर दी जायगी तो फिर क्राइसेज आयेगा, उस के बाद आप फिर कहेंगे कि ज्यादा पैदा करो। इसी तरह से गेहूं की बात है—अगर गेहूं की पैदावार कम होगी, तो फिर दिक्कत पैदा होगी। इस लिए यह गलत पालिसी है। आप मेहरबानी कर के किसान को ज्यादा पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दीजिए और जो सामान ज्यादा पैदा होता है उस को विदेशों में, दूसरे देशो में भेजने का प्रबन्ध कीजिए। अपने माल के लिए विदेशों में मंडियां तलाश कीजिए, बाहर की मंडियों में मुश्किल ग्राहक ढूंढने की जरूरत है। बाहर के लोग यह कहते है कि जब हमें माल की जरूरत होती है, तब तो आप देते नहीं हैं, लेकिन जब हम दूसरा इन्तजाम करने जाते हैं, तब हमारे पास उसे बेचने के लिए आते है।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं—हरियाणा और पंजाब में आप सब्जियों को बहुत तेजी से पैदा कराइये और साथ ही गल्फ-कन्ट्रीज में ऐसा इन्तजाम कीजिए कि उस को वहां बेचा जा सके। उन के साथ इन्तजाम करें ताकि सामान बाहर भेजा जा सके। जब आप का पैटर्न बदल जाएगा, तो यहां के आदमियों को पैसा मिलेगा, किसानों को अपनी मेहनत का दाम मिल सकेगा और बाहर के देशों को भी अनाज भेजा जा सकेगा।

सभापति महोदय : श्री ए० सी० जार्ज।

चौधरी बलबीर सिंह : सिर्फ एक मिनट और दे दीजिए।

सभापति महोदय : आप बहुत बोल चुके हैं।

श्री ए० सी० जार्ज

SHRI A. C. GEORGE (Mukandapuram): Mr. Chairman, Sir, at the very outset when I participate in this discussion on Agriculture Ministry, instead of going through the normal ritual of either congratulating him or decrying him I only want to say how lucky he is. During the past two, three years, the agriculture in this country has been fairly good, because of God's grace and nature's kindness. Weather is fairly good. The monsoon is rather favourable. The farmers are basically hard-working. Mr. Barnala is lucky and this Government is now fairly on a good footing.

When he took over, we had a stock situation which was unique and unprecedented in the history of independent India. So, he inherited one of the best stocks of foodgrains this country ever had. I particularly congratulate him because unlike the other Ministers, he did not spoil what he got in a Government where almost all other Ministers, whatever they inherited like a prodigal son or like a spoilt child, they were in a spree of frenzy to friter away everything that they got. Here I mention the Finance Ministry. They inherited a foreign exchange reserve of nearly 4000 crores which was accumulated with hard labour of our boys in foreign countries, in which the contribution of Keralites is not very small. Now, the Finance Ministry has tried their level best to see how to empty the coffers. About Commerce Ministry, the same thing applies. For the first time since independence we have record adverse balance of payment of nearly Rs. 1600 crores. I am proud to say because I was the junior Minister of Foreign Trade that we handed over a surplus balance of payment.

About Industry Ministry, the less said the better. The speeches which the Minister makes at lunch, after lunch and at dinner, all are contradictory. And the officers say that they do not take them seriously. So, they blow hot and cold. One day it is nationalisation, the other day it is denationalisation.

About External Affairs Ministry, we know how an aggression was committed under the very nose of our External Minister.

Mr. Barnala, I thank you very much. You did not atleast spoil what you got. I am reminded of a small story which has its bearing on the Agriculture Ministry. In a congregation the cap of the priest was sent for contribution. It was a misers' congregation. In that crowd the cap went round without contribution of a penny. Finally, from that congregation the cap came back to the parson. He took it up, looked into the cap and found there was nothing; he just turned it up and shook it; there was nothing. Then he raised his hand up and said "Oh! Lord I thank thee from his congregation I got back at least my hat." This is the case of the Agriculture Ministry. From the Ministry of Agriculture we got back our hat. So, I congratulate him for not spoiling it.

Of course, he did something in Kerala. Perhaps, he was under the evil influence of the Kerala Government at the time of the constitution of the Coconut Board. Of course, I know that it has been passed in a hurried manner. It has not only been concentrated, but super-concentrated with bureaucracy. It is not going to serve the purpose which he has in mind.

I never question in *bona fides*, because I know that in his heart of hearts he is a son of the soil, he is a farmer and the blood of a farmer is in him. So, I never question his *bona fides*. Kerala is a State where the name of the State itself is inherited from a tree. I was trying in my own limited way to find out whether there is any other instance throughout the world of a country being named after a three, but I could not find one. It is only in Kerala it was known as the land of Keras, which means coco nuts. Of course, some of our friends

in the north pronounce it as Kerala, which means bittergourd.

The production of coconut is our mainstay. The other day we were reading that in spite of the efforts made by the Government to increase the acreage under coconut cultivation in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Orissa and Bengal, the production of coconut has gone down by about 7 per cent in a decade. Here I want to make a specific suggestion for his consideration. In the Kuttanad area, which is the main coconut producing area, we are facing one of the biggest attacks of a disease by insects because of which the coconut production is going down. Since none of us has found a solution for this virus so far, I want to make a suggestion. Just as we did once for rubber, we must go in for a complete removal of the trees In rubber what was done was slaughter tapping after which the emaciated trees were cut off. We gave both subsidy and loan so that there will be an incentive for the farmer to cut down the old trees Instead sticking to his meagre income, since we have not found a solution for this virus, we should encourage the farmers to cut down the trees and replant them. I would request the Agriculture Minister to take immediate measures to create a fund for coconut replantation. In order to encourage the farmers, we have to give the incentive of a loan as well as subsidy so that the farmer will be forced to cut down his trees, which are virus-ridden, and plant new trees. For that a coconut Development Fund has to be created so that the present virus may be fought and production may be increased with a new variety of plantations.

So far as the Coconut Board is concerned, even at this stage I would say that the Minister must take measures to re-vamp it, to regroup it and make it more popular-based rather than bureaucracy-based.

Then I come to another point. We have now got a regulated market, cooperatives and so many other methods to see that the farmers get a proper remuneration for their work. In the hilly slopes of the Malabar area, known as the *Malayora Pradesam*, people from the plans have gone to the mountain slopes, cultivated the virgin land and made a paradise out of it. Even though in a State like Kerala we have got a lot of transportation facilities, in the slopes of the hills there are no proper roads The realisation of the farmer for any crop is directly related to the accessibility to the market In a State like Kerala, where virgin land has been cultivated and many cash crops have been grown, where there is cultivation of the hill slopes of Kerala, there should be a connecting road from Quilon via Kottayam, Idiki, Ernakulam, Trichur, Palghat, Calicut, Malappuram to Cannanore There is a proposal for a hill side road, which should be looked into by the Transport Ministry All these areas should be directly linked so that the farmers can get a reasonable realisation upon their efforts I would urge upon the Government to take steps to see that a specific allotment is made for this type of facilities for the farmers who have gone to the inaccessible areas and created wealth there for the benefit of the country.

16 hrs.

Sir, in my constituency there is a proposal for a sluice-cum-bridge in Elanthikkara Kanakkankadavu across Chalakudy river It is a multi-purpose project. It is a project which will create a bund and save at least 13,000 acres of good paddy land from erosion by saline water This proposal is jointly funded by the State Government and the Central Government. It is a bund-cum-bridge It will serve the purpose of bridging the river and at the same time the bund will serve the purpose of preventing the paddy land from being eroded by saline water for which purpose there is this proposal. So, I urge upon the Minister to kindly fish out the old files and see that it is sanctioned immediately. I understand the sea-erosion is also coming under the

[Shri A. C. George]

purview of the Agriculture Ministry. These days when we talk about disarmament and peace and preventing war, there is a regular war going on at the coast of India, at the western coast especially the south western coast coming down from Karnataka to Kerala and the eastern coast of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. This coast has to be protected by anti-sea erosion measures. The funds allotted to Kerala are only a pittance, if not meagre. So, I hope the anti-sea erosion measures will be taken to protect the coast.

श्री अर्जनसिंह भाई पटेल (पोरबन्दर) : सभापति महोदय, कृषि और सिंचाई मंत्री ने इस विभाग की जो मांगें सदन के सामने रखी हैं, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। गत 2 साल में कृषि सिंचाई मंत्रालय ने अन्न उत्पादन, सिंचाई क्षेत्र और डेरी उद्योग में काफी प्रगति की है, लेकिन मैं कुछ प्रमुख बातें इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

जब कृषि राज्यमंत्री श्री भानुप्रताप सिंह जी राज्य मंत्री नहीं थे, संसद् सदस्य थे, तब उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। उसके कुछ उद्गार मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। कृषि साधनों पर सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष-कर उनके उत्पादन मूल्य के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार हैं :—

उर्वरक पर 41.99 प्रतिशत कर है, कीटनाशी दवाओं पर 55.00 प्रतिशत, बिजली की मोटरों पर 26.73 प्रतिशत, ट्रेक्टर पर 44.74 प्रतिशत, ट्रेक्टर पुर्जों पर 26.93 प्रतिशत और डीजल तेल पर 74.47 प्रतिशत कर हैं।

मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि क्या उनके मंत्रालय में कोई योजना है जिससे इन अप्रत्यक्ष करों को कम किया जा सके? वह अप्रत्यक्ष करों को कम करने के लिए क्या करना चाहते हैं?

भारत का राजपत्र जो 9 मार्च का प्रकाशित हुआ है इसमें फर्टिलाइजर के दाम लिखे हैं। 19 प्रकार के फर्टिलाइजर इसमें लिखे हैं। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए सभी को पढ़ता नहीं हूं, लेकिन 3, 4 के बारे में बताना चाहता हूं। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपरफास्फेट ट्रिपुल, डायमोनियम फास्फेट के बारे में बताता हूं कि इसमें लिखा है कि इनका प्रति टन का भाव इस प्रकार है :—

अमोनियम सल्फेट 890 रुपये, यूरिया का 1450 रुपये, सुपरफास्फेट ट्रिपुल का 1600 रुपये और डायमोनियम फास्फेट का 2200 रुपये, एन० पी० के० का 1800 से 2000 रुपये और सुपर फास्फेट ट्रिपुल (पाउडर) का 1500 रुपये है।

आज अनाज का दाम क्या है, 20 रुपये किलो का दाम 20 रुपये है। एक टन पर 1 हजार किलो होता है, उसके हिसाब से लगाइये तो एक किलो फर्टिलाइजर का दाम 2 रुपये पड़ता है और अनाज का दाम 1 रुपये आता है जब कि खाद का दाम 2 रुपये होता है। यह बात अच्छी नहीं है। अनाज का जो दाम होता है, उससे ज्यादा दाम फर्टिलाइजर का नहीं होना चाहिए।

जहां तक वाणिज्यिक फसलों का सम्बन्ध है, हमारे देश में पांच मुख्य तिलहनें पैदा होते हैं : मूंगफली, तोरिया-सरसों, तिल, अलसी और अरण्डी। कुल मिला कर तिलहन का उत्पादन 1973-74 में 80.85 लाख मीट्रिक टन, 1974-75 में 80.53 लाख मीट्रिक टन, 1975-76 में 90.91 लाख मीट्रिक टन, 1976-77 में 70.83 लाख मीट्रिक टन और 1977-78 में 80.93 लाख मीट्रिक टन हुआ। 1978-79 में वह 88 लाख मीट्रिक टन होने वाला है। सभी तिलहनों में मूंगफली की पैदावार 70 प्रतिशत है। पिछली सरकारों ने तीस सालों में मूंगफली के बारे में कुछ नहीं किया। क्या हम भी कुछ नहीं करना चाहते हैं?

गुजरात, और गुजरात में खास कर सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र में खास कर जूनागढ़, राजकोट, जामनगर, अमरेली और भावनगर वैगरह जिले देश की एक-तिहाई मूंगफली पैदा करते हैं। सरकार ने इसके लिए क्या किया है और क्या करना चाहती है? मैंने सुना है कि जूनागढ़ में राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र खोला गया है। लेकिन वहां पर काम कुछ नहीं हुआ है। मैं जूनागढ़ में रहता हूं। मैं कृषि मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र में तुरन्त काम शुरू करें।

सभापति महोदय, कृषि विभाग की 1978-79 की रिपोर्ट, पेज 9, पैराग्राफ 12 में कहा गया है कि 1978 से 1983 के अंत तक कृषि-जिंसों का निर्यात 3125 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है। वह किस तरह बढ़ाया जा सकता है? बार बार कृषि-जिंसों की निर्यात-बंदी की जाती है। बार बार नहीं होनी चाहिये। कृषि-उत्पादन की किसी भी जिंस पर किसी प्रकार का निर्यात-शुल्क नहीं होना चाहिए। निर्यात पर एस० टी० सी० और नाफेड की मानोपली नहीं होनी चाहिए। उत्पादकों, किसानों, व्यापारियों और परिसंस्करणकर्ताओं की सलाह और सेवायें सक्रिय रूप से लेनी चाहिये। कृषि-जिंसों पर निर्यात-शुल्क रद्द करना जरूरी है।

विभिन्न कृषि-जिंसों पर प्रतिटन के हिसाब से निर्यात-शुल्क इस प्रकार है : एच० पी० एस० मूंगफली की गिरी : 1500 रुपये, मूंगफली साबुत : 1150 रुपये, रुई: 2500 रुपये, मूंगफली की खली (डीआयल्ड)केक : 125 रुपये। क्या मंत्री महोदय वित्त मंत्रालय से बात-चीत कर के इस निर्यात-शुल्क को रद्द कराना चाहते हैं? 3125 करोड़ रुपये का निर्यात सरकार किस तरह करेगी?

करेगी ? जब उत्पादन होगा, तभी वह निर्यात कर सकेगी । लेकिन निर्यात-शुल्क को कम नहीं किया जाता है, बल्कि उसको बढ़ाया जाता है । पांच सात दिन पहले एक सवाल के जवाब में बताया गया कि एच० पी० एम० और मानुल मूंगफली और रूई का निर्यात शुल्क बढ़ा दिया गया है । यदि मंत्री महोदय एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वित्त मंत्रालय से मिल कर निर्यात-शुल्क को रद्द कराना चाहिये ।

जहां तक कृषि मूल्य आयोग का सम्बन्ध है, प्रश्न यह है कि वह भाव कैसे तय करता है । कृषि-उत्पादन के मूल्य तय करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिये (1) कृषि की जमीन की कीमत, (2) जमीन की कुल कीमत का बैंक रेट के हिसाब से 5 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज, (3) किसान व कुटुम्ब द्वारा की गई मेहनत, (4) खेत-मजदूरों को दी गई मजदूरी, (5) आयल इंजिन, बिजली के पम्पस, ट्रेक्टर, ट्रेलर वगैरह औजारों और यंत्रों का खर्च, (6) बैलों की कीमत, (7) बिजली, डीजल आयल, फर्टिलाइजर, कीटनाशक दवाओं का खर्च, (8) लिया गया कर्ज और उसका ब्याज, (9) जमीन महसूल और उपकर ।

यह सब हिसाब लगा कर लागत तय होनी चाहिये, जैसा कि उद्योग और व्यापार में होता है । इसके अलावा कृषि मूल्य आयोग में कोई किसान नहीं है । उसमें सब एयर-कण्डीशन में बैठने वाले लोग हैं । किसी ने खेती देखी नहीं है, नदी भी नहीं देखी है शायद हवाई जहाज से देखी होगी । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में किसान के प्रतिनिधि को रखिए ।

अन्त में मैं कुछ सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूं —

1 कृषि उत्पादों की लागत—सभी प्रकार का खर्च गिन कर उनका भाव तय किया जाये ।

2 मूंगफली एच० पी० एम० डी० आयल्ड केक्स (मूंगफली की खली) रूई वगैरह इन सब कृषि उत्पादों का निर्यात शुल्क रद्द किया जाये ।

3 सिंचाई और ग्रामीण मार्गों में पिछड़ा हुआ—गुजरात को खास प्रकार से—आर्थिक सहायता दी जाये ।

4 कृषि भाव पंच (एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन) में किसानों का पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिये ।

5 फसल और पशु बीमा योजना को शीघ्र अमल में लाये ।

6 गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के समुद्रतटीय जमीन के कुओं का पानी खारा हो गया है । माधवपुर, पेड, पोरबन्दर, मियाणी, ओखा, नवलखी, मांडवी तक "क्षार प्रवेश अवरोधक योजना" के लिए वित्तीय सहायता दी जाये ।

7 फर्टिलाइजर डीजल, कृषि आयल और कीट नाशक दवायें, कृषि उपयोगी यन्त्रों, मशीनों का उत्पादन शुल्क रद्द किया जाये ।

8 मूंगफली जैसी मुख्य तिलहन के लिए जूनागढ़ में मन्जूर किये गये "अनुसंधान केन्द्र" का कार्य शीघ्र चालू किया जाय ।

9 मूंगफली का न्यूनतम सहायक मूल्य 250 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिये ।

10 किसानों के लिए 5 प्रतिशत की दर से कर्जा दिये जाने का प्रबन्ध होना चाहिये ।

11 नर्मदा योजना का कार्य शीघ्र चालू किया जाये और इस योजना में केन्द्रीय सरकार पूरी वित्तीय सहायता दे ।

12 गुजरात के ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के लिए पूरा अनुदान मन्जूर किया जाये ।

13 कृषि जिन्सों का निर्यात बढ़ाया जाये और कई तथा खाने के तेलों का आयात बन्द किया जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं तथा मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे सुझावों पर ध्यान दें ।

SHRI A. R. BADRI NARAYAN (Shimoga) I rise to oppose the Demands for Grants in respect of the Ministry of Agriculture and Irrigation for the reasons that have been reflected by my cut motions, several in number I hope the hon Minister for Agriculture will go through these cut motions and try to afford as much relief as is possible

With regard to the Central Budget, we are all happy that the Budget is now rural-oriented, a departure from the usual practice of its being urban-oriented I am glad that the hon Finance Minister has provided considerable money for the development of rural areas, from the point of view of agriculture, rural industries, roads and things like that, which go to make up the prosperity of the villagers I am very happy that the Agriculture Ministry is headed by a son of the soil, who is himself a practcal and pragmatic farmer and

[Shri A. R. Badri Narayan]

who has abundant sympathy for the agriculturists. I hope that the red tape of the bureaucracy would not come in the way of implementation of the pious intentions of the Central Government. The Janata Government has solemnly pledged to end the neglect of agriculture and solve the problems of poverty and unemployment within ten years by adopting the strategy of according the top most priority to agriculture and cottage industries. With all the pious intentions of the Government, the agricultural production in this country has been characterised by extreme instability resulting in chronic shortage of foodgrains and also of raw materials, necessitating massive imports which in foodgrains alone is more than Rs. 6,000 crores and in edible oils, it is about Rs 1400 crores. This lag in agriculture has restricted the expansion of the home-market, has hampered the industrialisation of the country, has caused repeated crisis in the formulation of the plans and has also made us increasingly dependent on the imperialists' aid, undermining the economic independence of this country.

Even the limited wealth that is produced by the farmers is all nequitably distributed in the country. The States have drained a part of the income by its taxes and duties; the monopolies and the multinationals have drained through price loot in the capital market; the landlords, the usurers, the hoarders, the profiteers and the bureaucrats have drained through rent, interest, profit, bribes, etc. The peasants produce plenty and suffer while the exploiters fatten, prosper and flourish.

Under the land reforms, only 1.29 million acres of surplus land out of available 21.52 million acres have been distributed. About 20 million acres are yet to be distributed. The Janata Government has put land reforms in the reverse gear. Though I belong to Karnataka, I must in fairness say that practically the tenancy is abolished in the State of Karnataka and the tiller of the soil is now the owner of the land. I would request the Janata Government to see that, in various States, instead of aiding and abetting the landlords to snatch away the tiny patches of land distributed to the poor peasants, this must be put an end to. Several Janata State Governments are shamelessly seeking to enact reactionary amendments to ceiling laws as a legal cover in the marauding of land reforms. Equally shameful is the record of subjecting the peasantry to intensified price loot.

The *Economic Times*, index says that the prices of agricultural commodities have fallen and the prices of manufactures have risen further. The agricultural production has declined by 10 per cent whereas the production of manufactures has increased by 6 per cent, thus causing 15 per cent loss to the agricultural sector. It amounts to roughly about Rs. 2500 crores in a year. This is the annual tribute that is paid by the farmers to the capitalists, the industrialists and the monopolists. The agricultural inputs over 1970-71 output have gone up as follows: diesel—116.6; lubricating oil—209.3; electricity—95.6; cement —87.8, iron—89; fertiliser—75.9; pesticides—131 and tractor—118. While the output of wheat has gone up only by 48 per cent, paddy by 51 percent, jowar by 54 per cent, jute by 40 per cent, cotton by 79 per cent, sugarcane by 33 per cent, the general index of all commodities has risen by 86 per cent. Since 1970-71 the prices of agricultural in-puts, except fertilizers, have risen much higher than the prices of agricultural outputs. The fall in agricultural prices has not been passed on to the consumers. Thus, while raw materials are cheaper, the manufactured items are dearer, for example, cotton and cloth, jute and gunnies, tobacco and cigarettes, oilseeds and edible oils. The fall in whole-sale prices has not been reflec-

ted in retail prices; for example, the wholesale price index for food articles has fallen by 10 per cent but the index of consumer prices has risen by 10 per cent. In December 1978 it was 340 and in March 1977 it was 312. The peasants who are the majority consumers have lost both as producers and as consumers and the gainer are industrialist and traders and the big capitalists, the sharks of the so-called free market. Firstly, they dismantled controls, demolished food-zones and have withdrawn restrictions on forward trading speculation, hoarding land profiteering and, secondly, they have liberalised the credit for hoarding, profiteering and speculation, while restricting the same to State Trading agencies like the FCI, the CCI and the JCI. The increase in bank credit to the private commercial sector has gone up to 2275 crores during 1977 as against 1592 crores in the previous year. There is liberalised import of raw materials in which our production is sufficient to meet our domestic requirements, *viz.*, cotton, rubber, copra and jute. They imported 14 lakh bales of high-priced cotton, paying a subsidy of 72 crores, and 100 crores for staple fibres

Fourthly, there should be a comprehensive distribution system and a widening up of the existing one whereby we are left to the mercy of big traders and mill-owners. Salt, cement, paper, coal, diesel, Kerosene, cooking gas, soda, edible-oils, etc. are all disappearing from the market.

Again, the sugarcane price has been reduced from Rs. 12.50 and Rs. 16.50 per quintal to Rs. 10/-, though the cost of cultivation has gone up. It should not be less than Rs. 12.50 per quintal.

Apart from these things, I wish to say that the farmer is the producer for the country and he deserves the same attention as industrial workers now get. Concentration hereafter should be not only on the industrialists but also on the farmers. The human facilities that have got to be given to the farmer should not be delayed.

MR. CHAIRMAN: Please conclude

SHRI A. R. BADRI NARAYAN: One more point, Sir, and I will conclude. You must conquer the adverse effect of floods on the one hand of delayed and reduced monsoon on the other. I would also refer to unharnessed river waters and linking of the rivers. I am very happy that the Prime Minister has been pleased to announce some days back that the Garland Canal scheme has been under the consideration of the Central Government and that the USSR and the World Bank are likely to finance us, assist us with money as well as with technical knowhow. Leave alone the Garland Canal scheme, there are the South Indian rivers which flow to the west without being utilised in any manner; the water is unnecessarily flowing into the Arabian Sea. A method must be found out to link these various rivers of the South so that we may utilise the waters properly.

Hon. Chairman has been very good to me. He has been asking me to stop. I have got quite a number of points to speak on, but I do not wish to transgress the ruling of the Chair. So, I conclude by appealing to the hon. Agriculture Minister to bear in mind the several points which I have been trying to give in a very constructive manner. I hope he will apply his mind and do the things which are the most dear to his heart in the agricultural sector.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): अधिष्ठाता महोदय अब तक कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अनुदानों पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उन सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। कुछ ने हमारी प्रशंसा की है, बधाई दी है और कुछ ने हमारी आलोचना की है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : निन्दा नहीं की है।

श्री भानु प्रताप सिंह : जिस ने निन्दा की है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं और उसका कारण बताता हूं ।

आज जो देश में कृषि की स्थिति है उसका एक सुनहला पहलू है और एक काला पहलू है । जिसने केवल सुनहला पहलू देखा है उसने बधाई दी है और जिस ने सिर्फ काला पहलू देखा है उसने निन्दा की है । मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि एक संतुलित बैलेन्स्ड व्यू ले लेना चाहिये । हमने कुछ उपलब्धियां की हैं ऐसी उपलब्धियां जिनके बारे में दूसरे देश वाले हमारी आज प्रशंसा कर रहे हैं । लेकिन हममें कुछ अभी कमियां भी हैं उससे मुझे इनकार नहीं है । मैं दोनों पहलुओं पर थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा ।

जहां तक उपलब्धियों का प्रश्न है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि उसकी चर्चा तो दूसरे ही करें तो ठीक होगा । मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जो देश 2 वर्ष पहले तक दूसरों के सामने अपना पेट भरने के लिए हाथ फैलाता था आज वह दूसरों का पेट भरने योग्य बन गया है । अभी थोड़े समय पूर्व हमारे जार्ज साहब उधर से बोल रहे थे उन्होंने भी लैफ्ट हैण्डेड कम्प्लीमेंट दिया उन्होंने कहा कि सब मंत्रालयों को तो नहीं कह सकता मगर कृषि मंत्रालय को कह सकता हूं कि जैसा उन्होंने चार्ज दिया था उसको बिगाड़ा नहीं है । इसको मैं लैफ्ट हैंडिड काम्प्लीमेंट इस लिए कहता हूं कि ठीक है उन्होंने एक अन्न भंडार दिया था लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं--- वह इस समय यहां मौजूद नहीं हैं---कि वह अन्न भंडार किस प्रकार से बना था । क्या वह अन्न इस देश में पैदा हुआ था ? विदेशों से मंगा कर अरबों रुपयों या विदेश भेज कर वह अन्न भंडार बना था । उस अन्न भंडार को बनाने का दूसरा तरीका यह था कि अपने देश के किसानों के घरों से जबर्दस्ती पुलिस भेज कर उनकी मर्जी के खिलाफ़ बहुत कम कीमत पर जब्रिया गल्ला वसूल किया गया ।

आज हमारा अन्न भंडार न तो विदेशी अन्न से भरा है और न हम ने किसी किसान से उसकी मर्जी के खिलाफ़ जब्रिया वसूली की है । जो कर्जा उन्होंने लिया था उस कर्जे को हम ने उतार दिया । सोवियत रूस से जो 20 लाख टन गेहूं लिया गया था वह करीब करीब उनको वापस दिया जा चुका है । उलटे हमने उनको दो लाख चावल देने का टन अभी फैसला किया है । अगर इन दोनों परिस्थितियों में जार्ज साहब को कोई अन्तर नपर नहीं आता है तो मैं तो यही कहूंगा कि देखने का दोष है ।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जहां तक किसानों का प्रश्न है कांग्रेस के शासन और आज के शासन में उनको कोई अन्तर नज़र नहीं आता है । याददाश्तें बहुत छोटी हुआ करती हैं इस लिए मैं बहुत संक्षेप में केवल कुछ पायंट्स बता देना चाहता हूं कि क्या अन्तर हुए हैं ।

पहला अन्तर तो यह हुआ कि पहली पांचों पंच वर्षीय योजनाओं में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए व्यय की गई धनराशि 19 से 23 प्रतिशत होती थी मगर अब उसको करीब करीब दुगना कर दिया गया है । इसके परिणाम भी सामने आने शुरू हो गये हैं । पांचों पंच वर्षीय योजनाओं में सिचाई पर जितना व्यय हुआ था उससे अधिक इन पांच वर्षों में सिचाई पर व्यय होने जा रहा है । पिछले वर्ष 28 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई पहुंचाई गई । यह बिना धन को लगाये हुए नहीं हो सकता था । इसमें बहुत बड़ी धनराशि लगानी पड़ी है ।

अभी कुछ दिन पूर्व सोवियत यूनियन के डिपुटी मिनिस्टर, एग्रीकल्चर, मुझ से मिलने आये थे, जब मैंने उनसे कहा कि भारत में 28 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिचाई की व्यवस्था एक साल में की गई है, तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया और कहा कि हमारे इतने बड़े विशाल देश में किसी एक साल में दस लाख हैक्टेयर से अधिक अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई ।

जब इस सरकार ने चार्ज लिया था, उस समय एक राज्य से दूसरे राज्य में अन्न नहीं जा सकता था । राज्य तो छोड़िये, एक ज़िले से दूसरे ज़िले को अन्न नहीं जा सकता था । और मेरा ज़िला तो ज़िला तो इतना बदकिस्मत था कि नदी के इस पार आधे ज़िले से नदी के उस पार भी अन्न नहीं जा सकता था । इमर्जेन्सी से पहले भी और इमर्जेन्सी के दौरान भी चारों तरफ किसानों को घेर कर उनको लूटने की व्यवस्था बनी हुई थी । वे अपना माल कहीं बेच नहीं सकते थे, सिवाये सरकारी एजेंसियों को । उसके दुष्परिणाम भी थे, परन्तु उसकी कोई चिन्ता नहीं की जाती थी ।

जनता सरकार ने पहला काम यह किया कि इस देश में एक बाज़ार कायम किया "एक राष्ट्र एक बाजार" का जो उद्देश्य था, उसको प्राप्त किया । दिल्ली के निवासी भले ही इसके लाभ को न समझते हों, लेकिन जा कर बम्बई और पूना के लोगों को पूछिये कि उनको कितनी राहत मिली है---केवल इस कारण से कि खाद्यान्नों के आवागमन पर से सारे प्रतिबन्ध हटा दिये गये हैं । जिन लोगों को दस बारह रुपये किलो के हिसाब से चावल मिलता था, आज उनको दो रुपये किलो के हिसाब से चावल मिल रहा है ।

चीनी की दोहरी नीति थी ---चीनी दोहरे मूल्य पर बिकती थी । एक माननीय सदस्य ने कहा कि अब तो चीनी 2-90 रुपये पर आ गई । लेकिन वह भूल गये कि पहले क्या स्थिति थी । अगर फ्री-चीनी और लेवी-चीनी की वेटेड-एवेज ली जाय तो आज की चीनी से भाव ऊंचा था । जहां तक उपलब्धि का प्रश्न है---गांव वालों को चीनी नहीं मिलती थी और मेरा तो ऐसा विश्वास है कि चीनी की उस दोहरी-मूल्य-नीति के कारण इस देश में कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपये की ब्लैक मनी जैनरेट होती थी, उस को हमने समाप्त किया और इस का एक लाभ अभी भी स्पष्ट है कि चीनी की खपत देश में एक दम बढ़ गई ।

पिछले दिनों हमारे सामने एक सब से बड़ी समस्या यह थी कि चीनी उद्योग में उत्पादन खपत से ज्यादा था, वह समस्या प्रायः सुलझ गई है। जिस गति से चीनी की खपत बढ़ी है—डी-कण्ट्रोल होने के बाद से—आप देखेंगे कि 60 लाख टन चीनी की खपत इस देश में हो जायगी और साथ ही साढ़े-छः लाख टन हम विदेशों को भी भेजेंगे। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जितनी चीनी बनेगी; उस से कुछ ज्यादा ही देश के अन्दर खपत होने वाली है तथा विदेशों को भेजी जाने वाली हैं। इस तरह से चीनी उद्योग की जो सब से बड़ी समस्या थी, उस को हम ने हल किया है।

अब मैं "फूड-फार-वर्क" के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप को मालूम है—पीछे "फूड-फार-हंगर" नाम की एक स्कीम चली थी, वह अन्तर्राष्ट्रीय स्कीम थी, परन्तु जितना उस स्कीम के अन्तर्गत सारे संसार में अनाज व्यय होता था, उस से ज्यादा "फूड-फार-वर्क" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने पिछले वर्ष व्यय किया है। जो लोग भूखे रह जाते थे, जिन को पूरे वर्ष काम नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे यहां खेतों में चन्द महीने ही काम होता है, ऐसे लोगों को बेकारी और भुखमरी का सामना करना पड़ता था, आज उन्होंने हमारी इस योजना के कारण भर-पेट भोजन पाया है। हम लोग यह चर्चा करते हैं और वह ठीक भी है कि खेतिहर मजदूरों को मिनिमम वेज मिलना चाहिये। लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं—फूड-फार-वर्क योजना में काम करके आज जो उन को मिला है, वह मिनिमम-वेज दिलाने से उन को नहीं मिल सकता था। आज इस योजना में एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं मिल रहा है, तब फिर वह 2 या 3 रुपये की मजदूरी करने नहीं जायगा। इस तरह एक तरफ हम ने लोगों को रोजगार दिया, लोगों का पेट भरा और दूसरी तरफ बहुत सारे निजी-इयूरेबिल एसेट्स भी खड़े हुए हैं। मैं माननीय सदस्यों को आमन्त्रण देता हूं—वे चल कर देखें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में किस तरह से काम हुआ है और गांव वाले इस योजना से कितने खुश हैं।

एक शिकायत यह की गई कि "फूड-फार-वर्क" योजना में सड़ा हुआ अनाज दिया जाता है। श्रीमन्, यह नितान्त असत्य है, क्योंकि राज्य सरकारों को मैंने बारम्बार स्वयं लिखा है कि इस गल्ले को उसी प्रकार से स्वीकार करें जिस प्रकार से "फेअर ब्राइस-शाप्स" का गल्ला स्वीकार करते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार को यह अधिकार है कि गल्ले का चार्ज लेने से पहले उस की क्वालिटी को चख सकते हैं। किसी भी राज्य सरकार के ऊपर कोई भी रद्दी माल जबरदस्ती नहीं थोपा जायगा, यह बात बारबार स्पष्ट की जा चुकी है और उन को भी अपना अधिकार मालूम है। जहां तक फूड-फार-वर्क का प्रश्न है, उस के लिए मैंने विशेष रूप से लिखा है कि यद्यपि उन को यह गल्ला मुफ्त में मिल रहा है लेकिन इस की कीमत करल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को चुकानी है। इस-लिये इस गल्ले को देख कर लें और इस के साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि किसी राज्य सरकार ने आज तक मेरे पास गल्ले की क्वालिटी के बारे में या कम से कम फूड-फार-वर्क के गल्ले के बारे में लिख-कर नहीं भेजा बल्कि उल्टे आज उस की मांग इतनी ज्यादा है कि हम को सोचना पड़ता है कि क्या हम उस की मांग को पूरा कर सकेंगे। पहले तो, प्रारम्भ में यह योजना शुरू की गई थी, उस समय हम को यह कहना पड़ता था कि आप इस काम को करवाइए लेकिन आज यह इतनी लोकप्रिय हो गई है कि हमारे लिये मुसीबत हो गई कि हम किस हद तक उन की मांगों को पूरा कर सकेंगे।

रोजगार बढ़ाने के लिए दुग्ध योजना भी चालू की गई है जिस पर अगले पांच वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च आएगा।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : सात सालों में।

श्री भानु प्रताप सिंह : इस से मैं समझता हूं कि छोटे किसानों को और भूमिहीनों को बहुत राहत मिलेगी।

फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की कीमत पिछले 2 वर्षों में 200 रुपये टन गिराई गई है... (व्यवधान)... आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि इस के भाव पेट्रोलियम से तय होते हैं। 1970-71 के मुकाबले में पेट्रो-लियम किस भाव पर मिल रहा था।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगले वर्षों के अन्दर जो कर्जे दिये जायेंगे, उस का सूद भी 2 प्रतिशत गिराया गया है। पिछले कई वर्षों से देश में जो तम्बाकू पैदा करने वाले किसान हैं, उन को एक्साइज ड्यूटी वगैरह में परेशान किया जाता था और उन की संख्या बहुत बड़ी है, आज वे राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि इस से सरकार ने उन से एक्साइज ड्यूटी की वसूली बन्द कर दी है।

अब तक हम क्या कर चुके हैं, उस के बारे में मैंने 10, 11 प्वाइण्ट्स के बारे में बताया है। जो पहले नहीं होता था और जिस के बारे में इस सरकार ने कुछ किया है, वह मैंने आपको बताया है। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि आगे हम लोग क्या करना चाहते हैं। यह मैं मानता हूं कि जो खरीददारी की योजना बनती है, बहुत से किसान अपना गल्ला सपोर्ट प्राइस पर भी नहीं बेच पाते। यह बात सही है परन्तु उस में जो कठिनाइयां हैं, उन की ओर भी आप ध्यान दें। सारी खरीददारी एफ० सी० आई० नहीं करती। वास्तव में यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और राज्य सरकारों को बारम्बार लिखा जा चुका है कि जो भी गल्ला वे खरीदेंगी अगर वह स्पेसीफिकेशन के मुताबिक है तो, उनका खर्चा अदा कर के भारत सरकार उस को ले लेगी। अगर कहीं कोई भी कमी होती है, तो उस के लिए राज्य सरकार भी जिम्मेवार है। बहुत सी राज्य सरकारें ऐसी हैं जो एफ० सी० आई० की अपने एरिया में आपरेट नहीं करने देती। तरह तरह के उन के पैटर्न हैं। कहीं

[श्री भानु प्रताप सिंह]

पर राज्य सरकार और एफ० सी० आई० दोनों खरीदती है, किसी राज्य में केवल एफ० सी० आई० खरीदती है और किसी राज्य में केवल राज्य की अपनी एजेन्सी खरीदती है। तो इस चीज को भी आप समझें। यह सब होते हुए भी हमारा यह बहुत स्पष्ट फैसला है और इस फैसले से हम ने सभी मुख्य मंत्रियों को अवगत करा दिया है कि अगर कहीं भी कृषि पदार्थ की सपोर्ट प्राइस घोषित होगी और उस को अगर वे अपने राज्य में खरीदेंगे और वह हमारी एफ० सी० आई० के स्पेसीफिकेशन के मुताबिक होगा, तो उस की कीमत दे कर और उस के खरीदने का खर्च भी दे कर भारत सरकार उस को ले लेगी। आज इस बात की भी आवश्यकता है कि जहां आप हमारे ऊपर इतने आरोप लगाते हैं कुछ राज्य सरकारों पर भी दबाव डालने की कृपा करें। नायडु साहब बार बार नाराज होते हैं। उनकी नाराजगी मेरी समझ में नहीं आती है। हम ने आन्ध्र प्रदेश की सरकार के मुख्य मंत्री को स्पष्ट कर दिया है कि वह चाहे जितना भी चावल और धान खरीदें सब एफ० सी० आई० लेने को तैयार है। इस वास्ते वह इस नाराजगी को कुछ उधर भी करने की कृपा करें।

इन सब कठिनाइयों को देखते हुए एक नई योजना चलाने का फैसला किया गया है जिस का जिक्र हमारे वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया था और वह ग्रामीण गोडाउन बनाने की है —

श्री पद्मचरण सामन्तसिंहेरा (पुरी) : फूड-फार-वर्क में आप उड़ीसा को चावल क्यों भेजते हैं वह तो वहां पहले से ही काफी है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : उन से आप कहें कि हम को लिख कर भेज दें। जबर्दस्ती हम किसी को नहीं देते हैं। मांगेंगे तभी देंगे।

रूरल गोडाउंज की नई योजना स्वीकृत हो चुकी है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि 5-6-7 गावों के बीच में एक डेढ़ या ढाई सौ टन के लिए गोदाम बने और वहां छोटे किसान नजदीक से आ कर अपना गल्ला रख सकें और वहां दोनों ही काम कर सकेंगे, अगर बेचना चाहें स्पोर्ट प्राइस पर तो बेच सकेंगे और अगर रखना चाहें तो रख सकेंगे और अगर रखना चाहेंगे तो रख कर उसके मुकाबले से उनको नकदी काम चलाने के लिए बैंक से एडवांस दिला दिया जाएगा। यही किसान हैं जिन को सब से ज्याद रक्षा की आवश्यकता है। यह केवल राज्य सरकार पर ही निर्भर नहीं है। अब तो हम चाहते हैं कि किसान भी स्वयं संगठित हों। हम दावा नहीं करते हैं कि हमने सब ठीक कर लिया है और कुछ करने को बाकी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जरा हमारी कठिनाइयों पर भी गौर करें। पहली तो यह है कि खेती का कारोबार ऐसा नहीं है जिस को तत्काल दुरुस्त किया जा सके। एक फसल अगर इस साल मारी जाएगी तो अगले साल आप उस में कुछ संशोधन कर सकेंगे। फैक्टरी में अगर कोई काम गड़बड़ दिखाई देता है तो एक सप्ताह और दस दिन में उसको ठीक किया जा सकता है लेकिन स्विच दबाने से जैसे एक पंखा चलने लगता है उस तरह से खेती के बारे में नहीं हो सकता है। अब तक की जो व्यवस्थायें थीं वे कमी का मुकाबला करने के लिए थीं। देश में कमी का एक वातावरण था। उद्देश्य यह था कि गावों से अधिक से अधिक गल्ला निकाल कर, जबर्दस्ती या जैसे भी हो उपभोक्ताओं को खिलाया जाए, उनकी रक्षा की जाए। यह आवश्यक भी था। आज परिस्थिति बदल गई है। आज की परिस्थिति में मैं समझता हूं कि गावों में गोदाम बनने चाहिये ताकि छोटे किसान को दूर जा कर परेशान न होना पड़े और वे अपना माल रख कर उसकी कुछ कीमत पा कर जब भाव बढ़े तो उसका लाभ उठा सकें। इसी उद्देश्य से रूरल गोडाउज बनाने की योजना रखी गई है।

यहां मांग की गई है जिस पर विचार हो रहा है लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है कि जो खाद्यान्न किसान स्वयं रखे रहें और बाद में सप्लाई करें गवर्नमेंट को तो उसका भी जो खर्चा एफ०सी०आई० वगैरह का आता है वह अधिक दे कर उससे ले लिया जाए। डैफर्ड प्रोक्योरमैंट के लिये ऊंची कीमत दीजिये इसमें सभी का लाभ है। आप इस बात को इस प्रकार से समझें कि जिस वक्त गेहूं प्राप्त होता है पंजाब और हरियाणा में मई के शुरू में आयेगा कई बार 6 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है तो उस वक्त हमारे पास रखने की जगह की कमी होती है ट्रांस्पोर्ट की कमी होती है। सभी प्रकार से मंडियों में भी जगह नहीं रहती है। इस प्रकार से यह सोचा गया है कि कुछ तो माल रखा जायेगा पंजाब रूरल गोडाउन्स में और कुछ किसान अपने घर पर ही रख ले तो उसको बरसात के बाद अक्तूबर नवम्बर में और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में सरकारी भाव देकर ले लिया जाये। लेकिन आज किसान क्यों रखें ? जब पूरे वर्ष तक एक ही भाव रहना है तो उसका परिणाम यह होता है कि हरेक यह चाहता है कि दुकान खुलते ही पहुंचा दिया जाये। तो इससे जहां एफ०सी०आई० पर बहुत बड़ा भार आता है वहां यह भी होता है कि जब बहुत लोग इकट्ठे होते हैं तो किसानों के साथ दुर्व्यवहार भी होता है। लेकिन उस भार को कम करने के लिये मैं समझता हूं कि यह दो योजनाएं सहायक सिद्ध होंगी।

अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है अब तक सिंचाई के लिये सिर्फ 2 हैक्टर तक के किसानों को सब्सीडी मिलती थी अब सोचा जा रहा है कि यह 4 हैक्टर तक के किसानों को सब्सीडी दी जायेगी। उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक छोटे नल कूप बनाकर किसान स्वयं स्वावलम्बी बनें।

मैं एक कृषक के नाते कह सकता हूं कि खेती अच्छी वही कर सकता है जिसका पानी का स्रोत उसके अपने कंट्रोल में हो। यह तभी सम्भव है जब अधिक से अधिक किसान अपने नल कूप बनायें। अपने देश में बहुत बड़ा उत्तर भारत का भाग है जहां नीचे पानी की कमी नहीं है जहां आसानी से पानी निकल सकता है। तो उस जल का हमें लाभ उठाना चाहिये। प्रायः लोग कहते हैं

कि मौसम। मौसम की कृपा से कुछ हुआ" इस बात पर मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा वह अपने विचारों को रख सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि यदि हम सिंचाई के साधनों को बहुत तेजी से बढ़ा सकें, तो इस मौसम के उतार चढ़ाव से इस देश को मुक्ति मिल सकती है। आज मौसम पंजाब का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आप विश्वास रखिये, चाहे जैसा भी मौसम होगा, पंजाब और हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसल होगी। तो हम उसी स्थिति में पहुंचने के लिये किसानों की सहायता करना चाहते हैं कि वह अधिक से अधिक नलकूप बनायें।

एक बात की मैं और चर्चा करना चाहता हूं। गरीबी दूर करने की सब की स्वीकृति है, लेकिन गरीबी कैसे दूर होगी? गांव की गरीबी दूर करने के लिये दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो पूंजी और दूसरे कुछ नया ज्ञान विज्ञान। अगर कोई समझता हो कि केवल इस बात की चर्चा कर के कि बड़े किसान छोटे को लूट रहे हैं, या इस प्रकार की बातें कर के कोई गरीबी दूर करने की कोशिश करे तो वह राजनीतिक लाभ तो उठा सकता है, लेकिन देश की गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर करने के लिये पूंजी और नई जानकारी का पहुंचाना बहुत जरूरी है। जहां तक पूंजी का प्रश्न है, मैं बतला चुका हूं कि भारत सरकार जितना व्यय करती थी, उसका दुगना व्यय अब करने जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारी यह भी कोशिश होगी कि हम वहां कुछ थोड़ी जानकारी भी पहुंचायें। जब मैं कभी किसी कृषि अनुसंधान केन्द्र पर जाता हूं तो ऐसा लगता है कि यहां जानकारी का ऐसा जखीरा है कि अगर हमारा इस्तेमाल हो तो इस देश का चित्र बदल सकता है। लेकिन दुःख की बात है कि वह जानकारी, जिससे दूसरे देशों के लोगों ने फायदा उठाया है, हमारे देश के लोगों ने उससे लाभ नहीं उठाया। हां बीज जरूर कुछ बिखर गए हैं, लेकिन बाकी जानकारी वहीं की वहीं रह गई है।

एक योजना, जिसका निवारी जी ने जिक्र किया—लैब टु लैण्ड—उसका उद्देश्य है कि जितने अनुसंधान केन्द्र हैं वे अपने पड़ोस में सबसे गरीब लोगों को छांट कर अपने विज्ञान के द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। 150 हजार परिवार छांटे जायेंगे। इसके अतिरिक्त एक योजना यह भी है कि गांवों से कुछ पढ़े लिखे लड़कों को लेकर उन केन्द्रों पर दो तीन महीने रखकर किसी एक काम के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा—चाहे आर्टिफिशल इन्सेमिनेशन हो, सेरिकल्चर हो, पोल्ट्री कीपिंग हो या इंजन रिपेयर, मोटर रिपेयर का काम हो। जितने भी धंधे गांवों में चल सकते हैं उनकी ट्रेनिंग देने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। इन्टेसिव डेवलपमेन्ट ब्लाक्स में पहले से ही यह योजना लागू है लेकिन दुःख की बात है कि लोगों को यह मालूम नहीं है। मुझे स्वयं इस बात पर आश्चर्य है, यद्यपि एक साल में गाइडलाइन्स लिखी गई हैं लेकिन इसकी जानकारी नहीं है। 2300 ब्लाक्स से बढ़ाकर 2600 ब्लाक्स में लागू किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि यह योजना सारे देश में लागू की जाए। गांवों के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको नया काम सिखाया जायेगा। नौकरी देने के लिए हम उनको यह काम नहीं सिखा रहे हैं बल्कि तीन, चार, पांच महीने की उनकी ट्रेनिंग होगी जिसमें वे काम सीख कर गांवों में जायें और सेल्फ एपलायड पर्सन की तरह से अपना कारोबार शुरू करें। इसमें एक तो उनका अपना रोजगार हो जायेगा और दूसरे लोगों के लिए उदाहरण भी बनेंगे। (व्यवधान)

दो एक बातें मैं और कहना चाहूंगा। माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसी बातें कही जिनका उत्तर देने से यद्यपि नतीजा नहीं निकलना फिर भी मैं निवेदन करूं, जैसे चन्द्र शेखर सिंह जी ने यहां पर कहा कि जेल में जितना राशन दिया जाता है उसके हिसाब से देखा जाये तो इस देश के लिए कम अनाज पैदा हो रहा है फिर भी कहा जाता है कि अनाज फाजिल है इसलिए सरकार के सारे आंकड़े गलत हैं। माननीय सदस्य केवल यह भूल गए कि जेल में बच्चे नहीं रहते। बालिग की खुराक और दूसरी तरफ सभी की खुराक में थोड़ा फर्क है। (व्यवधान)

इस बात की चर्चा भी की गई कि पहले चीनी बहुत एक्सपोर्ट होती थी और यह सरकार निकम्मी है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है। उन्हें नहीं मालूम कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का क्या भाव है। जिस समय का माननीय सदस्य जिक्र करते हैं उस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का मूल्य 700 पाउंड प्रति टन था और आज 100 पाउंड प्रति टन है। उस समय की सरकार ने चीनी बेच कर भुनाफा कमाया था हम आज भी बेचते हैं लेकिन घाटे पर बेचते हैं।

एक्सपोर्ट की बात भी कही गई। इस विषय में मझे ज्यादा नहीं कहना है मैं भी एक्सपोर्ट का बड़ा हिमायती हूं लेकिन साथ ही मैं यह बतलाना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट भी ऐसे नहीं हो सकता है कि आज आपने फैसला किया कि एक्सपोर्ट होगा और कल एक्सपोर्ट हो जाये। दुनिया के लोग मह बाये बैठे नहीं रहते हैं। एक्सपोर्ट के लिए हर एक को अपने कन्टमर बनाने पड़ते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रवेश नया होगा और उसको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी—यह देखना है। हमारा यह है

17 00 hrs

श्री चन्दन सिंह (कैराना) मेअरमैन साहब मझे एक बात कह लेने दीजिये। रात मेरे बच्चे ने टेलीफोन किया कि पिताजी 20-25 किलो मूंग लेते आना। बड़ी मश्किल से मूंग मिली, मैं मूंग लेने गया तो वह अफसर मीटिंग में था। मेरे बच्चे ने कीट-नाशक दवा भी लाने के लिये कहा था, जब मैं उस के केन्द्र में पहुंचा तो मालूम हुआ कि यह कानून है कि आर्डर देने के एक महीने बाद मिलेगा। मैंने कहा कि सोइंग का टाइम तो अब है, मैं तीन दिन बाद सोइंग करने जा रहा हूं, दवा एक महीने बाद मिलेगी तो उस से क्या फायदा होगा। मंत्री जी इस तरह के कानून को बदलिये, जरूरत आज है एक महीने बाद मिलेगी, इस से क्या फायदा है।

श्री भानु प्रताप सिंह यह शिकायत सुन कर मुझे थोड़ा अफसोस हुआ है। मैं तो चौधरी साहब को बहुत अच्छा किसान मानता आया हूं। जिस टीक की आप बात कर रहे हैं—वह इन आक्युलेशन है, जब किसान पहली बार मूंग बोता है तब उस को डालनी होती है। जब वह तिलहन या दूसरी फसलें उस से ले चुका है तो उस को दोबारा डालने की जरूरत नहीं होती है।

श्री चन्दन सिंह खेत की मिट्टी को बदला नहीं जा सकता है।

श्री भानु प्रताप सिंह आप उसकी बात मानते क्यों हैं।

अन्त में केवल एक बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। यह मान कर चलना कि केवल भारत सरकार या भारत सरकार के मंत्री कृषि की स्थिति को सुधार सकते हैं—यह एक गलत धारणा है। इस काम में बहुत सारे फरीक हैं। सब से बड़ा फरीक तो राज्य सरकार है, उस के बाद स्वयं किसान है। बढ़िया से बढ़िया योजनायें बनाई गई है, लेकिन अगर मौके पर डीजल न मिले, फर्टिलाइजर न मिले तो दिक्कत होती है—हम ने उन समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न किया है लेकिन सब के सहयोग से ही यह काम सफल हो सकता है।

आलू की चर्चा की गई। आलू के बारे में मैं कहना चाहता हूं—सरकार की पूरी सहानुभूति होते हुए भी किसानों की समुचित मदद नहीं की जा सकी और उस का मुख्य कारण यह है कि मदद करने के लिये जो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिये वह नहीं है। हमारे पास पर्याप्त कोल्ड-स्टोरेज होने चाहिये, रेफ्रीजरेटेड-वेगन्ज होने चाहिए—लेकिन वे नहीं हैं। जो थोड़े-बहुत कोल्ड स्टोरेज हैं—वे सब भर चुके हैं। हम ने राज्य सरकारों से कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में कोल्ड-स्टोरेज बनाये जाने चाहिये। अभी कुछ दिन पहले इसी विषय पर बात करने के लिये मैं वेस्ट बंगाल गया था। उन्होंने कहा कि हमारे यहां बिजली नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी बात को माना और कहा कि हम 100 नये कोल्ड-स्टोरेज बनायेंगे, लेकिन अब उन के मुख्य मंत्री जी का पत्र हमारे पास आया है कि उन के पास सीमेन्ट नहीं है। आप इस बात पर विचार कीजिये—कृषि की समस्या का बहुत ज्यादा सम्बन्ध बिजली, सीमेन्ट, डीजल और लोहेवालों से है। हमारी अर्थ-व्यवस्था में इन का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, कभी-कभी थोड़ा-बहुत मतभेद हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पुराने ढर्रे पर खेती करें, छोटे-छोटे उद्योग हों, तो उन से देश का भला होगा। मैं कहता हूं—उद्योग की बात तो छोड़ दीजिये, खेती भी उस तरह से नहीं चल सकती है, जब तक हमारे उद्योग ऐसे न हों जो हमारी खेती की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें।

17.04 hrs.

[DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*].

इसलिए आप हम को जब जांचें, आंकें, तो इन सारी बातों को ध्यान में रख कर आंकें। यह कहना आसान है कि सरकार ने कुछ नहीं किया लेकिन जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, उन की तरफ भी आप ध्यान दें।

आलू की बात बहुत की जाती है पर आलू का क्या किया जाए। मैं पिछले साल से पूछ रहा हूं कि हम को यह तो कहा दिया जाता है कि किसानों की मदद कीजिए मगर जब मैं यह पूछता हूं कि किस प्रकार से मदद की जाए, तो कोई उत्तर नहीं मिलता।

अन्त में मैं कुछ एफ०सी०आई० के बारे में कहना चाहता हूं। मैं स्वयं यह दावा नहीं करता कि यह एक बहुत बढ़िया और एफीशियेन्ट आर्गेनाइजेशन है, परन्तु जिस प्रकार से आलोचना की गई है वह भी सही नहीं है। सब से पहले तो मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि एफ०सी०आई० का काम केवल खरीद कर उपभोक्ताओं को गल्ला पहुंचाना नहीं है। यह एक प्रकार से इन्श्योरेंस है। जो आप 570 करोड़ रुपये का बात करते हैं कि इतना घाटा होता है, उस में से आधे से ज्यादा बफर स्टाक के लिए है पर यह तो एक पालिसी मैटर है कि क्या हम को बफर स्टाक रखने की जरूरत है या नहीं? अगर जरूरत है तो उस को आप इन्श्योरेंस मानिये, उस को नुकसान में मत गिनिये। संसार के जितने भी खाद्य पदार्थ आदि के आर्गेनाइजेशन हैं और यू०एन०ओ० में जो एफ०ए०ओ० का आर्गेनाइजेशन है, उन सब का यह कहना है कि रिजर्व फूड स्टाक होना चाहिए, न केवल अपने लिए स्टाक फूडस्टफ का होना चाहिए बल्कि और दूसरों के लिए भी होना चाहिए। अब अगर हम बफर स्टाक रख रहे हैं, तो वह न केवल अपने देशवासियों के लिए मुसीबत के वक्त काम आएगा बल्कि और जो हमारे पड़ोसी हैं उन के काम भी आ सकता है और इस के रखने पर जो खर्चा होता है, उस को अगर आप हमारी नालायकी गिनने लग जाएं, तो यह हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हैं। एफ०सी०आई० में भी उसी प्रकार के लोग हैं, जैसे कि और दूसरे सभी विभागों में और सभी वाक्स आफ लाइफ में हैं। इस देश में ईमानदारी का क्या स्टैन्डर्ड है, यह सब को मालूम है लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आज तक किसी माननीय सदस्य ने एफ०सी०आई० के किसी कर्मचारी या अधिकारी के बारे में मेरे पास शिकायत नहीं भेजी है। हां, पचासों माननीय सदस्यों ने उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पैरवी की है, जिन के बारे में यहां खड़े हो कर उन को नालायक और बेईमान कहते हैं।

श्री एस० रामगोपाल रेड्डी रिकमेंडेशन करते हैं पैरवी कोई नहीं करता है। . . (व्यवधान) . . .

श्री भानु प्रताप सिंह : जिनको यहां कहते हैं कि भ्रष्ट है उन्हीं की पैरवी करते हैं. . . (व्यवधान) . . मेरे पास शिकायत लाए या प्रमाण लाएं, तो

मैं देख सकता हूं लेकिन मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं लाई गई है।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे केन्द्र की हो या राज्यों की हो, वे पूरा सहायता किसानों की नहीं कर सकती जबतक कि किसान संगठित हो कर खुद अपनी सहायता न करें। दुनिया का कोई भी मुल्क मैं ऐसा नहीं जानता जहां के किसान अपने माल को बेचने के लिए स्वयं संगठित न हों। यहां पर ही ऐसा है कि सारी बातों की आशा सरकार द्वारा करने की की जाती है। कोई काम हो, वह केन्द्रीय सरकार की मदद से करना चाहते हैं और अगर केन्द्रीय सरकार से छुट्टी मिल जाए, तो राज्य सरकारों की मदद चाहते हैं परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस ने उत्पादन किया है क्या उस का कोई फर्ज नहीं है उस को अपने आप बेचने का। बेचने में कुछ मदद तो हो सकती है लेकिन दुनिया के जो दूसरे लोग हैं, वे अपने सहकारी संगठन बनाते हैं और अपने माल को बेचते हैं। दूसरे देशों में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने यहां ही गुजरात को ले लें। उत्तर प्रदेश और बिहार और दूसरी जगहों के लोग भी यह कहते हैं कि धान का जो समर्थन मूल्य आप ने 85 रुपये निश्चित किया है, वह कम है लेकिन गुजरात के किसी किसान को इस के बारे में शिकायत नहीं है क्योंकि उन्होंने किसानों की एक कोआपरेटिव सोसाइटी बना रखी है और उसी धान को वे 85 रुपये की बजाए 100 रुपये पर किसानों से खरीदती है और उस धान को खरीद कर उस का चावल बनाती है और बगल में ही, फेयरप्राइस शाप के पास, उस को बेचती है। तो आज इस बात की भी आवश्यकता है कि लोग कुछ अपने कर्त्तव्य को समझें, जो जनता के नेता हैं और जो गांव वालों के प्रतिनिधि चुन कर आए हैं, वे उनको सुझाव दें, उनको संगठित करें।

यहां पर भ्रष्टाचार की काफी चर्चा की गई है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। भैंसों के लेन-देन में होने वाले भ्रष्टाचार के विषय में एक दिन पूरी मीटिंग की गई, कुछ एम०पीज० भी थे लेकिन कुछ हल नहीं निकल सका। पूछा गया कि कोई हल हो तो बताया जाए लेकिन कुछ हल नहीं निकला। अन्त में इतना ही हल निकल पाया कि किसानों का कोई संगठन हो जो उनके हितों की वहां रक्षा करे तभी उनकी रक्षा हो सकती है।

अपने देश में क्या होता है इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। गोंडा जिले में नलकूप बनाने के लिए एक संगठित प्रयास चल रहा है। उस में तो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। बजाय इसके कि केवल शिकायतें करते रहें हम को देखना चाहिये कि आखिर हम भी प्रतिनिधि हैं, हमारा भी कुछ कर्त्तव्य है, वहां जा कर हम देखें और इसको दूर करवाएं....
(इंटरप्शंस)

एक माननीय सदस्य : संसद सदस्यों की बात कोई सुनता नहीं है।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं नहीं मान सकता हूं कि संसद सदस्य अगर ध्यान दें तो उनके देखते हुए भ्रष्टाचार हो सकता है।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Madam Chairman, at the outset I congratulate both the Ministers for having done good work and I support their demands from this side of the House for they have done good work in the field of sugar industry; they have reduce excise duty; they have decontrolled sugar and they have given freedom to the sugar factories to export sugar. This is a good thing which they have done.

The Food Corporation of India has done its best to accommodate as much foodgrains as possible and the procurement is more than the capacity of the godowns. Now the Minister says that he is going to construct some godowns in the villages. I want to know how much time he will take to complete that scheme. He wanted some cold storage. He must not put this scheme into cold storage; he must put it into action.

I also want to congratulate our scientific officers who are doing very good research work. They have produced high yielding and disease resistant variety; for which the Minister has not congratulated them; I want that at least his senior colleague Mr. Barnala should pay good compliments to scientists who have done excellent work. Nowhere in the world has such a phenomenon occurred. Our yields have gone up on account of the efforts of the government plus our scientific research work. They are doing good work in this country, which is comparable to any other country including America or Russia. It should not be forgotten. The worry in this country is not on how much we produce but now the fertility of the soil is decreasing; desert is advancing. I want to know from the Ministers what they are going to do, when they are going to complete the Rajasthan canal that can *stop* the advancement of the desert. It is a national prob-

[Shri M. Ram Gopal Reddy]

lem; it is not the problem of Rajasthan. If anybody thinks that it is the problem of Rajasthan he is not doing justice to this country. Rajasthan canal must be completed in the shortest possible time and all the green patches that are to be developed must be developed. In this country we are mercilessly and wrecklessly cutting the trees; that is causing inundation by rivers which take away the fertile soil to the Bay of Bengal or to the Arabian Sea. That must be stopped. It is a national problem. I want that the fertility of the soil must not only be maintained but improved. One Minister is coming and another Minister is going. In between, whether the fertility of the soil is increased or not? This is important for this country and not how much we are producing?

Now the per acre yield will go down because you are producing more with the application of inorganic fertilisers. Inorganic fertilisers are destroying the fertility of the land. We want manure—cow dung and other organic matter. We want green leaves. The trees have been cut. In Haryana and in Punjab many trees have been planted and protected. In this country if 100 trees are cut, not a single tree is planted. Trees must be planted which will protect the fertility of the soil and prevent soil erosion. If there are no trees, soil erosion occurs. Due to soil erosion river belt is filled up. That is why floods are caused. Brahmaputra is eating away good soil of that area. Similarly soil erosion by sea is causing great havoc in all the coastal areas. Day by day our country is becoming small because of soil erosion by sea and rivers. What has been done in Bombay Marine Drive, such sort of thing must be done in this country. Then alone we can protect soil erosion by sea and wind. We must grow trees. We must have a plan. Formerly, our Shri K. M. Munshi had planned for tree-planting. That plan was not properly implemented for various reasons. I want to know from the Ministers how they are going to protect forests. The minimum requirement of the forest is that about 33 per cent o fthe total area of the land should be under forest. Now it has gone to 24 or 22 per cent. Day by day, it is decreasing. That is the greatest danger. Now the fertility of the soil has gone down. The production of the soil also will go down. It is a serious thing. This point has not been made by anybody.

It is very good that the Janata Government, for whatever it may be, they are paying attention to the kisans. In Andhra Pradesh our Chief Minister has exempted the land revenue on 2 1/2 acres and below. Will similar instructions be given to the other States—at least to the Janata ruled States? That must be implemented. If you protect the small farmers, then alone there will be prosperity. Of course, in your younger days you might have sung:

मेरी माता के सिर पर ताज रहे,

तो ताज तो आ गया है,

Now we are independent.

घर-घर में आदमी के अनाज रहे।

मगर घर-घर में अनाज नहीं है। तो आपके गोदाम भरने से लोगों का पेट नहीं भरना है। लोगों का पेट भरना है तो उनमें खरीदने की शक्ति पैदा करनी चाहिये। शक्ति पैदा करने के वास्ते आप क्या करना चाहते हैं। आपके पास सरप्लस अनाज इस वास्ते है कि आदमी खरीद नहीं सकता है। आप फूड फार वर्क में खाना देकर उससे काम लेना चाहते हैं। यह स्कीम अच्छी होगी, मगर इसका ज्यादा प्रचार नहीं होना चाहिये। देश के बाहर यह बात नहीं जानी चाहिये कि यहां के लोग इतने गरीब हैं कि खाना मिलने के नाम पर काम करने को तैयार हैं। यह हमारी सैल्फ रैस्पैक्ट के खिलाफ है। आप मेहरबानी कर के इस स्कीम का नाम बदल दीजिये। जैसा आपने विलिंग्डन हस्पताल का नाम डा० राम मनोहर लोहिया हस्पताल किया है, किसी और हस्पताल का नाम कृपलानी हस्पताल किया है और कुटुम्ब कल्याण बनाया है, इसी तरह से इसका नाम भी बदल दीजिये। यह फूड फार वर्क बहुत खराब चीज है, इसका प्रचार नहीं होना चाहिये।

यदि फूड फार वर्क के लिये लोग काम करने को आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लोग गरीब हैं। खाना खरीदना चाहते हैं, तो उनकी पर्चेजिंग कैपेसिटी होनी चाहिये। फूड फार वर्क पर आपको पूरा ध्यान नहीं देना चाहिये।

• यह कहना कि फूड कार्पोरेशन सब करप्शन है फला है तो मेरी कांस्टीटुएन्सी में भी 7, 8 जगह फूड कार्पोरेशन खुले हैं एक दो जगह पर और खोलने का था। खाली मैं लैटर लिखता हूं कि वैइंग सैंटर और पर्चेजिंग सैंटर खुलें निजामाबाद आन्ध्र प्रदेश में। मैं कहना चाहता हूं कि जो एम०पी० इन्हें बुरा भला कहने को आते हैं वह खुद एक्शन क्यों नहीं लेते? जब मैं कर सकता हूं तो दूसरे एम०पी० भी कर सकते हैं उसके वास्ते पार्लियामेंट का फोरम और समय बर्बाद नहीं होना चाहिये।

कौन ऐसा व्यक्ति है वह जैनरल मैनेजर हो या कोई और अफसर कि अगर कोई पार्लियामेंट का मम्बर डट कर कहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो फिर भी वैसा करने की हिम्मत करे? हम लोग तो आपोजीशन में हैं जब हम लोगों की बात चलती है तो आप लोगों की गवर्नमेंट तो सैंटर और स्टेट्स में है आपकी बात क्यों नहीं चलती है? इन बातों की शिकायत यहां पर नहीं आनी चाहिए। मिनिस्टर साहब या फूड कार्पोरेशन के मैनेजर को एक लैटर लिखना ही काफी है। फूड कार्पोरेशन हो या कोई और संस्था हो ऐसा नहीं हो सकता है कि वह पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज की बात को न माने। आखिर इसमें हमारा कोई पर्सनल गेन तो नहीं है। हम किसानों के नुमायंदे हैं। हम यही चाहते हैं कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए उन्हें पूरा पैसा मिलना चाहिए उनकी लूट खसूट नहीं होनी चाहिए और उन्हें व्यापारियों के चंगुल से बचाना चाहिए। ये काम करने के लिए हम लोग पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव हैं। अगर हम लोगों की बात वहां नहीं चलती है तो मिनिस्टर साहब को कहने से वह आदमी वहां से जा सकता है सस्पेंड और डिसमिस हो सकता है। इसलिए हम लोगों को इस बारे में प्रयत्न करना चाहिए।

श्री हरीकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय कृषि मंत्रालय की अनुदान-मांगों पर बोलने के लिए आपने मुझे जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

आज कल कृषि के बारे में हमारे देश में आम धारणा बन चुकी है कि हमारा देश अनाज के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो गया है और हम दूसरे देशों को अनाज भेजने लगे हैं। यह एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है और इस के लिए हम सरकार और मंत्री महोदय को बधाई देना चाहते हैं। यों तो हमारे देश में जो क्लाईमेट है वह भी इस स्थिति के लिए मुख्य रुप से बहुत हद तक जिम्मेदार है जिसमें कृषि का उत्पादन बढ़ा है। लेकिन हमें अभी बहुत कुछ कार्य करने हैं। सब से पहले मैं फ्लड कंट्रोल के बारे में कहना चाहता हूं।

मेरा सुझाव है कि हमें कृषि को बाढ़ से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए। सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाये हैं लेकिन इस बारे में जितनी तत्परता की आवश्यकता है वह हमें नीचे के कर्मचारियों और दूसरे लोगों में दिखाई नहीं देती है जो इस कार्य को करने के लिए जिम्मेदार है। मैं खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर कुछ कहना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम नदियों में हर साल भयंकर बाढ़ आती है जिससे कृषि को बहुत नुकसान होता है। मैं अपने जिले गोरखपुर में राप्ती घाघरा रोहिणी और नारायणी नदियों की बाढ़ के बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो बांध बनाने की स्कीम चालू की गई है उसे अतिशीघ्र कार्यान्वित कराये अन्यथा इस समय लोगों को बहुत क्षति उठानी पड़ती है और कृषि का बहुत नुकसान होता है।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर भारत और देश के काफी बड़े हिस्से में फ्लड कंट्रोल के लिए कैप्टन दस्तूर की गारलैंड कैनाल की स्कीम पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए। उन्हें संसद् सदस्यों की एक मीटिंग में बुलाया गया था जिसमें उन्होंने गारलैंड कैनाल स्कीम के बारे में बहुत विस्तार के साथ बताया था। जो बातें उन्होंने बताई थीं अगर वे सब ठीक हैं तो हम कह सकते हैं कि गारलैंड कैनाल के बनने के बाद न केवल बाढ़ पर नियंत्रण हो जायेगा बल्कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिलने की भी सम्भावना है। इस लिए इस स्कीम पर बड़ी गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए। योजना मंत्रालय की मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधान मंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया था और कहा था कि सरकार उसके बारे में कार्य कर रही है। लेकिन यदि वह बहुत ही यूजफुल स्कीम है तो देखना चाहिए कि उसे जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाये।

फ्लड कंट्रोल के अलावा दूसरी बात मैं शुगर इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने जब कभी भी इस सवाल को सदन में उठाया है बराबर यह कहा है कि शुगर इंडस्ट्री में तमाम मिल मालिक हमारे किसानों का और आम जनता का शोषण कर रहे हैं। उस शोषण से मुक्ति के लिए और साथ ही उस पर पूरी तरह से एक नियंत्रण स्थापित रखने के लिए जिस से कभी उस की कमी न होने पाये शुगर इंडस्ट्री के राष्ट्रीयकरण की दिशा में सरकार को अवश्य सोचना चाहिए।

लैंड रिफार्म के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि लैंड रिफार्म की जो स्कीम चलाई गई है उस में अभी भी ठीक ढंग से जमीन का बंटवारा नहीं हो पा रहा है और लोगों को जमीन नहीं मिल पा रही है। इस में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है लेकिन केन्द्रीय सरकार को भी इस में तत्परता दिखाने की आवश्यकता है। तमाम गांवों के अंदर सीलिंग के बाद जमीन निकली हुई है लेकिन उस का ठीक ढंग से बंटवारा नहीं हुआ है। जिस की जमीन निकली हुई है वही लोग उस पर खेती भी कर रहे हैं। इसलिए आज जो कृषि के कार्य में लगे हुए मजदूर हैं उन की दशा सुधारने के लिए और साथ ही भूमिहीनों की दशा को भी सुधारने के लिए उस भूमि के बंटवारे पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उस में किसी प्रकार की कमी करना देश के गरीब लोगों के प्रति एक बहुत बड़ा अन्याय होगा जब कि हमारी सरकार वचनबद्ध है कि गरीबों का हित करेंगे।

[श्री हरीकेश बहादुर]

वनों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हमारे पहाड़ों के अन्दर जो जंगल काटे जा रहे हैं या काटने की जो योजनाएं हैं उन्हें तुरन्त रोकना चाहिए। हमें नये जंगल लगाने चाहिए न कि ऐसी जगहों से जंगल काट लेने चाहिए खास तौर से पहाड़ों में जंगल काट लेने से जो भू स्खलन होता है उस से कितनी हानि उठानी पड़ती है। अभी भागीरथी में भू स्खलन के बाद जो एक बहुत बड़ी चट्टान आ कर रुक गई थी उस से कितना खतरा पैदा हो गया था यह हमें पता है। तो जंगल काटने से इस तरह की घटनाएं होती हैं इसलिए बजाय जंगल काटने के नये जंगल लगाने की दिशा में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

इर्रीगेशन फैसिलिटीज के बारे में यह जान कर के हमें प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। लेकिन हमें इस दिशा में भी बहुत तेजी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है और राज्य सरकारों को जहां केन्द्रीय सरकार इस कार्य के लिए पैसे देती है वहीं उसे पैसे दे कर ही अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो जाना चाहिए बल्कि बराबर राज्य सरकारों पर इस बात का दबाव भी डालने की कोशिश करते रहना चाहिए कि राज्य सरकारें इस काम को पूरी तेजी से करें। अगर इर्रीगेशन फैसिलिटीज ठीक ढंग से नहीं दी जायेंगी तो कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ेगा और हम आत्म निर्भरता के जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पायेंगे।

ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के संबंध में माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बातें बतायी हैं। बात बहुत उत्साह-वर्द्धक है। बहुत तेजी से यह काम हो रहा है और खास तौर से यह जो फूड फार वर्क स्कीम चली है उस से तमाम गांवों के अन्दर लिंक रोड्स बन रही हैं और दूसरे तरह के भी कार्य हो रहे हैं लेकिन उन कार्यों में जिस तरह की तेजी होनी चाहिए वह नहीं है क्योंकि हम ने देखा है कि सरकारी अधिकारी जो राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं वे लोग उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन उन के न ध्यान देने के बावजूद भी क्योंकि जन प्रतिनिधियों का उन पर दबाव रहता है इसलिए काफी काम हुआ है। अगर उस मशीनरी को स्ट्रीम लाइन करने की व्यवस्था की जा सके तो वह भी करना चाहिए और सरकार को उस दिशा में भी सोचना चाहिए।

इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह संगठन हमारे देश में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नये अनुसंधान करने के लिए बनाया गया था और इस ने महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह पता नहीं चलता कि यह संस्था कृषि उत्पादन के लिए बना है या सूसाइड के नये नये तरीके ढूंढने के लिए। हमेशा ही वहां पर सूसाइड होता रहता है और नये नये तरीके से होता है। कभी कोई गले में फन्दा लगा लेता है कभी कोई ऊपर से कूद जाता है कभी कोई तीसरी मंजिल से कूदता है कभी कोई चौथी मंजिल से कूदता है। इस तरह के तमाम कार्य वहां पर हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी को देखना चाहिये कि वहां पर क्या कारण है जो इस प्रकार की बातें होती हैं। कहा जाता है कि आई० सी० ए० आर० में वैज्ञानिकों के गुट बने हुए हैं और वे एक दूसरे से इस प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा में रहते हैं कि एक दूसरे का पांव खींचने में लगे रहते हैं। माननीय मंत्री जी को देखना चाहिये कि सही तरीके से वहां उनको प्रोमोशन वगैरह मिले और जो सुविधाएं आवश्यक हैं वह मिले। इस पर ध्यान देना चाहिये।

पोटैटो रिसर्च इंस्टीच्यूट जो है उस के बारे में मैं ने एक पत्र लिखा था माननीय मंत्री जी को 23 नवम्बर 1978 को। वह पत्र उन्होंने एकनालेज किया है। उस के बाद उस में क्या हुआ यह कुछ नहीं पता चला। वहां के निदेशक के बारे में मैंने कुछ आरोप लगाए थे जो मुझे मिले थे। वह मैंने उन को भेजे थे। मुझे लगता है कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई अन्यथा माननीय मंत्री जी ने हमें सूचित किया होता। इस प्रकार से तमाम लोगों के बारे में जैसा कि अभी भानु प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि आप लोग कोई बात बताते नहीं हैं तो हम बताते हैं और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो उससे बड़ी निराशा होती है। जहां तक माडर्न बेकरी का सम्बन्ध है वहां पर कोई ब्रिगेडियर यादव थे मैनेजिंग डायरेक्टर उनको कम्पलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया। उनके खिलाफ तरह तरह के चार्जेज थे। शायद सी बी आई के द्वारा भी इन्क्वायरी हुई थी। उनके ऊपर क्या कार्यवाही हुई है—इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। सम्भवत कोई कार्यवाही हुई हो नहीं है। आज माडर्न बेकरी की स्थिति यह है कि उसकी यूटि-लाईजेशन कैपेसिटी लगातार घटती चली जा रही है। मंत्रालय की ओर से जो किताब दी गई है उसमें बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं किन्तु उसकी स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती चली जा रही है। उसमें केवल नौकरशाही का ही बोल बाला है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कम्पनी पेय-77 का उत्पादन भी कर रही है लेकिन यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि पेय-77 का कंजम्शन उस मात्रा में नहीं हो रहा है जितना कि दूसरे पेयों का है। कम्पनी अपने प्रोडक्ट को उस क्वालिटी का नहीं बना पा रही है जिस क्वालिटी की आवश्यकता है। इसी प्रकार से और भी उद्देश्य थे जिनके लिए आप काम करना चाहते थे लेकिन आज वे सारे काम बन्द हो गए हैं।

दिल्ली मिल्क स्कीम के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट इसको कम्पनी के रूप में बदलने की योजना बना रही है जिसके कारण बहुत सारे कर्मचारियों में क्षोभ व्याप्त है। वे यह समझते हैं कि कुछ नये तरीके के उपकरण आयेंगे और कम्पनी बना कर कुछ इस प्रकार के काम किए जायेंगे जिनसे तमाम लोगों का रेट्रेन्चमेण्ट होगा। तो इसको बचाने के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एफ सी आई के गोदामों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं बहुत संक्षेप में, जो प्वाइंट्स मैंने लिख रखे हैं उनको बता रहा हूं ताकि मंत्री जी उन पर ध्यान दे सकें। एफ सी आई के गोदामों के

लिए वर्ल्ड बैंक ने लगभग 360 करोड़ रुपया दिया है लेकिन अभी तक उस काम की शुरुआत ठीक ढंग से नहीं हुई है। खास तौर से रूरल एरियाज में कहीं एफ सी आई के गोदाम नहीं बन रहे हैं। यदि उत्पादन बढ़ा है तो उस का रखने के लिए जगह भी चाहिये। हमेशा अनाज सड़ता है और हमेशा इस सदन में तरह तरह की बातें आती हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस के अलावा बोरों की कमी की बात भी कही जा रही है। यदि बोरे नहीं होंगे तो उस को कैसे रखा जायगा ? यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रोपाउड रेलवे लाइनइन रूरल एरियाज के बारे में रेल मंत्री जी ने कहा था कि वहां कृषि फार्म है जहां कृषि की काफी पैदावार होती है वहां रेलवे लाइन बनाएंगे। मझे पता नहीं रेल मंत्रालय की ओर से कोई पत्र आप के पास आया है या नहीं जिसके आधार पर आप बता सकें कि कौन से क्षेत्र हैं जहां पर रेलवे लाइन बनाई जायगी। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में जो रामपुर काठगोदाम लाइन है वहां पर कृषि का बहुत बड़ा क्षेत्र है। रामपुर काठगोदाम की पहले से ही प्रापाउड लाइन थी लेकिन उस को रोक दिया गया है। उस का रेलवे बनाने नहीं जा रही है। इसलिए कृषि मंत्री जी को कहना चाहिये कि रेलवे ने अगर इस तरह की कोई योजना बनाई है तो उस रेलवे लाइन को फौरन बनाना चाहिये।

गेहूं वगैरह की प्राइस के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कृषक जो कुछ भी पैदा करते हैं उस का उचित मूल्य उन को मिलना चाहिये। उस का क्या प्रबन्ध हो रहा है उस के बारे में मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिये। खाद के दाम तो जरूर कम किए गए हैं। पहले भी कुछ कम हुये थे। अनाज के दाम भी कुछ बढ़ाए गए हैं लेकिन उस के बावजूद कृषक महसूस करता है कि उस को उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। मझे उम्मीद है कि मंत्री जी अपने जवाब में इन सारी बातों को स्पष्ट करेंगे। किसानों को राहत देने के लिए वे खास तौर से कुछ योजनायें बनायेंगे। अन्त में पुन दोहरा देना चाहता हूं कि फ्लड कण्ट्रोल के ऊपर वह विशेष रूप से ध्यान दें क्यों कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा हमेशा बाढ़ से जलमग्न हो जाता है और उस में बड़ी क्षति होती है।

SHRI K. MALLANNA (Chitradurga): Madam Chairman, at the outset I want to congratulate the Agriculture Minister for having tried to help the agriculturists in the country. 60 per cent of the agricultural families are living below the poverty line. Government have introduced some measures in order to improve their economic condition in the rural areas, like the Food for Work Programme, Drought-Prone Areas Programme, Desert Area Development Programme, Small Farmers Development Agency, Tribal Area Development Programme and Hilly Area Development Project, apart from the Antyodaya or village development These are the measures taken by the Government to ameliorate or improve the working conditions of the rural folk.

Madam Chairman, I am coming from a constituency which has been declared as a backward area by the Planning Commission and almost all of my constituency is covered by the DPAP programme and also by Small Farmers Development Agencies (SFDA). Both these programmes are Centrally sponsored schemes. These schemes are introduced just to help the rural folk, i e, the very oppressed and depressed class in the existing rural society.

Madam Chairman, the drought-prone area in the country covers nearly 74 districts in 13 States. That means, it covers 12 per cent of the total population In terms of area it covers 5.66 lakh square kilometres, that is, 20 per cent of this area I find now that for the year 1979-80 it has been allotted Rs. 59 44 crores I feel it is very insufficient because the Planning Commission has declared more than 200 districts as backward areas under the drought-prone area programme. Madam the idea behind this is to tap the underground water and to irrigate these areas with underground water and river water. They have taken up soil conservation, then horticulture and so many other programmes to improve and provide jobs to the rural people, namely, the small farmers and the agriculturists

Madam Chairman, under the IRD programmes that is the Integrated Rural Development programmes, the DPAP and SFDA programmes are included. Unfortunately they have not planned anything except mentioning about some soil conservation and some afforestation. Planning should be made according to the situation of the area. Take, for example, my constituency.

[Shri K. Mallanna]

Though it is declared as under drought-prone area programme, they want to dig up the underground water. There is a big river called Bhadra going by the side of my constituency If Bhadra water is taken to my constituency, it covers about 12 to 13 taluks. Then if all the 12 or 13 taluks are irrigated by this Bhadra project, I think what the Government has thought to improve this under the DPAP programme will be successful It is only by investing money on the minor irrigations, that too which cost above Rs 50,000, that success can be achieved. But nothing is mentioned about minor irrigations, about the tubewell's and borewells. If we request the agency to take up a tube well or bore well, they will say it does not come under minor irrigation, and so it cannot be taken up under DPAP But then, how can you tap underground water without tube wells or bore wells? So, it is only a name sake

In the DPAP areas, agro-based industries should be started They are said to be encouraging horticulture, sericulture, piggery, poultry etc, but it is all only in name because implementation is not properly done I want the Ministry to take up these things intensively.

So far as advance of loans to these programmes is concerned the banks are giving a lot of trouble and causing a lot of inconvenience to the poorer section of the society. Though a subsidy of 30 to 60 per cent is given to agricultural labourers and farmers, the nationalised and local banks are not coming forward to help these poor people. So, I request the hon. Minister to look into the matter and give them easy loans

Unfortunately, though these programmes are meant for the economic development of the poorer sections, they have not been properly implemented. I suggest that agricultural centres should be started at least in the DPAP areas like the industrial centres which have been started in the city and town areas to help small-scale and other industries.

The poor ryots and agricultural labourers have no house or shed to rear poultry. When they ask for a loan, the bank people enquire if they have got a shed or a house, and that too scientifically constructed. They say they cannot afford it, and the bank people do not give the money.

Similarly, sericulture requires well-built weather-proof houses for the cocoons to be reared properly, but small farmers owning two or three acres of land are unable to build these houses, and the bank people are not giving them money, with the result they are unable to take to this industry

If at all there is any programme to help the rural folk, it is the dairy farming programme Here also, the bank people reject loan applications on the ground that the ryots have no proper cow sheds I would request the hon Minister to consider all these things and to establish agricultural centres in the rural areas.

I want to stress one more point. As far as the milk societies are concerned, we have to consider the pricing policy. In my State, the State Government, has, with great difficulty, introduced in certain pockets a scheme called Karnataka Dairy Scheme, under which the minimum price fixed for milk is Rs. 1 35 per litre. In Gujarat it is Rs. 1.65. I do not know about other States. The cost of the inputs are rising. The cost of feeding the cattle has gone up. The cost of buffaloes and cows has also gone up. So, they are not able to maintain the cattle. It is very difficult to purchase milch animals because they are very costly. So, I would request the hon. Minister to fix up the minimum price for the milk because that would help many people in the rural areas. It would also give employment to many people. Easy availability of manure would enable them to improve the fertility of the land.

Then I would come to the marketing facilities in the rural areas. Under DPAP programmes, poor ryots and agriculturists are being given loans to purchase buffalows and cows. But they are not finding market for the milk. So, they are unable to repay the loans advanced to them. So, I would request the Minister to take the necessary steps to improve the marketing facilities. If they are really keen to improve the economic condition of the small and marginal farmers, they have to establish agricultural centres, fix the minimum price for their produce and also improve the marketing facilities.

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति जी, अभी जो बहस चल रही है, उस के बारे में सब से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों से सम्बन्ध रखने वाली इस बहस में तीन तरह के लोग हैं, जिन्होंने हिस्सा लिया है। एक तो वास्तव में किसान हैं, जो गांव में खेत की मेंढ पर खड़ा हो कर अपनी खेती करता है। दूसरा वह है, जो कोठी शहर में रखता है लेकिन उस का फार्म देहात में है और वह भी अपने आप को किसान कहता है और तीसरे ऐसे लोग हैं जो एअर-कण्डिशण्ड मकानों में गद्दों पर बैठ कर केवल किसानों से सम्बन्धित कुछ किताबें पढ़ कर ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं और वे भी अपने आप को किसान समझते हैं।

सही मायने में गांव की समस्या के बारे में ऐसे लोग विचार करते हैं जिन्होंने गांव को कभी देखा नहीं, जिनके घर की औरतों को भादों की अंधेरी रात में टिहुना भर कीचड़ हेल कर कभी सड़क के किनारे पाखाने पर नहीं बैठना पड़ा, वह कभी गांववाली औरतों की कठिनाई के बारे में नहीं जान सकते। आज भी गांव में बसने वाली करोड़ों ऐसी औरतें हैं, जिनको 12 घण्टे तक पाखाने को अपने पेट में सड़ा कर रखना पड़ता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उनके पाखाना जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सूर्यास्त होता है तो गांव के बाहर जब पाखाने को जाती हैं और सड़क के किनारे पर पाखाने पर बैठती हैं, उस समय कोई राही रास्ते से निकलता है तो आधा पाखाना पेट में लेकर खड़ी हो जाती हैं। गांव में बसने वाली उन करोड़ों औरतों के बारे में वही जान सकता है जिस ने कभी उस वातावरण को देखा हो, वहां पला हो, जिसको उस वातावरण की असलियत का ज्ञान हो। आजाद भारत में गांव में बसने वाली करोड़ों महिलाओं के पाखाना जाने की भी व्यवस्था नहीं हो पाई और न जनता राज्य में ही उस तरफ कोई दृष्टि है और न उसको सुधारने की चिन्ता है।

जिस देश में माताएं रोगिणी होंगी, रोगिणी के पेट से कभी स्वस्थ संतान पैदा नहीं हो सकती, देश की संतान मां के पेट से ही रोगिणी होगी, उस संतान से कभी देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती। इसलिए, अगर सीमाओं की सुरक्षा करनी है तो गांव की करोड़ों महिलाओं के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए पहले उनके पाखाने की व्यवस्था करनी होगी।

आज हम खेती पर चर्चा करते हैं। खेती के लिये जो लोग पिस रहे हैं, एक तरफ सरकारी तंत्र है और दूसरी तरफ व्यापारी। इस व्यापारी और नौकरशाही की चक्की में खेती पिस रही है। कबीरदास ने कहा था—

चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोय,
दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोय।

व्यापारी की बात जब हम करते हैं तो उसको क्यों नहीं बढ़ावा मिलेगा? व्यापार में लाइसेंस, परमिट, घूस, तरक्की, मुनाफा और फाइव-स्टार होटल सब कुछ है लेकिन खेती में न लाइसेंस, न परमिट, न घूस और न खेती करने वालों के पास फाइव-स्टार होटल जहां वह मौज कर सकें। जहां सुख और सुविधाओं का अम्बार है, वहां व्यापार की तरक्की होगी, खेती में यह सुख-सुविधाएं नहीं हैं इसलिए किसानों की उपेक्षा होती रहेगी। आज जब यह कहते हैं कि जनता सरकार ने बहुत ज्यादा किया, मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने इस बजट में गांव के प्रति, किसानों के प्रति कुछ ध्यान दिया है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देख लें कि शहरों में बसने वाले जो मुट्ठीभर आदमी हैं, जिनके हाथ में समाचार पत्र हैं और दूसरे साधन हैं वही आज वित्त मंत्री के खिलाफ और इस बजट के खिलाफ हंगामा खड़ा किये हुए हैं कि यह बजट महंगाई का बजट है और फला है।

मैं पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों में आपने गांव के लिए क्या किया? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे कृषि मंत्री जी और दूसरे लोग कहते हैं कि गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया गया है, गांव पर बहुत खर्चा हुआ है, लेकिन हैरत में पड़ जाता हूं जब इनका दिया हुआ इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण देखता हूं जिसमें लिखा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना पर जहां कृषि और समस्त क्षेत्र पर 14.7 प्रतिशत खर्च किया गया था, वहां 1978–83 की योजना में जो इन्होंने दर्शाया है वह 13.7 प्रतिशत है। यह आर्थिक सर्वेक्षण इन्हीं का दिया हुआ है। यह कहते हैं कि खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में जहां 11.7 प्रतिशत खेती पर व्यय था वहां 78–83 वाली प्रस्तावित योजना में इसे घटाया गया है जिसका प्रारूप अभी तैयार नहीं है। उसमें 13.7 प्रतिशत है और 1978–79 वाले परिव्यय में बताया है कि 15.0 है। सिंचाई में जहां चौथी योजना में 8.6 प्रतिशत बताया गया है वहां 1978–83 वाली योजना में 11.5 है, केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि यह बता रहे हैं। 1978–79 में जो 10 प्रतिशत इन्होंने खर्चे में रखा है जब कि 1978 से 83 वाली योजना में 1 प्रतिशत कमी है।

उद्योग में जहां चौथी पंचवर्षीय योजना में 18.2 प्रतिशत इन्होंने रखा था वहां 1978–83 की

(श्री हुकम देव नारायण यादव)

योजना मे 19 2 प्रतिशत है। यहा भी जो बडे उद्योग है, उसके अनुसार अगर चौथी पच वर्षीय योजना के मुकाबले इनकी जो योजना बनन जा रही है उसमे इन्होंने 1 2 प्रतिशत ज्यादा खर्च रखा है और कृषि में 1 प्वाइण्ट कम कर के रखा है। यह इनकी सर्वेक्षण की किताब में प्रकाशित हुआ है।

मेरे एक प्रश्न के उत्तर मे वित्त मत्री ने नवम्बर, 1978 तक बैंको द्वारा दिय गय कर्जों के बारे म ये आकडे दिये कृषि 11 5 प्रतिशत लघु उद्योग 11 6 प्रतिशत बडे उद्योग 39 6 प्रतिशत। हिन्दुस्तान के लगभग 70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते है और 80 10 प्रतिशत लोग गावो मे बसते है। कृषि पर निर्भर करने वाले लगभग 70 प्रतिशत लोगो का केवल 11 5 प्रतिशत बैंक ऋण दिये गये जब कि बडे उद्योगो को 39 6 प्रतिशत दिये गये। ये आकड क्या दर्शाते है? सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम खेती की तरफ बढ रहे है और बडे उद्योगो मे एकाधिकार को खत्म करने के लिए आर्थिक विकेन्द्रीकरण की तरफ बढ रहे है। लेकिन बैंको का दृष्टिकोण यह बताता है कि सरकार आर्थिक विकेन्द्रीकरण और खेती की तरफ नहीं बढ रही है क्योकि कृषि को कम ऋण दिया जा रहा है।

सभापति महोदय माननीय सदस्य दो मिनट मे समाप्त करे।

श्री हुकम देव नारायण यादव : अन्य सदस्यो को 15, 15 मिनट दिय गये है। मुझे थोडा समय और दिया जाय।

सभापति महोदय नही माननीय सदस्य दो मिनट मे समाप्त कर दे।

श्री हुकम देव नारायण यादव जिस देश मे खेती पर भार जितना कम होता है वह देश उतना ही धनवान होता है। क्या कृषि मत्रालय द्वारा इस दिशा मे कोई कार्यवाही की जा रही है कि खेती पर से भार को कम किया जाय? खेती पर भार तब तक कम नही होगा जब तक कि कुटीर उद्योगो को बढावा नही दिया जायगा। रूस मे कुल आबादी का 31 9 प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर है अमरीका मे 4 0 प्रतिशत ब्रिटेन मे 2 8 प्रतिशत और जापान मे 20 7 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर है लेकिन भारत मे जनसख्या का 69 7 प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर करता है।

यह दर्शाता है कि जिस देश मे खेती पर जितनी कम जनसख्या का भार है वह देश उतना ही मालदार और खुशहाल है लेकिन जिस देश मे खेती पर ज्यादा जनसख्या का भार है वह देश उतना ही गरीब है। अगर हम भारत जैसे गरीब देश के आगे बढाना चाहते है उसकी तरक्की करना चाहत है तो खेती पर से भार को कम कर के अधिक से अधिक लोगो को कुटीर उद्योगो की तरफ ले जाना होगा। लेकिन कुटीर उद्योगो का विकास तब तक नही हो सकता है जब तक कि हम यह तय न करे कि जिन वस्तुओ का निर्माण मनुष्य के हाथो से हो सकता है उनका उत्पादन बडे कारखाना मे नही होगा।

मेरे सामने प्रति व्यक्ति उपभोग के बारे मे भारत सरकार के ये आकडे है —

	1955-56	1977-78
	किलोग्राम	किलोग्राम
खाद्य तेल	2 5	3 9
चीनी	5	7 2
सूती कपडा	11 4 मीटर	11 8 मीटर

इससे पता चलता है कि जहा 1955-56 म कपडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 11 4 मीटर थी वहा 1977-78 मे वह घट कर 11 मीटर रह गई। एक तरफ रुई के दाम रकम हो रहे है और दूसरी तरफ कपडे के दाम बढे रहे है।

18 hrs

गावो के सुधार की बात कही जाती है मगर श्री जार्ज फर्नांडीस उद्योग मत्री ने कहा है कि नैशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन अपने उत्पादन मे से केवल 40 प्रतिशत मोटा और साधारण कपडा बनाता है। मै निवेदन करना चाहता हू कि जिस देश म 60 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते है और 80 फीसदी लोग गावो मे रहत है वहा की नैशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन का दृष्टिकोण यह होना चाहिय कि वह अपने उत्पादन का 60 या 80 फीसदी मोटा और साधारण कपडा तैयार करे। पैसा करने पर ही गाव वालो के तन पर कपडा हो सकता है। इस लिए अगर सरकार किसानो और गाव वालो के लिए कुछ करना चाहती है तो उसे इस दिशा मे सोचना होगा।

1971-72 मे कृषि उत्पादो का सूचकाक 100 4 था और थोक कीमतो का सूचकाक 105 6 था। 1971-72 से लेकर दिसम्बर 1979 तक थोक कीमतो का सूचकाक निरन्तर बढता चला गया है और यही स्थिति विनिर्मित उत्पादो के सूचकाक की रही है जो लगातार बढता रहा है। कृषि के सूचक अक हास की ओर गए है। अप्रैल 1977 मे जहा दूसरी वस्तुओ का सूचकाक 184 था वहा कृषि का 172 था। 1978 मे जहा दूसरी वस्तुओ का सूचकाक 184 पर ही खडा है वहा कृषि उत्पादन की वस्तुओ का सूचकाक 172 से घट कर 169 पर चला आया है। तो लगता है कि कृषि उत्पादन की वस्तुओ का सूचकाक ह्रास की ओर चला जा रहा है और दूसरी वस्तुओ का सूचकाक बढता चला जा

रहा है। जब तक उस का रोका नहीं जायेगा तब तक विकास नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए।

---

18 02 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

POSTAL ACCOUNTS IN HARYANA

श्रीमती मृणाल गोरे (बम्बई उत्तर) सभापति महोदया, 12-3-79 का प्रश्न संख्या 284 का जो उत्तर दिया गया है उस के बारे में मैं यह चर्चा चलाना चाहती हूं। उस दिन सवाल के जवाब में जो बताया गया उस में यह कहा गया कि 50 हजार रुपये से ऊपर के जो डिपाजिट्स 1974 में हरयाने के पोस्ट आफिसेज में किए गए उस के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। मैं उस दिन बराबर पूछती रही कि कुल मिला कर 74, 75 और 76 तीन सालों में इस प्रकार के कितने लोगों ने डिपाजिटस किए थे और कितनों के बारे में जांच अभी तक हो गई है। मुझे जो मालूमात मिली है उस के मुताबिक 1974-75 और 76 में लगभग 712, पचास हजार रुपये के ऊपर के डिपाजिटस हरयाना के पोस्ट आफिसेज में हुए। इस के बारे में देखने लायक चीज तो यह है कि उस में कई डिपाजिट्स ऐसे हैं कि वहां 30 मार्च को डिपाजिट किया, 2 अप्रैल को पैसा उसी एकाउंट में से वापस ले लिया, 29 मार्च को डिपाजिट किया और 2 अप्रैल को वापस ले लिया या फिर 31 मार्च को डिपाजिट किया और 3 अप्रैल को ले लिया। ऐसे ही तीन चार दिन के लिए इतनी बड़ी रकम डिपाजिट कर के जो वापस ले ली गई उसमें कई व्यक्तिगत डिपाजिट्स भी हैं, कई म्यूनिसिपैलिटीज के हैं, कई पुलिस इंसपेक्टर्स के हैं तहसीलदार के हैं, डी एम्स के हैं, कोआपरेटिव मिल्स के हैं, जिला परिषदों के डिपाजिट्स हैं, कई तरह के डिपाजिट्स इस प्रकार के हैं और इस के बारे में दिसम्बर, 1977 से इस सरकार के पास लगातार कई शिकायतें आई हैं, इसके बावजूद भी अभी तक इन की जांच पूरी नहीं हुई है यह हमारी शिकायत है।

उस दिन के सवालों के जवाब में कम्यूनिकेशंस डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि इस में केवल 13 केसेज हैं जिन में पोस्टल डिपार्टमेंट के रूल्स का उल्लंघन किया गया है। मैं यह कहना चाहूंगी, उस दिन भी मैं बार-बार कह रही थी कि जो 10 फरवरी, 1978 के करेक्ट में आया है, उस में जो लिस्ट आई है और जो पचास नाम आए हैं उस में से 13 केसेज ऐसे हैं कि जहां पोस्टल डिपार्टमेंट के रूल्स वायोलेट हुए हैं लेकिन उस के साथ साथ बाकी कई डिपाजिट्स के केसेज हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि कुल मिला कर कितने ऐसे केसेज हैं। केवल करेक्ट में जो पचास केसेज दिए गए हैं उन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, 74, 75 और 76 सालों में कुल मिला कर कितने एकाउंट ऐसे खोले गए, कितनों के बारे में पोस्टल डिपार्टमेंट के रूल्स का उल्लंघन हुआ और उन के बारे में अभी तक क्या हुआ?

मंत्री महोदय उस दिन बार बार कहते रहे हैं कि जांच चल रही है, ऐक्शन ले रहे हैं, कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार की बातें वह करते रहे। मेरा यह कहना है कि जब 77 साल से यह बात चल रही है और अब काफी बातें सामने आ गई हैं, इनकम टैक्स विभाग भी इस के बारे में तलाशी कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इस में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि 2 मार्च 1979 को कंवर लाल गुप्त जी के अनस्टार्ड क्वेश्चन नम्बर 1762 का जो जवाब दिया गया है उस में 1974 साल के 5 लाख के ऊपर के जो डिपाजिट्स हैं, उन के 85 कैसेज के नाम दिए गए हैं। मुझे खेद है कि इस लिस्ट में भी नाम दिया है, कितना डिपाजिट रखा उस की तारीख दी है लेकिन उस का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कि यह डिपाजिट फिर से वापस कब लिए गए, कब विदड्रा किए गए, क्या एकाउण्ट था इस की तारीख नहीं है। इस से ज्यादा शक होता है। दो तीन दिन के लिए पांच लाख आठ लाख दस लाख ऐसा एमाउण्ट रखा गया। किस के नाम से रखा गया, क्या बेनामी एकाउण्ट थे, इस के बारे में तीन केसेज के बारे में तो उस दिन भी मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा था कि ये बेनामी एकाउण्टस हैं, ऐसा लग रहा है—आर पी सी का पांच लाख का डिपाजिट, श्री एन के गंग, ज्वाइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, हरयाना गवर्नमेंट का पांच लाख का डिपाजिट और श्री कश्मीरी लाल, दि दून स्टूडेंट आफ डेलही यूनिवर्सिटी का 1 करोड़ 35 लाख का डिपाजिट। मैं कहना चाहूंगी कि केवल 74 साल के बारे में ही आप मत कहिये, 74, 75 और 76 इन तीनों सालों में लगातार हरियाणा के पोस्ट आफिसेज में इस प्रकार के एकाउण्ट्स खोले गए। ऐसा लग रहा है कि इस का उपयोग बेनामी एकाउण्ट्स खोल कर कुछ राजनैतिक कामों के लिए हो रहा था। तो क्या यह बात सही नहीं है? इसके बारे में फाइनेन्स डिपार्टमेंट भी जांच कर रहा है। कहां तक इस की जांच हुई है, यह मैं जानना चाहूंगी।

तीसरी बात यह है कि जो जांच अभी तक हुई उस के आधार पर क्या आप ने डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उन के ऊपर कोई ऐक्शन लिया? आप ने कहा है कि तीन पोस्ट मास्टर इन्वाल्व्ड हैं। उस दिन भी आप ने यह कहा था। तो इस में ऐक्शन लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है? इस से ऐसा लगता है कि लोगों के मन में जो शक पैदा हुआ है वह बिल्कुल वाजिब है। तीन दिन के लिए, 6, 8 या 10 लाख कोई नहीं रखता है। कुछ न कुछ इस में दाल में काला है। असलियत क्या है वह सदन की जानने की इच्छा है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि आप कृपा कर के पूरी तरह से बताएं। उस दिन जैसा लग रहा था कि तेरह केसेज ही हैं, उन में से कितनी पर ऐक्शन ले रहे हैं या लेने का विचार चल रहा है, इस प्रकार की बात आप मत करें। मतलब 74, 75 और 76 इन तीनों सालों में कितने एकाउण्ट्स थे

[श्रीमती मृणाल गोरे]

और क्या हुआ है यह बताएं। अगर फाइनेंन्स डिपार्टमेंट के पास दूसरे मामलों के बारे में जांच चल रही है तो उन की तरफ से भी जवाब आने की जरूरत थी। आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस में जांच करेगा तभी पूरा पता चलेगा। क्या इस जांच में बंशी लाल या दूसरे राजनैतिक नेताओं का सम्बन्ध है और क्या बेनामी एकाउण्ट्स का प्रयोग किया गया है, इस का भी ठोस जवाब आना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि इस के बारे में पूरा जवाब दें।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदया, सब से पहले "करेंट" के 3 फरवरी के ईशू में 30 करोड़ रुपये के बेनामी घोटाले का जिक्र आया था। जब कुछ लोगों ने कहा कि यह मनगढ़न्त बात है तो फिर "करेण्ट" ने अपने 10 फरवरी के अंक में इस का पूरा ब्योरा ही दे दिया, जिस में डिपाजिट्स और विद्ड्राग्रल्ज—करनाल हैड पोस्ट-आफिस—के 23 कैसेज का उल्लेख है। म इन को पढ़ूंगा नहीं, लेकिन सब के नाम, डेट-आफ-डिपाजिट, डेट-आफ-विद्ड्राग्रल्ज और उस के बाद रोहतक हैड क्वार्टर के 1973 से 1975 तक के 26 केसेज के डिपाजिट्स और विद्ड्राग्रल्ज का उल्लेख है। हम को तो यह देख कर आश्चर्य होता है—30 ता० को काश्मीरी लाल ने 1 लाख 35 हजार जमा कराया और ता० 2 को वह निकाल लेते हैं। हमें तो यह सारा काम जो हुआ है—घोटाले का काम मालूम पड़ता है। वित्त विभाग ने जो उत्तर दिया है—उस में तो बहुत थोड़ा कर के दिखाया है, जैसे आइस-बर्ग होता है, 1/10 भाग पानी के ऊपर होता है, 9/10 भाग नीचे होता है। इस को देखते हुए मैं तो यह समझता हूं कि आधे घण्टे की चर्चा तो बहुत कम है, इस पर 2 घण्टे की चर्चा होनी चाहिये थी।

फाइनेंन्स मिनिस्ट्री ने जो उत्तर दिया है, उस में 145 लाख के बेनामी—ट्रांजेक्शन का जिक्र किया है...

Shri R. P. Singh, the then District Industries Officer at Panipat—Rs. 5 lakhs.

Shri N. K. Garg, the then Joint Director of Industries in Haryana Government—Rs. 5 lakhs.

Shri Kashmiri Lal, the then Student of the Delhi University—Rs. 1.35 crores.

यह क्या तमाशा है? उस समय के जो राजनेता थे, वे तो भ्रष्टाचार में शामिल थे ही, लेकिन जो आप के डाक-तार विभाग के, पोस्ट-आफिस के लोग थे, वे भी भ्रष्टाचार के प्रशान्त समुद्र में डूब थे और जब हमारे संचार मंत्री जी ने बतलाया कि हम उन के ऊपर एक्शन लेंगे—क्या उनके ऐसा कहने की जरूरत थी, यह एक्शन तो कभी का हो जाना चाहिये था ताकि वे आगे कोई ऐसा काम न करें। उन्होंने सदन में मृणाल बहिन के प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि हम उन पर कार्यवाही करेंगे—वह कार्यवाही अब तक क्यों नहीं हुई? आज मृणाल बहिन ने उन को जो चुनौती दी है कि अब तक उन्होंने क्या किया—यह ठीक ही है।

इस में दो मुख्य बातें है—मैं जानता हूं इस सारे घोटाले को ले कर संचार मंत्री कह देंगे कि यह वित्त मंत्रालय का काम है और वित्त मंत्रालय कह देगा यह पोस्ट आफिस का काम है जनता जहन्नुम में जाय। मैं आप से जानना चाहता हूं—यदि यह आप के वश की बात नहीं है और वित्त मंत्रालय के लिए किसी मर्यादा की सीमा का बन्धन है—तो क्या वे इस बड़े घोटाल की जांच करने के लिए—जिस में 30 करोड़ का सवाल तो सुना ही है हो सकता है कि 130 करोड़ हो—सी० बी० आई० को जांच के लिए भजेंगे? मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस मामले में लीपा पोती का काम चल रहा ह। मोहनहिम ने कहा है कि उस ने करोड़ों रुपया दिया है, वह रुपया कहां गया? इन्दिरा गांधी जी क पास सैकड़ों करोड़ रुपया पहुंचा—उस का पता कैसे लगेगा? सभापति महोदय क्या सार्वजनिक जीवन को स्वस्थ और साफ़ रखने के लिय मुझे संचार मंत्री जी से यह आश्वासन मिल सकता है कि व इस सारे बेनामी घोटाले की जांच के लिए इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को देंगे?

दूसरा सवाल यह है कि आप के विभाग की जो नीति है कि इण्डिविजुअल एकाउण्ट में 25 हजार रुपया जमा किया जा सकता है और जो मिक्स्ड एकाउण्ट ह उन में 50 हजार रुपया जमा किया जा सकता है, लाख-लाख-दो दो लाख और पांच-पांच लाख पोस्ट आफिस में किस नियम के तहत जमा किया गया यह बताया जाए। अगर एसा करके नियमों का भंग किया गया है तो अभी तक उनको दंडित करने में, जो कि इससे सम्बन्धित ह आपके कदम क्यों थरथरा रहे ह। इन दोनों बातों का म आप से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : माननीय सदस्या ने बहुत अहम प्रश्न किया है और उस दिन का हवाला दिया है कि हम ने केवल 13 केसिस का ही क्यों उल्लेख किया बाकी हमने क्यों नहीं बताए और उन को हमने बचाया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस दिन सवाल सिर्फ करेंट वाले का था। आज जब आपने सारे सवाल पूछे हैं तो मैं कुछ छिपाऊंगा नहीं और हर चीज बताऊंगा। सब से पहले उनका प्रश्न यह था कि सिर्फ 13 केसिस थे या और ज्यादा थे और एक साल क ही थे या कई सालों क थे। म बता दूं कि 1973-74 में ऐसे 1180 केसिस में जो कि 25 हजार की लिमिट और पचास हजार की लिमिट से ज्यादा के थे और इंडिविजुअल केसिस थे। 1974-75 में 616 केसिस थ; 1975-76 में 8 केसिस थे और 1976-77 में 84 केसिस थे। ऐसे केसिस थे जिन में इन डाकखानों में अलग अलग जगह अलग-अलग ढंग से रुपया जमा किया गया।

25 हजार और 50 हजार से ऊपर। हमने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की और करनी चाहिए थी या नहीं, करनी चाहिये थी यह भी मैं आपको बता देता हूँ।

श्रीमती मृणाल गोरे सभी केसिस में नियमों का भंग हुआ है ?

श्री बृज लाल वर्मा. हमारे नियमों में यह है कि इंडिविजुअल केसिस में 25 हजार जमा होना चाहिए और अगर ज्वाइण्ट खाता है तो पचास से ऊपर नहीं हो सकता है परन्तु उसमें अगर ज्यादा जमा है तो हम उस पर ब्याज नहीं देते हैं। नियम 8 और 9 के मुताबिक ब्याज न देने की बात आती है। पचास हजार से या पच्चीस हजार से ऊपर किसी की जमा राशि हो तो उसके ऊपर जितनी रकम है उस पर हम ब्याज नहीं देते हैं। इन नियमों का आधार लेते हुए हमारे कर्मचारियों ने उसको जमा कर लिया। इस खयाल से और इन नियमों की वजह से उस पर कोई कारवाई करने में हम ने अपनी असमर्थता प्रकट की। दूसरा सवाल यह उठता है कि यह कैसे हो गया,—कैसे दो तीन दिन में विदड़ा कर लिया गया, तीन तारीख को जमा हुआ और दो तारीख को वह विदड्रा हो गया सिर्फ दो तीन रोज के लिए जमा हुआ। यह सच बात है। एक सदस्य ने बताया है कि एक आदमी ने 1 करोड़ 35 लाख कैश जमा करवा दिया। अब आप जानते हैं कि जिस वक्त की यह बात है उस वक्त वहां पर कौन मुख्य मंत्री था, कैसा वहां पर शासन था, किस प्रकार की जोर जबर्दस्ती वहां पर चल रही थी। एक गरीब कर्मचारी जो वहां पर डाकखाने में काम कर रहा था उसकी छाती पर बैठ कर उसको जमा करने के लिए कहा जाए तो वह क्या कर सकता था। सरकारी अधिकारियों द्वारा उसके साथ जबर्दस्ती की गई। उसने सोचा कि नियमों के मुताबिक उसने जमा किया। जमा करना उसका फर्ज था। विदड्रा नियमों के मुताबिक हुआ। खाता उसका बराबर है, साफ है। उसको कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुक्सान यह हुआ कि उसको अधिक देर तक बैठना पड़ा, और हर प्रकार से उसको डर हुआ, भय हुआ। जिस व्यक्ति ने जमा और विदड्रा किया था उसकी वजह से उसका कुछ व्यक्तिगत फायदा नहीं हुआ बल्कि तकलीफ ही उलटे हुई।

तीन आदमियों के ऊपर हमने एक्शन लिया और वह इसलिए लिया कि उसको ठीक ढंग से जो कुछ करना चाहिये था वह नहीं हुआ। एक्शन इस कारण से नहीं लिया कि उसने पच्चीस या पचास हजार से ज्यादा जमा किया। उसकी पांच छः महीने इनक्रीमेंट्स रोकी और उसके खिलाफ जब वे अपील में गए तो उनको वार्निंग मिली और वे छूट गए।

डा० रामजी सिंह बेनामी किसी नाम से क्या हो सकता है ?

श्री बृजलाल वर्मा बेनामी नहीं है हमारे खातों से किस के नाम से जमा हुआ और किस के नाम से विदड्रा हुआ "बिल्कुल साफ है।"

डा० रामजी सिंह हस्ताक्षर किस ने प्रमाणित किए हैं ?

श्री बृजलाल वर्मा. यह जांच का सवाल है। लेकिन हमारा काम एजेंसी का काम होता है। हम उसके हकदार नहीं हैं। अगर एक गरीब आदमी आता है कहीं से पचास हजार लाता है या एक करोड़ लाता है अब वह कहां से लाता है इसकी जांच हम नहीं कर सकते हैं, यह हमारे अधिकार से बाहर की चीज है। हम सिर्फ जमा करने वाले हैं और विदड्राअल देने वाले हैं। इसके अलावा इससे हमारा कुछ मतलब नहीं है कि कैसे और कहां से कोई लाया है,...

डा० रामजी सिंह चाहे चोरी करके लाया हो ?

श्री बृजलाल वर्मा चोरी कर के लाया हो तो भी हमारा काम जमा करना है। हम नहीं कह सकते हैं कि चोरी का पैसा है और जमा नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो उलटे हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी।

यह कहा गया है कि दो तीन रोज के लिए जमा हुआ जो कि नहीं होना चाहिये था। इसके बारे में फाइनेन्स डिपार्टमेंट के पास हमारे अधिकारियों ने रिपोर्ट की कि इस प्रकार से जमा हो रहा है इसको आप देखें। 1974 में रिपोर्ट की। ऐसी बात नहीं है कि नहीं की। परन्तु एक्शन हम नहीं ले सकते हैं। फाइनेन्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स वाले लेंगे। हम ने उनको सूचना दे दी। हमारे अधिकारियों ने हरियाणा गवर्नमेंट को भी सूचना दे दी और 1974 में दे दी। जहां तक काश्मीरी लाल की बात है हमने 21-7-74 को बैंकिंग विभाग को इस की सूचना दी। जिस किसी के बारे में डाउट हुआ उसकी सूचना दी। बहुत से डाउटफुल लगे उनकी सूचना जनवरी, 1975 में दी, हमारे अधिकारियों ने दी। लेकिन सब चीजें जो हुई हैं ऐसी परिस्थितियों में हुई हैं कि जिन को जानते हुए भी हम कुछ कर नहीं सकते थे। फाइनेन्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी चाहिये। इसलिए मैंने पहले ही स्पीकर साहब का इशारा किया था कि जो जानकारी ये विभाग दे सकते हैं वह हम नहीं दे सकते हैं। हम तो सिर्फ खाता रखने वाले हैं और एजेंसी के बतौर काम करते हैं।

श्रीमती मृणाल गोरे तीन केसिस में क्या सजा दी ?

श्री बृजलाल वर्मा मैंने बताया है कि इनक्रीमेंट्स रोकी थी। फिर उसके बाद अपील में उनको दोषी नहीं पाया गया। इसलिए इनको सिर्फ वार्निंग दी गई और छोड़ दिया गया।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil) There are some arrears in the rural areas of Haryana. E.D.S. are there

[Shri Vayalar Ravi]

in the post offices. But are they authorised to collect money? I think they have not been authorised to do it. What arrangement have you made in these areas?

SHRI BRIJ LAL VERMA: It is not only the case of E.D.S. in those post offices, but it is in the case of others also. This thing has happened with regular Government offices also.

SHRI VAYALAR RAVI: They have no authority. But what arrangements have been made to collect the money?

SHRI BRIJ LAL VERMA: It has not been made....

डा० रामजी सिंह : मैं एक अन्तिम सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे संचार मंत्री बहुत ही असहाय और निरीह अनुभव कर रहे हैं। उनसे इस दिशा में अगर कुछ नहीं हो सकता, और वित्त मंत्री भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो संचार मंत्री जी भी मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैं और ज्वायण्ट रिस्पोंसिबिलिटी है। अगर आपसे नहीं हो सकता और वित्त मंत्री इस पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो आप तो इसके महत्व को समझते हैं। क्या आप इसको मंत्रिमंडल में ले जा कर सी० बी० आई० की जांच के लिए अपना प्रस्ताव रखेंगे ताकि इसकी पूरी तहकीकात हो और इस पर कार्यवाही हो सके।

श्री बृज लाल वर्मा : मैंने पहले ही कहा कि हम इस में बिल्कुल असहाय नहीं हैं। हमने पूरे-पूरे कागजात जो हमें मिले हैं, फाइनेन्स डिपार्टमेंट और इनकम-टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिये हैं और उनकी जांच चालू है। ऐसी बात नहीं है कि जांच चालू नहीं है। जिस गवर्नमेंट ने बोगस रूप से यह जमा कराया है, यहां तक कि गवर्नमेंट आफिसर्स को दबाव डालकर, बैंक्स को दबाव डालकर, वहां के अधिकारियों पर दबाव डालकर, अपने बैंक से विदड्रा कर के पोस्ट आफिस में जमा कराया, इस वास्ते जमा करते हैं कि दो-तिहाई पैसा डेवलपमेंट फण्ड के लिए मिलता है, इसलिए यह सारी चीजें करते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि किस एजेन्सी ने यह करवाया ?

श्री बृजलाल वर्मा : बंसीलाल। इस वास्ते ऐसी बात नहीं है, यह सब किया गया है और जोर-जबर्दस्ती से अफसरों को दबाकर बैंक आफिसरों को दबा कर यह सारी चीजें उन्होंने की हैं।

जिन अधिकारियों ने इसमें एक्शन लेना है, [illegible] सूचित कर दिया है, उन्हें सूचित कर दिया है [illegible] यह मत सोचिये कि हम किस[illegible] चाहते हैं।

श्रीमती मृणाल गोरे : आपके आफिसर्स को इस प्रकार दबाया गया तो आपकी और भी जिम्मेदारी है, इसकी पूरी जांच करनी होगी, आप इसे परसू कीजिए।

श्री बृज लाल वर्मा : हमने कर दिया है।

श्रीमती मृणाल गोरे : नहीं तो आपके आफिसर्स और पोस्ट आफिसेज बदनाम हो रहे हैं। आपको यह करना चाहिये कि पूरी जांच सी० बी० आई० की तरफ से हो जाये।

श्री बृजलाल वर्मा : यह किया है और उसके साथ-साथ 14 करोड़ 54 लाख रुपये....

एक माननीय सदस्य : क्या यह सरकार इसकी इन्क्वायरी सी० बी० आई० को सौंपेगी ?

श्री बृज लाल वर्मा : इस प्रकार से जो प्राविन्शियल गवर्नमेंट ने कर्ज के रूप में ले लिया है उसकी वसूली के लिए फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने 7 किश्तें की हैं और हरियाणा गवर्नमेंट से वसूली कर रही है। इसकी भी कार्यवाही फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने कर दी है और उनसे वसूली शुरू हो गई है। यह सारी कार्यवाही हो रही है। जिस प्रकार से बोगस ढंग से जमा कर के ज्यादा पैसा कर्ज में ले लिया है, खर्च में लेने के लिए जो प्राविन्शल गवर्नमेंट ने जाल रचा है, वह इसका फायदा न उठा पाये, इसके लिए भी फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने कार्यवाही कर दी है। इस प्रकार से यह मत सोचिये कि किसी भी प्रकार से फाइनेन्स डिपार्टमेंट या इन्कमटैक्स डिपार्टमेंट चुप बैठा है। कार्यवाही शुरू हो गई है। क्योंकि यह पुरानी सरकार का गलत काम है और उस गलत काम को हम किसी भी प्रकार से बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो कुछ भी हो सकता है, नियमानुसार हम काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य यह न सोचें कि हम किसी बात को उनसे छिपायेंगे। यह सब से बड़ा स्थान है, जहां पर सारे देश के प्रतिनिधि हैं। हम उनसे कोई बात छिपायेंगे नहीं, और नियमानुसार जो भी उचित कार्यवाही होगी, उसको करेंगे, और इसमें किसी प्रकार से मुरव्वत नहीं करेंगे।

18.31 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 12, 1979/Chaitra 22, 1901 (Saka)

GMGIPND—M—430 L S—23-6-79—880

PLS. 40. XXV. 35, 79
880

© 1979 By Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and conduct of Business in Lok Sabha (Sixth Edition) and printed by the General Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi.